राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 250

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, रविवार, 16 फरवरी 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

जयशंकर बोले– चिंता मत करें, भारत अकेले सुलझा लेगा कश्मीर मसला

>>13

सरोकार

जंगल के 'मंगल' की खातिर पुराने रेलवे ट्रैक को टाटा

लखनऊ : लगातार घटते जंगल के बीच उप्र के लखीमपुर खीरी से बड़ी मिसाल

पेश होने जा रही है। वन्य जीवन बचा रहे, इसलिए कोर्ट के आदेश पर 127 साल पुराने उस मीटरगेज ट्रैक को आज से बंद कर दिया जाएगा, जो जंगल के बीच से गुजरता है। (पेज-15)

रविवार विशेष

एक अयोध्या प्रभु राम की, दूजी उनके नाम की

प्रयागराज : एक अयोध्या प्रयागराज में भी है, और यहां भी राम मंदिर के निर्माण

की तैयारी हो रही है। इस अयोध्या में भगवान जन्मे नहीं तो क्या हुआ, हर मन और तन में बसे हैं। बस्ती के हर व्यक्ति के नाम में राम समाहित हैं। पीढ़ियों से। (पेज-15)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▸ पृष्ठ 4

तेजस्वी से पहले बेरोजगार यात्रा वाली बस पर सवार हुआ विवाद

पटना : बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की बेरोजगारी हटाओ यात्रा के लिए जिस बस को तैयार किया गया है, उस पर उनसे पहले विवाद सवार हो गया है। राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि यह बस जिस व्यक्ति के नाम पर है, उसका नाम गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की सूची में है।

नेशनल न्यूज ▸ पृष्ठ 5

असहमति को राष्ट्र विरोधी बताना ठीक नहीं : जस्टिस चंद्रचूड़

अहमदाबाद : किसी मसले पर मतभेद होना और उसे उजागर करना लोकतंत्र का मूल तत्व है। इसके जरिये जनभावना सामने आती है। इसे राष्ट्रविरोधी या अलोकतांत्रिक ठहराना ठीक नहीं है। यह बात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कही है।

बिजनेस ▸ पृष्ठ 12

ई-वे बिल में फर्जीवाड़े पर कसेगी नकेल

नई दिल्ली : बिहार के चारा घोटाले में जिस तरह कागजों में स्कूटर पर कई-कई टन माल की ढुलाई हुई, उसी तर्ज पर ई-वे बिल में फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा है। सरकार ने तय किया है कि ई-वे बिल जनरेट करने के लिए वाहन का ट्रांसपोर्ट विभाग सिस्टम से जुड़ना अनिवार्य होगा।

अंतरराष्ट्रीय ▸ पृष्ठ 13

कश्मीर पर गूगल का दोहरा चरित्र उजागर

वॉशिंगटन : इंटरनेट पर सर्वाधिक लोकप्रिय सर्च इंजनों में से एक गूगल मैप्स ने एक अजीब करामात की है। यह देशों की सीमाएं जगह के हिसाब से बदलकर दिखाता है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत के बाहर से देखने पर यह कश्मीर की सीमा (आउटलाइन) को 'डॉटेड लाइन' के रूप में 'विवादित' बताता है।

टेलीकॉम सेक्टर के लिए राह बनाने में जुटी सरकार

तैयारी ▸ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली कमान, आला अधिकारियों के साथ बैठक

वोडाफोन आइडिया के दिवालिया प्रक्रिया में दाखिल होने के आसार

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) बकाये को लेकर जो रुख दिखाया है, उसके व्यापक असर को देखते हुए सरकार रास्ता निकालने में जुट गई है। मामले की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में है और कोशिश है कि इस फैसले के संदर्भ में दूरसंचार सेक्टर के लिए एक भावी रोडमैप तैयार किया जाए। रोडमैप में सरकार हर तरह का विकल्प लेकर आगे बढ़ रही है जिसमें वोडाफोन के दिवालिया होने की स्थिति में संभावित हालात से निपटने की योजना भी है। यह भी ध्यान रखा जाएगा कि ऐसी स्थिति में दूरसंचार क्षेत्र के ग्राहकों के हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे।

दूसरी तरफ, शुक्रवार को भारती एयरटेल के बाद शनिवार को वोडाफोन आइडिया ने भी एजीआर मद का अपना बकाया भुगतान करने की तैयारी के संकेत दिए हैं। हालांकि कंपनी ने दोहराया है कि भारत में उसका भविष्य पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट की 17 मार्च को होने वाली सुनवाई पर निर्भर करता है।

इस बीच, सूत्रों के मुताबिक दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने आदेश के बावजूद शुक्रवार रात तक बकाया भुगतान नहीं करने वाली टेलीकॉम कंपनियों को सोमवार शाम तक की मोहलत देने का मन बनाया है। अगर तब तक भी कंपनियां भुगतान नहीं करती हैं, तो विभाग उन पर कानूनी कार्रवाई शुरू करेगा।

उधर, उच्चपदस्थ सूत्रों ने इस बात पर चिंता जताई है कि दूरसंचार कंपनियों पर बकाये को लेकर जो माहौल बन रहा है वह इकोनॉमी के लिए सकारात्मक नहीं है। यही वजह है कि केंद्र सरकार इस समस्या के समाधान के लिए उच्चस्तरीय कदम उठाने में जुटी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में कैबिनेट सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, संचार मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के आला अधिकारियों की बैठक शुक्रवार से ही शुरू हो गई है। यह स्पष्ट है कि दूरसंचार कंपनियों को बकाया राशि का भुगतान करना होगा, लेकिन इससे जुड़ी दूसरी समस्याओं का भी समाधान निकालना होगा।

शुक्रवार को डीओटी की तरफ से सभी कंपनियों को यह नोटिस जारी किया कि उन्हें शुक्रवार को आधी रात से पहले ही बकाये राशि का भुगतान करना होगा। लेकिन शनिवार को देर शाम तक एक भी कंपनी की तरफ से कोई भी भुगतान नहीं हुआ है। एयरटेल ने सूचित किया है कि वह 20 फरवरी तक 10 हजार करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। सूत्रों का कहना है कि भुगतान नहीं करने की स्थिति में डीओटी उन पर आर्थिक जुर्माने से लेकर उनका लाइसेंस रद करने तक की कार्रवाई कर सकता है।

- कैबिनेट से विशेष प्रस्ताव पारित करवाने का विकल्प भी सामने
- सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 17 मार्च को होगी सुनवाई

अमित शाह फाइल

सरकार की चुनौती

- भुगतान करने की वजह से अगर कोई कंपनी दिवालिया होती है तो उसके ग्राहकों के हितों की रक्षा करनी होगी
- बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसी सरकारी कंपनियों पर भी एजीआर मद में हजारों करोड़ रुपये बकाया है, जिसके भुगतान की व्यवस्था करनी होगी
- दूरसंचार कंपनियों को कर्ज देने वाले बैंकों के हितों की रक्षा करनी होगी, इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एक समग्र रोडमैप बनाना होगा
- अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकार कैबिनेट से विशेष प्रस्ताव भी पारित करवा सकती है, अटॉर्नी जनरल से भी कई स्तरों पर विमर्श चल रहा है
- कोशिश यह हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान इस रोडमैप का एक विस्तृत मसौदा पीठ के सामने पेश किया जाए

आगे की कार्रवाई

- नोटिस के बावजूद शनिवार तक एक भी कंपनी ने नहीं किया भुगतान
- सोमवार को दूरसंचार विभाग फिर जारी कर सकता है नोटिस
- वोडाफोन की तरफ से हो सकता है बड़ा फैसला

अंदर के पन्नों में

टेलीकॉम कंपनियों की दुर्गति का अंजाम बैंकों को भुगतना होगा पेज>>3

कांग्रेस ने पूछा, टेलीकॉम कंपनियों पर 'कृपा' क्यों पेज>>3

दूरसंचार क्षेत्र का संकट पेज>>8

पीडीपी से इस्तीफा देकर बोले तांत्रे, लाश बन चुका था अनुच्छेद-370

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक शाह मोहम्मद तांत्रे ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी को कुछ लोग अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। अनुच्छेद-370 की समाप्ति का विरोध नाजायज है, क्योंकि बीते 70 सालों में तीन दर्जन से ज्यादा संशोधनों के चलते यह सिर्फ एक लाश ही था, जिसे हम ढो रहे थे। अच्छा हुआ यह खत्म हो गया।

2014 में जिला पुंछ की हवेली विधानसभा सीट से चुनाव जीतने वाले शाह मोहम्मद तांत्रे ने कहा कि हमने लोगों की बेहतरी के लिए सियासत को जरिया बनाते हुए पीडीपी का दामन थामा था। बीते माह हम कुछ लोगों दिलावर मीर, रफी अहमद मीर, जफर इकबाल, अब्दुल मजीद पडरु, राजा मंजूर, जावेद हसन बेग, कमर हुसैन, अब्दुल रहीम ने लोगों के मसलों के हल के लिए उपराज्यपाल से मुलाकात की। हमारी इस मुलाकात पर पार्टी के कुछ ओहदेदारों ने हम सभी को निकालने का फरमान जारी कर दिया।

यह वह पीडीपी नहीं है जो हीलिंग टच के लिए बनी थी पेज>>6

भारत की दो टूक, पाक पोषित आतंकवाद पर ध्यान दे तुर्की

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पाक-तुर्की के संयुक्त घोषणापत्र में कश्मीर के जिक्र पर भारत सख्त
- कहा-भारत के अंदरूनी मामलों में बोलने से बाज आए तुर्की, अपनी समझ बढ़ाए

कश्मीर मामले पर तुर्की के बेतुके बोल पर भारत ने सख्त आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि भारत के अंदरूनी मामलों से तुर्की दूरी बनाकर रखे। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने शुक्रवार को पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर काफी बयानबाजी की। शनिवार को भारत ने इस पर बेहद तल्ख प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह भारत के अंदरूनी हालातों पर प्रतिक्रिया देना बंद करें और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की तरफ ध्यान दें। इससे पहले कश्मीर मसले पर पाकिस्तान के सुर में बोलने वाले मलेशिया को भारत सबक सिखा चुका है। भारत ने मलेशिया से पाम ऑयल आयात को हतोत्साहित करने की दिशा में कदम उठाए थे। माना जा रहा है कि अगर तुर्की के बोल नहीं सुधरे तो इस दिशा में भी भारत सरकार कुछ कदम उठा सकती है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, 'तुर्की-पाकिस्तान संयुक्त घोषणापत्र में कश्मीर के संबंध में दिए गए बयान को भारत पूरी तरह खारिज करता है। हम तुर्की के नेतृत्व से कहना चाहते हैं कि भारत के अंदरूनी मुद्दों पर टिप्पणी से बाज आए और इस पूरे मामले पर अपनी समझ विकसित करे। पाकिस्तान के समर्थन से आतंकवाद किस तरह भारत व इस समूचे क्षेत्र के लिए खतरा पैदा कर रहा है, इस पर ध्यान दे।'

दरअसल, शुक्रवार को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इस्लामाबाद में राजकीय भाषण में कश्मीर का जिक्र किया और कहा कि कश्मीर के बारे में तुर्की वैसा ही सोचता है जैसा पाकिस्तान सोचता है। उसके बाद दोनों देशों के संयुक्त घोषणापत्र में भी कश्मीर को लेकर टिप्पणी की गई थी। गौरतलब है कि एर्दोगन सितंबर, 2019 में भी संयुक्त राष्ट्र महासम्मेलन में पाकिस्तान व मलेशिया के साथ मिलकर कश्मीर पर इस तरह का बयान दे चुके हैं।

रवीश कुमार की फाइल फोटो। एएफपी

पिछली बार एर्दोगन के बयान के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रस्तावित तुर्की यात्रा स्थगित कर दी थी। भारत ने इस बारे में आधिकारिक एलान से पहले ही यात्रा को लेकर दोनों देशों में चल रही बातचीत रोक दी थी। तुर्की के राष्ट्रपति ने फिर कश्मीर मुद्दा उठाकर भारत के खिलाफ कूटनीतिक चाल चली है। जिस तरह तुर्की ने पाकिस्तान के साथ रक्षा संबंधी रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश की है, भारत का ध्यान निश्चित तौर पर उसकी तरफ भी गया है। यही नहीं परमाणु संपन्न देशों के विशिष्ट संगठन एनएसजी में भारत की सदस्यता की राह में भी तुर्की इस कारण अड़ंगे लगाता है कि अभी उसमें पाकिस्तान को शामिल करने की कोशिश नहीं हो रही है। ऐसे में देखना होगा कि भारत अब तुर्की को लेकर किस तरह का कूटनीतिक कदम उठाता है।

एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बना रह सकता है पाकिस्तान पेज>>13

सीएए विरोधी धरने के लिए शायर इमरान को 1.4 करोड़ का नोटिस

मुरादाबाद : सीएए के विरोध में उप्र स्थित मुरादाबाद के ईदगाह पर चल रहे धरने में शामिल होना शायर इमरान प्रतापगढ़ी को भारी पड़ गया है। धारा-144 का उल्लंघन कर धरने में शामिल होने पर पुलिस ने उन्हें एक करोड़ चार लाख 8 हजार 693 रुपये वसूली का नोटिस भेजा है। पुलिस ने उनके वाट्सएप पर नोटिस भेजा है। वह पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर मुरादाबाद से चुनाव लड़ चुके हैं। अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम राजेश कुमार की तरफ से सीआरपीसी की धारा-111 के तहत पुलिस की रिपोर्ट पर यह नोटिस जारी हुआ है। (पेज-5)

क्रूज पर फंसे अपने नागरिकों को निकालेंगे भारत-अमेरिका

टोक्यो : भारत और अमेरिका ने कोरोना वायरस संक्रमण की आशंका में जापान में क्रूज पर फंसे अपने नागरिकों को निकालने का फैसला किया है। जापान के योकोहामा बंदरगाह पर खड़े इस शिप से अमेरिका रविवार शाम को विशेष विमान के जरिये अपने नागरिकों को निकालने का काम शुरू करेगा। भारत इसके लिए आइसोलेशन अवधि खत्म होने (यानी बुधवार तक) का इंतजार करेगा। इस बीच शिप में मौजूद 67 और लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इस तरह क्रूज पर संक्रमित होने वालों की संख्या 285 हो गई है। (पेज-13)

रामलीला मैदान में आज सीएम पद की शपथ लेंगे केजरीवाल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- गूंजेगा, 'इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा'
- दिल्ली के 50 लोगों के लिए बनाए गए दो विशेष मंच

दिल्ली विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीत दर्ज कर आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल रविवार को तीसरी बार रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दिसंबर 2013 और फरवरी 2015 में भी केजरीवाल ने इसी मैदान में सीएम पद की शपथ ली थी। बताया जा रहा है कि समारोह में मंच से केजरीवाल अपना पसंदीदा गीत 'इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा' भी गाएंगे।

रविवार को रामलीला मैदान के लगभग 20 फीट ऊंचे और 50 फीट के स्थायी मंच से केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 50 मेहमानों के बैठने के लिए मुख्य मंच की दोनों ओर विशेष मंच बनाए गए हैं, जो दो फीट नीचे हैं। इसके ठीक नीचे दाहिनी तरफ मीडिया के लिए मंच और सामने की तरफ नवनिर्वाचित विधायकों के बैठने की व्यवस्था होगी। समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता दिया गया है। दिल्ली के सातों सांसदों, सभी निगम पार्षदों, भाजपा व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों को भी आमंत्रित किया गया है। समारोह में मंत्री व विधायक परिवार के साथ शामिल होंगे।

शनिवार को आप के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि समारोह में पिछली बार से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। इसलिए 5-5 हजार लोगों के लिए अलग-अलग ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ही हमारी वीआइपी है। इसलिए दूसरे राज्यों के लोगों को नहीं बुलाया गया है।

अरविंद केजरीवाल। फाइल

मालूम हो कि केजरीवाल ने वर्ष 2013 में कांग्रेस के समर्थन से 49 दिनों तक सत्ता में रहने के बाद इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद फरवरी 2015 में हुए चुनाव में 70 में 67 सीटें जीती थीं। इस बार पार्टी ने 62 सीटें हासिल की हैं। 2013 व 2015 में उपराज्यपाल नजीब जंग ने शपथ दिलाई थी, इस बार उपराज्यपाल अनिल बैजल शपथ दिलाएंगे। यह वही मंच है, जहां से 2011 में अन्ना हजारे ने जनलोकपाल के लिए अनशन किया था। इस आंदोलन में केजरीवाल ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिसके बाद उन्होंने राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया।

मंच पर होंगे 'दिल्ली के 50 निर्माता' पेज>>2

मध्य प्रदेश का झगड़ा सोनिया तक पहुंचा सिंधिया ने बीच में छोड़ी समन्वय बैठक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कमलनाथ

- कमलनाथ ने दिया जवाब, कहा-चाहें तो सड़क पर उतर जाएं सिंधिया
- पार्टी के वरिष्ठ नेता डैमेज कंट्रोल में जुटे

ज्योतिरादित्य सिंधिया सभी फाइल

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच चल रही खींचतान अब पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी तक पहुंच गई है। शनिवार को दिल्ली में वैसे तो सरकार और संगठन के बीच आपसी समन्वय को मजबूत बनाने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बैठक रखी थी, लेकिन इसमें तल्खी इस कदर दिखी कि सिंधिया बैठक को बीच में छोड़कर चले गए। वहीं कमलनाथ भी सिंधिया को लेकर सख्त दिखे। बैठक खत्म होने के बाद जब उनसे सिंधिया के सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने के एलान को लेकर सवाल किया गया, तो नाराजगी भरे अंदाज में उन्होंने इसका जबाब दिया और कहा कि 'तो उतर जाएं।'

पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेताओं के बीच तल्खी बढ़ने की खबर सामने आने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। साथ ही पूरे मामले से सोनिया को भी अवगत कराया गया है। इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि 'पूरी कांग्रेस पार्टी सिंधिया जी के साथ है। हम सबने घोषणा पत्र में मिलकर वादे दिए थे। पांच सालों में कमलनाथ जी सभी वादों को पूरा करेंगे। ज्यादातर वादों पर काम तेजी से चल रहा है।' वहीं मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी महासचिव दीपक बाबरिया ने बताया कि बैठक में पार्टी नेताओं की बयानबाजी और अनुशासनहीनता को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन बैठक में सिंधिया के बयानों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। इस बीच उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बैठक छोड़कर जाने के सवाल पर उनका बचाव किया और कहा कि 'पहले से उनकी कोई बैठक तय थी, इसलिए वह जल्दी चले गए।'

पार्टी सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ के घर पर हुई इस बैठक में सिंधिया के साथ कई मुद्दों पर नोकझोंक हुई। इस बैठक में कमलनाथ और सिंधिया के अलावा दिग्विजय, दीपक बाबरिया, जीतू पटवारी, अरुण यादव, मीनाक्षी नटराजन मौजूद थे। इस बीच पार्टी समन्वय समिति की अगली बैठक में भोपाल में करने को लेकर भी सहमति बनी है।

गेस्ट शिक्षकों को नियमित करने का मसला : बता दें कि सिंधिया चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादे के मुताबिक किसानों की कर्ज माफ और गेस्ट शिक्षकों को नियमित नहीं किए जाने से नाराज हैं। इसी को लेकर उन्होंने गुरुवार को कहा था कि वादे पूरे नहीं हुए तो वो कमलनाथ सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। कमलनाथ का कहना है कि घोषणापत्र में पांच साल के लिए वादे किए गए हैं, पांच महीने में पूरे करने के लिए नहीं।

सिंधिया की अपनी ही सरकार के खिलाफ मुखालफत की कई हैं वजहें पेज>>4

दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति ने मार्क जुकरबर्ग का हवाला देकर किया दावा- सोशल नेटवर्किंग साइट पर मैं नंबर वन, मोदी दूसरे स्थान पर, ट्वीट में भारत दौरे को लेकर कहा, बेसब्री से कर रहा हूं इंतजार

फेसबुक पर मोदी को नंबर दो बताकर फंसे ट्रंप

वाशिंगटन, प्रेट्र : भारत दौरे को लेकर उत्साहित अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फेसबुक पर फॉलोअर्स के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नंबर दो बताकर फंस गए हैं। उन्होंने कहा कि सोशल नेटवर्किंग साइट ने अपने प्लेटफार्म पर लोकप्रियता के मामले में मुझे नंबर एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरे नंबर पर रखा है। यह बड़े सम्मान की बात है। हालांकि, ट्रंप के दावे के उलट रिकार्ड की बात करें तो फॉलोअर्स के मामले में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बड़ा अंतर है। मोदी के फॉलोअर्स करीब साढ़े चार करोड़ तो ट्रंप के तीन करोड़ से भी कम हैं।

ट्रंप ने फेसबुक के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग के हवाले से दावा किया। उन्होंने शनिवार को ट्वीट के जरिये कहा, 'मुझे लगता है कि बड़े सम्मान की बात है। मार्क जुकरबर्ग ने हाल में बताया, ''डोनाल्ड जे. ट्रंप नंबर वन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे नंबर पर हैं। दरअसल मैं दो हफ्ते में भारत जा रहा हूं। मुझे इसका बेसब्री से इंतजार है।'' ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया के साथ 24 और 25 फरवरी को भारत के पहले दौरे पर रहेंगे। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे के दौरान नई दिल्ली और अहमदाबाद की यात्रा करेंगे।

वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में पत्नी मेलानिया के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप दंपती फ्लोरिडा के पाम बीच स्थित मर-ए-लागो स्टेट रवाना हुए। यहां वह सप्ताहांत छुट्टियां व्यतीत करेंगे। एपी

ये हैं फॉलोअर्स के सरताज

- 12.5 करोड़ फॉलोअर्स दिग्गज फुटबाल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हैं
- 10 करोड़ फॉलोअर्स कोलंबिया की सिंगर शकीरा के हैं

पहले भी कर चुके हैं दावा : फेसबुक पर लोकप्रियता के मामले में ट्रंप पहले भी खुद को शीर्ष पर और प्रधानमंत्री मोदी को दूसरे पायदान पर होने का दावा कर चुके हैं। उन्होंने पिछले माह दावोस में वर्ल्ड इकोनामिक फोरम से इतर एक इंटरव्यू में कहा था, 'मैं फेसबुक पर नंबर वन हूं और आप जानते हैं कि दूसरे स्थान पर कौन हैं? भारत के मोदी।'

यह कहता है रिकार्ड

समाचार एजेंसी एएनआइ के अनुसार, फैक्ट चेकिंग में ट्रंप के दावे के उलट तथ्य सामने आए हैं। फॉलोअर्स और लाइक्स के मामले में मोदी और ट्रंप में बड़ा अंतर है। फेसबुक पर प्रधानमंत्री मोदी के करीब 4.4 करोड़ और ट्रंप के 2.75 करोड़ फॉलोअर्स हैं। लाइक्स के मामले में भी बड़ा अंतर है। मोदी के 4.45 करोड़ और ट्रंप के पास 2.6 करोड़ लाइक्स हैं।

सियासी हस्तियों में सबसे आगे ओबामा

सियासी हस्तियों के फॉलोअर्स के मामले में मोदी और ट्रंप से आगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा हैं। उनके 5.35 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ओबामा के लाइक्स की संख्या 5.5 करोड़ है।

एसटी पुलिसकर्मियों पर मेहरबानी को लेकर घिरी ममता सरकार

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- पुरस्कृत करने को लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना
- विरोधी दलों ने लिया आड़े हाथ, कहा- निकाय व विस चुनाव के चलते किया ऐसा

कोलकाता के पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी थानों व ट्रैफिक गार्ड को जारी की गई एक अधिसूचना को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। गत 11 फरवरी को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अनुसूचित (तफसिली) जनजाति समुदाय के जो पुलिस कर्मचारी विभाग में बेहतर कार्य कर रहे हैं, उनकी सूची तैयार कर पुलिस मुख्यालय को भेजी जाए। पुलिस मुख्यालय उक्त कर्मचारियों को पुरस्कृत करेगा। इसको लेकर बंगाल की ममता सरकार घिर गई है। सभी विपक्षी दलों, भाजपा, कांग्रेस और माकपा ने उसको आड़े हाथों लिया है।

पुलिस मुख्यालय के इस फैसले को जानकार राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। उनका मानना है कि गत लोकसभा चुनाव में इस समुदाय के वोट से वंचित होने के कारण अब सरकार अनुसूचित जनजाति के पुलिसकर्मियों पर मेहरबान हो गई है। इसका एक और उदाहरण यह है कि पिछले दिनों पेश हुए राज्य के बजट में सरकार ने बंधु व जय जोहार नाम की दो योजनाएं शुरू करने की घोषणा की थीं, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति समुदाय के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1000 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी इस तरह की अधिसूचना में जानकार सियासी हित देख रहे हैं।

सभी पुलिस कर्मचारियों को समान नजरिये से देखना चाहिए : तालुकदार पेज>>4

मंच पर होंगे 'दिल्ली के 50 निर्माता'

पहल ▶ सफाई कर्मचारी, डॉक्टर समेत विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले आमंत्रित

सिसोदिया बोले, दिल्ली के विकास को इनके सहयोग से आगे बढ़ाया जाएगा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में इस बार मुख्यमंत्री केजरीवाल के मंच पर सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, बाइक एंबुलेंस चालक, अभियंताओं समेत विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले 50 लोग भी मौजूद रहेंगे। इन्हें दिल्ली के निर्माता नाम से सम्मान दिया गया है।

आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने शनिवार को प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि दिल्ली के हर एक आदमी का एक सपना है कि हमारी दिल्ली कुछ अलग होनी चाहिए। इसे इनके सहयोग से आगे बढ़ाया जाएगा। सपनों के ये निर्माता अपने-अपने क्षेत्र के कार्य का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ उनके मंच पर साथ रहेंगे। सिसोदिया ने कहा कि यह आम आदमी की बड़ी जीत है। इन लोगों ने केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस और केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को जिताया है। यह दिल्ली के उन लोगों की जीत है, जो दिल्ली को लेकर सपना देखते हैं। जो लोग दिल्ली को बनाते हैं, दिल्ली को चलाते हैं, यह उनकी जीत है। उनको एक 'करप्शन फ्री गवर्नेंस' मिली, एक मददगार सरकार मिली। इसलिए केजरीवाल ने यह तय किया कि शपथ ग्रहण में उनके मेहमान भी वही लोग होंगे, जिन्होंने दिल्ली को बनाया है। इनमें दिल्ली के उद्योगपति, व्यापारी, दुकानदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वकील, पत्रकार, खिलाड़ी, छात्र, बस ड्राइवर, दिल्ली के सफाई कर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता सहित हर क्षेत्र के लोग हैं। इन क्षेत्रों से करीब 50 लोग यहां मौजूद रहेंगे। ये केजरीवाल के साथ मंच पर मौजूद रहेंगे। केजरीवाल ने पूरी दिल्ली को खुला निमंत्रण दिया है कि आप लोग यहां आएं।

सिसोदिया ने कहा कि शिक्षा का क्षेत्र चुनाव में बड़ा मुद्दा रहा है इसलिए यहां शिक्षा से जुड़े लोग भी रहेंगे। काफी शिक्षकों के फोन आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम भी शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। काफी स्कूल प्रमुख भी यहां रहेंगे। 50 विशेष मेहमान होंगे। ये मेहमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ स्टेज पर उपस्थित रहेंगे। दिल्ली के निर्माताओं में विशेष रूप से स्कूल प्रमुख, स्कूल के चपरासी को बैठाया जाएगा। छात्रों का प्रजेंटेशन भी होगा।

सिसोदिया ने कहा कि इनमें मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर भी रहेंगे। दिल्ली के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति के अंदर बैठा फरिश्ता है। उस फरिश्ते को और मजबूत करने के लिए केजरीवाल पिछले कार्यकाल में फरिश्ते योजना लेकर आए। इसके तहत बहुत सारे लोगों ने समय रहते हुए हिम्मत करके बहुत सारे लोगों की जानें बचाईं। फायर फाइटर्स की फैमिली का भी प्रतिनिधित्व रहेगा। दिल्ली के सफाई कर्मियों एवं बस मार्शल भी मंच पर रहेंगे। मंच पर बस व मेट्रो ड्राइवर, बस कंडक्टर, ऑटो ड्राइवर, सिग्नेचर ब्रिज बनाने वाले आर्किटेक्ट, अनधिकृत कॉलोनियों में पूरे पांच साल तक काम करने वाले इंजीनियर्स एवं वर्कर्स भी रहेंगे। दिल्ली के किसान भी वहां होंगे।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयार ऐतिहासिक रामलीला मैदान। संजय

पिछली सरकार में मंत्रियों को मिले विभाग

अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री

जल विभाग

मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री शिक्षा, वित्त, योजना, पर्यटन, सतर्कता, सेवाएं, महिला एवं बाल विकास, कला एवं संस्कृति व भाषा, इसके अलावा वे सभी विभाग जो अन्य किसी मंत्री को आवंटित नहीं हैं।

सत्येंद्र जैन : स्वास्थ्य, उद्योग, लोक निर्माण विभाग, बिजली, गृह और शहरी विकास विभाग

गोपाल राय : श्रम व रोजगार, विकास, सामान्य प्रशासन विभाग, बाढ़ एवं नियंत्रण विभाग

इमरान हुसैन : खाद्य एवं आपूर्ति और चुनाव विभाग

राजेंद्रपाल गौतम : गुरुद्वारा इलेक्शन, अनुसूचित जाति-जनजाति व समाज कल्याण विभाग

कैलाश गहलोत : परिवहन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, राजस्व, कानून एवं न्याय और पर्यावरण

भावी कैबिनेट के साथ तीन माह के एजेंडे पर केजरीवाल ने की चर्चा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने सरकार की प्राथमिकताओं एवं योजनाओं को तेजी से क्रियान्वित करने के लिए शनिवार को अपने भावी मंत्रिमंडल के साथ एक्शन प्लान पर चर्चा की। सीएम आवास में डिनर की टेबल पर मुख्यमंत्री एवं उनके कैबिनेट सहयोगियों के बीच सरकार के तीन महीने के एजेंडे पर बात हुई।

दिल्ली सरकार की प्राथमिकताएं तय की गईं और साथ ही दिल्ली को ग्लोबल सिटी बनाने के रोडमैप पर भी चर्चा की गई। डिनर टेबल पर आप सरकार के डेवलेपमेंट मॉडल पर हुई चर्चा की जानकारी देते हुए सीएम के कैबिनेट सहयोगी मनीष सिसोदिया ने बताया कि सभी मंत्रियों को शपथ लेते ही तुरंत केजरीवाल की दस गारंटी वाले चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में तेजी से काम करना है। चुनाव के दौरान किए गए गारंटी कार्ड वादे के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य मुद्दों पर सरकार बनने के बाद केजरीवाल सहित सभी मंत्रियों का खास ध्यान रहेगा। सिसोदिया ने कहा कि कुछ चीजें तुरंत होंगी तो कुछ में समय लगेगा लेकिन हमारी सरकार हर काम को पूरी लगन एवं मेहनत के साथ करेगी क्योंकि इन कामों के लिए ही हमें चुना गया है।

गोपाल राय ने रामलीला मैदान में तैयारियों का जायजा लिया

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली में चुनी गई नई सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों की निगरानी के लिए दिल्ली सरकार की पूरी सरकारी मशीनरी के साथ ही पार्टी के नेता और पदाधिकारी भी सक्रिय हैं। शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। राय ने तैयारियों में लगे लोगों से जानकारी ली और पूछा कि लोगों के बैठने की क्या व्यवस्था है।

दिल्ली के ऐतिहासिक सफर का हमसफर रामलीला मैदान

संजीव कुमार मिश्र, नई दिल्ली

- स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल सरीखे नेताओं ने यहां कई रैलियां कीं
- मैदान की जगह पर था तालाब, आसपास बस्तियां थीं, इस कारण इसे बस्ती का तालाब कहा जाता था।

दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को अरविंद केजरीवाल की ताजपोशी होगी। करीने से सजी कुर्सियां और फूलों से महकता स्टेज मैदान की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। यहां यह जानना भी दिलचस्प है कि दिल्ली के ऐतिहासिक सफर का हमसफर रहा यह मैदान कभी तालाब हुआ करता था। इसके आसपास बस्तियां थीं। इस कारण इसे बस्ती का तालाब कहा जाता था।

इतिहासकार आरवी स्मिथ कहते हैं कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की सेना में हिंदू सैनिक बहुतायत थे। सैनिक लाल किले के पीछे यमुना के रेत पर रामलीला का मंचन करते थे। 1845 में तालाब के बड़े हिस्से को समतल कर मैदान बना दिया गया। बाद में सैनिकों ने यहीं रामलीला का मंचन शुरू किया, जिसके बाद यह रामलीला मैदान के नाम से प्रचलित हो गया। लेकिन 1880 के बाद यह मैदान ब्रितानिया सिपाहियों के संरक्षण में आ गया। सिपाहियों ने यहां कैंप बनाए, जहां लंबी ड्यूटी के बाद सिपाही आराम करते। सिपाहियों के जाने के बाद काफी समय तक यह मैदान बच्चों के खेलकूद के लिए ही इस्तेमाल होता रहा। हालांकि बाद के वर्षों में जैसे-जैसे दिल्ली की आबादी बढ़ी, खुले स्थानों की कमी हुई, तो यह मैदान रैलियों, जनसभाओं समेत बड़े कार्यक्रमों के लिए उपयोग होने लगा।

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल सरीखे नेताओं ने यहां से कई रैलियां कीं। ऐसा भी कहा जाता है कि सन 1945 में यहां मोहम्मद अली जिन्ना ने एक रैली की थी। जब जिन्ना रैली में बोलने लगे तो भीड़ में से कुछ लोगों ने मौलाना जिन्ना जिंदाबाद के नारे लगाए। जिन्ना ने मौलाना की इस उपाधि पर नाराजगी जताई और कहा कि वह राजनीतिक नेता हैं न कि धार्मिक मौलाना। स्मिथ कहते हैं कि सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए भी इसका खूब प्रयोग हुआ। दिसंबर 1952 में जम्मू-कश्मीर के मसले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यहां सत्याग्रह किया था। प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने 1956 और 57 में मैदान में विशाल जनसभाएं कीं।

जब भावुक हो गए जवाहर लाल नेहरू

रामलीला मैदान में 28 जनवरी 1961 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ भी आई थीं। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था। भारत-चीन के बीच युद्ध के बाद 26 जनवरी 1963 को यहां एक जनसभा का आयोजन किया गया था। युद्ध के ठीक दो महीने बाद आयोजित इस कार्यक्रम में लता मंगेशकर ने ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी गाना गाया था। कहते हैं, पंडित जवाहर लाल नेहरू समेत सभा में मौजूद हर एक शख्स की आंखें नम हो गई थीं। गाने का एक साउंड ट्रैक भी नेहरू जी को बतौर उपहार दिया गया। इसके दो साल बाद सन 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी रामलीला मैदान में एक सभा का आयोजन किया था। इसमें उन्होंने जय जवान, जय किसान का नारा एक बार फिर दोहराया था। 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के निर्माण और पाकिस्तान से युद्ध जीतने का जश्न मनाने के लिए इसी मैदान में एक बड़ी रैली की थी।

गुप्ता के साथ ही बिष्ट और बिधूड़ी भी नेता प्रतिपक्ष की रेस में

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- भाजपा के हैं आठ विधायक, पार्टी हाई कमान की ओर टिकी हुई है सबकी नजरें

विधानसभा चुनाव में भाजपा को आठ सीटें मिली हैं और नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में प्रमुख रूप से तीन विधायक शामिल बताए जा रहे हैं। पार्टी विधायक दल की बैठक की तिथि अभी तय नहीं हुई है। अगले सप्ताह बैठक हो सकती है। इसके साथ ही संभावना जताई जा रही है कि पार्टी हाई कमान द्वारा नेता प्रतिपक्ष के नाम पर अंतिम फैसला लिया जाएगा और विधायकों की बैठक के बाद इसकी घोषणा की जाएगी।

इस बार विजेंद्र गुप्ता, मोहन सिंह बिष्ट, रामबीर सिंह बिधूड़ी, ओमप्रकाश शर्मा, अभय वर्मा, जितेंद्र महाजन, अनिल वाजपेयी, अजय महावर चुनाव जीते हैं। करावल नगर से पांचवीं बार जीत हासिल करने वाले बिष्ट और बदरपुर से चौथी बार विधानसभा पहुंचे रामबीर सिंह बिधूड़ी को भी इस पद का दावेदार माना जा रहा है।

गौरतलब है कि पिछली बार भाजपा को मात्र तीन सीटें मिली थीं। विजेंद्र गुप्ता, ओपी शर्मा और जगदीश प्रधान विधानसभा पहुंचने में सफल रहे थे। गुप्ता को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। इस बार भी वह विधानसभा पहुंचने में सफल रहे हैं, लेकिन उन्हें नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिलेगी या नहीं, इस पर अब तक फैसला नहीं हुआ है।

बिधूड़ी को मिला था सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार

रामबीर सिंह बिधूड़ी अनुभवी विधायक हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले बिधूड़ी कई पार्टियों में रह चुके हैं। 1993 में वह जनता दल के टिकट पर विधानसभा पहुंचते थे। जनता दल विधायक दल के नेता भी चुने गुए थे। उसके बाद वह वर्ष 2003 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक का भी पुरस्कार मिला था। वर्ष 2012 में भाजपा में शामिल हुए और 2013 में वह विधानसभा पहुंचे थे। 2015 में चुनाव हारने के बाद इस बार फिर से वह विधायक चुने गए हैं।

भाजपा के पुराने नेता हैं बिष्ट

दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट भाजपा के पुराने नेता हैं। 1998 से 2013 तक वह लगातार करावल नगर से चुनाव जीतते रहे हैं। 2015 में उन्हें हार मिली थी, लेकिन एक बार फिर से वह चुनाव जीतने में सफल रहे हैं।

बड़ी राजनीतिक घटनाओं का भी रहा गवाह

मैदान धर्म, स्वतंत्रता संग्राम ही नहीं अपितु बड़ी राजनीतिक घटनाओं के लिए भी जाना जाता है। सन 1975 में 25 जून को रामलीला मैदान से ही लोकनायक जय प्रकाश नारायण ने हुंकार भरी थी। विपक्षी नेताओं के साथ इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था। 'सिंहासन खाली करो कि जनता आती है' का नारा यहां गूंज पड़ा। सरकार ने 25-26 जून 1975 की रात आपातकाल लगा दिया। सन 1977 में यहां फिर से विपक्षी दलों की गर्जना हुई। जनता पार्टी के बैनर तले बाबू जगजीवन राम के नेतृत्व में कांग्रेस छोड़कर आए मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और चंद्रशेखर के साथ भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन रूप जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी इसी मैदान के मंच पर एक साथ नजर आए। जून 2011 में बाबा रामदेव प्रकरण और फिर अन्ना आंदोलन का भी यह मैदान गवाह बना। यह मैदान आम आदमी पार्टी के राजनीतिक सफर का भी गवाह बना। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसी मैदान पर पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब रविवार को वह तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

मेट्रो में महिला से छेड़छाड़, मौन रहे यात्री

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

महिलाओं के लिए सुरक्षित मानी जाने वाली मेट्रो में एक महिला के साथ फिर छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। घटना ब्लू लाइन मेट्रो में घटी। पीड़िता के मुताबिक यात्रा के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर एक शख्स लगातार उनकी पीठ को छूता रहा। पीड़िता ने उसे दूर रहने की हिदायत भी दी, लेकिन वह हरकत से बाज नहीं आया। पीड़िता ने इस संबंध में ट्विटर पर दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन में शिकायत की है। मेट्रो पुलिस भी मामले की छानबीन में जुट गई है। इससे पहले गत बुधवार को येलो लाइन मेट्रो में भी युवती से अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया था। चार दिन में महिलाओं के साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ के दो मामले सामने आने से मेट्रो अधिकारी चिंतित हैं। मेट्रो में महिला सुरक्षा पर सवाल भी उठने लगे हैं।

पीड़ित महिला ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के ट्विटर पर शुक्रवार को घटना की जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा है कि ब्लू लाइन में यात्रा के दौरान भीड़ में एक शख्स ने खुलेआम उन्हें प्रताड़ित किया। वह उनकी पीठ को छूता रहा। उन्होंने आरोपित को ऐसा करने से रोका, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस दौरान कोच में सवार किसी यात्री ने भी मदद नहीं की।

पीड़िता ने लिखा है कि भीड़भाड़ वाली मेट्रो में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिला सुरक्षा के लिए हर कोच में एक पुलिसकर्मी नियुक्त किया जाना चाहिए। साथ ही पीड़िता ने इस प्रकार की घटना को कम करने के लिए मेट्रो में महिला कोच की संख्या भी बढ़ाने की मांग की। इस संबंध में मेट्रो पुलिस का कहना है कि पीड़िता से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। उनसे जानकारी मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधर, डीएमआरसी ने ट्वीट कर पीड़िता से घटना के बारे में पूरी जानकारी देने की बात कही। इससे पहले येलो लाइन मेट्रो में बुधवार को एक युवती के साथ एक शख्स ने अश्लील हरकत की थी। गुरुग्राम निवासी युवती दिल्ली में नौकरी करती हैं। घटना के वक्त वह वापस अपने घर जा रही थीं। तभी युवक ने उनके साथ अश्लील हरकत की। युवती ने आरोपित की तस्वीर भी ले ली थी। बाद में उन्होंने घटना के बारे में घिटोरनी मेट्रो पुलिस में शिकायत दी थी।

अश्लील हरकतें करने वाला इंजीनियर गिरफ्तार : येलो लाइन मेट्रो में युवती से अश्लील हरकतें करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित अभिलाश कुमार गुरुग्राम का रहने वाला है और बतौर सिविल इंजीनियर प्राइवेट कंपनी में कार्य करता है। पुलिस ने आरोपित को उसके मेट्रो कार्ड के रिचार्ज के माध्यम से पकड़ा है।

> मेट्रो में छेड़खानी की शिकायतों को डीएमआरसी ने गंभीरता से लिया है। येलो लाइन पर हुई पहली घटना में घिटोरनी मेट्रो थाने में मामला दर्ज कर पुलिस कार्रवाई कर रही है। छेड़खानी की दूसरी घटना की भी जांच चल रही है। मेट्रो का सुरक्षा विभाग लगातार मामले पर नजर रख रहा है और पुलिस को जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
>
> -अनुज दयाल, प्रवक्ता, डीएमआरसी

पार्क होटल में आग, न दमकल को पता न पुलिस को खबर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- धुएं से तबियत बिगड़ने पर 11 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया
- दमकल विभाग ने होटल प्रबंधन को जारी किया कारण बताओ नोटिस

कनाट प्लेस स्थित द पार्क होटल के बेसमेंट में जेनरेटर यूनिट में शनिवार सुबह आग लग गई। धुएं से 11 लोगों की तबीयत बिगड़ गई।

उधर, इसकी सूचना होटल कर्मियों ने पुलिस और दमकल विभाग को नहीं दी और अपने स्तर पर ही गुपचुप तरीके से आग को बुझा दिया। कुछ देर बाद आग दोबारा भड़क उठी। इसका धुआं एयर कंडीशनिंग सिस्टम और शाफ्ट के जरिये ऊपर की मंजिलों के कमरों में भर गया। कमरों में धुआं भरने से होटल में ठहरे लोगों का दम घुटने लगा। इस वजह से चौदह लोगों की तबीयत बिगड़ गई और एक होटल का कर्मचारी राहत कार्य के दौरान शीशा टूटने की वजह से जख्मी हो गया। इसके बाद 11 लोगों को गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन 11 लोगों में से नौ लोग नार्वे के नागरिक हैं। इनमें से नार्वे नागरिक आबदी बाशिर व जोशिम वान सहित गुरुग्राम निवासी कुंदन राय का इलाज चल रहा है। अन्य आठ को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई थी।

दमकल विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि होटल ने आग की घटना को छिपाए रखा। शुक्र है कि आग काबू में हो गई। यदि आग तेजी से फैलती तो वहां ठहरे विदेशियों सहित अन्य की जान खतरे में पड़ सकती थी। दमकल विभाग ने होटल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विभाग के अधिकारियों की टीम होटल का निरीक्षण करेगी। देखा जाएगा कि आग के पीछे की वजह क्या थी। वहां क्या खामियां हैं। इस संबंध में जब होटल प्रबंधन से बात की गई तो उन्होंने मेल पर जानकारी देने का आश्वासन दिया, लेकिन खबर लिखे जाने तक कोई मेल प्राप्त नहीं हुआ।

होटल से मात्र 100 मीटर दूर है संसद मार्ग थाना

दरअसल द पार्क होटल संसद मार्ग थाने से कुछ सौ मीटर पर स्थित है। वहीं, दमकल विभाग का मुख्यालय भी करीब है। नई दिल्ली के एडिशनल डीसीपी दीपक यादव ने बताया कि होटल से न तो पुलिस को और न ही दमकल विभाग को सूचना मिली थी। अस्पताल ने राजेंद्र नगर थाने को सूचित किया था। जिसके बाद कॉल को संसद मार्ग थाने में स्थानांतरित कर दिया गया था। वहीं बाद में पुलिस ने होटल पार्क में लगी आग के बारे में दमकल विभाग को बताया था।

> फिलहाल अस्पताल में मरीजों का इलाज जारी है। उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है। कुछ लोगों का इलाज करने के बाद उनको छुट्टी दे दी गई है।
>
> -डॉ. एस कटोक्ष, अतिरिक्त निदेशक (मेडिकल), गंगा राम अस्पताल

नौ बजे हुई थी घटना, पौने बारह बजे मिली पुलिस को सूचना

पुलिस के मुताबिक पार्क होटल में आग की घटना सुबह करीब नौ बजे हुई थी। मामला ज्यादा न बढ़े इसके लिए होटल कर्मियों ने आग को अपने स्तर पर बुझा दिया था। लेकिन दोबारा से आग फिर से सुलग उठी। पुलिस के अनुसार घटना की जानकारी गंगा राम अस्पताल ने राजेंद्र नगर थाना पुलिस को शनिवार सुबह पौने बारह बजे दी थी। दमकल विभाग को 12.22 बजे घटना के बारे में बताया गया।

कमरे का शीशा तोड़कर लोगों को बाहर निकाला

जब धुआं होटल के कमरों तक पहुंच गया तो कमरों में मौजूद लोगों को परेशानी होने लगी। उनका दम घुटने लगा तो वे बाहर की ओर भागे। इस दौरान कमरों में फंसे कुछ लोगों को होटल स्टाफ ने कमरे का शीशा तोड़कर बाहर निकाला। इसमें स्टाफ का एक सदस्य भी घायल हो गया। उसका भी अस्पताल में इलाज करवाया गया।

समस्या

शादी के बाद ससुराल के लोगों से बीमारी की बात छिपाती हैं महिलाएं, एम्स में डॉक्टरों के सामने आ चुके हैं इस तरह के 7-8 मामले

सिलियक की बात छिपाना शादीशुदा जिंदगी पर पड़ा भारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

गेहूं में मौजूद ग्लूटेन प्रोटीन की एलर्जी के कारण सिलियक रोग से किसी भी उम्र में लोग पीड़ित हो सकते हैं। लेकिन अक्सर बचपन में यह बीमारी उभरकर सामने आती है। यह रोग होने पर जीवनभर ग्लूटेन फ्री (मुक्त) भोजन आवश्यक है। एम्स में शनिवार को इस बीमारी पर आयोजित सम्मेलन में संस्थान के डॉक्टरों ने कहा कि ओपीडी में इस बीमारी से पीड़ित कई ऐसी महिलाएं पहुंचती हैं जिन्होंने शादी के बाद ससुराल के लोगों से बीमारी की बात छिपाई और ग्लूटेन फ्री भोजन बंद कर दिया। जिससे सेहत तो खराब होती ही है, कई महिला मरीजों की शादीशुदा जिंदगी भी प्रभावित हुई।

एम्स के गैस्ट्रोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. गोविंद मखारिया ने कहा कि देश में 0.67 फीसद लोग सिलियक रोग से पीड़ित हैं। यह बीमारी गेहूं व जौ में मौजूद ग्लूटेन प्रोटीन की एलर्जी के कारण होती है। गेहूं में मौजूद 10 ग्राम प्रोटीन में से आठ ग्राम ग्लूटेन प्रोटीन होता है। कई लोगों को इससे एलर्जी होती है। इस वजह से भोजन पच नहीं पाता। इस कारण बच्चे एनीमिया से पीड़ित हो जाते हैं और उनका कद बढ़ नहीं पाता। एम्स की हर ओपीडी में 70 से 80 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। मौजूदा समय में एम्स में करीब 1300 मरीजों का इलाज जारी है। डॉ. मखारिया ने कहा कि सात से आठ ऐसे मामले देखे गए हैं, जिनमें महिला मरीजों द्वारा शादी के बाद बीमारी की बात छिपाने से उनकी शादीशुदा जिंदगी प्रभावित हुई। एक महिला मरीज शादी के चार साल बाद इलाज के लिए पहुंची। उनकी सेहत में लगातार गिरावट के कारण वह दुबली हो गई थीं और बीमार रहने के कारण प्रेगनेंसी में दिक्कत हुई। इस वजह से तलाक भी हो गया। इलाज के बाद उन्होंने दूसरी शादी की और मां भी बनीं। इसलिए बीमारी होने पर इसे छिपाना नहीं चाहिए।

15 खाद्य वस्तुओं पर ग्लूटेन मुक्त का दावा निकला गलत

सिलियक से पीड़ित लोगों के लिए बाजार में बिस्कुट, केक, सहित कई तरह की खाद्य वस्तुएं बिकती हैं, जिसे ग्लूटेन मुक्त होने का दावा किया जाता है। इसके मद्देनजर एम्स के डॉक्टरों ने दिल्ली के विभिन्न स्टोर व ऑनलाइन स्टोर से खाद्य वस्तुओं के 700 सैंपल लेकर जांच की। इनमें से 85 फीसद सैंपल सही पाए गए लेकिन 15 फीसद सैंपल में ग्लूटेन मुक्त होने का दावा गलत पाया गया। जल्द ही एम्स इस अध्ययन को मेडिकल जर्नल में प्रकाशित करेगा।

लिपस्टिक में भी इस्तेमाल होता है ग्लूटेन

एम्स के डॉक्टर कहते हैं कि लिपिस्टक में भी ग्लूटेन का इस्तेमाल होता है। इसलिए सिलियक रोग से पीड़ित महिलाओं को इसके इस्तेमाल के प्रति सचेत रहना चाहिए। चिप्स व आइसक्रीम में भी ग्लूटेन का इस्तेमाल होता है।

मक्का, फल, सब्जियों का इस्तेमाल पीड़ितों के लिए फायदेमंद

मक्का, चने की मिक्स आटा, दाल, फल व हरी सब्जियां इस बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए फायदेमंद होती हैं। एम्स के गैस्ट्रॉलॉजी विभाग के डॉ. अनुप सराया ने बताया कि आटे में 50 मिलीग्राम ग्लूटेन की मौजूदगी भी मरीज के लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए घर में चक्की रखकर खुद मिक्स आटा तैयार करें।

एम्स में घटेगी सर्जरी की वेटिंग मई में शुरू होगा सर्जिकल ब्लॉक

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- नवनिर्मित सर्जिकल ब्लॉक में 12 मॉड्युलर ऑपरेशन थियेटर तैयार
- पहले फेज में 100 बेड के साथ शुरू होगी चिकित्सा सुविधा

एम्स में नए ओपीडी ब्लॉक में छह विभागों की ओपीडी सेवा शुरू होने के बाद मरीजों के लिए एक और राहत की खबर यह है कि नवनिर्मित सर्जिकल ब्लॉक में भी जल्द चिकित्सा सुविधा शुरू होगी। एम्स प्रशासन ने इसके लिए तैयारी शुरू दी है। दो फेज में नवनिर्मित सर्जिकल ब्लॉक में चिकित्सा सुविधाएं शुरू होंगी। पहले फेज में मई के अंत तक 100 बेड के साथ इस सर्जिकल ब्लॉक में मरीजों का इलाज शुरू होगा। इससे किडनी प्रत्यारोपण व अन्य सर्जरी की वेटिंग कम होने की उम्मीद है।

उल्लेखनीय है कि एम्स में मरीजों का भारी दबाव है। इसलिए मरीजों को सर्जरी के लिए लंबी तारीख दी जाती हैं। सामान्य सर्जरी के लिए भी मरीजों को छह माह तक इंतजार करना पड़ता है। वहीं किडनी प्रत्यारोपण के लिए मरीजों को एक साल तक इंतजार करना पड़ता है। यूरोलॉजी व गैस्ट्रोइंटेस्टाइन सर्जरी से संबंधित बीमारियों के ऑपरेशन के लिए भी लंबी वेटिंग है। इसका कारण एम्स के मुख्य अस्पताल में मरीजों की तुलना में बेड व ऑपरेशन थियेटर (ओटी) की कमी है। इसके मद्देजनर सर्जिकल ब्लॉक का निर्माण किया गया है। करीब दो-ढ़ाई साल से इसका भवन बनकर भी तैयार है, लेकिन ऑपरेशन थियेटर में तकनीकी खामियों के कारण इसमें अब तक इलाज शुरू नहीं हो पाया है। संस्थान के डॉक्टरों के कहने पर नए सिरे से अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर तैयार किए गए। इसमें 12 ऑपरेशन थियेटर की सुविधा होगी।

न्यूज गैलरी

देवबंद पर विवादित बयान के लिए नड्डा ने गिरिराज को किया तलब

नई दिल्ली : भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवबंद पर विवादित बयान के लिए शनिवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को तलब किया। गिरिराज ने तीन दिन पहले सहारनपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था, 'मैं पहले भी कह चुका हूं कि देवबंद आतंकवाद की गंगोत्री है। दुनिया भर के तमाम बड़े आतंकी यहीं पैदा होते हैं।' इस बयान की आलोचना होने के बावजूद उन्होंने कहा कि वह अपने इस बयान पर कायम हैं कि 'देवबंद आतंकवाद की गंगोत्री है।' उन्होंने कहा, 'मेरा बयान सही है और यदि किसी को कोई समस्या है तो उत्तर प्रदेश पुलिस से सूची मांग ले कि कितने लोग आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हैं।' (एएनआइ)

संविधान की 70वीं वर्षगांठ मनाने को कर्नाटक विस का विशेष सत्र

बेंगलुरु : पहली बार दो से तीन मार्च को कर्नाटक विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। 1950 में देश का संविधान मंजूर होने की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यह कदम उठाया जाएगा। शनिवार को एक अधिकारी ने कहा, 'विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने संविधान के 70 साल पूरे होने पर विशेष सत्र बुलाया है। पांच मार्च से 2020-21 के लिए बजट सत्र शुरू होने जा रहा है।'देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन गणराज्य बनने के लिए लोकतांत्रिक सरकार के साथ संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। अधिकारी ने कहा कि दलगत घेरेबंदी से परे हटते हुए सभी पार्टियों के विधायक सदन में संविधान पर बोलेंगे। दो दिवसीय विशेष सत्र संविधान के उद्देश्य और उसकी विशेषता पर केंद्रित रहेगा। (आइएएनएस)

राज्यसभा में तृणमूल के डेरेक ने पूछे सबसे ज्यादा सवाल

नई दिल्ली : तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन बजट सत्र के पहले हिस्से में राज्यसभा में सवाल पूछने में सबसे आगे रहे। उन्होंने इस दौरान 18 सवाल पूछे। उच्च सदन के कुल 118 सदस्यों ने नीतियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर 1,120 अतारांकित प्रश्न उठाए और सरकार से उसका लिखित उत्तर मांगा। राज्यसभा सचिवालय ने एक बयान में यह जानकारी दी। मंगलवार को संपन्न हो गए सत्र के पहले हिस्से के सात दिनों के दौरान हर दिन कम से कम 160 अतारांकित प्रश्न उठाए गए। राज्यसभा ने बताया है कि कुल अतारांकित प्रश्नों में से 50 फीसद उच्च सदन के 35 सदस्यों द्वारा पूछे गए। ब्रायन ने 18 सवाल, वाइएसआरसीपी के वेमीरेड्डी प्रभाकर ने 17 और निर्दलीय सांसद परिमल नाथवानी ने 16 सवाल पूछे। भाजपा के केजे अलफोंस, कांग्रेस से कुमारी शैलजा और केटी सुब्बारामी रेड्डी समेत 10 सदस्यों में से प्रत्येक ने 15-15 सवाल पूछे। भाजपा के विजय गोयल, नारायण राणे और शिवसेना के संजय राउत ने 14-14 सवाल उठाए। (प्रेट्र)

दलित बहुल गांवों में दिखेगी चमक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

विकास की दौड़ में पिछड़े और दलित बहुल गांवों को संवारने के अभियान को सरकार अब और तेज करेगी। इस मुहिम में 2024-25 तक देश के करीब 27 हजार ऐसे गांवों का कायाकल्प करने की योजना है जहां मौजूदा समय में दलितों की आबादी पांच सौ या इससे अधिक है। फिलहाल इसके तहत तेजी से काम शुरू हो गया है। करीब दस हजार गांवों के विकास का खाका तैयार है। इनमें से सात हजार से ज्यादा गांवों के विकास के लिए पैसा भी जारी कर दिया गया है। दो हजार से ज्यादा गांव अकेले उत्तर प्रदेश के हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मुताबिक, फिलहाल यह योजना यहीं नहीं रुकने वाली है, इसके दायरे में जल्द वह गांव भी आएंगे, जहां दलितों की आबादी पचास फीसद है। मौजूदा समय में देश भर में ऐसे गांवों की संख्या 46 हजार से ज्यादा है। इनमें उत्तर प्रदेश के करीब दस हजार गांव और बंगाल के 7928 गांव शामिल हैं। हालांकि, सरकार ने पीएम आदर्श ग्राम योजना के तहत वर्ष 2024-25 तक जिन 27 हजार गांवों के कायाकल्प की योजना बनाई है, उससे बंगाल ने खुद को अलग रखा है। ऐसे में बंगाल को छोड़कर देश के सभी राज्यों में दलित गांवों को संवारने के अभियान पर तेजी से काम चल रहा है।

खास बात यह है कि योजना के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जहां प्रत्येक गांवों को 21 लाख रुपये दिए जाते हैं। साथ ही गांवों के विकास को लेकर केंद्र और राज्य की ओर से चलाई जाने वाली योजनाओं को भी एकीकृत कर इनसे जोड़ा गया है। योजना की खासियत यह है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से मिले पैसे को सिर्फ गांवों के सार्वजनिक विकास कार्यों पर ही खर्च किया जा सकता है। गांवों की योजना बनाने वाली कमेटी में दलित सभासदों का बहुमत में रहना जरूरी है। मंत्रालय का मानना है कि इस पहल से वह अपनी जरूरत के मुताबिक, गांवों को संवारने को लेकर अपनी राय रख सकेंगे।

2024-25
तक एससी आबादी वाले करीब 27 हजार गांवों का होगा कायाकल्प
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बनाई योजना
- योजना में उत्तर प्रदेश के 22 सौ से ज्यादा गांवों को किया गया है शामिल

आदर्श गांव में इंटरनेट और हर घर को मिलेगा साफ पानी भी

सरकार ने फिलहाल दलित बहुल गांवों को संवारने के लिए जो पैमाना तय किया है, उसके तहत प्रत्येक गांवों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। साथ ही प्रत्येक घर तक नल-जल की सुविधा भी रहेगी। इसके तहत सभी को साफ पानी दिया जाएगा। हालांकि समय के मुताबिक आदर्श गांव की परिभाषा बदलती रहती है, लेकिन इन गांवों को जो प्लान किया जा रहा है, उसके तहत उन्हें इस तरह की सभी बुनियादी सुविधाओं से जोड़ा जाएगा, जो कि सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी हो।

मादक पदार्थों के तस्करों के निशाने पर भारत

नई दिल्ली, प्रेट्र : दुनिया के सबसे प्रमुख अफीम उत्पादन क्षेत्र 'गोल्डन क्रीसेंट' और 'गोल्डन ट्राइएंगल' के बीच स्थित होने के कारण भारत मादक पदार्थों के तस्करों के निशाने पर है। अधिकारियों ने शनिवार को यह आशंका जाहिर की। मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने के लिए बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनामिक को-आपरेशन (बिम्सटेक) के सदस्यों का दो दिवसीय सम्मेलन शुक्रवार को समाप्त हुआ।

सम्मेलन के बाद जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, 'गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्राइएंगल की भौगोलिक स्थिति सभी बिम्सटेक सदस्यों को खतरनाक स्थिति में डाल देती है। दुनिया में अफीम उत्पादन के दो केंद्रों गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्राइएंगल के बीच भारत जोखिम वाले इलाके में आता है। उल्लेखनीय है कि गोल्डन क्रीसेंट में अफगानिस्तान, ईरान व पाक के इलाके आते हैं जबकि गोल्डन ट्राइएंगल वह इलाका है जहां पर थाइलैंड, लाओस, म्यामांर की सीमाएं रुअक और मेकांग नदी के संगम पर मिलती हैं।

उद्धव सरकार की आलोचना के अगले दिन पवार ने की तारीफ

जलगांव, प्रेट्र : एलगार परिषद मामले की जांच एनआइए को सौंपने की इजाजत देने के लिए शिवसेना के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार की आलोचना करने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने एक-दूसरे की तारीफ की। शुक्रवार को कोल्हापुर में पत्रकारों से बात करते हुए पवार ने कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा एलगार परिषद मामले की जांच पुणे पुलिस से लेकर एनआइए को सौंप देना सही नहीं है। लेकिन, राज्य सरकार द्वारा मुकदमा हस्तांतरण का समर्थन करना और ज्यादा गलत बात है।

हालांकि, शनिवार को जलगांव जिले में किसानों की एक रैली को संबोधित करते हुए पवार ने ठाकरे की फोटोग्राफी हुनर की तारीफ की। राकांपा अध्यक्ष ने कहा कि महाराष्ट्र को एक अच्छा फोटोग्राफर मिला है, जिसने चंद्रकांत पाटिल जैसे बाघ की तस्वीर खींची है। उनका इशारा स्थानीय निर्दलीय उम्मीदवार चंद्रकांत पाटिल की तरफ था, जिन्होंने अक्टूबर 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के कद्दावर नेता एकनाथ खडसे की बेटी को हराया था।

- एलगार परिषद मामले की जांच एनआइए को सौंपे जाने पर पवार ने की थी सरकार की आलोचना
- उद्धव ने राकांपा प्रमुख को अपना मार्गदर्शक बताया, भाजपा को दी सरकार गिराने की चुनौती

शरद पवार। फाइल

इस पर उद्धव ने खडसे का नाम लिए बगैर कहा कि चूंकि यहां चंद्रकांत पाटिल जैसा एक बाघ था, इसलिए हर कोई भाग गया। ठाकरे ने पवार को अपना गाइड भी बताया। उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री के तौर पर काम करता हूं, तो लोगों का आशीर्वाद और शरद पवार साहेब का मार्गदर्शन मेरे साथ रहता है। ठाकरे ने विपक्षी दल भाजपा को सरकार गिराने की चुनौती भी दी।

टेलीकॉम कंपनियों की दुर्गति से बैंक भी होंगे प्रभावित

डर ▶ एसबीआइ चेयरमैन ने जताई आशंका

कहा-टेलीकॉम सेक्टर की किसी कंपनी के बंद होने से पूरा सिस्टम होगा प्रभावित

नई दिल्ली, प्रेट्र : एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) को लेकर चल रही बहस के बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआइ) के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा है कि अगर एक भी टेलीकॉम कंपनी दिवालिया हुई तो उसका अंजाम बैंकों को भुगतना होगा। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक के चेयरमैन का यह बयान एजीआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद आया है। कोर्ट के आदेश के बाद टेलीकॉम कंपनियों को 1.47 लाख करोड़ रुपये की देनदारी समय-सीमा के भीतर चुकानी होगी। इससे संकट में चल रहे टेलीकॉम सेक्टर पर संकट के बादल और गहरा गए हैं।

रजनीश कुमार ने कहा कि सेक्टर की किसी कंपनी के बंद होने से समूचे सेक्टर पर बुरा असर पड़ेगा। इससे बैंक, वेंडर्स, कर्मचारी, उपभोक्ता सभी किसी न किसी रूप में प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी कॉरपोरेट कंपनी के बंद होने से इकोनॉमी बुरी तरह प्रभावित होती है। इसलिए कंपनी को बंद होने से बचाने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए। कुमार ने बताया कि घरेलू टेलीकॉम सेक्टर की दो कंपनियां एयरसेल और रिलायंस कम्यूनिकेशन दिवालिया हो चुकी हैं। बैंकों द्वारा इन कंपनियों को दिया गया कर्ज एनपीए की श्रेणी में जा चुका है। इस परेशानी से ही अब तक बैंक नहीं उबर पाए हैं। अगर अब कोई और कंपनी बंद होती है तो स्थिति और खराब होगी।

रजनीश कुमार। फाइल

इस समय अकेले एसबीआइ ने टेलीकॉम सेक्टर को करीब 29 हजार करोड़ रुपये का कर्ज दे रखा है। इसमें से करीब नौ हजार करोड़ रुपये एनपीए की श्रेणी में जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरबीआइ ने कहा है कि वह इससे बैंकिंग सेक्टर पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर विचार कर रहा है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और दूसरी टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर मामले में देनदारी नहीं चुकाने पर कोर्ट की अवमानना का दोषी करार दिए जाने की चेतावनी दी थी। इन कंपनियों पर सम्मिलित रूप से करीब 1.47 लाख करोड़ रुपये की देनदारी है।

'बढ़ा हुआ टैरिफ वापस कराए सरकार'

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

टेलीकॉम कंपनियों से एडजस्टेड ग्रास रेवेन्यू (एजीआर) के एक लाख दो हजार करोड़ रुपये की वसूली नहीं होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले दिनों कॉल दरों में 40 फीसद तक की बढ़ोतरी को मुद्दा बनाते हुए पार्टी ने आरोप जड़ा कि टेलीकॉम कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश के 112 करोड़ प्री-पेड सेल फोन ग्राहकों पर एक लाख 60 हजार 28 करोड़ रुपये का बोझ डाल दिया गया है। सरकार टेलीकॉम कंपनियों से एक लाख करोड़ से अधिक की रिकवरी करते हुए बढ़ा हुआ टैरिफ वापस कराए।

यहां हरियाणा कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि क्या प्री-पेड मोबाइल ग्राहकों की लूट और सेल फोन कंपनियों को छूट ही न्यू इंडिया है? प्री-पेड मोबाइल ग्राहकों पर सालाना 35 हजार 561 करोड़ का बोझ डाल दिया गया है। मौजूदा सरकार के अगले साढ़े चार साल में मोबाइल कंपनियां उपभोक्ताओं की जेब से एक लाख 60 हजार 28 करोड़ रुपये अतिरिक्त निकाल लेंगी जो बकाया एजीआर से कहीं बहुत अधिक है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1999 में बनाई गई टेलीकॉम नीति के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को 15 फीसद एजीआर देना था, लेकिन इस पर अदालत के स्टे के बाद कंपनियों की अपील पर इसे पहले घटाकर 13 फीसद और फिर आठ फीसद कर दिया गया।

- 112 करोड़ प्री-पेड सेल फोन ग्राहकों पर डेढ़ लाख करोड़ से ज्यादा का अतिरिक्त बोझ डालने का आरोप
- एजीआर को घटाकर आधा करने के बावजूद वर्ष 1999 से सेलफोन कंपनियां नहीं कर रहीं भुगतान

रणदीप सुरजेवाला। फाइल

ये सवाल भी उठाए

सुरजेवाला ने पूछा कि क्या प्री-पेड उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ 40 फीसद तक बढ़ाकर कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले एक लाख दो हजार करोड़ रुपये के भुगतान की वसूली की जा रही है? टेलीकॉम कंपनियों से रिकवरी को लंबित करने के पीछे राज क्या है?

उन्होंने कहा कि विगत 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन-आइडिया, एयरटेल भारती, टाटा टेलीसर्विसेस (जिसकी मालिक अब एयरटेल है) व रिलायंस जियो को एक लाख दो हजार करोड़ रुपये दूरसंचार विभाग (डीओटी) में जमा कराने का आदेश दिया था। इसके बाद 20 नवंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में टेलीकॉम कंपनियों द्वारा साल 2020-21 व 2021-22 के लिए दी जानी वाली 42 हजार करोड़ रुपये की उगाही को लंबित कर दिया गया। दिसंबर के पहले सप्ताह में वोडाफोन-आइडिया, एयरटेल और रिलायंस जियो ने प्रीपेड ग्राहकों के लिए 'सेलफोन शुल्क' व 'डेटा इस्तेमाल शुल्क' को 40 से 50 फीसद तक बढ़ा दिया। इसके बावजूद 23 जनवरी को केंद्र सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से एक लाख दो हजार करोड़ की रिकवरी को रोकते हुए आदेश जारी कर दिया कि टेलीकॉम कंपनियों पर भुगतान के लिए दबाव न डाला जाए। 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा फिर चेताने के बावजूद इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई।

जून तक पहली एयर डिफेंस कमान गठित करेंगे सीडीएस

नई दिल्ली, एएनआइ : तेजी से कदम बढ़ाते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत इस साल जून तक एकीकृत ट्राइ-सर्विस कमान स्थापित करना चाहते हैं। वायुसेना के एक अधिकारी इसके प्रमुख होंगे। सरकारी सूत्रों ने कहा, 'सैन्य मामलों के विभाग को दिए गए आदेश के तहत पहली एकीकृत सैन्य संरचना तैयार की जाएगी। यह एयर डिफेंस कमान होगी जिसके प्रमुख एक एयर मार्शल होंगे।'

सीडीएस ने सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाने और वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया से बातचीत शुरू कर दी है। सूत्र ने कहा कि वह एकीकृत एयर डिफेंस कमान का ढांचा आदि तय करने में जुटे हैं। सैन्य मामलों के विभाग को संयुक्त सैन्य कमान तैयार करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही युद्ध क्षेत्र कमान भी बनाने के लिए कहा है जो तीनों सेनाओं को शामिल करते हुए एक विशाल पुनर्गठन होगा।

जनरल रावत युद्ध क्षेत्र कमान के अतिरिक्त प्रायद्वीप कमान और लाजिस्टिक कमान तैयार करने पर भी काम कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि युद्ध क्षेत्र कमान या अन्य एकीकृत कमान की अगुआई करने के लिए अतिरिक्त जनरल रैंक का कोई पद सृजित नहीं किया जाएगा। तीनों सेनाओं के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी इसके प्रमुख बनाए जाएंगे।हर सर्विस के पास उसकी अपनी एयर डिफेंस व्यवस्था है। एयर डिफेंस कमान एयर डिफेंस, सेना, वायुसेना एवं नौसेना की संपत्तियों को एकीकृत करेगी और संयुक्त रूप से देश को हवाई सुरक्षा प्रदान करेगी।

मौजूदा सामाजिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करें वैज्ञानिक : मोदी

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों से देश के सामने मौजूद कुपोषण जैसी वर्तमान सामाजिक समस्याओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की है। मोदी ने शुक्रवार को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए वर्चुअल प्रयोगशालाएं विकसित करने पर बल दिया, ताकि विज्ञान को देश के प्रत्येक छात्र तक ले जाया जा सके।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार मोदी ने युवाओं को विज्ञान की ओर आकर्षित करने और भावी पीढ़ी में वैज्ञानिक सूझ-बूझ मजबूत करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे भारतीयों के बीच अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में सहयोग बढ़ाने के लिए कदम उठाने का भी सुझाव दिया।

मोदी ने वैज्ञानिकों से कहा कि वे भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने पर काम करें। उन्होंने कहा कि सीएसआइआर को कृषि उत्पादों और जल संरक्षण के क्षेत्र में उपयोगी अनुसंधान के जरिये 'भारत के सामने मौजूद वर्तमान सामाजिक समस्याओं' पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिकों को जिन चुनौतियों पर ध्यान देने की जरूरत है, उनमें 5जी वायरलेस तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवीकरणीय ऊर्जा संचय के लिए किफायती एवं अधिक समय तक चलने वाली बैटरी शामिल है।

मोदी ने विश्वस्तरीय वस्तुओं के उत्पादन के लिए आधुनिक विज्ञान के साथ पारंपरिक ज्ञान को जोड़ने की जरूरत को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने नई खोजों के व्यावसायीकरण की भी बात की। उन्होंने वैज्ञानिकों से आम आदमी के जीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करने की अपील भी की।

- प्रधानमंत्री ने विज्ञान को देश के प्रत्येक छात्र तक पहुंचाने पर दिया जोर
- आधुनिक विज्ञान के साथ पारंपरिक ज्ञान को जोड़ने की जरूरत बताई

नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रेट्र

केरल पुलिस की बंदूक गायब होने की रिपोर्ट से मेरा कोई लेना-देना नहीं : राज्यपाल

कोच्चि (केरल), एएनआइ : केरल के राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान ने कहा है कि राज्य पुलिस की बंदूकें और गोलियां गायब होने संबंधी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पर उनकी कोई भूमिका नहीं है। यह रिपोर्ट सरकार के लिए है। खान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, 'यह सरकार के लिए है, न कि मेरे लिए। हर चीज की एक प्रक्रिया है... हमारे पास संस्थान हैं और हमें उनका सम्मान करना सीखना चाहिए। यह रिपोर्ट पीएसी (लोक लेखा समिति) को जाएगी, जहां से यह विधानसभा जा सकती है। इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है।'

बता दें कि केरल पुलिस के हथियारों के आधुनिकीकरण की ऑडिट में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने स्पेशल आर्म्ड पुलिस बटालियन (एसएपीबी) की 25 राइफलें तथा 12,061 जिंदा कारतूसों को गायब होना पाया है। कैग का यह भी कहना है कि एसएपीबी में हथियारों और गोली-बारूद से संबंधित रिकॉर्ड उचित तरीके से नहीं रखा गया है।

छात्र को डिग्री देने से मना करने पर आइआइटी खड़गपुर से जवाब तलब

नई दिल्ली, प्रेट्र : मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय ने आइआइटी खड़गपुर से व्हिसलब्लोअर प्रोफेसर राजीव कुमार के छात्र को डॉक्टरेट की डिग्री देने से इन्कार करने के मसले को अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सामने रखने का निर्देश दिया है। प्रोफेसर ने संस्थान पर उनके खिलाफ बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है।

प्रोफेसर कुमार और उनके छात्र महेश शिरोले की अपील पर मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। आइआइटी खड़गपुर के साथ चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में उनकी नियुक्ति हुई है।

शिरोले की याचिका का हवाला देते हुए मंत्रालय ने आइआइटी खड़गपुर के रजिस्ट्रार को भेजे पत्र में इस मसले को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के समक्ष रखने को कहा है, ताकि कोई निर्णय हो सके। कुमार द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में मंत्रालय के इस पत्र के बारे में पता चला है। आइआइटी खड़गपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष आरपीजी-संजीव गोयनका ग्रुप के चेयरमैन संजीव गोयनका हैं।

आइआइटी खड़गपुर। फाइल

प्रत्येक स्वायत्त आइआइटी में एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, जो संस्थान के सामान्य कामकाज को देखता और नियंत्रित करता है। कुमार ने कहा है कि शिरोले ने पीएचडी की डिग्री के लिए 2014 में अपनी थीसिस जमा की थी, जिसे भारत के एक परीक्षक ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन एक विदेशी परीक्षक ने उसे अस्वीकार कर दिया।

कुमार ने कहा है कि विदेशी परीक्षक ने पक्षपात और दुराग्रह की भावना से काम किया और उसकी नियुक्ति नियमों के खिलाफ की गई है। बार-बार अनुरोध करने के बावजूद आइआइटी ने थीसिस को किसी अन्य परीक्षक के पास नहीं भेजा। पिछले तीन साल के दौरान शिरोले ने राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और एचआरडी मंत्रालय को पत्र भेजकर अपनी परेशानी बताई है।

कुमार ने कहा है कि उन्होंने 2006 और उसके बाद से आइआइटी में अनियमितताओं को उजागर किया था, इसलिए संस्थान उनके छात्र के साथ प्रतिशोधात्मक रवैया अपना रहा है।

बढ़ी परेशानी

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए मंत्री को दो मई को कोर्ट में पेश होने को कहा है

शशि थरूर मानहानि मामले में रविशंकर प्रसाद को समन

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र : कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में शनिवार को स्थानीय अदालत ने केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को पेश होने का समन जारी किया। थरूर के वकील ने मीडिया को बताया कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए मंत्री को दो मई को कोर्ट में पेश होने को कहा है।

थरूर ने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में प्रसाद द्वारा की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर दिसंबर, 2018 में यह केस दर्ज कराया था। आरोप है कि रविशंकर प्रसाद ने थरूर को 'हत्यारोपित' कहा था। उनके इस बयान के लिए थरूर ने कानून मंत्री को भेजे कानूनी नोटिस में बिना शर्त माफी मांगने की मांग की थी।

थरूर का कहना है कि सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है और अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी गई है। इसमें उन पर भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 308 तथा 498ए के तहत आरोप लगाए गए हैं। मालूम हो कि ये दोनों ही धाराएं हत्या के अपराध की नहीं हैं। थरूर ने कहा था, 'फाइनल रिपोर्ट में मौत को हत्या नहीं बताया गया है।'

तिरुअनंतपुरम से सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री थरूर ने कहा है कि 28 अक्टूबर को सुबह 5.38 बजे प्रसाद ने ट्विटर पर 2 मिनट 18 सेकंड की उनके प्रेस कांफ्रेंस की एक वीडियो क्लिप झूठे, दुर्भावनापूर्ण तथा बहुत ही अपमानजनक बयानों के साथ पोस्ट की थी। यह वीडियो उन्हें बदनाम करने के लिए पोस्ट किया गया, जिसमें उनके खिलाफ झूठे तथा अपमानजनक आरोप लगाए गए कि वह हत्या के एक मामले में आरोपित हैं और चार्जशीट दायर है। थरूर के मुताबिक, जनता में उनकी छवि को खराब करने के लिए इरादतन ऐसे झूठे और असत्य बयान दिए गए। उन्होंने रविशंकर प्रसाद को वकीली नोटिस भेज कर 48 घंटे में बिना शर्त माफी मांगने तथा उनके प्रेस कांफ्रेंस की वीडियो क्लिप व अपमानजनक बयान हटाने की मांग की थी। नोटिस के जवाब में प्रसाद ने अपने ट्वीट का बचाव करते हुए कहा था कि वह अपमानजनक नहीं है। थरूर ने अपनी शिकायत में कहा है कि प्रसाद ने आइपीसी की धारा 499 (मानहानि) के तहत अपराध किया है, जो धारा 500 (मानहानि की सजा) के तहत दंडनीय है। उन्होंने प्रसाद के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है।

- दो मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश
- थरूर को हत्यारोपित बताने का मामला

शशि थरूर।

रविशंकर प्रसाद। सभी फाइल

कांग्रेस नेता थरूर पर लगा पांच हजार रुपये जुर्माना

जासं, नई दिल्ली : मानहानि के एक मामले में अदालत में पेश नहीं होने के कारण कांग्रेस सांसद शशि थरूर पर राउज एवेन्यू अदालत के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहुजा ने पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। थरूर पर आरोप है कि उन्होंने एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। शिकायतकर्ता भाजपा नेता राजीव बब्बर के मुताबिक शशि थरूर के शब्दों से उन्हें ठेस पहुंची थी। पिछले साल दायर मानहानि के मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू अदालत में हो रही है। थरूर इस मामले में पहले पेश होते रहे हैं, लेकिन इस बार पेशी पर न आने के चलते उन पर जुर्माना लगाया गया है।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

भाजपा में सारे लोग पुराने साथी कोई अड़चन नहीं आएगी : मरांडी

आनंद मिश्र, रांची

- कहा, मेरा भाजपा से बाहर रहना राजनीतिक तपस्या
- आगामी 17 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी में झामुमो के विलय की तैयारी

झारखंड विकास मोर्चा के आगामी 17 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी में विलय की तैयारियों के बीच इसके केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा में हम सभी लोगों ने साथ में काम किया है। एक परिवार की तरह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई खेमेबाजी होगी।

गौरतलब है कि बाबूलाल मरांडी ने वर्ष 2006 में भाजपा छोड़ी थी और पूरे 14 वर्ष बाद घर वापसी कर रहे हैं, निश्चित रूप से यह उनके लिए खास क्षण हैं। उन्होंने कहा कि हमने भाजपा छोड़ी, लेकिन कहीं गए नहीं थे। 2006 से 2014 वर्षों तक जनता के बीच रहे। इस दौरान लगभग छह से सात लाख किलोमीटर की यात्रा की। झारखंड को नजदीक से देखने का मौका मिला। लोगों के दुख-तकलीफ को महसूस किया। इसे आप राजनीतिक तपस्या भी कह सकते हैं।

भाजपा में जवाबदेही के सवाल पर मरांडी बोले कि दायित्व संगठन को सौंपना है। हमने अपनी ओर से कह दिया है कि हमें घूमने-फिरने का काम सौंप दें। बाकी पार्टी क्या निर्णय लेती है, यह उन्हें तय करना है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने भाजपा में विलय का प्रस्ताव पारित कर दिया है और इससे भाजपा को भी अवगत करा दिया गया है। भाजपा ने भी सहमति दे दी है। इलेक्शन कमीशन को भी इसकी सूचना दे दी गई है। अब हमारा रोल समाप्त हो गया है।

भाजपा में वापसी की चर्चा पर वह बोले कि 2006 में लोकसभा चुनाव जीतने के साथ ही उनकी तरफ से वापसी की कोशिशें की गई थीं। पिछले 12-13 सालों से भाजपा, आरएसएस व अन्य मित्र बार-बार मुझसे कहते थे, लेकिन मै बहुत देर तक अड़ा रहा। अब जब मन हुआ तो लगा अब देर क्या करना है। जहां तक निर्णय लेने की बात है तो इसे संयोग कह सकते हैं।

तेजस्वी की बेरोजगार यात्रा वाली बस पर विवाद

राज्य ब्यूरो, पटना

तेजस्वी यादव। फाइल

- बीपीएल सूची वाले के नाम से बस खरीद नए विवाद में फंसा लालू का परिवार
- बस मालिक के रूप में दर्ज है पूर्व एमलसी का मोबाइल नंबर

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बेरोजगारी हटाओ यात्रा के लिए जिस बस को तैयार किया गया है, उस पर उनसे पहले विवाद सवार हो गया है। राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि यह बस जिस व्यक्ति के नाम पर है, उसका नाम गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की सूची में है।

उन्होंने आरोप लगाया कि बस भ्रष्टाचार की रकम से खरीदी गई है। तेजस्वी की इस बस ने अत्यंत पिछड़ी जाति के एक गरीब को जालसाजी के मकड़जाल में फंसा दिया है। नीरज ने कहा कि तेजस्वी यादव सुधर नहीं सकते, क्योंकि उनकी विरासत ही पूरी तरह दागी है। यह बेनामी संपत्ति अर्जित करने की विरासत में एक हाई टेक कड़ी है।

मंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में दस्तावेज भी पेश किए। इनके मुताबिक शाही बस के मालिक अत्यंत पिछड़ा समुदाय के एक निर्धन व्यक्ति मंगल पाल हैं। बख्तियारपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी और उप विकास आयुक्त, पटना द्वारा 20 फरवरी, 2008 को अनुमोदित बीपीएल सूची में शामिल है। बस मालिक मंगल हिदायतपुर के हैं।

मंत्री के मुताबिक परिवहन विभाग में बस मालिक के नाम से दर्ज मोबाइल नंबर राजद के पूर्व विधायक अनिरुद्ध यादव का है। आज भी अनिरुद्ध यादव का यही मोबाइल नंबर है। उन्होंने तेजस्वी से पूछा कि जालसाजी और आर्थिक अपराध के इस मामले में उन्होंने अत्यंत पिछड़ी जाति के एक गरीब को क्यों फंसा दिया है? नीरज ने कहा कि कहीं यह राज्यसभा या विधान परिषद में अनिरुद्ध यादव के साथ हुई डील का हिस्सा तो नहीं है। क्योंकि उनके परिवार पर इस तरह की डील के आरोप पहले भी लगते रहे हैं।

23 फरवरी से राजद की बेरोजगारी हटाओ यात्रा : तेजस्वी यादव 23 फरवरी से बेरोजगारी हटाओ यात्रा शुरू करने वाले हैं। वह जिस बस से यात्रा करने वाले हैं उसे अत्याधुनिक सुविधायुक्त रथ के रूप में तैयार किया गया है। बस का नाम युवा क्रांति रथ रखा गया है। इसके माध्यम से तेजस्वी, नीतीश सरकार के खिलाफ अभियान चलाएंगे और लोगों को लामबंद करेंगे।

राजद के पूर्व विधायक अनिरुद्ध यादव ने कहा कि मंगल पाल उनका नौकर नहीं है। वह 10 वर्ष की उम्र से साथ रह रहा है और भाई की तरह है। उसकी पत्नी जिला परिषद की सदस्य है। वह ठेकेदारी करता है। आयकर रिटर्न भरता है। यह बात सही है कि उसका परिवार गरीब है। किंतु मंगल गरीब नहीं है। उसने अपने बूते पर बस की खरीद की है।

पार्टी ने बस किराए पर ली है। मुझे इतना ही पता है। बाकी बातें पार्टी के पदाधिकारी बताएंगे। नीरज कुमार को असली मुद्दा बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए। इस पर कोई बात नहीं कर रहा है।
- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष

तेजस्वी यादव के परिवार को दान लेने की आदत है। घर के नौकर से लेकर एमपी और मंत्री तक से राजद अध्यक्ष दान लेते रहे हैं। किसी से जमीन, किसी से मकान तो किसी से फ्लैट और फार्म हाउस। उसी परंपरा का पालन करते हुए तेजस्वी ने दान में किसी गरीब से बस स्वीकार की है।
- डॉ. संजय जायसवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

नीरज कुमार को पहले अपनी पार्टी में झांकना चाहिए कि कितना भ्रष्टाचार है। वह बौखलाहट में बोल रहे हैं।
-भाई वीरेंद्र, राजद विधायक

वाराणसी में आज छह घंटे से अधिक रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी

जागरण संवाददाता, वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को वाराणसी में छह घंटे से अधिक समय तक रहेंगे। सेना के विशेष विमान से वह सुबह लगभग सवा दस बजे वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री सेना के हेलीकॉप्टर से बीएचयू हेलीपैड आएंगे। यहां से उनका काफिला सड़क मार्ग से जंगमबाड़ी पहुंचेगा।

जंगमबाड़ी में वीरशैव महाकुंभ आयोजन में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से वापस बीएचयू आएंगे और हेलीकॉप्टर के जरिए रामनगर के सूजाबाद पहुंचेंगे। सूजाबाद से उनका काफिला चंदौली के पड़ाव स्थित पं. दीनदयाल स्मृति उपवन पहुंचेगा। पं. दीनदयाल की प्रतिमा के अनावरण के बाद यहां प्रधानमंत्री की जनसभा भी निर्धारित है। इसी क्रम में वह हेलीकॉप्टर से बड़ा लालपुर पहुंचेंगे और फिर सड़क मार्ग से हस्तकला संकुल जाएंगे। संकुल में यूपी डिजाइन संस्थान की ओर से आयोजित दो दिनी प्रदर्शनी का शुभारंभ करने के साथ ही प्रधानमंत्री सूबे के शिल्पियों व विभिन्न देशों से आए खरीदारों संग संवाद करेंगे।

न्यूज गैलरी

गिरिराज ने आंबेडकर प्रतिमा पर किया माल्यार्पण तो विपक्ष ने गंगा जल से धोया

बेगूसराय : बाबा साहेब डा. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर भाजपा नेता एवं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के माल्यार्पण करने के बाद वामपंथी समेत अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने गंगाजल से प्रतिमा को धोकर उसका शुद्धिकरण किया। नेताओं ने कहा कि 14 फरवरी को बलिया प्रखंड परिसर स्थित आंबेडकर पार्क में प्रतिमा को स्पर्श कर संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले गिरिराज ने डॉ. आंबेडकर को अपवित्र कर दिया था। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के प्रतिनिधि अमरेन्द्र कुमार 'अमर' ने प्रेस वार्ता में आंबेडकर की प्रतिमा को गंगा जल से धोने की निंदा करते हुए कहा कि जिन्ना की सोच वाले लोग ऐसा कर रहे हैं। (जासं)

बेहतर इलाज को दिल्ली एम्स भेजे जाएंगे लालू

रांची : रिम्स (राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान) के पेइंग वार्ड में इलाजरत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बेहतर इलाज के लिए नई दिल्ली स्थित एम्स भेजने की तैयारी चल रही है। अलबत्ता इस प्रक्रिया में 15 दिन से एक महीने का समय लग सकता है। बताते चलें कि रिम्स में पिछले डेढ़ वर्ष से लालू चिकित्सारत हैं, परंतु उनके स्वास्थ्य में कोई खास सुधार नहीं हो रहा है। इधर इलाज के लिए उन्हें बाहर ले जाने की मांग लंबे समय से हो रही है। यहां उनका इलाज कर रहे डा. डीके झा ने शनिवार को हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए कहा कि लालू की बीमारी ऐसी नहीं है कि उन्हें ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़े। दवा से ही उपचार करना होगा। (जासं)

छत्तीसगढ़ में भाजपा के हाथ से जाएंगी राज्यसभा की सीटें

रायपुर : छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के दो सदस्यों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा और भाजपा के रणविजय सिंह जूदेव का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है। दोनों सीटों के लिए चुनाव की प्रक्रिया अगले महीने शुरू होगी। विधानसभा में सदस्यों की संख्या के लिहाज से इस बार एक सीट पर भी भाजपा की जीत मुश्किल दिख रही है। प्रदेश में राज्यसभा की कुल पांच सीटें हैं। फिलहाल इनमें से तीन भाजपा और दो कांग्रेस के पास है। छत्तीसगढ़ में 15 वर्ष तक सत्ता में रही भाजपा विधानसभा में बहुमत के आधार पर अब तक राज्यसभा की तीन सीटों पर लगातार कब्जा रखे हुए थी। वहीं, दो सीट लगातार कांग्रेस को जा रही थी। इस बार विधानसभा में पार्टी की सदस्य संख्या इतनी भी नहीं है कि वह एक सीट भी बचा सके। ऐसे में एक-एक कर तीनों सीटें भाजपा से छिन सकती हैं। राज्य कोटे की दो राज्यसभा की सीट इस वर्ष अप्रैल में खाली हो रही है। (नईदुनिया)

मप्र, सिक्किम व केरल को मिले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष

मिली तैनाती ▶ संघ के करीबी वीडी शर्मा को मध्य प्रदेश की कमान

जेएनएन, नई दिल्ली

वीडी शर्मा।

के. सुरेंद्रन। फाइल

दिल्ली की चुनावी गहमागहमी से फुरसत मिलते ही भाजपा ने अपने संगठनों को कसने की कवायद शुरू कर दी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को पार्टी के तीन प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की। केरल में पार्टी के युवा महासचिव के. सुरेंद्रन को प्रमोट कर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि, मध्य प्रदेश की कमान संघ के करीबी समझे जाने वाले वीडी शर्मा को सौंपी गई है। दल बहादुर चौहान सिक्किम के प्रदेश अध्यक्ष बरकरार रखे गए हैं।

वामदलों के गढ़ केरल को लंबे समय बाद भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष मिला है। पिछले साल पीएस श्रीधरन को मिजोरम का राज्यपाल बनाए जाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली चल रहा था। विपक्ष के प्रति आक्रामक रहने वाले सुरेंद्रन को पार्टी ने उनके 50वें जन्मदिन से कुछ हफ्ते पहले ही यह तोहफा दिया है। सुरेंद्रन ने कहा कि वह पार्टी के भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। राज्य में भाजपा का वामदलो के साथ खूनी संघर्ष चलता है।

सुरेंद्रन प्रदेश भाजपा के लोकप्रिय नेता हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के विधायक पीबी अब्दुल रजाक को कड़ी टक्कर दी थी। रजाक बड़ी मुश्किल से मात्र 89 वोट से जीते थे। 140 सदस्यीय केरल विधानसभा में ओ. राजगोपाल भाजपा के इकलौते सदस्य है। सुरेंद्रन को पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव और कोन्नी विधानसभा उपचुनाव में भी उतारा था। वो जीते तो नहीं, लेकिन पार्टी का वोट प्रतिशत जरूर बढ़ा। सुरेंद्रन को विदेश राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन का करीबी माना जाता है। सुरेंद्रन के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती इस साल के आखिर में होने वाले निकाय चुनावों के लिए पार्टी के सभी धड़ों को एक करने और विपक्ष को कड़ी टक्कर देने की है।

राकेश सिंह की जगह लेंगे शर्मा : खजुराहो से सांसद विष्णुदत्त शर्मा यानी वीडी शर्मा जबलपुर के सांसद राकेश सिंह का स्थान लेंगे, जिन्हें विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। शर्मा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के रास्ते पार्टी में आए थे। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से निकटता के चलते उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई गई है। मुरैना के रहने वाले शर्मा को चंबल क्षेत्र में भाजपा की ओर से ब्राह्मणों का सशक्त चेहरा माना जाता है।

चौहान लगातार दूसरी बार बने अध्यक्ष

दल बहादुर चौहान को सिक्किम का प्रदेश अध्यक्ष बरकरार रखा गया है। वह 2023 तक प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बने रहेंगे। चौहान ने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की मदद से पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प दोहराया है। उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ सलाह-मशविरा के बाद जल्द ही पार्टी की राज्य इकाई के गठन की घोषणा की है। चौहान के प्रदेश अध्यक्ष रहते भाजपा को सिक्किम में बड़ी सियासी कामयाबी मिली थी। एसडीएफ के 10 विधायक भी पार्टी में शामिल हुए और विधानसभा की दो सीटो के लिए हुए उपचुनाव में भी पार्टी को जीत मिली थी।

राजद-कांग्रेस ने मांझी कुशवाहा से बनाई दूरी

राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले ही महागठबंधन के घटक दलों के रास्ते अलग-अलग दिखने लगे हैं। नागरिकता कानून (सीएए) एवं राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनपीआर) के खिलाफ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम), विकासशील इंसान पार्टी (वीआइपी), जन अधिकार पार्टी (जाप) और वामदलों के नेताओं-कार्यकर्ताओं ने शनिवार को गांधी मैदान में धरना दिया। लेकिन इस धरने से राजद एवं कांग्रेस ने दूरी बना ली। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजधानी में रहते हुए भी वहां जाना जरूरी नहीं समझा और न ही राजद का कोई अन्य नेता पहुंचा। जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा एवं उदय नारायण चौधरी तो धरने पर बैठे किंतु पप्पू यादव एवं मुकेश सहनी नहीं पहुंचे। हालांकि उनके समर्थक मौजूद थे।

धरने से राजद और कांग्रेस की दूरी पर जीतनराम मांझी ने सफाई भी दी। कहा, रणनीतिकार एक फ्रंट पर एक साथ नहीं जाते। अपने मोर्चे पर काम करते हैं। जो लोग नहीं आए हैं, वे भी केंद्र के कानून के खिलाफ हैं।

सभी दलों की रणनीति अलग-अलग है। जनता का मकसद इसे खत्म करने का है। जबतक कानून वापस नहीं हो जाता हम सब एक पैर पर खड़े रहेंगे। वहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया कि पूरे प्रदेश में ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ मेरी पार्टी खड़ी है। भाजपा के लोग क्या करते हैं यह मैंने करीब से देखा है।

अखिलेश ने कहा, मुझे जान से मारने की धमकी मिली

जागरण संवाददाता, कन्नौज

- पूर्व सीएम बोले, दो दिन पहले मिली थी धमकी, प्रेसवार्ता में दूंगा पूरी जानकारी
- सपा के महिला सम्मेलन में घुसे एक युवक ने लगाए जय श्रीराम के नारे

अखिलेश यादव। फाइल

समाजवादी पार्टी के महिला सम्मेलन के दौरान शनिवार को तब हड़कंप मच गया, जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के संबोधन के बीच एक युवक अचानक जय श्रीराम के नारे लगाने लगा। कार्यकर्ताओं ने उसे तुरंत दबोच लिया और पीटकर पुलिस के हवाले कर दिया। इसी के बाद अखिलेश यादव ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि दो दिन पहले उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है।

हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्हें किसने और क्यों धमकी दी है। वह बोले- यहां इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पूरी जानकारी लखनऊ में ही प्रेसवार्ता कर दूंगा। कन्नौज के सपा कार्यालय में आयोजित सम्मेलन में संबोधन के दौरान अखिलेश अपनी सरकार के कार्य बता रहे थे कि इसी बीच सबसे पीछे खड़े एक युवक ने सवाल कर दिया कि आपने बेरोजगारों के लिए क्या किया। अखिलेश ने उसे आगे आने को कहा। इस पर युवक बेरीकेडिंग पर चढ़ गया और जय श्रीराम के नारे लगाने लगा। कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई कर दी। अखिलेश ने इसके तुरंत बाद अपनी जान को खतरा होने की बात कही। उन्होंने बताया कि दो दिन पहले किसी ने फोन पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। युवक की नारेबाजी पर नाराजगी जताते हुए अखिलेश ने पुलिस को फटकार लगाते हुए युवक को किसी भाजपाई द्वारा भेजे जाने की आशंका जताई। दूसरी तरफ कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि युवक से पूछताछ हो रही है कि वह वहां क्यों गया था।

पूछा- पुलवामा में कहां से आया आरडीएक्स

पुलवामा हमले पर सपा अध्यक्ष ने पूछा- सरकार बताए कि पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया और जवानों को शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। छिबरामऊ में 10 जनवरी को हुए भीषण बस हादसे के बाद अपेक्षित मुआवजा न दिए जाने और जांच में देर होने पर भी उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया।

आरक्षण विवाद में मध्यस्थता करेंगे मुख्यमंत्री रूपाणी

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

विजय रूपाणी। फाइल

लोक रक्षक दल भर्ती परीक्षा के परिपत्र को रद करने की मांग को लेकर गांधीनगर सत्याग्रह छावनी में धरने पर बैठी एससी-एसटी तथा ओबीसी वर्ग की युवतियां शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा से मिलने निकलीं, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री रूपाणी खुद मध्यस्थता कर रहे हैं। जल्द इसके हल होने की उम्मीद है।

गुजरात सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से एक अगस्त 2018 को एक परिपत्र जारी किया गया था। इसके तहत एससी एसटी व ओबीसी की मेरिट सूची तैयार करने के बाद जनरल कैटेगरी की सूची तैयार की गई। इसको लेकर लोक रक्षक दल भर्ती परीक्षा की आरक्षित वर्ग की युवतियों ने दो माह पहले गांधीनगर में धरना देना शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि सरकार के इस तरीके से इस वर्ग को आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। आरक्षित वर्ग की मेरिट में टॉप आने वाली युवतियों को भी आरक्षित सूची में डाल दिया गया। सरकार ने जब इस परिपत्र को रद करने के संकेत दिए तो अनारक्षित वर्ग के नेता विरोध पर उतर आए। पाटीदार, राजपूत व ब्राह्मण समाज के नेताओं ने उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल से मुलाकात कर अपनी नाराजगी प्रगट की। आरक्षित वर्ग के भाजपा सांसद व विधायकों सहित कांग्रेस भी इस आंदोलन के समर्थन में आ गई और सरकार ने दबाव में आकर गत दिनों भरोसा दिलाया कि सरकार अगस्त 2018 के विवादास्पद परिपत्र को रद कर देगी, लेकिन अब अनारक्षित वर्ग इस परिपत्र के पक्ष में खड़ा हो गया।

विपक्ष मजबूत नहीं रहा तो बिल्ली की लड़ाई में बंदर को हो जाएगा फायदा : शत्रुघ्न सिन्हा

जागरण संवाददाता, रांची

- रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद से शरद यादव, शत्रुघ्न सिन्हा व कमर आलम ने की मुलाकात
- बिहार चुनाव को लेकर हुई लालू से बात, महागठबंधन पर कोई मतभेद नहीं : शरद

रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज करा रहे सजायाफ्ता लालू प्रसाद से शनिवार को मिलने पहुंचे पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा (बीच में)। जागरण

बिहार में महागठबंधन को लेकर चल रही रस्साकशी को दूर करने के लिए शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव ने रिम्स में लालू प्रसाद से मुलाकात की। लगभग तीन घंटे तक चली मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब शरद यादव ने कहा कि बिहार में चुनाव की रणनीति पर लालू प्रसाद से बात हुई है। बिहार में महागठबंधन को लेकर कोई मतभेद नहीं है। पूर्व सांसद और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी शनिवार को लालू से मुलाकात की। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने विपक्षी एकता की वकालत की। कहा कि इसके अभाव में दो बिल्ली की लड़ाई में बंदर को फायदा हो जाएगा।

शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि लालू यादव से उनकी पारिवारिक मित्रता रही है। लिहाजा वे उनका कुशल क्षेम जानने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि लालू का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन उनका जीवन जीने का जज्बा बहुत ही मजबूत है। बिहार से राज्यसभा की सीट खाली होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। सब लोग मिलकर जो तय करेंगे, वही होगा। राजद के राष्ट्रीय महासचिव कमरे आलम ने भी इस दौरान लालू यादव से मुलाकात की। नेताओं ने कहा कि दिल्ली में अहंकार व झूठ के प्रचार की हार हुई है, जबकि लोकतंत्र की जीत हुई है। बिहार में चुनाव से पूर्व विपक्षी गठबंधन में हो रही खींचतान के सवाल को नेताओं ने सिरे से खारिज किया। कहा कि वहां विपक्ष मजबूत है। किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। एक अन्य के सवाल के जवाब में शरद यादव ने कहा कि आगामी चुनाव में तेजस्वी सीएम का चेहरा होंगे।

भौतिकवादी सुख में वृद्धि के बावजूद लोग आंदोलन कर रहे : भागवत

अहमदाबाद, प्रेट्र : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि भौतिकवादी सुख-सुविधाओं में कई गुणा वृद्धि के बावजूद समाज में हर कोई नाखुश है और निरंतर आंदोलन कर रहा है। वह यहां संघ के कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों को संबोधित कर रहे थे।

संघ प्रमुख ने कहा, 'ऐशो-आराम में बढ़ोतरी के बावजूद हर कोई नाखुश है और आंदोलन कर रहा है। चाहे वह मालिक हो या नौकर, विपक्षी दल हो या आम आदमी, छात्र हो या शिक्षक, हर कोई नाखुश और असंतुष्ट है।' भागवत 'वर्तमान विश्व परिदृश्य में भारत की भूमिका' विषय पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा, 'भारत को धर्म (ज्ञान) देना है, ताकि ज्ञान फैले लेकिन मनुष्य रोबोट न बने। हमने हमेशा वैश्विक परिवार की बात की है न कि वैश्विक बाजार की।' संघ प्रमुख ने कहा कि यह सोचना कि हम बेहतर दुनिया में रह रहे हैं, आधा सच है। दुनिया में सुविधाओं का समान बंटवारा नहीं हुआ है। जंगल राज कायम है। सक्षम व्यक्ति गरीब को कुचलकर आगे बढ़ रहा है। विश्व के विनाश के लिए ज्ञान का ज्यादा उपयोग हो रहा है।

सियासत

राज्य में सीमित दखलंदाजी है सिंधिया की नाराजगी की वजह, प्रदेश कांग्रेस में मचा घमासान, बढ़ी तल्खी

सिंधिया की सरकार के खिलाफ मुखालफत की कई वजहें

रवींद्र कैलासिया, भोपाल

ज्योतिरादित्य सिंधिया। फाइल

- कमलनाथ सरकार के सवा साल के कार्यकाल में कई बार सवाल उठा चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया
- पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के मुकाबले भी कम ही मिल पाती है प्रदेश में सिंधिया को तवज्जो

पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज क्यों हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ से उनकी दूरी की वजह क्या है? ऐसी क्या मजबूरी आ गई, जो उन्हें सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने का एलान करना पड़ा? उक्त सवालों को लेकर सत्ता के गलियारों में तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अलबत्ता, राजनीति के कुछ जानकारों का मानना है कि प्रदेश की राजनीति में अलग-थलग पड़ने की वजह से सिंधिया सरकार के खिलाफ मुखालफत कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सरकार पर पकड़ और उनकी दूरी भी एक वजह बताई जा रही है। ये बातें इस ओर भी इशारा कर रही हैं कि कांग्रेस में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है।

यह पहला मौका नहीं है, जब सिंधिया ने सार्वजनिक तौर पर नाराजगी का इजहार किया हो। कमलनाथ सरकार के सवा साल के कार्यकाल में वे कई बार सवाल उठा चुके हैं। सिंधिया की नाराजगी की वजह लोकसभा चुनाव में मिली हार को तो माना ही जा रहा है, साथ-साथ 15 साल बाद सत्ता में आई पार्टी की सरकार में उनकी सीमित दखलंदाजी भी मुख्य वजह मानी जा रही है।

सरकार में जितनी तवज्जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मिलती है, सिंधिया को उस मुकाबले कम ही मिल पाती है। कहा जाता है कि सरकार में नौकरशाहों की पदस्थापना हो या सरकारी संस्थाओं में राजनीतिक अशासकीय नियुक्तियां, दिग्विजय सिंह समर्थकों के काम आसानी से हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने की सवा साल की अवधि में उन्होंने वचन पत्र को लेकर दूसरी बार सरकार को घेरा है।

पहले पूरी तरह से किसान कर्ज माफी नहीं हो पाने पर घेराबंदी की थी। गत दिनों टीकमगढ़ जिले में हुए एक कार्यक्रम में अतिथि शिक्षकों को लेकर उन्होंने पार्टी के वचन पत्र को ग्रंथ बताते हुए कहा कि अगर उसके मुताबिक काम नहीं हुआ तो वे सड़क पर उतर जाएंगे। इसके अलावा सिंधिया ने सरकार के शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में बड़े माफिया पर कार्रवाई नहीं होने पर भी नाराजगी जताई थी। इसी तरह महाराष्ट्र व हरियाणा विधानसभा चुनाव और अभी दिल्ली चुनाव परिणाम पर वे पार्टी को आत्मचिंतन की जरूरत बता चुके हैं।

ये वजह भी है दूरी बढ़ने की

सिंधिया 2018 में केंद्र से प्रदेश की राजनीति की तरफ आने की कोशिश में जुटे दिखाई दे रहे थे, लेकिन राज्य में सरकार बनने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर होना पड़ा तो उनके चेहरे पर निराशा का भाव दिखाई दिया था। हालांकि, सरकार में उन्होंने अपने समर्थकों को मंत्री पद दिलाने में कोई कमी नहीं रखी। इसके बाद वे राज्य की राजनीति से दूर होने लगे। लोकसभा चुनाव में जब वे अपने ही पुराने सहयोगी से चुनाव हार गए तो उनके विरोधी प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को मौका मिल गया।

सभी पुलिस कर्मचारियों को समान नजरिये से देखना चाहिए : तालुकदार

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

पूर्व पुलिस आयुक्त तुषार तालुकदार का कहना है कि नौकरी मिलने के बाद सभी पुलिस कर्मचारियों को समान नजरिये से देखना चाहिए। कोई कर्मचारी अगर बेहतर कार्य करता है तो जातपात नहीं देखकर उसके कार्य को तवज्जो देना चाहिए। तालुकदार ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसी अधिसूचना नहीं देखी है।

इस तरह की अधिसूचना पुलिस कर्मचारियों की आपसी एकता में विष घोलेगी। कोलकाता के एक ट्रैफिक गार्ड का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में अभी तक इस तरह की अद्भुत अधिसूचना नहीं देखी है। सिर्फ अनुसूचित जनजाति के पुलिस कर्मचारियों का ही क्यों चयन किया जा रहा है, यह समझ से परे है। इस बारे कोलकाता पुलिस के उपायुक्त (ट्रैफिक) रुपेश कुमार का कहना है कि यह पुलिस का अंदरूनी विषय है। इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते।

राजनीतिक दलों ने सरकार को घेरा : अधिसूचना को लेकर राजनीतिक दलों ने ममता बनर्जी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा का कहना है कि इस तरह की अधिसूचना सचमुच चकित करने वाली है। पुलिस मुख्यालय ने सरकार के इशारे पर आगामी निकाय तथा विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह निर्णय लिया है।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता अब्दुल मन्नान तथा माकपा नेता सुजन चक्रवर्ती का कहना है कि पुलिस मुख्यालय की यह अधिसूचना पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। इस बारे सवाल पूछने पर तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने किसी प्रकार की टिप्पणी करने से साफ इन्कार कर दिया और कहा कि यह पुलिस मुख्यालय का निजी फैसला है।

1700 करोड़ रुपये के 30 प्रोजेक्ट वाराणसी में लांच करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज। पीएमओ के मुताबिक, पीएम वीडियो कांफ्रेंसिंग से उज्जैन-वाराणसी के बीच चलने वाली महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।

न्यूज गैलरी

पीएम की सलाह, तनावमुक्त और खुशनुमा माहौल में दें बोर्ड परीक्षा

नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं शनिवार से शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर छात्रों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि तनावमुक्त और खुशनुमा माहौल में बोर्ड परीक्षा दें। उन्होंने छात्रों को एग्जाम वॉरियर बताते हुए कहा कि महीनों के कठिन परिश्रम और तैयारी का निश्चित तौर पर अच्छा परिणाम आएगा। उन्होंने ट्वीट में माता-पिता और शिक्षकों को भी शुभकामनाएं दीं। मालूम हो कि 15 फरवरी से अतिरिक्त और वैकल्पिक विषयों की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। 10वीं कक्षा के मुख्य विषयों की परीक्षा 26 फरवरी और 12वीं के मुख्य विषयों की परीक्षा 27 फरवरी से शुरू होंगी। इसमें 18 लाख से भी ज्यादा बच्चे 10वीं कक्षा और 12 लाख से भी ज्यादा बच्चे 12वीं कक्षा की परीक्षा में उपस्थित हो रहे हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी समय-समय पर विद्यार्थियों से रूबरू होते रहते हैं। वह तालकटोरा स्टेडियम से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिये देश को संबोधित करते हैं और छात्रों से संवाद भी करते हैं। (जासं)

रामलला के दर्शन मार्ग से पकड़ा गया संदिग्ध

अयोध्या : श्रीराम जन्मभूमि के पास रामलला के दर्शन मार्ग से शनिवार शाम एक संदिग्ध युवक पकड़ा गया। चेकिंग प्वाइंट डी-1 के करीब खुफिया विभाग के लोगों को युवक पर संदेह हुआ और उनके इशारे पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पास ही स्थित श्रीराम जन्मभूमि थाने लाकर उससे पूछताछ की गई। पकड़ा गया युवक पहली नजर में मानसिक मंदित प्रतीत हो रहा है, लेकिन पुलिस अधिकारियों को युवक का यह रवैया भ्रमित करने वाला भी लग रहा है। (संसू)

बदायूं में अनुसूचित जाति के दंपती को मंदिर प्रवेश से रोका

बदायूं : उप्र के बदायूं स्थित सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गांव भगवतीपुर में मंदिर में ताला डालकर अनुसूचित जाति के दूल्हा-दूल्हन को प्रवेश से रोका गया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद उन्हें दर्शन के लिए प्रवेश तो मिल गया, लेकिन इस मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने से अनुसूचित जाति के लोगों में आक्रोश है। गांव निवासी सोनू की शादी दो दिन पहले हुई है। शुक्रवार को दुल्हन को विदा कराकर बरात वापस घर आई तो परंपरा और मान्यता के चलते गांव देवता के मंदिर में वर-वधू पूजा अर्चना करने गए। आरोप है कि गांव में दबंग प्रवृत्ति के कुछ लोगों ने मंदिर में ताला डाल दिया। काफी देर तक वर-वधू मंदिर के बाहर खड़े रहे। वजह पूछने पर कहा गया कि अनुसूचित जाति के लोगों को मंदिर में नहीं जाने देंगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूजा कराई,लेकिन कार्रवाई नहीं की। (जासं)

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बढ़ गया रामलला का चढ़ावा

रघुवरशरण, अयोध्या

अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रामलला के चढ़ावे में भारी वृद्धि हुई है। नौ नवंबर को आए फैसले से पहले रामलला का चढ़ावा औसतन छह लाख रुपये मासिक था, जो बढ़कर अब दस लाख रुपये तक पहुंच गया है।

रामलला का दानपात्र 15 दिन के अंतराल पर खोला जाता है। प्रत्येक महीने में पहली बार पांच और दूसरी बार 20 तारीख को यह पात्र खुलता है। फैसला आने के बाद पहली बार 20 नवंबर को खोले गए दानपात्र से छह लाख से अधिक रुपये निकले थे, जबकि दो-तीन वर्षों से इस रकम का औसत पौने तीन से सवा तीन लाख रुपये के बीच चला आ रहा था।

फैसला आने के बाद छह बार खोला गया दानपात्र : रामलला का दानपात्र फैसला आने के बाद से अब तक छह बार खोला जा चुका है और हर बार फैसले से पूर्व के मुकाबले लगभग डेढ़ से दोगुनी तक रकम निकल रही है। 20 नवंबर के बाद पांच दिसंबर को रामलला के दानपात्र से पांच लाख रुपये निकले थे, जबकि इसके बाद के पखवाड़े में 3.24 लाख रुपये। पांच जनवरी को जब दानपात्र खुला, तब चढ़ावे में फिर तीव्र वृद्धि दर्ज की गई और इस पखवाड़े में चढ़ावे की राशि छह लाख रुपये तक जा पहुंची। 20 जनवरी को दानपात्र से पांच लाख रुपये आए, जबकि पिछली बार यानी छह फरवरी को चढ़ावे की राशि 4.89 लाख रुपये गिनी गई।

अयोध्या के अस्थाई मंदिर में विराजमान रामलला। जागरण

रामलला के खाते में 11 करोड़ से अधिक

रामलला के चढ़ावे में वृद्धि तो तीन माह की है, लेकिन बैंक में उनका खाता करीब तीस साल पुराना है। रामलला के चालू खाते में वर्तमान में करीब तीन करोड़ रुपये जमा हैं। रामलला के नाम से साढ़े आठ करोड़ रुपये से अधिक का फिक्स डिपॉजिट भी है।

आचार्य सत्येंद्रदास, रामलला के मुख्य अर्चक। जागरण

आने वाले दिनों में मंदिर के शिलान्यास के साथ रामलला के चढ़ावे में कई गुना वृद्धि होगी। इस उत्साह का आकलन मंदिर निर्माण के लिए दान देने वालों के एलान से किया जा सकता है।

- आचार्य सत्येंद्रदास, रामलला के मुख्य अर्चक।

कोठारी बंधु की बहन ने राम मंदिर ट्रस्ट का हिस्सा बनने की जताई इच्छा

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- **भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और राम माधव के समक्ष इच्छा व्यक्त कर चुकी हैं पूर्णिमा कोठारी**
- **सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए सभी निर्णय लेने के लिए किया है इस ट्रस्ट का गठन**

अयोध्या में 30 अक्टूबर, 1990 को राम मंदिर आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में मारे गए कारसेवक भाइयों राम व शरद कोठारी की बहन पूर्णिमा कोठारी ने 'श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' का हिस्सा बनने की इच्छा व्यक्त की है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए सभी निर्णय लेने के लिए हाल ही में इस ट्रस्ट का गठन किया है।

पूर्णिमा ने कहा, 'राम मंदिर के लिए मेरे दोनों भाइयों ने शहादत दी थी और उनके सपने को साकार करने के लिए मैं भी पिछले 30 वर्षों से लड़ाई में शामिल रही हूं। बहुत से लोगों ने कहा है कि मुझे ट्रस्ट में स्थान मिलना चाहिए। मैंने इस मामले में भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और राम माधव के समक्ष पहले ही अपनी इच्छा व्यक्त की है। पिछले महीने मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के महासचिव सुरेश भय्याजी जोशी को भी इस बाबत एक पत्र लिखा था। देखते हैं आगे क्या होता है।' पूर्णिमा ने आगे कहा कि 23 जनवरी को मैं अयोध्या में थी। मुझे महंत नृत्य गोपाल दास जी ने भी आर्शीवाद दिया था। इनके अलावा अयोध्या में अन्य संत भी हैं, जो मानते हैं कि मुझे भी ट्रस्ट का हिस्सा होना चाहिए। उन्हें लगता है कि जिन लोगों ने राम मंदिर के लिए अपना जीवन लगा दिया उनके परिवार के सदस्यों को ट्रस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। बता दें कि राम मंदिर के लिए शहादत देने वाले कोठारी बंधु कोलकाता के ही रहने वाले थे। उनकी इकलौती बहन पूर्णिमा और कोठारी भाइयों के दोस्त राजेश अग्रवाल जो अयोध्या में गोलीबारी के दौरान उनके साथ थे, मिलकर राम-शरद कोठारी स्मृति समिति नामक एक संगठन का संचालन करते हैं और प्रत्येक साल वे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल आदि के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन करने वालों के लिए कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें पुरस्कृत करते हैं। पूर्णिमा लोहे के पुर्जों के अपने पारिवारिक व्यवसाय को भी देखती हैं। गौरतलब है कि राम और शरद कोठारी आरएसएस के नियमित सदस्य थे। 30 अक्टूबर 1990 को कारसेवा के दौरान गुंबद पर भगवा फहराने और तोड़फोड़ के बाद पुलिस फायरिंग में दोनों की जानें चली गई थी।

किसी मामले पर असहमति को राष्ट्र विरोधी बताना ठीक नहीं

रखा पक्ष ▶ सीएए पर छिड़े आंदोलन के बीच जस्टिस चंद्रचूड़ की ताकीद

कहा कि मतभेद लोकतंत्र का मूल तत्व, लेकिन राष्ट्र विरोधी न हो

- **देश के विभिन्न हिस्सों में सीएए और एनआरसी के विरोध में हो रहे आंदोलनों को लेकर था उनका इशारा**

अहमदाबाद, प्रेट्र : किसी मसले पर मतभेद होना और उसे उजागर करना लोकतंत्र का मूल तत्व है। इसके जरिये जनभावना सामने आती है।

इसे राष्ट्रविरोधी या अलोकतांत्रिक ठहराना ठीक नहीं है। लेकिन जब विरोध प्रदर्शन राष्ट्रविरोधी आंदोलन में तब्दील हो जाए तो वह संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ होता है। यह बात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कही है। जाहिर है उनका इशारा देश के विभिन्न हिस्सों में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध में हो रहे आंदोलनों को लेकर था।

15 वें जस्टिस पीडी देसाई मेमोरियल व्याख्यान में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, मतभेदों को उजागर होने से रोकने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल भी कानून व्यवस्था का उल्लंघन है। उन्होंने कहा, मतभेद उचित हैं।

लेकिन ध्यान रहना चाहिए जब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार विकास और सामाजिक समन्वय की योजना पेश कर रही हो तब मिश्रित समाज वाले देश में एकाधिकार की बात करना उचित नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, मतभेदों और सवालों को महत्व न देने से देश में राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतभेद 'सेफ्टी वाल्व' की मानिंद हैं जिनसे होकर जनभावना सामने आती है और सरकार को उनके अनुसार नीतियों में सुधार करने का संदेश मिलता है। लेकिन यह सब संविधान के दायरे में होना चाहिए।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। फाइल

असहमत होने पर अपनी बात रखें

गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में छात्रों को असहमति पर बोलने का संदेश देते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, यह भाव स्वविवेक से पैदा होता है। गलत बात के खिलाफ या असहमति पर बोलने से अधिवक्ता की पहचान बनती है। मुकदमे की सुनवाई के समय न्यायाधीश के आगे खड़े होकर सम्मानजनक तरीके से असहमति जताई जा सकती है। अपने वरिष्ठों और गुरुजनों के आगे भी इसी तरह से अपनी बात रखी जा सकती है। इसी प्रकार से असफलताओं से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हर व्यक्ति को कई बार असफलता मिलती है, वह उनसे सीख लेकर आगे बढ़ सकता है।

चावला के जेल जाने से हाथ मलती रह गई क्राइम ब्रांच

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- **दोबारा रिमांड पर लेने के लिए 19 फरवरी को अदालत में रखेगी पक्ष**

अंतरराष्ट्रीय सटोरिये संजीव चावला को जेल भेजे जाने से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच हाथ मलती रह गई और उससे पूछताछ नहीं कर सकी। हालांकि वह उसे रिमांड पर लेने की दोबारा कोशिश करेगी। हाई कोर्ट ने इस मामले में 19 फरवरी को केंद्र सरकार व दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है।

क्राइम ब्रांच के डीसीपी डॉ. राम गोपाल नाइक का कहना है कि उन्होंने ब्रिटेन की अदालत में कहा था कि चावला को भारत ले जाकर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जा सकता है। इसलिए उसको दोबारा रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट के समक्ष मजबूती से पक्ष रखेंगे। उनका कहना है कि वर्ष 2000 में केस दर्ज होते ही चावला दिल्ली छोड़कर ब्रिटेन भाग गया। इसलिए उससे कभी पूछताछ नहीं की जा सकी।

दरअसल, चावला को लंदन से प्रत्यर्पण पर दिल्ली लाने के बाद क्राइम ब्रांच ने गुरुवार शाम उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए 12 दिन की रिमांड ली थी। अचानक उसका भाई हाई कोर्ट चला गया और उसे राहत मिल गई। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहने वाले चावला के भाई का रियल एस्टेट का काम है। उसने हाई कोर्ट में बताया कि भारत सरकार ने ब्रिटेन की अदालत को आश्वासन दिया है कि चावला को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। उसे ट्रायल फेस करने के लिए बुलाया गया है न कि इंवेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। वहीं, एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि संजीव चावला से पूछताछ बहुत जरूरी है। वह किसी सटोरिये के कहने पर मैच फिक्सिंग के धंधे में आया था।

क्रिकेट मैच फिक्सर संजीव चावला। फाइल

छह लोगों को बनाया था आरोपित : मैच फिक्सिंग मामले में क्राइम ब्रांच ने शुरुआती जांच के आधार पर केस में केवल छह लोगों को आरोपित बनाया था। इसमें तत्कालीन दक्षिण-अफ्रीका के कप्तान हैंसी क्रोनिए, टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार, राजेश कालरा, बिट्टू, मनोहर खट्टर व संजीव चावला शामिल हैं। 2002 में हैंसी क्रोनिए की विमान हादसे में मौत हो गई। किशन कुमार, राजेश कालरा व बिट्टू को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। तीनों अभी जमानत पर हैं। बताया जा रहा है कि मनोहर खट्टर की मौत हो चुकी है, लेकिन इसका कोई सुबूत नहीं है।

विशेषज्ञों को उम्मीद सफल होगा अमेरिकी राष्ट्रपति का भारत दौरा

वाशिंगटन, प्रेट्र : दक्षिण एशियाई मामलों के अमेरिकी विशेषज्ञ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा को लेकर बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। उनका कहना है कि यह दौरा कई मायनों में पूरी तरह सफल होगा।

भारत मामलों के विशेषज्ञ और कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के वरिष्ठ सदस्य एशले टेलिस ने कहा, 'मेरा मानना है कि ट्रंप का दौरा दिलचस्प और पूरी तरह सफल होगा। यह भी उम्मीद है कि रक्षा बिक्री पर कुछ प्रगति हो सकती है।' थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के यूएस इंडिया पॉलिसी स्टडीज में वाधवानी चेयर के वरिष्ठ सलाहकार रिक रोस्सोव ने उम्मीद जताई है कि दोनों देश के नेता कारोबारी मोर्चे पर अड़चनों को दूर करने के लिए समझौते को अंतिम रुप दे सकते हैं। उन्होंने कहा, 'भारत बड़ा और उभरता बाजार है और अमेरिका के लिए उभरता रक्षा साझीदार है।' न्यू अमेरिका के वरिष्ठ सदस्य और ह्वाइट हाउस के पूर्व अधिकारी अनीश गोयल ने कहा, 'यह दौरा राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के लिए सियासी वरदान होगा। दोनों देशों को करीब लाने के लिहाज से यह अहम सकारात्मक दौरा है।'

डोनाल्ड ट्रंप फाइल

नेपाल में आयोजित इज्तमा में पाक और बांग्लादेश के मुस्लिमों को अनुमति नहीं

जागरण संवाददाता, मधुबनी

भारतीय सीमा से सटे नेपाल के सप्तरी जिले में तीन दिवसीय इस्लामिक सम्मेलन (इज्तमा) को सशर्त मंजूरी मिली है। शुक्रवार को अंतिम समय में नेपाल के गृह मंत्रालय ने कार्यक्रम स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया था। इस पर नेपाली मुस्लिम आयोग के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से भेंटकर अनुमति देने का अनुरोध किया। तदोपरांत आज नेपाल सरकार ने सिर्फ भारत-नेपाल के लोगों के शामिल होने की शर्त पर मंजूरी दे दी। आयोजकों ने भी शर्त मान ली है।

सप्तरी जिले में तीन दिवसीय इज्तमा शनिवार से शुरू होने वाला था। कार्यक्रम में सिर्फ भारत और नेपाल के मुस्लिमों को शामिल करने का सरकार व प्रशासन ने आदेश दिया था। मगर, इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, सऊदी अरब और इंडोनेशिया आदि देशों से भी मुस्लिम नेपाल पहुंचने लगे। करीब एक लाख लोगों के प्रवेश करने की सूचना नेपाल सरकार को मिली। इसके बाद वह हरकत में आई। गृह मंत्रालय ने इस कार्यक्रम को रद करने का आदेश दे दिया। आनन-फानन में नेपाल पुलिस ने सप्तरी जिला से सटे भारत-नेपाल सीमा को सुरक्षा कारणों से सील कर दिया। इससे यहां आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया।

दो लाख लोगों के भाग लेने का अनुमान : आयोजक हाफिज निजाम ने कहा कि चूंकि बाहर से लोग पहुंच चुके हैं, ऐसे में कार्यक्रम स्थगित करना संभव नहीं था। शर्त के साथ मंजूरी मिलने पर कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें दो लाख लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। वहीं, भारतीय सीमा पर तैनात एसएसबी अधिकारियों के अनुसार जवान सुरक्षा में लगे हैं। हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।

तिब्बती भी बन सकते हैं भारत में अफसर

दिनेश कटोच, धर्मशाला

- **पहली जनवरी 1962 से पहले भारत आने वाले लोगों के बच्चे इस वर्ष से माने गए पात्र**

निर्वासन का जीवन जी रहे तिब्बती समुदाय के युवा भी अब सरकारी अफसर बन पाएंगे। तिब्बती युवाओं को केंद्र ने सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने का बड़ा मौका प्रदान किया है। देशभर में रह रहे इस समुदाय के युवा अब संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा देकर सरकारी क्षेत्र में प्रशासनिक सेवाएं दे सकेंगे। इससे पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन नौकरी के लिए केवल वही युवा पात्र होंगे, जिनके माता-पिता जनवरी 1962 से पहले भारत आ गए थे और तब से स्थायी रूप से यहीं रहे रहे हैं। हालांकि अन्य स्तरों के लिए तो तिब्बती युवा पात्र होंगे, लेकिन आइएएस व आइपीएस के लिए पात्र नहीं होंगे।

1959 में तिब्बत से भारत आने के बाद इन्हें सरकार से मतदान का अधिकार हासिल करने के साथ शरणार्थी का दर्जा भी है। शरणार्थी तिब्बती हिमाचल के धर्मशाला की निर्वासित तिब्बत सरकार को चुनते हैं और अपने कार्यों को चलाने के लिए उनकी अपनी एक अलग व्यवस्था भी है। कई तिब्बती युवा निर्वासित सरकार की प्रणाली के तहत चयनित होकर अपनी सरकार में सेवाएं देते हैं। लेकिन यह पहली बार है कि उन्हें भारत सरकार की अखिल भारतीय सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं में पात्र माना गया है।

विश्व में 60 लाख तिब्बती शरणार्थी हैं। देखा जाए तो अधिकतर तिब्बती समुदाय के लोगों ने भारत की नागरिकता नहीं ली है, इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि अगर वह भारत की नागरिकता ले लेते हैं तो उनका शरणार्थी का दर्जा खत्म हो जाएगा और वह तिब्बत की स्वतंत्रता की लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन दूसरी ओर सरकारी क्षेत्र में तिब्बती समुदाय की भी सहभागिता के द्वार खोलने के फैसले का निर्वासित तिब्बत संसद ने स्वागत किया है। उनका मानना है कि पहले हमें मांगना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने यह एक सुनहरा मौका दिया है, जिसका लाभ युवा पीढ़ी को लेना चाहिए।

1350 तिब्बती मतदाता : बता दें कि करीब 1350 तिब्बती मतदाताओं ने विधानसभा चुनाव में भी वोट डाला था। कुल संख्या के 40 प्रतिशत के पास अभी भारत की नागरिकता है।

इसलिए मिला है वोट डालने का अधिकार : सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 1959 से 1985 तक भारत में पैदा होने वालों को मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने का अधिकार दिया गया है। इसके मिलने के बाद कुछ शर्तों के आधार पर भारतीय नागरिकता हासिल कर सकते हैं। 2017 में करीब 360 तिब्बती शरणार्थियों ने अपने नाम मतदाता सूची में शामिल करवाकर मतदाता पहचान पत्र बनाए थे।

शायर इमरान प्रतापगढ़ी को 1.4 करोड़ रुपये का नोटिस

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद

- **मुचलका नहीं भरने पर आगे की कार्रवाई होगी**

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में उप्र स्थित मुरादाबाद के ईदगाह पर चल रहे धरने में शामिल होना शायर और कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी को भारी पड़ गया है।

धारा-144 का उल्लंघन कर धरने में शामिल होने पर पुलिस ने उन्हें एक करोड़ चार लाख 8 हजार 693 रुपये वसूली का नोटिस भेजा है। पुलिस ने उनके वाट्सएप पर नोटिस भेजा है। वह पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर मुरादाबाद से चुनाव लड़ चुके हैं। अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम राजेश कुमार की तरफ से सीआरपीसी की धारा-111 के तहत पुलिस की रिपोर्ट पर यह नोटिस जारी हुआ है। नोटिस में कहा गया है कि मुरादाबाद में धारा-144 लगी हुई है। फिर भी ईदगाह के मैदान में सीएए के विरोध में धरना चल रहा है। पुलिस द्वारा अनुमति न देने के बावजूद इमरान प्रतापगढ़ी सात फरवरी को ईदगाह में चल रहे धरने में शामिल हुए। यह धारा-144 का उल्लंघन है।

धरने में एक विशेष समुदाय के लोगों को भड़काकर एकत्र किया जा रहा है। महिलाएं भी यहां एकत्र हैं। यहां की संवेदनशीलता को देखते हुए फोर्स लगानी पड़ रही है। कर्मचारियों को अपने मूल कार्यों से हटकर ड्यूटी करनी पड़ रही है। नगर क्षेत्र में कानून व्यवस्था भी बिगड़ने की आशंका बनी रहती है। पुलिस मुख्यालय के निर्धारित मानक के अनुरूप पुलिस बल पर प्रतिदिन 13 लाख 42 हजार 500 रुपये खर्च हो रहे हैं।

रखी बात

मप्र में ट्रिपल आइटीडीएम में आयोजित कार्यक्रम को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया संबोधित, मंडला के रामनगर में आदिवासी महोत्सव का भी किया उद्घाटन

'मातृभाषा आंख है तो अंग्रेजी चश्मा, घर में मातृभाषा में ही बात करें'

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश में जबलपुर और मंडला के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जनजातीय कलाकारों को सराहा तो युवा छात्रों को नसीहत भी दी। नायडू ने छात्रों से कहा कि मातृभाषा आंख है तो अंग्रेजी उसका चश्मा। घर में हर वर्ग के युवा मातृभाषा का ही इस्तेमाल करें। यह सीख उन्होंने शनिवार को डुमना स्थित पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान (ट्रिपल आइटीडीएम) में आयोजित प्रोजेक्ट्स अवलोकन कार्यक्रम में छात्रों को दी।

उन्होंने कहा कि विश्व में तकनीक तेजी से बढ़ रही है और इसके साथ कई चुनौतियां भी उत्पन्न हो रही हैं। जिस तरह से भारत ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र काम किया है, उससे एक बात पक्की हो गई है कि देश इस क्षेत्र में भी अव्वल हो रहा है।इससे पूर्व नायडू मंडला के रामनगर में आयोजित दो दिवसीय आदिवासी महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे। आदिवासी महोत्सव में जनजातीय संस्कृति की अनूठी झलक दिखाई दी। शनिवार को राजस्थान के जनजातीय कलाकारों ने चकरी, चरी व घूमर नृत्य प्रस्तुत किए। मोहगांव के कलाकारों ने शैला, करमा व गौंड़ी, बिछिया के कलाकारों ने नगाड़े की थाप पर बैगा नृत्य तथा निवास के कलाकारों ने रीना व करमा पर नृत्य किया। बालाघाट से आए आदिवासी नर्तक दल ने गौंडी परंपरागत नृत्य शैली की प्रस्तुति दी। चाढ़ा डिंडौरी के बैगानी लोक नृत्य दल ने बैगा लोक नृत्य, मेढ़ाखार डिंडौरी के कलाकारों ने गुदुम शैली, धुलिया नृत्य दल डिंडौरी ने गुदुम बाजा नृत्य, मेढ़ाखार डिंडौरी के कलाकारों ने करमा शैला लोक नृत्य, आदिवासी लोक नर्तक दल डिंडौरी ने बोना लोक नृत्य, लालपुर डिंडौरी के कलाकारों ने शैला नृत्य की प्रस्तुति दी। इन प्रस्तुतियों में लोक नृत्य व लोक संगीत की झलक देखने को मिली। लोकनायकों को श्रद्धांजलि देते हुए नायडू ने कहा कि आदिवासी संस्कृति को कायम रखना और जनजातियों का विकास करना हमारा संवैधानिक दायित्व भी है। भारत में अब तक करीब 250 भाषाएं विलुप्त हो गई हैं, जिनमें अधिकांश भाषा जनजातीय हैं। हमें विदेशी मानसिकता को छोड़कर अपनी मातृभाषा पर ध्यान देना चाहिए। इसे कभी न छोड़ें। विकास के लिए शांति जरूरी है। सरकार माओवाद को रोकने में सफल रही है।

मध्य प्रदेश के मंडला में आदिवासी महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल (बाएं से चौथे) और फग्गन सिंह कुलस्ते (बाएं से छठे) ने उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू को स्मृति चिह्न भेंट किया। नईदुनिया

शहीद राजाओं को दी श्रद्धांजलि : उपराष्ट्रपति ने गोंडवाना साम्राज्य के शहीद राजाओं को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति राज्यमंत्री प्रहलाद पटेल, केंद्रीय जनजातीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह, राज्यसभा सदस्य संपतिया उईके आदि उपस्थित रहे। आदिवासी महोत्सव के अंतिम दिन रविवार को जनजातीय विषयों पर संगोष्ठी आयोजित होगी जिसमें विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिया जाएगा।

अमित शाह और शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों की बैठक तय नहीं

नई दिल्ली, एएनआइ : गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि गृह मंत्री अमित शाह और शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के बीच रविवार को कोई बैठक तय नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया था कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के मसले पर रविवार को उनकी अमित शाह के साथ बैठक होने वाली है। हालांकि, प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं।

बातचीत के लिए उन्हें बुलाना सरकार की जिम्मेदारी है। प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को कहा कि सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के मुद्दे पर रविवार को उनकी अमित शाह के साथ बैठक होगी। उन्होने यह भी कहा कि बैठक के लिए उन लोगों ने गृह मंत्री से समय नहीं लिया है। जबकि, शाहीन बाग प्रदर्शन के आयोजकों में से एक सैयद अहमद तासीर ने मंच से कहा कि वे लोग गृह मंत्री से मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन गृह मंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए वे कितने लोगों से मिलना चाहते हैं। वहीं, एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि वो लोग रविवार को अमित शाह के घर की तरफ मार्च करेंगे। दूसरी ओर, गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ कल कोई इस तरह की बैठक तय नहीं है।' दरअसल, दो दिन पहले अमित शाह ने एक कार्यक्रम में कहा था कि अगर किसी को सीएए पर कोई भ्रम है तो वह उनके दफ्तर से उनसे मिलने का समय ले सकता है। वह तीन दिन के भीतर उससे मिलेंगे।

सीएए में भारतीय नागरिकों के खिलाफ एक शब्द नहीं : रेड्डी : हैदराबाद में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि सीएए में देश के 130 करोड़ नागरिकों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं है। उन्होंने शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से पूछा कि क्या वे पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों के लिए धरना दे रहे हैं।

न्यूज गैलरी

नगा उग्रवादियों के मददगारों के खिलाफ आरोपपत्र दायर

नई दिल्ली : एनआइए ने नगा उग्रवादी समूह की आर्थिक मदद करने वाले दो व्यक्तियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है। इन लोगों में एक स्वयंभू मेजर है। दोनों पर नगा उग्रवादी समूह एनएससीएन (आइएम) की आतंकी गतिविधियों की आर्थिक मदद में संलिप्त रहने का आरोप है। एनआइए की विशेष अदालत में दायर आरोपपत्र में दीमापुर, नगालैंड के लुकिन मशांगवा और तिराप अरुणाचल प्रदेश के जयकिशन शर्मा को नामजद किया गया है। जांच एजेंसी ने कहा है कि शुक्रवार को आरोपपत्र दायर किया गया। इन लोगों को आइपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धारा 120 बी और 384 के साथ ही यूएपीए(गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) की धारा 17 के तहत आरोपित किया गया है। एनआइए ने पिछले साल 17 सितंबर को मामला फिर से दर्ज किया था। जांच एजेंसी ने कहा कि पिछले साल 20 अगस्त को दीमापुर पुलिस की विशेष आपरेशन टीम ने माशंगवा और शर्मा के पास से 10,46,100 रुपये बरामद किए थे। माशंगवा एनएससीएन (आइएम) का स्वघोषित मेजर है और शर्मा अरुणाचल प्रदेश के तिराप जिले में ठेकेदार है। (प्रेट्र)

सुकमा में मुठभेड़ में नक्सली कमांडर ढेर

सुकमा: छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले के अरलंपल्ली और जग्गावराम जंगलों के बीच शनिवार शाम को डीआरजी (डिस्ट्रक्ट रिजर्व गार्ड) और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। एक नक्सली मारा गया। एसपी शलभ सिन्हा ने बताया कि मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से एक नक्सली का शव, एक बंदूक, हैंड ग्रेनेड और पिट्ठू बैग समेत नक्सली सामग्री बरामद की है। मारे गए नक्सली की शिनाख्त पेंटापाड़ निवासी मिलिशिया कमांडर माड़वी सुक्का के रूप में की गई है। (नईदुनिया)

चलती ट्रेन में पांच डकैतों को पुलिस ने दबोचा, सरगना फरार

रायपुर: रायपुर में गुरुवार रात प्लाईवुड कारोबारी बबलू शर्मा के घर में घुसकर 50.14 लाख की डकैती डालकर फरार हुए पांच डकैतों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अंतरराज्यीय ऑपरेशन चलाकर आरोपितों को चलती ट्रेन में दबोच लिया। सरगना अभी फरार है। बबलू के यहां दो साल पहले काम कर चुके मालाराम ने इस वारदात का प्लान बनाया था। वारदात के बाद पांचों निजामुद्दीन एक्सप्रेस से दिल्ली फिर वहां से राजस्थान भागने की फिराक में थे। इसकी खबर लगते ही दिल्ली में पहले से डटी रायपुर पुलिस टीम को अलर्ट किया गया। टीम ने निजामुद्दीन स्टेशन से 30 किमी पहले ट्रेन में चढ़कर एक-एक डिब्बे की तलाशी लेकर पांचों डकैतों को धर दबोचा। (नईदुनिया)

नौकरी छोड़ सियासत में उतरे शाह फैसल पर लगा पीएसए

कार्रवाई ▶ बीते छह माह में पीएसए के तहत बंदी बनाए गए फैसल आठवें नेता

दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पकड़ा गया था

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

नौकरशाही छोड़कर अलगाववादी भावनाओं के आधार पर सियासत में भविष्य तलाश रहे डॉ. शाह फैसल को भी प्रशासन ने शुक्रवार रात जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत बंदी बना लिया। 2009 के आइएएस टॉपर शाह फैसल 14 अगस्त 2019 से एहतियातन हिरासत में थे। सब जेल एमएलए हॉस्टल में अब केवल तीन नेता एहतियातन हिरासत में रह गए हैं। इनमें नेशनल कांफ्रेंस के पूर्व एमएलसी अली मोहम्मद डार, पीडीपी के पूर्व विधायक पीरजादा मंसूर हुसैन और आवामी इत्तेहाद पार्टी के बिलाल सुल्तान शामिल हैं।

पिछले छह माह के दौरान जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा पीएसए के तहत बंदी बनाए जाने वाले शाह फैसल मुख्यधारा की सियासत से संबंध रखने वाले आठवें नेता हैं। इनसे पूर्व नेकां अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पीडीपी

डॉ. शाह फैसल फाइल

अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, नेकां महासचिव अली मोहम्मद सागर, नेकां नेता हिलाल अकबर लोन, पीडीपी के सरताज मदनी और नईम अख्तर पर पीएसए लगाया जा चुका है।

जम्मू-कश्मीर कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की पांच अगस्त को घोषणा करने से पहले प्रशासन ने एहतियात के तौर पर अलगाववादियों, ट्रेड यूनियन नेताओं और मुख्यधारा की राजनीति करने वाले गैर भाजपा दलों के लगभग 500 प्रमुख नेताओं को हिरासत में या नजरबंद किया था। इनमें से कई को अपने घरों के आसपास व कुछ को संटूर होटल को सब जेल का दर्जा देकर वहां रखा गया था। हालांकि इनमें से अधिकांश को रिहा किया जा चुका है।

कौन हैं शाह फैसल

शाह फैसल ने वर्ष 2019 की शुरुआत में ही सरकारी सेवा से इस्तीफा दे दिया था। फैसल ने मुस्लिम व कश्मीर की विशिष्ट पहचान के संरक्षण के नाम पर अपनी सियासी पारी शुरू की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि कश्मीर में बेगुनाह लोगों की हत्याएं हो रही हैं। इसके बाद उन्होंने जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट नामक अपना संगठन बनाया था। लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद वह जब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में केंद्र के फैसले को कथित तौर पर चुनौती देने जा रहे थे। उस समय उन्हें दिल्ली स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पकड़ा गया था। हालांकि उन्होंने दावा किया था कि वह आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे हैं। इस पर सरकार ने कहा कि वह एक पर्यटक वीजा पर यात्रा कर रहे थे, न कि छात्र वीजा पर।

यह वह पीडीपी नहीं है जो हीलिंग टच के लिए बनी थी

प्रथम पृष्ठ से आगे

तांत्रे ने कहा कि हमें आज तक समझ में नहीं आया कि निष्कासन का फैसला किसने और किस हैसियत से लिया है। पूरे हालात पर गौर करने के बाद मैंने तय किया कि यह वह पीडीपी नहीं है जो लोगों को हीलिंग टच के लिए बनी थी। अब यह कुछ खास लोगों की पार्टी है, लिहाजा इससे दूर रहना बेहतर है। इसलिए मैंने पीडीपी से इस्तीफा दे दिया। उप राज्यपाल से मिलना, लोगों की मुसीबतों को दूर करने की बात करना, जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा मांगना कोई गुनाह नहीं है।

अच्छा हुआ खत्म हो गया अनुच्छेद-370 : उन्होंने कहा कि अनुच्छेद-370 की समाप्ति पर रोने का कोई फायदा नहीं है। यह तो एक लाश ही थी, जिसे हम उठाए हुए थे। कांग्रेस के शासनकाल में अनुच्छेद 370 में करीब तीन दर्जन संशोधन हुए थे। हमें जम्मू-कश्मीर के लोगों की खुशहाली के लिए एक नए जोश के साथ प्रयास करने चाहिए।

पार्टी में पैदा हो गए हैं अराजक तत्व : तांत्रे ने कहा कि पीडीपी संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद संगठन में कई लीडर और अराजक तत्व पैदा हो गए हैं। पूर्व वित्तमंत्री हसीब द्राबू को निकाल दिया गया, उसके बाद पार्टी हित की बात करने वाले कई विधायकों को दरकिनार किया गया तो उनमें से अधिकांश ने पीडीपी को ही छोड़ दिया।

मुआवजा राशि से संतुष्ट नहीं हैं कश्मीर के बागवान

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- सात नवंबर की बर्फबारी ने सेब की फल को पहुंचाया भारी नुकसान
- मदद की राशि को बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं घाटी के किसान

बारामुला में अपने बाग में घूम रहे अरशद हुसैन के चेहरे पर मायूसी को साफ देखा जा सकता है। पूछने पर उसने कहा कि सब तकदीर की बात है। पांच साल पहले रिटायरमेंट पर मिली धनराशि में 20 लाख रुपये खर्च कर मैंने यह चार कनाल का बाग तैयार किया था। पहली बार बाग में सेब की फसल हुई, फल ठीक आया था, लेकिन बर्फ भी खूब पड़ी। सबकुछ तबाह हो गया। फिर उम्मीद जगी कि मुआवजा मिलेगा, मुआवजा मिला लेकिन आठ हजार रुपये। वह इस मुआवजा राशि से असंतुष्ट हैं।

प्रशासन द्वारा दी गई मुआवजा राशि से असंतुष्ट होने वाले अरशद हुसैन अकेले किसान नहीं हैं। हुसैन ने कहा कि पहले यहां आतंकियों के बंद ने हमें नुकसान पहुंचाया और उसके बाद सात नवंबर की बर्फबारी ने। फसल का एक बड़ा हिस्सा खराब हो गया। एक दर्जन से ज्यादा पेड़ भी टूट गए। वह कहते हैं कि नुकसान करीब तीन लाख रुपये का हुआ है और मुआवजा आठ हजार रुपये मिला। नार्थ कश्मीर फ्रूट ग्रोअर्ज एंड डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष फैयाज अहमद मलिक ने कहा कि यहां बागवानी 70 प्रतिशत लोगों की रोजी रोटी का आधार है। बागवानी विभाग ने राजस्व विभाग के साथ मिलकर यहां नुकसान का जायजा लिया था, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला है। दो हजार रुपये से किसी टूटे पेड़ का इलाज नहीं हो सकता। एक क्षतिग्रस्त पेड़ को फिर से तैयार करने के लिए जो कील, बोल्ट, रस्सी चाहिए और दवा चाहिए, वही दो हजार रुपये में आती है। सरकार को चाहिए कि वह हमें पर्याप्त मुआवजा प्रदान करे।

प्रत्येक क्षतिग्रस्त पेड़ के आधार पर मुआवजा होना चाहिए। मलिक ने कहा कि एक पेड़ जो साल में 10 हजार से एक लाख रुपये तक का फल देता है, उसके लिए न्यूनतम मुआवजा पांच हजार रुपये तो हो। इस संदर्भ में जब निदेशक बागवानी एजाज अहमद बट से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो वह उपलब्ध नहीं हो पाए। बागवान इकबाल लोन ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार बाजार और हालात को देखते हुए उचित मुआवजा प्रदान करेगी। यहां लोगों को सात सौ रुपये, डेढ़ हजार रुपये जैसी मुआवजा राशि मिल रही है।

दो हजार रुपये प्रति कनाल मुआवजा तय : बागवानी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि यहां पर प्रत्येक कनाल जमीन के लिए दो हजार रुपये का मुआवजा ही तय किया गया है। यह राशि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष यानी एनडीआरएफ के नियमों के तहत दी जा रही है।

पाकिस्तान ने फिर की गोलाबारी कई घरों को पहुंचा नुकसान

जागरण संवाददाता, हीरानगर

- सीमावर्ती गांव छन्न टांडा, चक चंगा और गुज्जर चक को निशाना बना कर की गोलाबारी
- धमाकों से आसपास के कई लोगों के घरों में भी दरारें पड़ीं

पाकिस्तान ने एक बार फिर सीमावर्ती गांव छन्न टांडा, चक चंगा और गुज्जर चक को निशाना बना कर गोलाबारी की। इस दौरान लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है।

शनिवार सुबह चार बजे जब लोग घरों व बंकरों के अंदर गहरी नींद में सोए हुए थे, तभी पाक रेंजरों ने अचानक पप्पू चक पोस्ट से गांवों को निशाना बना कर गोलीबारी शुरू कर दी जो सुबह साढ़े छह बजे तक जारी रही। इस दौरान रेंजरों ने दर्जनों गोले गांवों में दागे जो मकानों और खेतों में गिरे। दो गोले छन्न टांडा के मनोहर लाल, विजय कुमार, बब्बू के घर की छत पर गिरे, जिससे छतों में दरारें आ गई और ऊपर रखीं पानी की टंकियां क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं, गुज्जर चक के अश्विनी कुमार के घर के पास एक गोला गिरने से घर भी नुकसान पहुंचा।

गोलीबारी के धमाकों से आसपास के कई लोगों के घरों में भी दरारें पड़ गईं। छन्नटांडा निवासी मनोहर लाल और पंच दौलत राम ने बताया कि गांवों में पिछले कई दिनों से गोलीबारी हो रही है। पहले घरों में गोले गिरते थे, लेकिन शनिवार सुबह रेंजरों ने गांवों को निशाना बना कर गोलीबारी की है, अगर इसी तरह गोलीबारी होती रही तो जान माल को नुकसान हो सकता है। हालांकि, बीएसएफ गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रही है।

प्रभावित गांवों का दौरा किया : हीरानगर के एसडीएम राकेश कुमार ने सुबह ही प्रभावित गांवों का दौरा कर गोलीबारी से हुए नुकसान का जायजा लिया और ग्रामीणों की समस्या सुनीं। इस दौरान उन्होंने गोलीबारी के समय बाहर न जाने की सलाह दी। गौरतलब है कि हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान पिछले छह माह से गोलीबारी करता आ रहा है। इससे पहले मनयारी, पानसर, रठुआ गांवों में भी गोलीबारी से काफी नुकसान हुआ था।

हवाई अड्डे के रनवे पर अचानक पहुंची जीप विमान को नुकसान

नई दिल्ली, एजेंसियां : पुणे हवाई अड्डे पर शनिवार सुबह एयर इंडिया के विमान का मुख्य हिस्सा तब क्षतिग्रस्त हो गया, जब उड़ान भरने के दौरान उसके पायलट ने रनवे पर अचानक पहुंचे एक व्यक्ति और जीप को बचाने के लिए तुरंत विमान को उठाने का फैसला किया। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना तब घटी, जब एयर इंडिया का ए-321 विमान पुणे हवाई अड्डा से उड़ान भर रहा था। इस घटना के बावजूद विमान दिल्ली हवाई अड्डा पर सुरक्षित उतर गया। डीजीसीए ने घटना की जांच का आदेश दिया है। अधिकारी ने कहा, 'टेक ऑफ के दौरान चालक दल के सदस्य ने रनवे पर एक जीप और एक व्यक्ति को देखा, तो उसने टक्कर से बचाने के लिए विमान को जल्दी मोड़ दिया।' उन्होंने कहा कि एयर इंडिया को कॉकपिट वायस रिकार्डर उसके विश्लेषण के लिए हटाकर रख लेने को कहा गया है। डीजीसीए के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि जांच के लिए विमान को तत्काल सेवा से हटा लिया गया है।

संगरूर में पेट्रोल लीक होने से स्कूल वैन में आग, चार बच्चे जिंदा जले

जेएनएन, संगरूर : पंजाब के संगरूर में बीस साल पुरानी खटारा स्कूल वैन ने चार मासूम बच्चों की जान ले ली। लोंगोवाल के गुरुद्वारा सिद्ध समाधां साहिब के पास शनिवार दोपहर दो बजे वैन में आग लग गई, जिससे तीन बच्चियों व एक बच्चे की जिंदा जलकर मौत हो गई। आठ बच्चों को राहगीरों ने कड़ी मशक्कत के बाद वैन से बाहर निकाला। इनको एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। दूसरी कक्षा तक के ये बच्चे लोंगोवाल गांव के रहने वाले थे।

बताया जा रहा है कि सिमरन पब्लिक प्राइवेट स्कूल ने कंडम हालत में कुछ समय पहले ही वैन खरीदा था। पेट्रोल लीक होने के कारण आग लगी। इसकी एक खिड़की जाम होने के कारण सभी बच्चों को नहीं निकाला जा सका। हादसे के दौरान 12 बच्चों सहित चालक व हेल्पर मौजूद थे। हादसे से गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान और विधायक अमन अरोड़ा भी उनके साथ धरने पर बैठ गए।

- बीस साल पुरानी खटारा स्कूल वैन बनी काल, आठ मासूमों को बचाया गया
- पहली व दूसरी कक्षा पढ़ते थे बच्चे मजिस्ट्रेट से जांच के दिए आदेश

पीड़ित परिवारों को साढ़े सात लाख

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हादसे की मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने पीड़ित परिवारों को साढ़े सात लाख रुपये प्रति परिवार देने की घोषणा की है। ट्रांसपोर्ट विभाग से प्रदेश के सभी स्कूल बसों की जांच करने व स्कूली बच्चों की सुरक्षा यकीनी बनाने के निर्देश दिए।

एसएसपी डॉ. संदीप गर्ग ने बताया कि स्कूल मालिक व प्रिंसिपल लखविंदर सिंह लक्की व वैन चालक दलवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला के आदेश के बाद स्कूल प्रबंधन पर धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) का मामला दर्ज कर लिया गया है।

सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थीं

मारुति वैन के पास से ट्रैक्टर पर जा रहे गुरमुख सिंह ने बताया कि जैसे ही उन्होंने वैन में आग लगी देखी तो तुरंत ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा, लेकिन वह समझ नहीं पाया। दोबारा कहने पर वैन रोकी। ड्राइवर व उसका सहायक गाड़ी से बाहर निकले। इतनी देर में आग लग गई और गाड़ी को आग ने घेर लिया। पांच-छह नौजवानों ने मिलकर साथ लगते खेत के गीली मिट्टी गाड़ी में डाली। गाड़ी की एक तरफ की खिड़की खुल गई, जिसमें बच्चों को बाहर निकाल लिया गया। धुआं अधिक होने के कारण पता नहीं चल पा रहा था कि गाड़ी में कितने बच्चे सवार हैं। केवल चीखें सुनाई दे रही थीं। जब तक आग पर काबू पाया, तब तक चार बच्चे जिंदा जल चुके थे। फायरब्रिगेड व पुलिस काफी देरी के बाद मौके पर पहुंचे।

ढाई लाख का इनामी गैंगस्टर राजू गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम

- दिल्ली समेत कई राज्यों के लिए बना हुआ था सिरदर्द
- थाईलैंड से आते ही एसटीएफ ने पालम एयरपोर्ट से दबोचा

उत्तर भारत के कई राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बने गैंगस्टर राजू बसौदी को स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) गुरुग्राम की टीम ने दिल्ली स्थित एयरपोर्ट से शनिवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। ढाई लाख का इनामी यह बदमाश लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, अनिल छिपी जैसे गैंगस्टरों के साथ मिलकर काम कर रहा था। उसके खिलाफ हत्या व हत्या के प्रयास जैसे 29 मामले दर्ज हैं। सोनीपत जिला अदालत ने उसे 10 दिन की रिमांड पर एसटीएफ को सौंप दिया है।

हरियाणा एसटीएफ के उप पुलिस महानिरीक्षक सतीश बालन ने भोंडसी स्थित मुख्यालय पर पत्रकारों को बताया कि राजू मूलरूप से सोनीपत के बसौदी गांव का रहने वाला है। वह वर्ष 2010 में अपराध की दुनिया में आया। उस पर सोनीपत, झज्जर, रोहतक, गुरुग्राम, दिल्ली के कई थानों में हत्या व लूटपाट और हत्या के प्रयास जैसे मामले दर्ज हैं। वह काफी दिनों से थाईलैंड में छिपा था। एसटीएफ को गुमराह करने के लिए राजू ने सोशल मीडिया के माध्यम से मनीमाजरा व मलोट (पंजाब) में दो हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। सतीश बालन ने बताया कि सोनीपत एसटीएफ ने राजू के खिलाफ रेड कॉर्नर जारी कर रखा था। शनिवार रात करीब बारह बजे वह दिल्ली एयरपोर्ट पर आया, तो इमीग्रेशन अधिकारियों ने पकड़ लिया। सूचना मिलने पर पहुंची एसटीएफ की टीम उसे गिरफ्तार कर सुबह तीन बजे गुरुग्राम ले आई और दिन में सोनीपत की अदालत में पेश किया। उसे कोर्ट ले जाने में एसटीएफ ने पूरी सावधानी बरती। चार गाड़ियों के बीच में रखकर उसे न्यायालय तक ले जाया गया था।

एसटीएफ प्रभारी ने बताया कि राजू बसौदी पर हत्या के 13, जानलेवा हमले के चार और लूट, डकैती व फिरौती के करीब 20 मामले दर्ज हैं। वर्ष 2017 में दिल्ली जेल से छूटने के बाद उसने एक ठेकेदार से रंगदारी मांगी थी। मना करने पर बसौदी ने उसे छह गोली मारी थीं, जिसमें वह जिंदा बच गया था। 2018 में राजू ने ठेकेदार को फिर फोन करके रंगदारी मांगी और कहा था कि छह गोली मारना मेरी चेतावनी थी, मैं 50 गोली मारता हूं। फिलहाल एसटीएफ ने उसको इसी मामले में गिरफ्तार किया है। राजू के पिता जिले सिंह ने बताया कि अप्रैल 2010 में जमीन विवाद में मारपीट हो गई, जिसमें गांव के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस मामले में राजू जेल चला गया। कुछ दिन पहले से उसकी संगत खराब होने लगी थी, लेकिन जेल जाने के बाद वह पूरी तरह अपराध की दुनिया में चला गया। जेल जाने के कुछ दिनों बाद ही परिवार का संपर्क उससे टूट गया और उन्होंने उसको कभी नहीं देखा। बाद में उन्होंने हाईकोर्ट में आवेदन देकर उससे नाता तोड़ते हुए अपनी संपत्ति से बेदखल भी कर दिया। उन्होंने बताया कि राजू की शादी कुरुक्षेत्र के लाडवा में तय हो गई थी, लेकिन एक माह पूर्व ही जेल जाने के कारण शादी नहीं हो पाई।

-सतीश देशवाल, जिला प्रभारी, एसटीएफ

डेंगू के प्रति जागरूकता रैली...

डेंगू जैसी बीमारी से बचाव के लिए कोलकाता में शनिवार को जागरुकता रैली निकाली गई। इसमें शामिल लोग मच्छरों के बड़े-बड़े आउटफिट पहनकर सड़कों पर निकलें। इसमें शामिल लोगों को कहना था कि इस आउटफिट की वजह से आम लोगों का ध्यान आकर्षित करने में काफी मदद मिली। प्रेट्र

बच्चों से चोरियां कराने वाले गैंग का पर्दाफाश तीन गिरफ्तार

ठाणे (महाराष्ट्र), प्रेट : शादी तथा अन्य आयोजनों में बच्चों से चोरियां कराने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में मीरा रोड से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। चोरी को अंजाम देने वाले दस वर्षीय एक बच्चे को भी हिरासत में लिया गया, जिसे कोर्ट के आदेश से भिवंडी रिमांड होम भेज दिया गया है।

पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि तीनों गिरफ्तार आरोपितों की पहचान मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सारंगपुर तहसील निवासी विक्रांत भनेरिया, चंदन सिंह राजपूत तथा आदित्य सिसोदिया के रूप में हुई है। नया नगर थाना के वरिष्ठ निरीक्षक कैलास बर्वे ने बताया कि ठाणे ग्रामीण जिला पुलिस ने गुरुवार को तीनों को गिरफ्तार किया। गैंग ने पहले भी कई चोरियां कराई थीं, लेकिन ताजा मामला 12 फरवरी को मीरा रोड स्थित एक मैरिज हॉल का है।

शिकायत के अनुसार, यह बच्चा दुल्हन के कमरे में घुस गया और वहां पड़े एक बैग से पर्स निकाल लिया। दुल्हन के एक रिश्तेदार ने यह देखकर जब बच्चे से पूछताछ की तो उसने बताया कि पर्स उसकी मां का है, लेकिन शक होने पर दुल्हन के रिश्तेदार ने बच्चे से उसकी मां के पास ले चलने को कहा, लेकिन बच्चे के ऐसा नहीं कर पाने पर उन्होंने बच्चे को हॉल के मैनेजर के हवाले कर दिया। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। दुल्हन के रिश्तेदार ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बर्वे ने बताया कि बच्चे से पूछताछ में यह बात सामने आई कि एक गैंग शादी के आयोजनों में चोरी कराने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करता है। चोरी के बाद बच्चों को पैसे दिए जाते हैं। बच्चे से मिली सूचना के आधार पर तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि देश के कई हिस्सों में इस प्रकार के गैंग सक्रिय हैं।

बदलती तस्वीर

कश्मीर घाटी में आबाद ट्यूलिप गार्डन में निकलने लगी फूलों की नई कोपलें, अब 55 प्रजातियों के साथ 13 लाख ट्यूलिप की सतरंगी बहार आने को तैयार

ट्यूलिप की सुगंध से महकेगा कश्मीर

जागरण संवाददाता, श्रीनगर

अनुच्छेद-370 के खत्म होने के बाद जम्मू-कश्मीर में बहार भी बदलने को तैयार है। जहां पहले बंदूक और बम धमाकों के बाद जलने की गंध उठती थी, वहां अब फूलों की खुशबू महकेगी। बस कुछ दिन और इंतजार करना होगा, फिर कश्मीर ट्यूलिप की खुशबू से सुगंधित हो उठेगा। विश्व प्रसिद्ध डल झील व जब्रवान पहाड़ी की तलहटी में आबाद एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों को बिलकुल नए और अनूठे अंदाज में दिखेगा। खास बात यह है कि इस बार गार्डन को हॉलैंड के कोकनहाफ गार्डन के तर्ज पर सजाया गया है। इसके अलावा चार नई प्रजातियां भी इसमें शामिल की गई हैं। मार्च के अंतिम सप्ताह में गार्डन पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा।

ट्यूलिप गार्डन में असिस्टेंट फ्लोरिकल्चर ऑफिसर, शेख अल्ताफ अहमद कहते हैं कि गार्डन की साफ सफाई शुरू हो गई है। बर्फ के नीचे दबी ट्यूलिप की कई प्रजातियों में प्रमुख परेड, गोल्डन परेड, एडिरम और लारगो शामिल की कोंपलें निकलने शुरू हो गई हैं। अगर मौसम और तापमान अनुकूल रहा तो अगले चंद दिनों में ट्यूलिप खिलना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि गार्डन को सजाने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस बार गार्डन में कई बदलाव किए गए हैं। कई नई चीजों को इसमें जोड़ा गया है। गार्डन के दूसरे टेरिस पर भी वाटर चैनल के क्षेत्र बढ़ाया गया है। शेख अल्ताफ अहमद ने कहा कि इस बार एम्स्टरडम और हॉलैंड के कूकुनहाफ गार्डन की तर्ज पर बाग के एक बड़े क्षेत्र पर लगे ट्यूलिप की क्यारियों को लहराती हुई आकृति दी गई है जो पर्यटकों को लुभाएंगी। इसके अलावा गार्डन में ट्यूलिप की चार नई प्रजातियों जिनमें पीले रंग की बिग स्माइल नामक प्रजाति भी शामिल है, की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व गार्डन में ट्यूलिप की 51 प्रजातियों के साढ़े बारह लाख ट्यूलिप के फूल अपनी बहार दिखाया करते थे, लेकिन अब 55 प्रजातियों के साथ 13 लाख ट्यूलिप की सतरंगी बहार का आनंद लेंगे। अहमद ने कहा कि इस वर्ष भी ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है और 25 फरवरी को इसको लेकर बैठक में फैसला लिया जाएगा। गार्डन मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में खोला जाएगा।

2007 में डल झील के किनारे बज्रवान की तलहटी पर आबाद 30 हैक्टेयर क्षेत्र में फैला एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन लोगों को समर्पित किया गया था। तब से लगातार डल झील और गुलमर्ग के साथ-साथ ट्यूलिप गार्डन यहां आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। ट्यूलिप की शार्ट लाइफ के कारण यह गार्डन संक्षिप्त समय यानी एक से डेढ़ माह के लिए ही खुला रहता है, लेकिन इतने समय में ही इस गार्डन के मनोहारी दृश्य का नजारा लेने पहुंचते हैं। बीते वर्ष डेढ़ महीने में करीब 1.80 लाख पर्यटक गार्डन देखने पहुंचे थे।

चुनाव बहिष्कार के अलावा क्या विकल्प : जीए मीर

राज्य ब्यूरो, जम्मू

जम्मू-कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष जीए मीर ने कहा कि कश्मीर में कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं करने दी जा रही हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव करवाने का औचित्य क्या है? जिस तरह का परिदृश्य है, उसमें चुनाव बहिष्कार के अलावा क्या विकल्प बचता है? अगर ऐसा करते हैं तो कहा जाएगा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का बहिष्कार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले गैर राजनीतिक आधार पर चुनाव करवाए गए और अब राजनीतिक आधार पर चुनाव करवाए जा रहे हैं। सरकार को या तो अधिसूचना में बदलाव करना चाहिए अन्यथा पहले करवाए चुनाव को अवैध घोषित कर देना चाहिए। जीए मीर जम्मू में पार्टी मुख्यालय में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की अगुआई करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

मीर ने आरोप लगाया कि भाजपा दवाब बनाने के लिए कश्मीर में मुख्यधारा की पार्टियों के नेताओं पर जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) लगा रही है। सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि देशभर में जो भी भाजपा की नीतियों के खिलाफ बोल रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जिन नेताओं पर पीएसए लगा रही है वो भाजपा के साथ काम कर चुके हैं। उमर अब्दुल्ला पूर्व एनडीए सरकार में मंत्री थे। महबूबा मुफ्ती के साथ भाजपा ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी। विपक्ष पर दवाब बनाने के लिए ही मुख्यधारा के विपक्षी नेताओं पर पीएसए लगाए जा रहे हैं। भाजपा को इससे कुछ हासिल नहीं होगा। जब उचित समय आएगा तो जम्मू-कश्मीर के लोग फैसला करेंगे।

स्याह तस्वीर के चमकने में है संदेह

जगदीप एस छोकर
संस्थापक, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स

राजनीतिक सुधार की दिशा में 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन चार पेज का यह फैसला इसलिए बहुत कारगर नहीं हैं, क्योंकि इसमें अधिकांश बातें पूर्व फैसलों की ही दोहराई गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को दिए अपने फैसले में 25 सितंबर 2018 के संवैधानिक बेंच के निर्णय का उल्लेख किया है। मूल रूप से 13 फरवरी का निर्णय 25 सितंबर के फैसले को ही दोहराता है। 13 फरवरी के निर्णय में केवल दो नये प्रावधान हैं। पहला तो यह कि राजनीतिक दलों को अपने चुनावी प्रत्याशियों की आपराधिक पृष्ठभूमि का विस्तृत ब्योरा अपनी वेबसाइट पर उनके चयन करने के 48 घंटे के अंदर अपलोड करना होगा। वेबसाइट पर डालने का प्रावधान तो 25 सितंबर के निर्णय में था ही, नई बात केवल 48 घंटे की है। इसी के साथ यह भी कहा गया है राजनीतिक दलों को इस सूचना को वेबसाइट पर डालने की पुष्टि निर्वाचन आयोग को 72 घंटे के भीतर भेजनी होगी। दूसरा नया प्रावधान है कि अगर कोई राजनीतिक दल किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को बतौर प्रत्याशी चयन करता है तो उस दल को ऐसे व्यक्ति के चयन की वजह का ब्योरा भी अपनी वेबसाइट पर डालना होगा।

इन दोनों नये प्रावधानों के कारगर ना होने के कारण बहुत सरल हैं। जहां तक प्रत्याशियों की आपराधिक पृष्ठभूमि को वेबसाइट पर डालने की और इसकी सूचना चुनाव आयोग को देने की बात है, तो प्रत्याशी को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि एक शपथपत्र द्वारा चुनावी नामांकन पत्र के साथ देने का प्रावधान तो 2003 से चला आ रहा है। इन शपथपत्रों में दी गई सूचना कई स्वैच्छिक संस्थाओं और समाचार पत्रों तथा टीवी द्वारा जनता तक पहुंचाई जाती है। जो सूचना जनता को 17 साल से मिल रही है, उसके राजनीतिक दलों के अपनी वेबसाइट पर डालने से क्या बदल जाएगा, यह समझ में नहीं आता। शपथपत्र चुनाव आयोग को ही दिए जाते हैं, इसलिए चुनाव आयोग को 72 घंटे के भीतर वेबसाइट पर लगाने की सूचना देना भी एक अनावश्यक कार्यवाही लगती है।

जहां तक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को प्रत्याशी चयन करने की वजहों को वेबसाइट पर लगाने का सवाल है, इससे दो बातें उभर कर आती हैं। पहली तो यह कि राजनीतिक दलों को कुछ भी मनघडंत कारणों के सोचने और उनको वेबसाइट पर डालने में कोई कठिनाई आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरी बात यह कि किसी भी दल द्वारा दिए गए कारण सही, विश्वासनीय और मानने योग्य हैं या नहीं, यह निर्णय करने की जिम्मेदारी किसकी है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कुछ नहीं कहता। होगा यह कि राजनीतिक दल अपने मनमुताबिक प्रत्याशी चयन करेंगे और कोई भी वजह वेबसाइट पर डाल देंगे।

असली बात तो यह है कि राजनीतिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट फूंक-फूंककर पांव रखने का प्रयत्न करता है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पिछले लगभग 20 वर्षों से ये सबको पता है कि कोई भी राजनीतिक दल चुनाव प्रणाली में कुछ भी सुधार या बदलाव नहीं चाहता, और अगर कुछ करने का प्रयत्न किया भी जाता है तो सब के सब दल एकजुट हो कर उसका विरोध करते हैं। इसका केवल एक ही इलाज है कि सुप्रीम कोर्ट अपने उस अधिकार का प्रयोग करे जिसके अंतर्गत (1) किसी कानून में अगर कोई कमी है, (2) संसद उस कमी को दूर नहीं करता या नहीं करना चाहता, और (3) कानून की उस कमी से जनहित को नुकसान हो रहा है; ऐसी स्थिति में संसद को ना केवल अधिकार है बल्कि उसका कर्तव्य भी है कि वे कानून की कमी को ठीक करे, जब तक उसका संज्ञान लेकर संसद उस पर कुछ कार्यवाही ना करे। सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिये कि जिन व्यक्तियों के विरुद्ध गंभीर अपराधों के मामले चल रहे हों, और जिनमें अदालत ने 'चार्जेज फ्रेम' कर दिए हों अर्थात उनको अदालत ने गंभीर अपराध के रूप में मान लिया हो, ऐसे लोगों को चुनाव में प्रत्याशी बनने के अयोग्य घोषित कर दिया जाय। क्या न्यायपालिका बिल्ली के गले में घंटी बांधने का सहस करेगी? इस प्रश्न का उत्तर तो न्यायपालिका को ही तय करना होगा।

राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर हमारे-आपके सब्र का बांध भले न टूटे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का धैर्य जवाब दे गया है। हाल ही में उसने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया कि विधानसभाओं और लोकसभा चुनावों में हर उम्मीदवार के आपराधिक इतिहास का विवरण सार्वजनिक करें। साथ ही चयन के 48 घंटों के अंदर वे बताएं कि किसी साफ-सुथरी छवि वाले उम्मीदवार की जगह उन्होंने दागी का वरण क्यों किया। शीर्ष अदालत का गुस्सा गैरजायज नहीं है। हाल ही दिल्ली विधानसभा में चुनकर आए 70 नए विधायकों में 37 (53 फीसद) पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एक हलफनामा पेश करके बताया कि देश भर में कुल 1765 सांसद या विधायक हैं जिनके ऊपर विभिन्न अदालतों में 3045 आपराधिक मामले दर्ज हैं। करीब हर माननीय पर दो मामले का औसत गिरता है। दरअसल राजनीति को 'हींग लगे न फिटकरी, रंग आए चोखा' समझने वाले लोग राजनीति में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। बिना निवेश और न्यूनतम जोखिम के ज्यादा रिटर्न देने वाले पेशे के तौर पर समझ रखने वाले ये तथाकथित माननीय जनता का भला कैसे कर सकते हैं।

इनके मुकदमों के त्वरित निपटान की बहस के बीच जरूरी यह है कि ऐसे लोगों को राजनीति में आने से ही रोका जाए। जिताऊ उम्मीदवार के लालच में इन्हें टिकट मिल जाता है, और मतदाता अपनी प्रिय पार्टी के नाम पर आंखें मूंद लेता है। वहीं मतदाता बाद में नाक-भौं सिकोड़ते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनके कल्याण के लिए आए धन को सांसद-विधायक महोदय गड़प कर गए। ऐसे हालात से बचने के लिए और देश में साफ-सुथरी राजनीति को बढ़ावा देने के लिए कानून-कायदों के साथ मतदाता बहुत बड़ा हथियार है। उसे चेतना ही होगा।

दागी अच्छे नहीं!

बिना निवेश झमाझम रिटर्न

जर्मनी के समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने अपने विश्लेषण 'राजनीति एक पेशा' में कहा था कि, 'राजनीति में आने की दो वजहें हैं : या तो लोग राजनीति के लिए जीते है, या फिर राजनीति पर जीते हैं। सवाल उठता है कि ऐसे क्या फायदे हैं जिनकी वजह से अपराध में डूबे लोग राजनीति में छलांग लगाते हैं। अपनी किताब व्हेन क्राइम पेज : मनी एंड मसल इन इंडियन पॉलिटिक्स में मिलन वैष्णव ने इन सवालों के जवाब दिए हैं। राजनीति आज ऐसा पेशा बनती जा रही है जिसमें लोगों को निवेश की जरूरत नहीं पड़ती और रिटर्न कई गुना ज्यादा हासिल होता है।

राजनीति और अपराध

आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसद और विधायक को मतदाता सम्मानित क्यों करते हैं? सीधा सा जवाब यह है कि ऐसे लोगों को पार्टी जिताऊ मानती है। राजनीतिक पार्टियां आपराधिक उम्मीदवारों को मतदाताओं के सामने आने का मंच देती हैं। यह एक ऐसा बाजार है जहां जिसका जितना अच्छा नेटवर्क होता है उसे उतना फायदा मिलता है। पार्टियां और आपराधिक राजनेताओं के बीच मांग और आपूर्ति का समीकरण काम करता है।

मतदाताओं की बारी

मतदाता क्यों ऐसे अपराधी उम्मीदवारों को अस्वीकार नहीं करते? दरअसल जहां कानून बेहद लचर हो और विखंडित समाज हो, वहां एक उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि अहम पूंजी मानी जाती है। ऐसे उम्मीदवार मतदाताओं का पुनर्वितरण, दादागिरी, सामाजिक बीमा और झगड़ों का निपटारा करके खुद की साख बनाते हैं। यह चारों माध्यम राज्य के विशेषाधिकार हैं और किसी अपराधी उम्मीदवार के ये गुण उसे विश्वसनीय बनाते हैं।

एक दूसरे के हित साधने वाली सोच ने दिया प्रवृत्ति को बढ़ावा

1980 में तीन चीजें समानांतर रूप से चल रही थीं- राजनीति का विखंडन, गहराती प्रतिस्पर्धा और कांग्रेस का खत्म होता वर्चस्व। इनके चलते भारतीय राजनीति में खालीपन आया। अनिश्चितता के इस दौर में चुनावी प्रतिद्वंद्वता कई गुना बढ़ गई। पार्टियों द्वारा काम पर रखे गए अपराधियों के मन में खुद सत्ता पर काबिज होने की इच्छा जगी। महंगे होते चुनाव के बीच अपराधियों द्वारा गलत तरीकों से कमाए गए अकूत धन के चलते पार्टियां उन्हें ऐसे उम्मीदवार के तौर पर पेश करती हैं जो चुनाव का खर्चा खुद वहन कर सकता है और पार्टी को कई तरीकों से आर्थिक मदद दे सकता है।

फूट डालो राज करो

आपराधिक छवि के लोग अपने फायदे के लिए समाज में मौजूद बंटवारे को और बढ़ाते हैं। वे रक्षात्मक अपराधीकरण के जरिए अपनी जाति या समुदाय के भाई-बंधुओं के मान-सम्मान की रक्षा करने का वादा करते हैं। उन्हें यह मर्म पता है कि रोजाना के इन मुद्दों का दीर्घकालिक उपाय कर देने से लोगों को उनकी जरूरत नहीं रहेगी। अगर सरकारें लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर देंगी तो आपराधिक उम्मीदवार अपनी चमक खो देंगे। यह सारे बिंदु मतदाताओं को प्रभावित करते हैं, जिससे वे अपराधियों को चुनना पसंद करते हैं। इसे यह साफ हो जाता है कि अज्ञानी मतदाता जैसा कुछ नहीं होता। मतदाता ऐसे उम्मीदवारों को उनके आपराधिक रिकॉर्ड की वजह से ही चुनते हैं।

बढ़ता मर्ज

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) और इलेक्शन वॉच द्वारा 2013 में पिछले दस साल यानी 2004 लोकसभा चुनाव के बाद हुए सभी चुनावों का अध्ययन किया। इसमें 62,847 उम्मीदवारों के शपथपत्रों के विश्लेषण से राजनीति में घुन की तरह लगते अपराधीकरण का स्याह चेहरा दिखाई पड़ा।

18% (11030)
उम्मीदवार जिनके खिलाफ 27,027 लंबित आपराधिक मामले

8% (5253)
उम्मीदवारों के खिलाफ दुष्कर्म, हत्या, भ्रष्टाचार, उगाही और डकैती जैसे 13984 गंभीर आपराधिक मामले

कितने गंभीर मामले

8.3%
उम्मीदवार जिनके ऊपर एक से अधिक गंभीर मामले

4.3% (2700)
दो या अधिक गंभीर मामलों वाले उम्मीदवार

152
दस या उससे अधिक गंभीर मामलों में लिप्त उम्मीदवार

14-40
या उससे अधिक गंभीर मामलों से जुड़े उम्मीदवार

5- 50
से अधिक गंभीर मामलों वाले उम्मीदवार

विजेता उम्मीदवारों पर नजर

2004 से 2013 के दौरान कुल 8882 विजेता उम्मीदवारों के शपथपत्रों का विश्लेषण हुआ।

28.4% (2497)
विजेतों पर 9993 लंबित मामले

13.5% (1187)
विजयी उम्मीदवारों पर 4824 गंभीर आपराधिक मामले

जीतने की संभावना

12%
साफ छवि वाले उम्मीदवारों के जीतने की औसत दर

23%
आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की जीतने की दर

23%
गंभीर अपराधों से जुड़े उम्मीदवारों के जीतने की दर

अपराध और धन का घालमेल

₹2.47
दूसरे स्थान पर आए उम्मीदवार की औसत संपत्ति

₹2.03
तीसरे स्थान पर आए उम्मीदवार की औसत संपत्ति

₹3.8
विजेता उम्मीदवार की औसत संपत्ति

₹4.27
आपराधिक छवि वाले विजेता की औसत संपत्ति

(करोड़ में)

₹4.4
गंभीर किस्म के आपराधिक छवि के विजेता की औसत संपत्ति

पार्टियों के लिए नियामक संस्था की दरकार

प्रो गुरु प्रकाश
विजिटिंग फेलो, इंडिया फाउंडेशन

देश के राजनीतिक दलों के अंदर पारदर्शिता, आंतरिक लोकतंत्र और स्वच्छ छवि आधारित नेतृत्व विकसित करने की जरूरत है। एक सूचकांक भी बने जो विभिन्न मापदंडों पर इन पार्टियों के कार्य-व्यवहार का निष्पक्ष मूल्यांकन करे।

स्वतंत्रता आंदोलन के समय की बात है। जवाहरलाल नेहरू ने एक सभा के दौरान कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली शासन की दूसरी सबसे बेहतर व्यवस्था है। इस पर वहां मौजूद लोगों ने उनसे पूछा कि सबसे बेहतर व्यवस्था क्या है फिर। इस पर नेहरू का जवाब था कि उसका पता अभी तक नहीं लगाया गया है लेकिन भविष्य में लोकतांत्रिक प्रणाली से भी बेहतर शासन प्रणाली हो सकती है इसकी संभावना सदैव बरकरार है।

एक समय था, जब राजनीति में विद्वान, विचारक और चिंतकों का दबदबा हुआ करता था। इस फेहरिस्त में वो नेता थे जो जनप्रिय होने के साथ समय-समय पर अपने बुद्धिजीवी होने का भी परिचय दिया करते थे। आंबेडकर, लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख के विचारों से हमारा पूरा समाज सिर्फ परिचित ही नहीं बल्कि प्रभावित भी है। वर्तमान में ऐसे नेताओं को शायद जीपीएस नेविगेशन प्रणाली भी नहीं ढूंढ़ पाए। देश के सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को राजनीति में अपराधियों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई और अनुच्छेद 129 और 142 का उपयोग कर राजनीतिक पार्टियों को दिशा निर्देश जारी किया है। राजनीति में धनबल, बाहुबल, परिवार, कारोबार और शृंगार हावी हो गया है। राजनीति कभी भी इस देश में अर्थार्जन की स्रोत नहीं रही। राजनीति में सादगी और वैचारिक पृष्ठभूमि से मजबूत लोगों की सख्त आवश्यकता महसूस हो रही है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की मानें तो पिछले डेढ़ दशक में संसद में दागियों की संख्या में पुरजोर वृद्धि हुई है। 2004 में जो आंकड़े 24 प्रतिशत के थे वह 2019 में बढ़कर 43 प्रतिशत के आसपास पहुंच चुके हैं। प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि इस दयनीय स्थिति के लिए सिर्फ राजनीतिक दल दोषी है या फिर हमें समाज के रूप में भी एक सामूहिक आत्ममंथन की दरकार है।

मैं आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से राजनीतिक दल कुछ सीख लेने का प्रयास करेंगे। आपस में आत्ममंथन करके कुछ मापदंड तय करेंगे। राजनीतिक दलों को अपने सामूहिक काल्पनिक क्षमता और वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं का अध्ययन कर के एक समावेशी राय बनानी होगी। क्या राजनीतिक दलों के लिए एक नियामक संस्था बनाने की आवश्यकता है? इस प्रश्न का उत्तर इन दलों के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को साथ मिलकर लेना चाहिए। क्या इन दलों के सांगठनिक व्यवस्था में पर्याप्त रूप में सामाजिक, लैंगिक, क्षेत्रीय और धार्मिक विविधता है?

भारतीय जनता पार्टी और वामदलों को छोड़ दें तो बाकी दल विचार आधारित ना होकर जाति आधारित या परिवार आधारित हैं। वंशवाद को चुनौती देना भी आज की जरूरत है। तमाम राजनीतिक दलों का उदाहरण हमारे सामने है। बात जमात से शुरू हुई, जाति पर आई और अंततोगत्वा परिवार पर रुक गई। कई दलों को चलाने वाले परिवार के अधिकतर सदस्य संसद पहुंचे हैं। प्रमुख पदों पर भी इनके परिवार की ही मौजूदगी होती है। सदन और संगठन में एक ही परिवार की भूमिका चिंता का विषय है। इस निर्णय का हम सभ्य समाज को स्वागत करना चाहिए। ये सुनिश्चित भी करना चाहिए कि पार्टियों के अंदर पारदर्शिता, आंतरिक लोकतंत्र और स्वच्छ छवि आधारित नेतृत्व कैसे विकसित हो। एक सूचकांक भी डेवलप करना चाहिए जो विभिन्न मापदंडों के आधार पर राजनीतिक दलों का निष्पक्ष मूल्यांकन करे। इसका स्वरूप सामाजिक हो या सरकारी, इसकी चर्चा की जा सकती है। इसी आशा और सकारात्मकता के साथ भविष्य की स्वच्छ राजनीति की तरफ एक मजबूत कदम हम बढ़ा सकते है। सुप्रीम कोर्ट बधाई का पात्र है।

जनमत

क्या राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के लिए सिर्फ हमारे राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं?

10% नहीं
90% हां

क्या मतदाताओं की सजगता से दागियों का राजनीति में प्रवेश रोका जा सकता है?

02% नहीं
98% हां

आपकी आवाज

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में अगर अपराधी प्रवेश करेंगे तो लोकतंत्र कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता। **विजय कुमार धनिया**

राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के लिए सिर्फ राजनीतिक दल ही जिम्मेदार हैं। अगर ऐसा ना होता तो सभी राजनीतिक दल इसके विरुद्ध कोई ना कोई कानून संसद या विधानसभा से पारित करा लेते। **प्रिंस यादव**

यदि देश के मतदाता दागी प्रत्याशियों को अपना बहूमूल्य मत किसी भी कीमत पर नहीं दें, तो ही पार्टियां भी किसी दागी को अपना प्रत्याशी बनाने से पहले हजार बार विचार करेंगी। **मुन्ना स्वर्णकार**

बड़ी त्रासदी

अपराध का मकड़जाल पूरे देश को जकड़ने लगा है। क्या संसद क्या विधानसभाएं, सब इससे प्रभावित हैं। यह बात और है कि देश के अलग अलग हिस्सों में राजनीति के अपराधीकरण की प्रक्रिया असमान है। कुछ हिस्सों में यह बहुत सघन है तो कुछ हिस्सों में अभी उम्मीद की किरण बाकी है। एडीआर ने 2019 के लिए संसद और विधानसभाओं में दागियों के प्रतिनिधित्व का एक विश्लेषण किया। एक नजर :

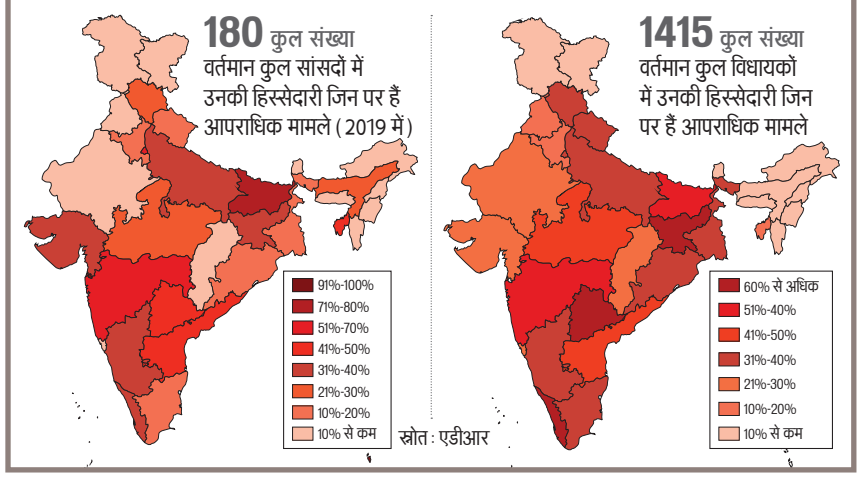

स्रोत : एडीआर

लोकलुभावन वायदों से किया जाए परहेज

देवेंद्र पई
कोर्स डायरेक्टर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश तब तक महत्वहीन होगा जब तक कि आम मतदाता लोकलुभावन नीतियों से परहेज नहीं करेगा, प्रत्याशी का मेरिट के अनुसार चयन नहीं करेगा। राष्ट्र निर्माण और स्वच्छ राजनीति के लिए उसे जगना होगा।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय चुनावी राजनीति में पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने का सुविचारित कदम है। राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के इस दौर में इसका स्वागत किया जाना चाहिए। हाल ही में दिल्ली विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों में से 50 फीसद से अधिक के खिलाफ गंभीर आपराधिक आरोप हैं, जो कि हमारे सामने यह सवाल खड़ा करता है कि क्या ऐसे निर्णयों का मतदाताओं पर प्रभाव पड़ता है।

दिल्ली चुनाव का मामला बहुत दिलचस्प है। देश की राजधानी होने के नाते हर किसी को उम्मीद है कि मतदाता और प्रतिनिधि दोनों ही बेहतर शिक्षित होंगे और देश के बाकी हिस्सों के लिए नजीर बनेंगे। यह तथ्य कि दिल्ली ने 50 फीसद विधायक दागी पृष्ठभूमि वाले चुने हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी दाखिल करते समय अपने धन और आपराधिक मामलों की घोषणा करते हैं और हर मतदान केंद्र के बाहर भारत के चुनाव आयुक्त द्वारा इस सूचना को प्रकाशित किया जाता है।

दिल्ली के चुनावों से यह भी पता चला है कि मतदाता अपने लिए या सरकार से परिवार के लिए जो कुछ मिला है, उससे अधिक चिंतित है। इसलिए अगर कोई पार्टी मुफ्त बिजली और पानी से सत्ता के गलियारों तक पहुंची है तो उम्मीदवारों पर शायद ही बात हो। उम्मीदवारों के चयन के कारणों में आसानी से हेरफेर किया जा सकता है। यह सोचना मूर्खतापूर्ण है कि राजनीतिक दल उम्मीदवारों को टिकट देने से पहले उनकी प्रोफाइल की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में दिन के अंत में सबसे अधिक वोट पाने की संभावना वाले उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा और राजनीतिक दल आत्मसमर्पण कर देते हैं।

नागरिकों को याद रखना चाहिए कि आखिर में वे लोकतंत्र में सबसे शक्तिशाली हैं। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से आम आदमी पार्टी का गठन चुनावी सफलता का एक और बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उसी के दम पर लोकतंत्र में आम आदमी की ताकत का अहसास कराया। जनता ने आप को कांग्रेस सरकार के स्वच्छ विकल्प के रूप में चुना। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश तब तक महत्वहीन होगा जब तक कि आम मतदाता लोकलुभावन नीतियों से परहेज नहीं करेगा। मतदाताओं को उम्मीदवार की प्रोफाइल और पार्टी के घोषणापत्र को पढ़ने के बाद मतदान करने की प्रवृत्ति विकसित करनी होगी। राजनीतिक दल महसूस करने लगेंगे कि लोगों ने अपराधियों को अस्वीकार कर दिया है और अब वे योग्यता के आधार पर वोट देने लगे हैं। मुफ्त की चीजों और निजी, परिवार या जाति से ऊपर उठ देश के निर्माण में निर्णय लेने लगे हैं, तभी हमारे लोकतंत्र में पारदर्शिता और मजबूती सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे।

दैनिक जागरण

प्रेम पवित्रता और सादगी के साथ ही प्राप्त हो सकता है

दूरसंचार क्षेत्र का संकट

एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी समायोजित सकल राजस्व की देनदारी के मामले में दो प्रमुख दूरसंचार कंपनियां जिस संकट से दो-चार हैं उसके लिए वे खुद भी जिम्मेदार हैं। दूरसंचार कंपनियां सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई खामी इसलिए नहीं निकाल सकतीं, क्योंकि उसने तो वही फैसला दिया जो विधि सम्मत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस संकट से निजी दूरसंचार कंपनियां ग्रस्त हैं उससे ही सरकारी क्षेत्र की भी कंपनियां ग्रस्त हैं। इनमें से कुछ गैर-दूरसंचार क्षेत्र की भी कंपनियां हैं। दूरसंचार कंपनियों के संकट के लिए एक हद तक नियामक संस्था और सरकारी नौकरशाही भी जिम्मेदार है। क्या यह बेहतर नहीं होता कि दूरसंचार विभाग और दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई समय रहते हस्तक्षेप करते और इस विवाद को सुलझाते कि राजस्व आकलन का उचित तरीका क्या होना चाहिए? यह आश्चर्यजनक है कि एक दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी दोनों में से किसी ने भी यह नहीं समझा कि कंपनियों के राजस्व आकलन के तौर-तरीकों को तर्कसंगत बनाने की जरूरत है। यह मामला कहीं न कहीं यही बताता है कि यदि समय पर चेतने और उपयुक्त कदम उठाने से इन्कार किया जाता है तो गंभीर संकट से ही दो-चार होना पड़ता है।

यह कम अजीब नहीं कि राजस्व आकलन का सवाल अनसुलझा होने के बाद भी दूरसंचार कंपनियां आपसी प्रतिस्पर्द्धा में बुरी तरह उलझीं। ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता बनाने की उनकी होड़ में ऐसी स्थिति तो बनी कि भारत में मोबाइल सेवाएं दुनिया भर से सस्ती हो गईं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उनकी गुणवत्ता का स्तर संतोषजनक नहीं हो सका। प्रतिस्पर्द्धा की ऐसी होड़ का कोई मतलब नहीं कि कंपनियां सेवाओं की गुणवत्ता के साथ ही अपने आर्थिक भविष्य की भी अनदेखी कर दें। फिलहाल यह कहना कठिन है कि सुप्रीम कोर्ट के बकाया राजस्व चुकाने के फैसले के बाद भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया अपनी देनदारी किस तरह चुकाती हैं। चूंकि वोडाफोन-आइडिया पहले से ही गहरे संकट में है इसलिए उसके बंद होने की भी नौबत आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो उसे कर्ज देने वाले बैंक भी संकट में आ सकते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि देश के दूरसंचार क्षेत्र में दो ही कंपनियां रह जाएं। इस स्थिति में प्रतिस्पर्द्धा का अभाव देखने को मिल सकता है। जो भी हो, एक ऐसे समय जब दुनिया 5-जी सेवाओं की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही हैं तब अपने देश में दूरसंचार क्षेत्र का संकट से घिरना कोई शुभ संकेत नहीं। बेहतर हो कि सरकार और नियामक संस्था के साथ ही दूरसंचार कंपनियां जरूरी सबक सीखने में और देरी न करें।

रोजगारपरक पहल

उत्तराखंड की 25 आइटीआइ संवरने जा रही हैं। विश्व बैंक की मदद से पांचवर्षीय उत्तराखंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट परियोजना के तहत इन आइटीआइ को आधुनिक बनाया जा रहा है। इन्हें स्मार्ट क्लास रूम के साथ ही आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि इनमें कुछ आइटीआइ को ट्रेड विशेष में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर विकसित किया जाएगा। ऐसा हुआ तो इन आइटीआइ से प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार की राह आसान होगी। प्रदेश सरकार पहले ही केंद्र के स्किल इंडिया मिशन का पूरा लाभ लेने की कोशिश कर रही है। छात्र-छात्राओं और युवाओं में कौशल विकास को लेकर नीति निर्धारित की जा चुकी है। इस कड़ी में आइटीआइ को सशक्त बनाने की मुहिम कारगर साबित हो सकती है। प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए 450 से अधिक आइटीआइ अनुदेशकों को भी प्रशिक्षित किया जा चुका है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाई जा रही सात आइटीआइ में औद्योगिक इकाइयों की सहायता से शोध एवं विकास कार्य कराने का कदम सार्थक है। इसे सधे तरीके से आगे बढ़ाया गया तो आशातीत परिणाम सामने आ सकते हैं। राज्य सरकार के पास संसाधन सीमित हैं। यही वजह है कि बाह्य सहायतित परियोजना के तहत केंद्र सरकार से भी राज्य को प्रोत्साहन मिल रहा है। आइटीआइ को मिलने वाली मदद ऐसी ही कोशिशों का नतीजा है। 25 आइटीआइ को संसाधनों से सरसब्ज कर बदलाव का आधार तैयार हुआ तो इसी तर्ज पर अन्य आइटीआइ को भी बदहाली से उबारा जा सकेगा। राज्य में आइटीआइ बेतहाशा खोले तो गए, लेकिन बहुत कम संख्या में आइटीआइ ठीक-ठाक हालत में हैं। बीते दिनों सरकार ने नजदीकी क्षेत्रों में चल रही कई आइटीआइ के विलय का सही फैसला लिया। रोजगारपरक प्रशिक्षण के लिहाज से इन अहम संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बेहद जरूरी है। इस मामले में हालिया फैसले उम्मीद जगाने वाले हैं। बेहतर होगा कि सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक कक्षाओं के लिए प्रस्तावित व्यावसायिक शिक्षा योजना को भी जल्द मूर्त रूप दिया जाए। आश्चर्यजनक ये है कि यह अहम योजना वर्षों से सिर्फ प्रस्ताव के रूप में फाइलों में दबी हुई है। अब इस मोर्चे पर ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए।

दिल्ली के जनादेश का संदेश

संजय गुप्त

दिल्ली में कांग्रेस को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन भाजपा सत्ता में आने के लिए कमर कसे थी। बावजूद इसके उसके विधायकों की संख्या दहाई तक भी नहीं पहुंच सकी

दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जोरदार जीत ने जहां यह साबित किया कि अरविंद केजरीवाल जनता की नब्ज कहीं अच्छे से पहचानने में समर्थ रहे वहीं यह भी कि उनके मुकाबले दोनों राष्ट्रीय दल भाजपा और कांग्रेस कुछ नहीं कर सके। जिस दिल्ली पर कांग्रेस ने 15 साल शासन किया वहां वह लगातार दूसरी बार अपना खाता भी नहीं खोल सकी। नतीजे यही बताते हैं कि दिल्ली के लोगों का कांग्रेस से मोहभंग हो गया है और वे बेहतर विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे है। निःसंदेह आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को पानी, बिजली के साथ महिलाओं को बस यात्रा की सुविधा मुफ्त देकर उसे अपनी ओर आकर्षित किया, लेकिन यह कहना ठीक नहीं होगा कि वह केवल इसी के बलबूते चुनाव जीती। करीब आठ महीने पहले दिल्ली की सभी सात लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। शायद इसी हार के बाद आम आदमी पार्टी अपनी कमियों को दूर करने में जुटी और अपनी पूरी मशीनरी के साथ बूथ स्तर तक सक्रिय हुई। ऐसी सक्रियता न तो भाजपा दिखा सकी और न ही कांग्रेस।

कांग्रेस दिल्ली में ऐसा कोई मुद्दा नहीं उभार सकी जो जनता का ध्यान खींच सकता। रही-सही कसर कांग्रेस नेताओं के अनमने ढंग से किए गए चुनाव प्रचार ने पूरी कर दी। राहुल और प्रियंका चुनाव प्रचार करने तब उतरे जब वह खत्म होने वाला था। लगता है वे चुनाव प्रचार के नाम पर केवल खानापूरी करना चाह रहे थे और उनका असली इरादा भाजपा की हार सुनिश्चित करना था। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन वह चुनाव प्रचार को गति नहीं दे सके। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत तो गिरा ही, उसके 60 से अधिक उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई। इस शर्मनाक पराजय के बाद कांग्रेस में कलह मची है, लेकिन यह कहना कठिन है कि पार्टी की रीति-नीति में कोई व्यापक बदलाव होगा। इसका संकेत इससे मिलता है कि कांग्रेस के कुछ नेता हार का ठीकरा उन शीला दीक्षित पर फोड़ रहे हैं जिन्होंने दिल्ली को संवारा। कांग्रेसी नेता बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन गांधी परिवार पर अपनी निर्भरता छोड़ने को तैयार नहीं। गांधी परिवार पर निर्भर कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं दिखता, सिवाय प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के साथ भाजपा और संघ पर कीचड़ उछालने के। लगता है गांधी परिवार और खासकर राहुल गांधी यह स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि सत्ता उनसे दूर चली गई है। उनका व्यवहार उस राजकुमार जैसा है जिसका राजपाट छिन गया हो।

अवधेश राजपूत

दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन भाजपा सत्ता में आने के लिए कमर कसे हुए थी। बावजूद इसके वह सत्ता से तो दूर रही ही, उसके विधायकों की संख्या दहाई तक भी नहीं पहुंच सकी। दिल्ली में हार के पहले महाराष्ट्र और झारखंड उसके हाथ से निकल चुके हैं और हरियाणा में उसे सरकार बनाने के लिए दुष्यंत चौटाला का सहारा लेना पड़ा। दिल्ली में भाजपा के कमजोर प्रदर्शन के कई कारण दिखते हैं और उनमें से कुछ का उल्लेख गृहमंत्री अमित शाह ने किया भी। उनके अनुसार कुछ नेताओं और खासकर अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा के उत्तेजक बयान पार्टी पर भारी पड़े। भाजपा ने शाहीन बाग धरने को भी मुद्दा बनाया, लेकिन वह भी कारगर नहीं रहा। दिल्ली की जनता ने इसे न तो चुनावी मुद्दे के रूप में लिया और न ही हिंदू-मुस्लिम मसले के तौर पर। निःसंदेह इसका यह मतलब भी नहीं निकाला जा सकता कि दिल्ली की जनता नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ है।

दिल्ली में भाजपा की एक कमजोरी यह भी रही कि वह अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर पेश नहीं कर सकी। यह अजीब है कि वह पांच साल में एक ऐसा नेता तैयार नहीं कर सकी जो केजरीवाल को चुनौती देने में सक्षम दिखता। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी पार्टी के अन्य सभी नेताओं को अपने पीछे एकजुट नहीं कर सके। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि दिल्ली भाजपा के नेता गुटबाजी का शिकार थे और मुख्यमंत्री के लिए किसी चेहरे का चयन न किए जाने के बाद भी यह गुटबाजी दूर नहीं हो सकी। भाजपा को यह भी समझ आना चाहिए कि राज्यों के चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर नहीं लड़े जा सकते और विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय मसले एक सीमा तक ही कारगर होते हैं। दिल्ली नौकरी-पेशा वालों का शहर है। बड़ी संख्या में व्यापारी वर्ग भाजपा का परंपरागत मतदाता है, लेकिन शायद वह थमी हुई अर्थव्यवस्था के चलते परेशान है और उसकी यह परेशानी भाजपा पर भारी पड़ी।

दिल्ली के चुनाव नतीजों के बाद भाजपा पर आगामी विधानसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव बढ़ गया है। इस वर्ष के आखिर में बिहार और अगले वर्ष बंगाल विधानसभा के चुनाव होने हैं। अभी दोनों चुनावों में समय है, लेकिन भाजपा को अपनी कमजोरियों को दूर करने पर तो ध्यान देना ही होगा। इसके साथ ही उसे इसकी भी चिंता करनी होगी कि तब तक अर्थव्यवस्था की हालत सुधर जाए। निःसंदेह विधानसभा चुनावों में आम जनता प्रधानमंत्री मोदी की कर्मठ और साहसिक फैसले लेने में सक्षम नेता वाली छवि पर मोहित होती है, लेकिन वह यह भी जानती है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो कोई और ही बैठेगा। दिल्ली में भाजपा का वनवास पांच साल के लिए और बढ़ गया है। उसे दिल्ली के अपने नेताओं की गुटबाजी पर लगाम लगाने के साथ ही इस पर भी ध्यान देना होगा कि उसके अधीन काम करने वाले नगर निगम अपने कामकाज में सुधार करें।

देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली की शासन व्यवस्था अन्य राज्यों से भिन्न है। कई बार यहां की जनता को यह पता नहीं चलता कि उसकी किस समस्या का समाधान किसे करना है-दिल्ली सरकार को या फिर केंद्र सरकार को? इसका कोई औचित्य नहीं कि दोनों के बीच तालमेल के अभाव में दिल्ली की समस्याओं का समाधान न हो। यदि आम आदमी पार्टी सरकार अपने कामकाज को और बेहतर करना चाहती है तो फिर उसकी कोशिश यह होनी चाहिए कि दिल्ली के नगर निगम उसके अधीन आएं।

response@jagran.com

मुफ्त का चंदन घिसने वाले नंदन

हास्य-व्यंग्य

हम ठहरे जनम-जनम के धुरंधर फोकटलाल। रस्ते का माल सस्ते में मिल रहा हो, तो एक के बदले दस उठा लाते हैं। हमारी इस नैसर्गिक प्रवृत्ति को बाजार भी बखूबी समझता है। वह सस्ते माल को पहले महंगा बताता है, फिर उस पर डिस्काउंट का आकर्षक ऑफर देता है। इसीलिए हम जहां कहीं पर भी 'सेल' लिखा हुआ पाते हैं, हमारे कदम अनायास ही उस तरफ बढ़ जाया करते हैं। हमें 'बाइ वन-गेट वन फ्री' का सम्मोहन अपनी ओर जिस तीव्रता से खींचता है, उसके सम्मुख विराट चुंबकीय शक्ति भी मात खा जाती है। हमें देखते ही दुकानदार कहता है, 'यह वाला पैकेट ले लो बाबूजी! एक पर एक फ्री का ऑफर चल रहा है।' हमें जरूरत एक पैकेट की होती है, लेकिन हम चार पैकेट खरीद लेते हैं। इस तरह बाजार हमें चूना लगा रहा होता है, लेकिन हम तो ठहरे जन्मजात डिस्काउंटखाऊ! हमें मुफ्त का चूना भी लग रहा हो, तो सहर्ष लगवा लेते हैं। इससे हमें आत्मिक संतोष की सहज प्राप्ति होती है। चूना ही सही, फ्री में कुछ तो लग रहा है।

हम जैसे फोकटलाल, सब्जी वाले से आधा किलो आलू भी खरीदते हैं तो फ्री का थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च अवश्य ले लिया करते हैं। वह तो सब्जी बेचने वाले चतुर होते हैं जो हमारी इस आदत को पहचानते हैं और घटतौली करके अपनी भरपाई कर लिया करते हैं। हम हमेशा ही मुफ्तखोरी की

सूर्यकुमार पांडेय

हमें मुफ्त का चूना भी लग रहा हो, तो सहर्ष लगवा लेते हैं। इससे हमें आत्मिक संतोष की सहज प्राप्ति होती है

तलाश में रहा करते हैं। मुफ्त का अखबार पढ़ते हैं। मुफ्त की बिजली-पानी चाहते हैं। जो कोई भी हमें यह दे देता है, हम उसकी जय-जयकार बिना सोचे-समझे कर देते हैं। मोबाइल के लिए भी वही स्कीम चुनते हैं जिसमें लाइफटाइम अनलिमिटेड वैल्यू मिले। साथ में यदि मुफ्त का नेट और फ्री एसएमएस मिले तो सोने पर सुहागा हो जाता है।

मैंने मुफ्तखोरों की एक ऐसी जमात भी देखी है जो किसी विवाह समारोह में जाती है तो सौ रुपये का व्यवहार देकर सपरिवार वाली प्लेट खाने की जुगाड़ में रहती है। मेला, महोत्सव, फेस्ट और प्रदर्शनी के लिए टिकट खरीद कर देखने में हमें आनंद नहीं आता। हमारा पहला प्रयास यही रहता है कि कहीं से फ्री के पास का इंतजाम हो जाए। ऐसे पास को हम अपना स्टेटस सिंबल समझते हैं। हम वे लोग हैं जो सेवा तो चाहते हैं, लेकिन वह भी फ्री-फोकटिया वाली। हम सेवाकर की दर देखकर ही बिलबिलाने लग जाते हैं। हमें वही भले लगते हैं जो मुफ्त सुविधाएं देने के वादे करते हैं।

अपनी यह 'फ्रीभोग्या वसुंधरा' कभी मुफ्तखोरों से खाली नहीं रही है। आपको अपने इर्दगिर्द एक से बढ़कर एक पैदाइशी फोकटलाल मिल जाएंगे। उनका मानना होता है कि पैसे बेवकूफ लोग खर्च करते हैं, समझदार व्यक्ति सदैव फ्री के जुगाड़ में रहते हैं। अब ऐसों को भला कौन समझाए कि डॉक्टर फ्री में दवाएं नहीं लिखते। यदि फ्री का पर्चा लिख भी दें, तो ऐसी दवा लिखेंगे, जो किसी खास केमिस्ट की शॉप पर ही मिलेगी और वह शॉप भी वही होगी, जहां से डॉक्टर साहब के अंतर्संबंध होंगे। वकील साहब भी फ्री में सलाह नहीं देते। अगर देंगे भी तो अदालत में तारीख पर तारीख लगती रहेगी। वैसे भी निःशुल्क सेवा वाला टाइम कब का लद गया। यह सुविधाशुल्क का दौर है। मुझे दुर्योग से पुलिस थाने जाना पड़ा। मैंने वहां देखा कि उस थाने के लोग खाली हाथ पकड़कर लाए गए मुजरिमों से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे। मेरे एक सरकारी अफसर साथी अक्सर कहते हैं, 'अगर हम सिफारिशी काम करने लग जाएंगे तो फिर खाएंगे क्या और खिलाएंगे क्या?' कुल मिलाकर हमारी फितरत ही कुछ ऐसी है कि हम हमेशा अपने लिए फ्री-फोकट की सुविधाएं चाहते हैं। अपनी बेटियों की शादियां फ्री में करने में विश्वास करते हैं, लेकिन बेटे के विवाह के मामले में फोकटलाल के स्थान पर चीकटलाल बन जाते हैं।

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य

आइआइटी-आइआइएम की पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों का प्रतिशत

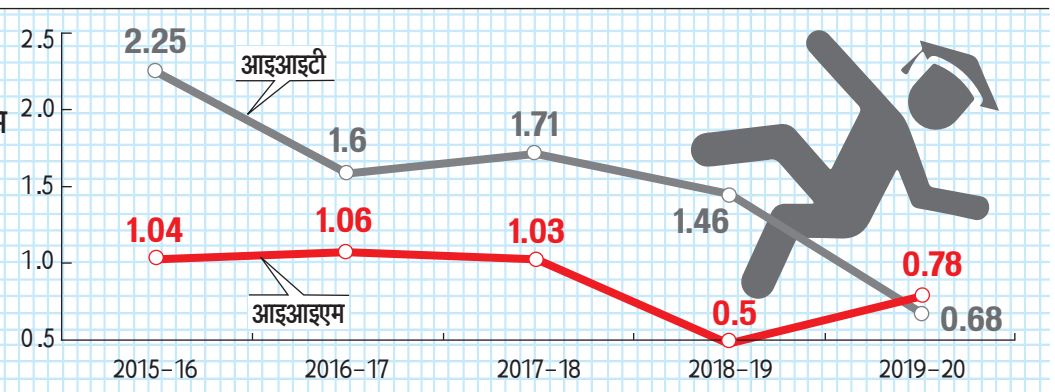

स्रोत : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

ऊर्जा

समय और अवसर

जीवन में बार-बार अवसर नहीं मिलता। कई बार तो अवसर आता है और हम पहचान नहीं पाते। इसलिए जो काम मिले उसे तुरंत और पूरे मनोयोग से करना चाहिए। इनके लिए किसी विशेष घड़ी या अवसर अथवा शुभ-अशुभ के आग्रह में नहीं पड़ना चाहिए। एक यूनानी नाटककार सफोक्लीज कहते हैं कि 'अवसर उसकी मदद कभी नहीं करता, जो अपनी मदद नहीं करते।' वास्तव में किसी काम को करने का संकल्प कर लेना ही अवसर को पकड़ लेना है और अनेक महापुरुषों की सफलता का रहस्य यही मंत्र रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बारे में कहा जाता है कि एक बार वह जो संकल्प कर लेते थे उसको पूरा करके ही दम लेते थे। संकल्प और अवसर का यह साथ बड़े महत्व का होता है। नेपोलियन ने एक बार कहा था कि मुझे एक अवसर दे दो फिर देखो मैं कैसा चमत्कार करके दिखाता हूं। नेपोलियन के अनुसार जो मनुष्य अवसर का सदुपयोग करता है वह सदा आगे बढ़ता है। किसी मनुष्य के जीवन में सफलता का रहस्य प्रत्येक अवसर के लिए सैनिक की भांति तैयार रहना ही है।

सही वक्त और सही अवसर पर काम करने से ही व्यक्ति को कामयाबी मिलती है। कई बार मनुष्य असमंजस और उधेड़बुन में ही रह जाता है और उसके हाथ से मौका निकल जाता है और अगर एक बार ये मौका हाथ से निकल जाए तो दोबारा लौटकर नहीं आता। समय और अवसर को जिसने नहीं पकड़ा वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। समय और अवसर का यदि व्यापक अर्थ देखें तो दोनों एक समान है। जो व्यक्ति समय की गतिशीलता को पहचान कर सामने आए अवसर को पकड़ लेता है और अपनी योग्यता को प्रदर्शित करता है तो वह अवश्य ही अपने जीवन को संवार लेता है। समय कभी ठहर नहीं सकता न किसी का इंतजार करता है। वह तो निरंतर गतिशील है।

कैलाश बिश्नोई

रहस्यों की परतें खोलेगा अनोखा पिंड

मुकुल व्यास

इस बर्फीली जगह के पड़ताल से वैज्ञानिक उस समय में झांक सकते हैं जब मौजूदा ग्रहों के बीज बोए जा रहे थे

सौरमंडल के बाहरी छोर पर स्थित एक छोटी सी चट्टान यह बता रही है कि बड़े ग्रहों का जन्म किस प्रकार हुआ। 'एरोकोथ' नामक यह चट्टान सबसे दूरवर्ती और सबसे प्राचीन पिंड है जिसका अवलोकन पृथ्वी के अंतरिक्ष यान ने किया है। वैज्ञानिकों ने नए शोध पत्रों में इस पिंड के रहस्यों को उजागर किया है। नई खोज से दशकों पुरानी इस गुत्थी को सुलझाने में मदद मिलेगी कि प्रारंभिक सौरमंडल की धुंधली धूल से पहली बार ग्रह किस प्रकार प्रकट हुए मूंगफली जैसे आकार का यह लाल पिंड काइपर बेल्ट में प्लूटो से एक अरब साठ करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। 36 किलोमीटर लंबे पिंड में जमी हुई अवस्था में मीथेन मौजूद है।

यह पिंड दो अलग पिंडों के धीमे विलय से बना है। काइपर बेल्ट हमारे सौरमंडल के बाहरी छोर पर एक ऐसा क्षेत्र है, जहां हजारों बौने ग्रहों और बर्फीले पिंडों की मौजूदगी है। इस पट्टी में मौजूद पिंड दरअसल अरबों वर्ष पहले सूरज के ग्रहों के निर्माण के बाद बचे अवशेष हैं। नासा का न्यू होराइजंस अंतरिक्ष यान पिछले वर्ष नए साल के दिन इस पिंड के बगल से गुजरा था। यह पिंड पृथ्वी से इतना ज्यादा दूर है कि यान द्वारा एकत्र आंकड़े अभी भी पृथ्वी पर पहुंच रहे हैं। एरोकोथ की अनोखी बनावट को देखते हुए कुछ वैज्ञानिकों ने उसे अंतरिक्ष का 'स्नो मैन' या बर्फ का पुतला भी कहा है। पहले इस पिंड का नाम 'अल्टिमा थुले' रखा गया था, लेकिन नाजियों से जुड़ा होने के कारण इस नाम पर विवाद हो गया जिसके बाद इसका नाम एरोकोथ रखा गया जो एक अमेरिकी आदिवासी भाषा का शब्द है।

वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के ग्रह वैज्ञानिक और अध्ययन के प्रमुख लेखक प्रो. बिल मैककिनन का कहना है कि एरोकोथ के बारे में एकत्रित जानकारी इतनी अहम है कि उसके सामने न्यू होराइजंस द्वारा 2015 में प्लूटो के बारे एकत्र जानकारियां भी फीकी हैं। उन्होंने बताया कि हमने एरोकोथ के बारे में जो जानकारी हासिल की है उसे देखते हुए यह पिंड बहुत ही अनोखा है। यह महज आलू जैसी चट्टान नहीं है। यह पिंड हमारे सौरमंडल के बारे में बहुत कुछ कहता है। काइपर बेल्ट में एरोकोथ जिस स्थान पर स्थित है वहां कभी धूल और गैस के बादल का बाहरी छोर था।

गैस और धूल के इस बादल को सोलर नेब्यूला भी कहा जाता था। सूरज जब पहली बार बना तब उसके चारों तरफ यह बादल मौजूद था। इस क्षेत्र में ग्रहों का विकास प्रारंभिक चरण में ही रुक गया था, क्योंकि उस समय उपलब्ध सामग्री का घनत्व कम था। इस बर्फीली जगह के अन्वेषण से वैज्ञानिक उस समय में झांक सकते हैं जब मौजूदा ग्रहों के बीज बोए जा रहे थे। यह स्थान सूरज से इतना दूर है कि वहां तापमान हमेशा न्यूनतम रहता है। इस तापमान पर पिंड एक टाइम कैप्सूल जैसी स्थिति में सुरक्षित रहते हैं।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

शीला पर ठीकरा

दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के साथ-साथ भाजपा का जो हश्र हुआ वह किसी से छिपा नहीं रहा। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के साथ ही भाजपा के कुछ नेता भी इसके लिए शीला दीक्षित को जिम्मेदार मानते हैं। कांग्रेस के दिल्ली प्रभारी ने स्पष्ट कहा था कि कांग्रेस का पतन उसी वक्त से शुरू हो गया था। हालांकि बाद में जब वह चौतरफा घिरे तो पीछे हट गए, लेकिन भाजपा की फजीहत के लिए भला शीला कैसे जिम्मेदार हुईं? भाजपा के एक पुराने नेता की बात मानी जाए तो शीला ने मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह परिसीमन कराया उसके बाद अब दिल्ली विधानसभा में पार्टी को बहुमत मिलना लगभग असंभव है। उनका कहना है कि दो तिहाई सीटों का समीकरण कुछ इस तरह बना है कि भाजपा 15-20 हजार वोटों के नुकसान से ही लड़ाई शुरू करती है। ये वे वोट हैं जो कांग्रेस के परंपरागत मतदाता हैं और इसीलिए अगर कांग्रेस अपने परंपरागत वोटों को बचा लेती तो भाजपा की जीत हो सकती थी। यानी ठीकरा शीला पर।

बुरे फंसे गहलोत

केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत वैसे तो विवादों से दूर ही रहते है, लेकिन पिछले दिनों संसद में वह एक ऐसे मुद्दे पर बयान देकर घिर गए जिससे उनका कोई वास्ता ही नहीं था। हकीकत यह थी कि पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े जिस मुद्दे पर उन्होंने बयान दिया था, वह पूरा मामला डीओपीटी से जुड़ा था, लेकिन आरक्षण शब्द का जिक्र आते ही वह खुद इसमें कूद पड़े। आनन-फानन उनका बयान तैयार किया गया जिसे उन्होंने संसद के दोनों सदनों में पढ़ा भी। स्थिति यह हुई कि इस बयान से जहां वह विपक्ष के सीधे निशाने पर आ गए, वहीं मंत्रालय भी मंत्री जी के इस बयान के बाद चकरघिन्नी बना हुआ है। जो लोग इस विषय को नहीं समझ रहे हैं, वे सीधे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से ही इससे जुड़े सवाल कर रहे है। परेशानी यह है वह सीधे तौर पर इससे पीछा भी नहीं छुड़ा पा रहे और निशाने पर भी वही होते हैं।

राजरंग

'लाइव' प्रबंधन

संसद की कार्यवाही के लाइव प्रसारण ने यूं तो संसद में आचरण को लेकर सांसदों की सतर्कता बढ़ा दी है, लेकिन मुसीबत भी कम नहीं है। ऐसा अक्सर दिखने लगा है कि कई सांसद या मंत्री तक सो रहे होते हैं या फिर चल रही चर्चा से अनभिज्ञ होते हैं। हाल में जब बजट जैसा महत्वपूर्ण अवसर था तब भी कुछ मंत्रियों का यही हाल दिखा था। वैसे बजट भाषण भी काफी लंबा था जिसे पढ़ते-पढ़ते खुद वित्त मंत्री भी कुछ अस्वस्थ हो गई थीं, लेकिन तमाम मंत्री स्वस्थ होने के बावजूद जम्हाई लेते दिखे। उसके बाद तो सोशल साइट्स पर तरह-तरह के मीम बनने शुरू हो गए। यही वजह है कि कुछ सांसद चर्चा के केंद्र में होने वाले वक्ता के पीछे बैठने से बचने की जुगत भिड़ाने में जुटे रहते हैं।

भाग्यशाली कौन

भाजपा में नए अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही यूं तो पदाधिकारियों को लेकर अटकल शुरू हो गई है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा भाजपा की शीर्ष नीति-निर्धारक संस्था संसदीय बोर्ड को लेकर है। यूं तो इसमें चार पद खाली हैं, लेकिन अटकल इस बात की है कि क्या इन चार में किसी महिला को भी जगह मिलेगी और अगर मिलेगी तो वह भाग्यशाली महिला कौन होगी जो सुषमा स्वराज की जगह लेगी। भाग्यशाली इसलिए, क्योंकि संगठन के स्तर पर ऐसी कोई महिला पर नजर नहीं जा रही है जिसका कद इतना उंचा हो और केंद्रीय मंत्री की बात की जाए तो दो महिलाएं हैं जिनके नाम सामने आते हैं। एक निर्मला सीतारमण और दूसरी स्मृति ईरानी।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

130 किलोमीटर तक के इलाके को कवर कर सकते हैं टिड्डी दल एक दिन में। केन्या, इथियोपिया और सोमालिया जैसे देशों में तो टिड्डी दल इतने घने हैं कि उनके पार कुछ देखना भी बहुत मुश्किल होता है।

अनंत विजय
anant@nda.jagran.com

आजकल

वैचारिक जकड़न से आजाद होते उपन्यास

इस दौर को पाठकों या व्यापक हिंदी समाज की रुचि की पूर्ति का दौर भी कहा जा सकता है। यह अकारण नहीं है कि अब प्रकाशक लगातार सार्वजनिक तौर पर अपनी पुस्तकों के नए संस्करणों की बात करने लगे हैं। वो खुलकर ये बताने लगे हैं कि अमुक उपन्यास या अमुक पुस्तक की इतनी प्रतियां बिकीं। इस बदलाव को एक सुखद बदलाव के तौर पर भी देखा और रेखांकित किया जाना चाहिए। ये दौर उन आलोचकों के लिए भी चुनौती का दौर है जो सिर्फ उन्हीं पुस्तकों पर विचार करते रहे हैं जो उनकी विचारधारा के करीब रही हैं

हिंदी कथा परिदृश्य की अगर बात करें तो हम पाते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में इसने अपने भूगोल का विस्तार किया है। वामपंथी विचार के प्रभाव में खास तरह की कहानियां या उपन्यास लिखे जा रहे थे। ये दौर बहुत लंबे समय तक चला और एक खास तरह की फॉर्मूलाबद्ध कहानियां और उपन्यास लिखे जाते रहे। एक गरीब होगा, उसका संघर्ष होगा, समाज के प्रभावशाली व्यक्ति के गरीबों के शोषण का चित्र होगा, उसमें लंबे लंबे वैचारिक आख्यान होंगे और फिर कई बार सुखांत तो कई बार दुखांत होगा। ये कथा-प्रविधि चलती रही। कुछ लेखक इससे हटकर भी लिखते रहे, लेकिन जोर इसी तरह के लेखन का रहा। दुनिया को बदलने का स्वप्न देखनेवाले कथा लेखक अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता की वजह से अपनी कहानियों या उपन्यासों को भी दुनिया को बदलने का औजार बनाते चले गए। जब इस तरह के औजार का प्रयोग हुआ तो उसने हिंदी के पाठकों को चौंकाया। लेकिन जब यही प्रविधि ज्यादातर लेखक उपयोग करने लगे तो पाठकों के बीच ऊब सी पैदा हुई।

विचारधारा की जकड़न वाले ऐसे कथा लेखक इस बात का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उद्घोष भी करते रहे कि वो विचारधारा के पोषण के लिए और उसको मजबूत करने के लिए लिखते हैं। वो पाठकों की परवाह भी नहीं करते थे, बाजार की परवाह करना तो खैर उनके मातृ-विचार के खिलाफ था। इसका दुष्परिणाम हिंदी साहित्य को झेलना पड़ा। एक समय ऐसा भी आया जब हिंदी साहित्य जगत में पाठकों की कमी को लेकर विमर्श शुरू हो गया। बड़े बड़े संस्थानों से लेकर साहित्यिक पत्रिकाओं में हिंदी के पाठकों की कमी का रोना रोते हुए लेख छपने लगे। पाठकों की कमी की बात जब मुखर होने लगी तो उसी दौर में ये हिंदी के कहानी संग्रह और उपन्यासों का संस्करण तीन सौ प्रतियों का होने लगा। लेकिन कभी भी इस बात की पड़ताल करने की कोशिश नहीं की गई कि पाठक क्यों कथा साहित्य से दूर जाने लगे हैं। लेखकों ने पाठकों की रुचि का ध्यान नहीं रखा और कहते भी थे कि वो रुचि का ध्यान रखकर लेखन नहीं कर सकते हैं। अगर बाजार की भाषा में इसको समझने की कोशिश करें तो कह सकते हैं कि वामपंथी लेखकों ने उपभोक्ता यानी पाठकों की रुचि का ध्यान नहीं रखा। वो रवींद्रनाथ टैगोर का कहा भी भूल गए। टैगोर साहब ने 'साहित्य की सामग्री' नामक अपने लेख की शुरुआत में ही कहा था- 'केवल अपने लिए लिखने को साहित्य नहीं कहते हैं। जैसे पक्षी अपने आनंद के उल्लास में गाता है उसी प्रकार हम भी अपने आनंद में विभोर होकर केवल अपने लिए ही लिखते हैं, मानो श्रोता या पाठक का उससे कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। यह बात बिल्कुल निर्विवाद रूप से नहीं कही जा सकती कि पक्षी जब गाता है तब पक्षी समाज जरा भी उसके ध्यान में नहीं होता। यदि नहीं होता तो न सही, इस बात पर तर्क करने से लाभ ही क्या है? परंतु यह तो मानना ही पड़ेगा कि लेखक की रचना का प्रधान लक्ष्य पाठक-समाज होता है।' लेकिन वामपंथी लेखकों ने पाठक समाज को ध्यान में नहीं रखा, उनका लक्ष्य तो कथा साहित्य से अपनी विचारधारा को पुष्ट करना था।

जब वामपंथी विचारधारा का पराभव शुरू हुआ तो हिंदी साहित्य का कथा लेखन भी इस वैचारिक लेखन से मुक्त होने लगा। इसके बीच आर्थिक उदारीकरण के बाद के दौर में ही कथाभूमि में पड़ने शुरू हो गए थे। इक्कीसवीं सदी के आरंभ में बदलाव का ये पौधा उगना शुरू हो गया था और लोगों ने इससे अलग हटकर उपन्यास लिखना शुरू कर दिया था। इसी दौर में मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों ने अपनी नवीनता की वजह से हिंदी के पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया था। भगवानदास मोरवाल का उपन्यास 'प्रेत' और मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास 'अल्मा कबूतरी' ने पाठकों को कथा के ऐसे प्रदेश से परिचय करवाया जिस ओर जाने से हिंदी के उपन्यास लेखक हिचकते थे। इन दोनों उपन्यासों में लेखकों ने जिन समुदायों को कथा के केंद्र में रखा है उसके जीवन को पाठकों के सामने पेश करने की कोशिश की, मोरवाल ने कुछ हिचक के साथ तो मैत्रेयी ने बोल्ड होकर। हम इन दोनों उपन्यासों को विचारधारा से मुक्त होने का प्रस्थान बिंदु मान सकते हैं। हालांकि मोरवाल के उपन्यासों में उसके अवशेष दिख जाते हैं।

इसके बाद के कथा लेखन खासकर उपन्यासों को देखें तो वहां वैचारिक प्रतिबद्धता को पाठकों की रुचि ने विस्थापित कर दिया। नए लेखकों ने विश्वविद्यालय कैंपस की जिंदगी को विषय बनाया और पाठकों ने उनको खूब पसंद किया। इनमें से कुछ लेखक अब कैंपस से बाहर निकल गए हैं और उन्होंने अपने दायरे का विस्तार कर लिया, जबकि कई लेखक अब भी कैंपस के ही चक्कर लगा रहे हैं। इनमें से जो लेखक कैंपस से बाहर निकल गए हैं उनकी व्याप्ति बढ़ी है और जो कैंपस में ही अटके हैं उनसे अपेक्षा की जा रही है कि वो अपनी कथाभूमि का विस्तार करें। पिछले दो-तीन वर्षों को देखें तो कथा भूमि का और विस्तार दिखाई देता है। अब उपन्यासों के विषयों में पहले की अपेक्षा अधिक विविधताएं दिखाई देने लगी हैं। हिंदी का लेखक समाज बहुत बड़ा है और उसी अनुपात में पुस्तकें भी प्रकाशित होती हैं। लेकिन जिन उपन्यासों ने अपनी विषयगत नवीनता की वजह से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा उसमें पर्यावरण और समाज में व्याप्त कानूनी असमानता को लेकर लिखा गया उपन्यास है। पिछले वर्ष के अंतिम महीने में दो ऐसे उपन्यास आए जिसने अपनी विषयगत नवीनता से पाठकों को चौंकाया। रत्नेश्वर ने फिर से पर्यावरण को अपने उपन्यास का विषय बनाया। उनका उपन्यास 'एक लड़की पानी पानी' ने पाठकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसमे रत्नेश्वर ने पानी की समस्या को बेहद रोचक तरीके से उठाया है। उपन्यास के केंद्र में पानी की समस्या है, उपन्यास के पात्रों के बीच पानी की कमी को लेकर चलनेवाला विमर्श है। इसी तरह से भगवानदास मोरवाल ने अपने नए उपन्यास 'वंचना' में महिलाओं और बच्चों के लिए बनाए गए कानून की खामियों को विषय बनाया है। इस उपन्यास में मोरवाल ने बेहद सधे हुए अंदाज में संवेदनशील तरीके से उन स्थितियों की चर्चा की है। इन दोनों उपन्यासों में लेखकों के सामने अपनी कृतियों को पठनीय बनाए रखने की चुनौती थी जिसका सामना दोनों ने बखूबी किया। इस तरह के विषय हिंदी उपन्यासों के लिए पहले बिल्कुल नहीं सोचे गए थे। अगर लिखे गए हों तो संभव है कि मेरी नजर में ना आए हों। मार्क्सवादी लेखकों ने तो पर्यावरण को इस वजह से अपने लेखन में तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उनके आराध्य ने ही इस विषय पर कुछ नहीं देखा।

ऐतिहासिक, पौराणिक और मिथकीय चरित्रों पर पहले भी लेखन होता था और अब उसमें काफी वृद्धि हुई है। राष्ट्रवाद के दौर में पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर ढेर सारे लेखकों ने महाभारत और रामायण के चरित्रों को लेकर उपन्यास लिखे। पहले नरेंद्र कोहली ने अकेले इन विषयों पर विपुल लेखन किया जिसे बाद में अमीश समेत अन्य लेखकों ने बढ़ाया। लेकिन पिछले ही साल नरेंद्र कोहली का एक उपन्यास 'सागर मंथन' प्रकाशित हुआ जिसमें उन्होंने कथा के एक नए क्षेत्र में प्रवेश किया जिसमें पौराणिकता के साथ विज्ञान भी है। कह सकते हैं कि हिंदी में कथा साहित्य के दौर को विचारधारा की गुलामी से मुक्त होने का दौर कह सकते हैं। उसको वर्तमान और भविष्य की चिंताओं को अपने अपने उपन्यासों का विषय बनाकर पाठकों के समक्ष ले जाने का जोखिम उठाने का दौर है।

फिर से

टिड्डियों से बढ़ता नुकसान

भारत समेत पाकिस्तान कई इलाकों में टिड्डी दलों की भयावहता बढ़ती जा रही है। हजारों की संख्या में आ रही टिड्डियां करोड़ों रुपये की फसल को कुछ घंटों में ही बर्बाद कर देती हैं। पाकिस्तान ने टिड्डी दल के हमले के कारण राष्ट्रीय आपातकाल का ऐलान किया है। टिड्डी दल बड़े पैमाने पर फसलों को बर्बाद कर रहे हैं जिससे खाद्य असुरक्षा की आशंका बढ़ जाती है। पाकिस्तान से आ रहे टिड्डी दल राजस्थान, पंजाब और गुजरात के कुछ जिलों में भी फसलों को नुकसान पहुंचा चुके हैं। राजस्थान में ही टिड्डी दल का हमला एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से इस पर मदद मांगी है। दूसरी ओर पंजाब में भी टिड्डी दल को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। गुजरात में भी दिसंबर महीने में टिड्डियों का हमला हुआ था जिसमें दो जिलों के 25 हजार हेक्टेयर की फसल तबाह हो गई थी। गुजरात सरकार ने प्रभावित किसानों को 31 करोड़ रुपये मुआवजे का ऐलान भी किया है।

क्या होती है टिड्डी : टिड्डी एक छह से आठ सेंटीमीटर आकार का एक कीड़ा होता है जो हमेशा समूह में चलता है। ये समूह फसलों को चट करता चलता है। टिड्डी हर दिन अपने वजन के बराबर खाना खा सकता है। इसलिए जब लाखों टिड्डियों का एक दल आगे बढ़ता है तो वह फसल के लिए बड़ा खतरा बन जाता है।

संयुक्त राष्ट्र के संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एक वर्ग किलोमीटर इलाके में आठ करोड़ टिड्डी हो सकते हैं। एक साथ चलने वाला टिड्डियों का एक झुंड एक वर्ग किलोमीटर से लेकर कई हजार वर्ग किलोमीटर तक फैला हो सकता है। एक टिड्डी पांच महीने तक जी सकता है। इनके अंडों से दो सप्ताह में बच्चे निकल सकते हैं। दो से चार महीनों का समय इनकी जवानी का समय होता है।

कितने बुरे हैं टिड्डी : टिड्डी चुनकर खाना नहीं खाते। वे अपने रास्ते में आने वाली हर खाने वाली चीज को खा सकते हैं। टिड्डी दल एक दिन में पांच से 130 किमी का इलाका कवर कर सकते हैं। केन्या, इथियोपिया और सोमालिया में तो टिड्डी दल इतने घने हैं कि उनके पार कुछ नहीं दिख रहा। टिड्डी दल का प्रभाव एक महाद्वीप से निकल दूसरे महाद्वीप तक पहुंचने लगा है। अफ्रीका के इथियोपिया, युगांडा, केन्या, दक्षिणी सूडान से आगे निकलकर ये टिड्डी दल यमन और ओमान होते हुए पाकिस्तान और भारत तक पहुंच गए हैं। राजस्थान व गुजरात के किसानों के हालात टिड्डी के चलते बुरे हुए हैं।

कैसे आए इतने टिड्डी : इस इलाके में सालों तक पड़े सूखे और उसके बाद आई भारी बारिश और बढ़ते तापमान ने टिड्डियों के जनन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा की। अच्छी बारिश की वजह से इन इलाकों में हरियाली भी बढ़ी है। हरियाली बढ़ना भी टिड्डियों के प्रजनन में बढ़ोतरी में एक बड़ी वजह है। इन देशों में टिड्डियों को रोकने के सही इंतजाम भी नहीं हैं. इसके चलते इनमें तेज बढ़ोत्तरी हुई है.

टिड्डियों को रोकने के लिए एक आम तरीका तेज आवाज का इस्तेमाल है। लेकिन जरूरी नहीं कि इससे टिड्डी आगे ना बढ़ें। कई बार तेज आवाज से टिड्डी तेजी से आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका इन्हें खाने का है। संयुक्त राष्ट्र ने इनकी रोकथाम के लिए रकम जारी की है, पर वह पर्याप्त नहीं है।

(डीडब्ल्यू डॉट कॉम से संपादित)
अंश, साभार)

ट्वीट-ट्वीट

पी चिदंबरम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर का विरोध करे। इसके लिए वह जेएनयू छात्रों को नुस्खे भी बता रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में जो सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही है वह एक मई से 15 जून के बीच एनपीआर कराने जा रही है। यलगार परिषद पर सरकार के रुख पर दूसरी सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी आपत्ति जताई है। बड़ी दुविधा और भ्रम की स्थिति है।
संजय निरुपम@sanjaynirupam

अगर उसेन बोल्ट से तेज दौड़ लगाने वाले श्रीनिवास गौड़ा के शरीर सौष्ठव पर नजर डालें तो उनमें अद्भुत एथलीट बनने की संभावनाएं दिखती हैं। अब या तो सरकार उन्हें सौ मीटर दौड़ के लिए प्रशिक्षित करे या फिर उनके खेल कंबाला को ओलंपिक स्पर्धा बनाया जाए। किसी भी सूरत में हमें श्रीनिवास के लिए स्वर्ण पदक चाहिए।
आनंद महिंद्रा@anandmahindra

मध्य प्रदेश भी गजब है जब मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवाल पूछा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया और वह इसके खिलाफ सड़क पर उतर सकते हैं तो इस पर मुख्यमंत्री ने भी कहा कि वे चाहें तो जरूर सड़कों पर उतरें।
मिलिंद खांडेकर@milindkhandekar

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की आधे से अधिक आबादी दयनीय दशा वाली उन झुग्गी बस्तियों में रहती है जहां तमाम बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। वे वहां रहने को इसलिए मजबूर हैं, क्योंकि किफायती दरों वाले मकानों की आपूर्ति सुस्त है। वहीं सरकार 28 मंत्रियों के बंगलों के कायाकल्प पर 28 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। यह मिसाल है कि हमारे नेता कितने बेशर्म हो सकते हैं।
तवलीन सिंह@tavleen_singh

रचनाकर्म

शून्य से शिखर का सफरनामा

प्रणव सिरोही

यह पुस्तक भारत में नए किस्म की उद्यमिता की विकास-यात्रा का दस्तावेज है, जिसमें तमाम उत्कर्ष एवं अपकर्ष का समावेश है...

पुस्तक : बिग बिलियन स्टार्टअप- द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी
लेखक : मिहिर दलाल
प्रकाशक : मैकमिलन
मूल्य : 699 रुपये

'फ्लिपकार्ट' की शुरुआत ऐसी कंपनी के रूप में हुई जो किताबों को सस्ते में मुहैया कराती थी। उसी 'फ्लिपकार्ट' की कहानी पर खुद एक किताब आ गई है, जो उसकी सफलता की गाथा को दर्शाती है। अब यह केवल किताबों की बिक्री तक सीमित न होकर अनेकानेक वस्तुओं की ऑनलाइन मंडी वाली एक भीमकाय कंपनी बन गई है। लेखक-पत्रकार मिहिर दलाल की किताब 'बिग बिलियन स्टार्टअप-द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी' में फ्लिपकार्ट की इसी कहानी को प्रस्तुत किया गया है।

यह चंडीगढ़ के दो लड़कों सचिन बंसल और बिन्नी बंसल की कहानी है, जो एक ही जगह के बाशिंदे होने के बावजूद कभी शहर में नहीं मिले। आइआइटी, दिल्ली उनके मेल का पहला पड़ाव बनती है। फिर अपनी कारोबारी जुगलबंदी से वे देश में खरीदारी की आदतें बदलकर रख देते हैं। अपनी कामयाबी से दुनिया भर के कारोबारी दिग्गजों को चमत्कृत भी करते हैं। यह किताब सफलता की आकांक्षा, उसके लिए अपेक्षित पुरुषार्थ और जीवन के तमाम उत्कर्ष-अपकर्ष की गाथा है।

आम धारणा के उलट सचिन और बिन्नी भाई तो दूर, सहपाठी भी नहीं रहे। बिन्नी सचिन के एक साल बाद आइआइटी पहुंचे, जहां उनके साथी वह कुणाल बहल थे, जिन्होंने बाद में स्नैपडील नाम की कंपनी बनाई, जो फ्लिपकार्ट की कड़ी प्रतिस्पर्धी रही। बिन्नी नौकरी के लिए गूगल के दर पर भी गए थे, लेकिन वहां उन्हें खारिज कर दिया गया। फिर उन्होंने अमेजन में आवेदन किया और वहां भी उन्हें नकारे जाने पर मुहर लगने को थी, लेकिन अमेजन में पहले से कार्यरत सचिन की 'सिफारिश' पर उनकी बात बन गई। वहीं से दोनों का साथ शुरू हुआ और वे फ्लिपकार्ट के लिए टीम बनाने में जुट गए।

यह पुस्तक कई अन्य पहलुओं से भी पर्दा उठाती है। मसलन, कौन उद्यमी सचिन के आदर्श रहे, जिनकी जीवनी उनके लिए किसी धर्मग्रंथ से कम नहीं? बंसलद्वय ने कितनी मामूली पूंजी के साथ फ्लिपकार्ट शुरू की? उन्होंने यही नाम क्यों चुना? उन्होंने उस बेंगलुरु को ही क्यों ठिकाना बनाया, जिसे पंडित नेहरू ने कभी 'सिटी ऑफ फ्यूचर' कहा था?

नए उद्यम को शुरू करने में सबसे बड़ी समस्या पूंजी की आती है, जिससे सचिन-बिन्नी की जोड़ी को भी दो-चार होना पड़ा। इससे जुड़े भी कई रोचक किस्से हैं। यह भी कि कैसे उन्हें एक्सेल के जरिये दस लाख डॉलर की पहली बड़ी पूंजी मिली। इसमें सबसे दिलचस्प किस्सा 'द विजार्ड ऑफ वॉल स्ट्रीट' नाम से मशहूर निवेश फर्म टाइगर ग्लोबल का है, जिसके कर्ताधर्ता ली फिक्सेल उभरते बाजारों की उदीयमान कंपनियों में निवेश के उत्सुक थे। उन्होंने जब फ्लिपकार्ट में निवेश के लिए संपर्क किया तो उन्हें तवज्जो नहीं मिली, क्योंकि प्रबंधन उनसे खास परिचित नहीं था। सचिन-बिन्नी बंसल को भी लगा कि कोई उन्हें फर्जी कॉल करके मूर्ख बना रहा है और वे उसे सबक सिखाकर ही रहेंगे। लेकिन तब उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा, जब फिक्सेल से मुलाकात के चंद हफ्तों बाद टाइगर ग्लोबल ने फ्लिपकार्ट में भारी निवेश किया। टाइगर की वित्तीय खुराक फ्लिपकार्ट की सेहत बनाने वाली साबित हुई। यह कंपनी के साथ ही उसके संस्थापकों के लिए भी खुशनुमा दौर था, जब सचिन की पत्नी प्रिया ने पुत्र को जन्म दिया और बिन्नी अपनी गर्लफ्रेंड त्रिशा के साथ परिणय सूत्र में बंधे। हालांकि इसके बाद उथल-पुथल का दौर शुरू हो गया। जो फिक्सेल सचिन-बिन्नी के रहनुमा बने थे, उन्होंने ही दोनों के पर कतर दिए और कंपनी का नियंत्रण दोनों के हाथों से निकलता गया।

कुल मिलाकर, यह पुस्तक भारत में नए किस्म की एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता की विकास-यात्रा का दस्तावेज है। चूंकि दलाल ने एक पत्रकार के रूप में काफी समय से फ्लिपकार्ट को कवर किया था, इसलिए उनके पास पर्याप्त सूचनाएं उपलब्ध थीं, जिन्हें उन्होंने किताब में बखूबी जगह भी दी है। हालांकि लालित्य बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ स्थानों पर 'फिक्शन' और 'नॉन-फिक्शन' का फ्यूजन पुस्तक का प्रवाह अवरुद्ध करता है। फिर भी इसकी विषयवस्तु बहुत रोचक है और शायद यही वजह है कि जल्द ही इस पर फीचर फिल्म भी बनने जा रही है।

पत्रकारिता के पितामह की कथा

जितेंद्र कुमार

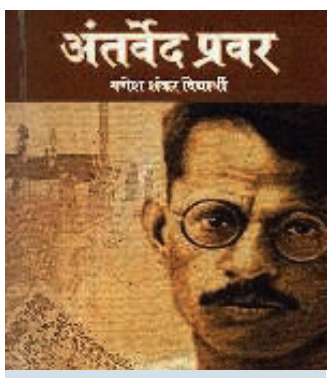

पुस्तक : अंतर्वेद प्रवर
लेखक : अमित राजपूत
प्रकाशक: लोकोदय प्रकाशन, लखनऊ
मूल्य : 240 रुपये

'अंतर्वेद प्रवर' के जरिये लेखक अमित राजपूत ने गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे हिंदी पत्रकारिता के पितामह के जीवन पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। यह किताब गणेश शंकर विद्यार्थी की जन्मभूमि से लेकर कर्मभूमि तक की प्रमुख घटनाओं का रोचक वर्णन करती है। अपनी पत्रकारिता के जरिये विद्यार्थी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अमूल्य योगदान तो दिया ही, समाज के कमजोर तबके की आवाज को भी बुलंद किया। आजादी के आंदोलन में गांधी जी के साथ काम करने से लेकर शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के लेखों को अपने अखबार 'प्रताप' के जरिये मंच दिया। इसमें स्वतंत्रता के समय की पत्रकारिता से लेकर समकालीन घटनाओं का रोचक वर्णन पढ़ने को मिलता है। विद्यार्थी जी के पत्र 'प्रताप' की मुख वाणी- 'जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, नर पशु निरा है, और मृतक समान है,' उनके निज जीवन में भी झलकती थी। जीवनपर्यंत वे किसानों की मदद के लिए तत्पर रहे। वे कहते थे कि हमें सच्चाई की लाज रखनी है। केवल अपनी मक्खन-रोटी के लिए रंग बदलना अच्छी बात नहीं है। पुस्तक में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं और तथ्यों का वर्णन है, जो शायद ही आपको कहीं और पढ़ने को मिले। झंडागीत का सृजन भी इनमें से ही एक है। लेखक ने बताया है कि कैसे विद्यार्थी जी ने अपने सहयोगी व मित्र श्याम लाल गुप्त को प्रेरणा देकर 'विजयी विश्व तिरंगा प्यारा' की रचना करवाई। यह वही तराना है जिसे हम बचपन से गुनगुनाते आए हैं। किताब में तथ्यों का वर्णन करते समय प्राथमिक स्रोतों का सहारा लेने की पूरी कोशिश की गई है। इसके लिए उद्धरणों का इस्तेमाल भी किया गया है। पत्रकारिता के दम पर अंग्रेजों की नाक में दम करने वाले विद्यार्थी जी के सामाजिक सरोकारों का वर्णन सजीव-सा प्रतीत होता है। लेखक सांप्रदायिक दंगों के समय विद्यार्थी जी के प्रयासों को उकेरने में सफल रहा है। कुल मिलाकर, किताब दिलचस्प और पठनीय है।

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या दागी नेताओं के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक दल उन्हें टिकट देने से परहेज करेंगे?

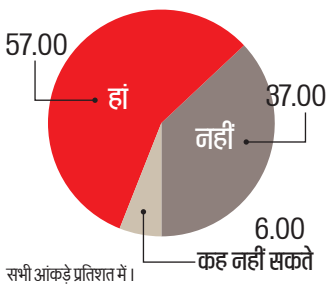

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या कुछ अमेरिकी उत्पादों के लिए भारतीय बाजारों को खोलने से दोनों देशों के व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

उतरो-उतरो सिंधिया सड़क देखती राह,
कमलनाथ की भी यही अब दिखती है चाह।
अब दिखती है चाह चुनौती भी दे डाली,
दिखे मराठा आन न जिह्वा जाए खाली।
आपस में भिड़ आप पार्टी को ही कुतरो,
शक्ति दिखाने हेतु सड़क पर जल्दी उतरो।
– ओमप्रकाश तिवारी

आशीष व्यास
संपादक, नई दुनिया, मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश डायरी

उज्जैन की प्रसिद्धि बढ़ाने में जुटी सरकार

सप्तपुरी में से एक महाकाल की नगरी उज्जैन। यानी यह देश के सात धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां सालाना तीन लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं। 12 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाले पिछले सिंहस्थ (कुंभ) मेले (वर्ष 2016) में भी आठ करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे। लेकिन अवसर विशेष के साथ सामान्य दिनों में आने वाले हजारों श्रद्धालु इस स्थल को अलग नहीं बनाते हैं। इसे अलग बनाते हैं यहां होने वाले दैनंदिन के वार-त्योहार और उत्सव। 12 महीने में 13 पावन (उत्सव) मनाने वाला यह शहर और यहां के लोग इस उत्सवधर्मिता में इतने रम गए हैं कि खास और आम सब एकाकार हो गया है। लेकिन यहां की अलौकिक और अलग परंपराएं वैसी प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर पाई हैं, जो न सिर्फ महाकाल को विश्वविख्यात होने की नई सीमाएं दिला सकें, बल्कि उज्जैन के साथ-साथ मध्य प्रदेश को भी अविस्मरणीय पहचान दिला सकें। क्योंकि ऐसे अनेक अवसर और उत्सव हैं, जो महाकाल के प्रांगण से शुरू होकर महाकाल के परिसर में ही समाप्त हो जाते हैं। उज्जैन को प्रचार-प्रसार और प्रभाव की दृष्टि से समृद्ध करने के लिए तीन सामयिक योग बन रहे हैं। पहला- शिव नवरात्रि, दूसरा- काशी महाकाल एक्सप्रेस और तीसर- आइफा। उज्जैन वैसे भी इन दिनों उत्सव में डूबा हुआ है। यही अवसर है जब इस नगरी को नए सिरे से समझा-समझाया जाए।

पहला दृश्य : महाकाल मंदिर प्रांगण में बीते गुरुवार से शिव नवरात्रि उत्सव का उल्लास छाया हुआ है। उत्सव के दौरान नौ दिनों तक संध्या आरती में भगवान महाकाल को अलग-अलग स्वरूपों में सजाया जाएगा। बारह ज्योतिर्लिंगों में महाकाल एकमात्र ज्योतिर्लिंग हैं, जहां शिव नवरात्रि उत्सव मनाया जाता है। उत्सव जितना पुराना है, इसकी परंपराएं भी उतनी ही अनूठी हैं। शिव नवरात्रि में राजा महाकाल नारदीय संकीर्तन से हरि कथा का श्रवण भी करते हैं। यह परंपरा दशकों से चली आ रही है। इंदौर के कानड़कर परिवार के सदस्य प्रतिवर्ष भगवान महाकाल को हरि कथा सुनाने आते हैं। यह परिवार नौ पीढ़ियों से महाकाल के आंगन में हरि कथा कर रहा है। नारदजी जिस प्रकार खड़े रहकर हरि नाम संकीर्तन करते हैं, उसी प्रकार खड़े होकर ही संकीर्तन पद्धति से हरि कथा का वाचन किया जाता है।

सवाल : उज्जैन-इंदौर और आसपास के श्रद्धालु इस परंपरा से परिचित हैं, लेकिन क्या उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक शिवभक्तों, पर्यटकों और लोगों के बीच यह परंपरा प्रचार प्राप्त कर पाई है?

दूसरा दृश्य : वाराणसी से इंदौर के लिए काशी-महाकाल एक्सप्रेस का उद्घाटन आज (16 फरवरी) को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह देश की तीसरी कॉरपोरेट ट्रेन होगी, जिसका संचालन तेजस की तरह आइआरसीटीसी के पास होगा। ट्रेन तीन ज्योतिर्लिंगों वाराणसी में काशी विश्वनाथ, उज्जैन में महाकालेश्वर और इंदौर के पास ओंकारेश्वर को जोड़ेगी। सुविधाओं के मामले में भी यह विशेष ट्रेन होगी।

सुझाव : ट्रेन की यह सुविधा आने वाले समय में यात्रियों की संख्या बढ़ाएगी। लेकिन अभी भी समय ज्यादा लग रहा है। निकट भविष्य में इसका सस्ता और कम समय लेने वाला विकल्प तलाशना होगा।

तीसरा दृश्य : महाकाल मंदिर समिति 'महाकाल एप' को अपग्रेड करने की तैयारी कर रही है। इस एप पर घर बैठे मंदिर परिसर का 360 डिग्री व्यू देखा जा सकेगा। भक्तों को एक क्लिक पर मंदिर में उपलब्ध जनसुविधाओं की जानकारी भी मिल जाएगी। फिलहाल एप पर लाइव दर्शन आदि की सुविधा ही मौजूद है। मंदिर समिति अब इसका उपयोग पब्लिक यूटिलिटी के रूप में करने की तैयारी कर रही है। जीपीएस व 360 डिग्री थ्रीडी व्यू से लैस होने के बाद भक्तों को शहर में प्रवेश करते ही मंदिर पहुंचने के मार्ग की जानकारी मिलेगी। मंदिर के नजदीक पहुंचते ही सामान्य दर्शनार्थी, वीआइपी गेट, शीघ्र दर्शन टिकट द्वार, भस्म आरती द्वार आदि तक पहुंचने का रास्ता दिखाई देगा।

संकट : प्रचार के लिए वर्चुअल वर्ल्ड की यह दुनिया बेहतर है। लेकिन इन दर्शकों को बतौर पर्यटक उज्जैन तक खींचकर लाना बड़ी चुनौती होगी।

महाकाल की नगरी के ये तीन दृश्य प्रमाण हैं कि उज्जैन की पहचान को नई परिभाषा देने के लिए कई प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रहे आइफा अवार्ड के जरिये अब राज्य सरकार ने विश्व स्तर पर अपने धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों की ब्रांडिंग का एजेंडा तैयार किया है। प्रदेश सरकार का मानना है कि आइफा के बहाने पर्यटन मानचित्र पर राज्य को यूनिक-डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया जा सकता है।

संकट में आ गई तीर्थयात्रा : आर्थिक संकट से जूझ रही मध्य प्रदेश सरकार ने अपने वित्तीय खर्चों में कटौती करते हुए करीब 4,000 बुजुर्गों की तीर्थयात्रा पर रोक लगा दी है। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के धार्मिक संगठन काफी नाराज हैं। राज्य सरकार की तीर्थ योजना का लाभ उठाने के लिए इन तीर्थयात्रियों को भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और मालवा-निमाड़ के साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों से चुना गया था। लेकिन अचानक सब स्थगित हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू की थी। इसके तहत 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के गैर-आयकर दाताओं को देश-प्रदेश के धार्मिक स्थानों की यात्रा करवाई जाती थी। विपक्ष ने एक बार फिर से सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए पुराने आरोपों को दोहराया है। इस तर्क के साथ कि सरकार की नीति और नीयत में बड़ा अंतर आता जा रहा है।

46 कंपनियों ने उत्तराखंड के ऊधमसिंहनगर जिले में उद्योग लगाने में रुचि दिखाई है। विभिन्न क्षेत्रों में निवेशकों से 613.64 करोड़ रुपये निवेश के प्रस्ताव मिले हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 16 फरवरी 2020

हिमाचल प्रदेश

समाज-सरकार करे धरोहरों का संरक्षण

धरोहरें बताती हैं कि हमारा इतिहास बुलंद था। ये पर्यटकों को भी आकर्षित करती हैं। देशी पर्यटकों के अलावा बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी जब भारत आते हैं तो वे यहां की धरोहरों को भी देखने जाते हैं। देशी पर्यटकों में तो धरोहरों को देखने का जबरदस्त क्रेज देखने में आ रहा है, बशर्ते उन्हें वहां तक पहुंचने, ठहरने आदि की बुनियादी सुविधाएं समुचित तरीके से उपलब्ध हों। हमारे अनेक धरोहर ऐसे भी हैं जो हमारी एक विशिष्ट पहचान बन चुके हैं और इन्हें उसी प्रकार से रेखांकित किया जाता है। ऐसे में धरोहर का मिटना पहचान को भुलाने की तरह है।

पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की पहचान पर्यटन राज्य के रूप में भी होती है। हर साल लाखों पर्यटक इन धरोहरों को देखने के लिए आते हैं, लेकिन इन्हें समग्रता से विकसित किए जाने की बात तो छोड़िए, सही रखरखाव पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिए जाने से कई धरोहरों पर समय के साथ धूल की परत भी मोटी होती जा रही है। नतीजा यह है कि कई धरोहरें आग की भेंट चढ़ चुकी हैं तो कई खंडहरों में तब्दील हो गई हैं। राज्य में बहुत कम धरोहरों पर सरकार का ध्यान है। कांगड़ा जिले में ही कई ऐसी धरोहरें हैं जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। कई धरोहरों के आसपास इतनी झाड़ियां उग आई हैं कि उनके अतिक्रमण के कारण इनका अस्तित्व बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इन धरोहरों के संरक्षण के लिए आवाज भी उठाई जाती है, लेकिन इनकी तरफ सरकार और स्थानीय प्रतिनिधियों का रवैया उदासीन रहता है। छोटी काशी के रूप में पहचाने जाने वाले हरिपुर कस्बे में सैकड़ों मंदिर हुआ करते थे, लेकिन अब कुछ ही मंदिर बचे हुए हैं। हरिपुर की पहचान सूखा तालाब के कारण भी होती रही है, लेकिन अब सूखा तालाब को लोगों ने 'डंपिंग साइट' बना दिया है। जन प्रतिनिधियों और प्रशासन को इसके बारे में जानकारी भी है, लेकिन इसके संरक्षण के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। वर्षों से यहां पर छिंज मेले का आयोजन भी होता रहा है। लेकिन अब जगह तंग होने के कारण यहां पर छिंज मेले का आयोजन करवाना भी मुश्किल हो गया है। हरिपुर कस्बे के चारों ओर चार द्वार होते थे, लेकिन अब मात्र दो द्वार ही बचे हैं, और वे भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। भारी बरसात में इनके गिरने की आशंका बनी रहती है। हरिपुर में करीब 800 साल पुराना श्रीराम मंदिर भी है, लेकिन इसके रखरखाव के लिए भी कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। जबकि ये धरोहरें असामाजिक तत्वों का अड्डा बनती जा रही हैं। इनकी सुरक्षा के बारे में स्थानीय प्रशासन को पर्याप्त इंतजाम करना होगा।

> धरोहरें हमें स्वर्णिम इतिहास और विरासत से रूबरू करवाती हैं। लिहाजा हमें समझना होगा कि इनकी बेकद्री अपनी जड़ों को भूलने की तरह है।

स्थानीय प्रशासन और सरकार को चाहिए कि ऐतिहासिक महत्व की इन धरोहरों के संरक्षण और रखरखाव पर ध्यान दे। इसके अलावा आम जनता को भी चाहिए कि धरोहरों के संरक्षण के लिए आगे आएं। इनके संरक्षण से जहां पर्यटन बढ़ेगा, वहीं लोगों को रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

बंगाल

विकास कार्य और सियासत

केंद्र और राज्य की सरकारें लोगों की अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए कार्य करती हैं। साथ ही ये दोनों ही सरकारें अपने-अपने स्तरों से आमजन के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का इंतजाम करती हैं। सरकारें विकास के जरिये लोगों को रोजगार मुहैया कराने से लेकर हर तरह की मदद करती हैं। परंतु विकास कार्यों को लेकर सियासी नफा-नुकसान देखा जाने लगे तो यह उचित नहीं है। बंगाल में इन दिनों सियासी नफा-नुकसान के भंवर में कई केंद्रीय योजनाएं फंसी हुई हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ ममता सरकार का टकराव जगजाहिर है। ऐसा पहली बार नहीं है कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार के साथ टकराव की स्थिति में हैं। गाहे-बगाहे उनका केंद्र सरकार से अनेक मसलों पर टकराव सामने आने लगा। आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, स्मार्ट सिटी समेत कई केंद्रीय योजनाओं को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में लागू नहीं होने दिया। यहां तक कि केंद्रीय परियोजनाओं के लिए वे समुचित जमीन तक नहीं मुहैया करा रही हैं। अब कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार के लिए ममता सरकार ने जमीन देने से साफ इन्कार कर दिया है। इस इन्कार के बाद एयरपोर्ट विस्तार की योजना ठंडे बस्ते में जाने के पूरे आसार दिख रहे हैं और इसका नुकसान बंगाल के लोगों को ही अधिक

प्रतीकात्मक फोटो।

होगा। चूंकि कोलकाता एयरपोर्ट से आवाजाही करने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए एयरपोर्ट पर विमानों की संख्या समेत अन्य सुविधाएं भी बढ़ानी होंगी। केंद्र सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोलकाता के निकटवर्ती क्षेत्र में विस्तार के लिए बंगाल सरकार से जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इसका कारण यह भी है कि कोलकाता एयरपोर्ट से कोई यात्री उतर कर अन्य जगह के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ना चाहता है तो उसे अधिक परेशानी न हो। इस बात को ध्यान में रखकर ही विस्तार करने की योजना है। दरअसल देश के पूर्वोत्तर राज्यों मसलन- मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम समेत असम से देश के अन्य हिस्सों में जाने के लिए सीधी विमान सेवा के अभाव में इन राज्यों के अधिकांश लोग पहले कोलकाता आते हैं, फिर यहां से दूसरे विमान से देश के अन्य हिस्सों तक जाते हैं। इन यात्रियों के लिए यहां ठहरने की व्यवस्था करनी होती है, जिसके लिए पर्याप्त जमीन की जरूरत है। लेकिन बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन अरविंद सिंह को स्पष्ट कर दिया है कि कोलकाता के आसपास एयरपोर्ट के लिए जमीन की व्यवस्था नहीं हो सकती। राज्य सरकार ने विकल्प के तौर पर कोलकाता से करीब 180 किलोमीटर दूर दुर्गापुर स्थित अंडाल एयरपोर्ट के विस्तार का प्रस्ताव दिया है। इसे केंद्र और एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए मानना संभव नहीं लगता है, क्योंकि विमानन मंत्रालय का कहना है कि कोलकाता से अंडाल की दूरी काफी है। इस विषय पर एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि हमलोग जमीन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। राज्य सरकार को ही जमीन की व्यवस्था करनी होगी। उनके मुताबिक, राज्य अगर जमीन नहीं देती है तो एक समय आएगा, जब कोलकाता एयरपोर्ट का विस्तार बंद हो जाएगा। उनका साफ कहना है कि अंडाल कोलकाता का विकल्प नहीं बन सकता है। ऐसे में ममता सरकार को चाहिए कि वह टकराव की राह पर ना चलकर विचार विमर्श कर उचित निर्णय लें, ताकि विकास कार्य सियासत से प्रभावित न हो सके।

झारखंड

नौकरशाही को सीख लेने की दरकार

अपराध अनुसंधान विभाग के अपर पुलिस महानिदेशक सस्पेंड कर दिए गए हैं। उनके खिलाफ वर्ष 2016 के राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के लिए कांग्रेस विधायक को लालच देने और कांग्रेस विधायक के पति को धमकाने का आरोप है। नौकरशाही पर इस तरह का आरोप लगना दुर्भाग्यपूर्ण हैं। ये आरोप बताते हैं कि अफसरों की एक लॉबी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता की तरह काम करती है। यही वजह है कि एडीजी पर हुई कार्रवाई के बाद से पिछली सरकार के चहेते अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। सरकारें आती जाती रहती हैं।

अफसर वहीं रहते हैं। अफसरों का काम यह नहीं होता कि वे किसी भी सरकार में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता की तरह काम करें। उनकी अपनी जवाबदेही होती है, जिम्मेदारी होती है। उन्हें ना केवल उस पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि सरकार में बैठे राजनेताओं को सही-गलत से भी अवगत कराना चाहिए। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए कि सीमाओं से इतर जो आदेश दिया जाए, उसका अनुपालन शुरू कर दें। कई बार तो नौकरशाह बिना नेताओं के आदेश के ही उन्हें खुश करने के लिए कई काम कर बैठते हैं। झारखंड में भी ऐसे अधिकारी हैं, जो सरकार गठन के साथ ही मुख्यमंत्री से लेकर अन्य मंत्रियों की परिक्रमा शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, उनके करीबियों को भी साधना शुरू कर देते हैं। पिछली सरकार के तत्कालीन एडीजी की भूमिका को भारत निर्वाचन आयोग ने भी संदिग्ध माना था। यही वजह रही कि उन्हें गत वर्ष हुए लोकसभा चुनाव से पूर्व राज्य के बाहर जाने का आदेश दिया गया था। उन्हें एडीजी विशेष शाखा के पद से भी हटा दिया गया था। लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने झारखंड में योगदान दिया। उसके बाद तत्कालीन सरकार ने उन्हें सीआइडी के एडीजी पद पर तैनात किया। हालांकि, राज्य में ऐसे लोगों की संख्या अभी भी काफी सीमित है। सरकार में अच्छे अधिकारियों की कमी नहीं है, जो सही को सही और गलत को गलत कहने का माद्दा रखते हैं। यही वजह है कि अभी भी हमारी व्यवस्था को दीमक नहीं लगा है।

> झारखंड में भी ऐसे अधिकारी हैं, जो सरकार गठन के साथ ही मुख्यमंत्री व मंत्रियों की परिक्रमा शुरू कर देते हैं जिसे सही नहीं कहा जा सकता है

वैसे देखा जाए तो ऐसा वाकया देश में पहली बार नहीं हुआ है। अनेक राज्यों में नई सरकार के गठन के बाद जब अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन नई सरकार की ओर से किया जाता है तो ऐसी बातें सामने आती हैं। हालांकि कई बार नई आने वाली सरकार अपना राजनीतिक हित साधने के लिए भी इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देती है, लेकिन किसी को दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत भी देने होते हैं, लिहाजा यदि कोई सरकार राजनीतिक विद्वेष के कारण इस तरह की हरकत करती है तो वह सच्चाई के पैमाने पर भविष्य में टिक नहीं पाता है। वैसे इस तरह की घटना से अधिकारियों को सबक लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वे किसी खास राजनीतिक दल के साथ खड़े हुए नहीं दिखें।

जम्मू कश्मीर

खनन पर प्रतिबंध आवश्यक

देश के अनेक इलाकों में नदियों में अवैध खनन की खबरें अक्सर आती रहती हैं। बड़ी संख्या में इससे जहां राजस्व का नुकसान होता है वहीं पर्यावरण को भी व्यापक क्षति होती है। जम्मू कश्मीर में कोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद नदी-नालों में चोरी छिपे खनन चिंताजनक है। खनन माफिया पत्थरों को नदी-नालों से निकाल कर स्टोन क्रशरों तक पहुंचाते हैं और फिर बिल्डिंग मेटीरियल के तौर पर माल तैयार किया जाता है। राज्य में यह धंधा तीन वर्षों से चल रहा है, जबकि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने खनन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। बावजूद इसके जम्मू के सीमावर्ती खौड़ और अखनूर में नदी, नालों और खड्डों से रेत बजरी का खनन बदस्तूर जारी है। जियोलॉजी एंड माइनिंग विभाग और पुलिस ने शुक्रवार को संयुक्त अभियान चलाते हुए रेत और बजरी से लदे 11 ट्रैक्टर ट्रालियां जब्त की हैं। विडंबना है कि जिला रियासी के दरिया चिनाब, कठुआ के रावी और जम्मू के तवी नदी से भी अवैध रूप से खनन हो रहा है। जियोलॉजी एंड माइनिंग विभाग ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई

प्रतीकात्मक फोटो।

से कतरा रहा है। विडंबना है कि विभाग ने तीन वर्षों में यदाकदा ही कोर्ट के निर्देश का अनुपालन किया। राज्य के पुनर्गठन और अनुच्छेद 370 हटने के बाद से राज्य के तमाम विभागों की जवाबदेही तय हो चुकी है। भ्रष्टाचार पर भी अब लगाम लगनी शुरू हो गई है। ऐसे में विभागीय अधिकारियों की कोशिश है कि अपनी साफ छवि पेश की जाए। पूर्ववर्ती सरकारों के नेताओं ने जिस प्रकार से राज्य को लूटा है, उसकी बानगी का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य को 80 हजार करोड़ रुपये विकास राशि उपलब्ध करवाई। विडंबना है कि नेताओं और नौकरशाहों ने राशि का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए ज्यादा किया। नेताओं और नौकरशाहों ने स्वार्थ की खातिर पर्यावरण को भी नहीं बक्शा। पर्यावरण संरक्षण को लेकर कोर्ट के निर्देश का भी अनुपालन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। रेत, बजरी, कंकर की बढ़ती मांग देखते हुए खनन माफिया रात के अंधेरे में तवी, बसंतर, झज्जर, चिनाब दरिया आदि से खनन कर रहा है। पुलिस की मिलीभगत से यह धंधा धड़ल्ले से जारी है। तवी नदी के आसपास स्टोन क्रशर पर नकेल कसने के लिए अब जियालॉजी एंड माइनिंग विभाग ने सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला तो किया, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। प्रशासन को चाहिए कि मामले को गंभीरता से लें। इससे पर्यावरण संरक्षण भी खतरे में है।

शिवनवरात्रि पर महाकाल सुन रहे हरि कथा, 111 साल पुरानी है परंपरा

जागरण विशेष ▶ अवंतिकानाथ को नारदीय संकीर्तन से हरि कथा सुनाने की परंपरा निभाता आ रहा कानड़कर परिवार

राजेश वर्मा, उज्जैन

- बाबा महाकाल के आंगन में छाया है शिवनवरात्रि का उल्लास
- भस्मारती से लेकर रात्रि तक गूंज रहीं शिव स्तुतियां और हो रहे भजन-कीर्तन

हरि अनंत हरि कथा अनंता... कहहिं सुनहीं बहुबिधि सब संता...। हरि अनंत हैं और उनकी कथा भी। संत उनकी कथाओं को बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। यह बात राजाधिराज बाबा महाकाल के प्रांगण में चरितार्थ हो रही है। बाबा के आंगन में इन दिनों शिवनवरात्रि का उल्लास छाया हुआ है। तड़के भस्मारती से लेकर रात्रि तक शिव स्तुतियां और भजन गूंज रहे हैं। मगर संध्या के समय श्रीरामचरितमानस की चौपाइयां भी सुनाई दे रही हैं।

राम कथा के प्रसंग संगीतबद्ध होकर श्रोताओं में आध्यात्मिकता का संचार कर रहे हैं। शिव को राम प्रिय हैं और राम को शिव। इसलिए 13 फरवरी से प्रारंभ शिवनवरात्रि के इन नौ दिनों में अवंतिकानाथ को नारदीय संकीर्तन से हरि कथा सुनाने की परंपरा है। ज्ञात इतिहास में यहां भगवान महाकाल को यह कथा सुनाने की परंपरा 111 साल पुरानी है। इंदौर के कानड़कर परिवार के सदस्य यह रीत निभाते आए हैं।

इस शिवनवरात्रि पर मंदिर प्रांगण के एक चबूतरे पर खड़े होकर रमेश श्रीराम कानड़कर भगवान को कथा श्रवण करा रहे हैं। रमेश अपने परिवार की नौवीं पीढ़ी के सदस्य हैं, जो महाकाल मंदिर में कथा सुना रहे हैं। प्रतिदिन शाम 4 से 6 बजे तक कथा का आयोजन होता है।

80 वर्षीय कानड़करजी ने बताया भगवान नारदजी जिस प्रकार खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ हरि नाम संकीर्तन करते रहते हैं, उसी प्रकार खड़े होकर संकीर्तन पद्धति से हरि कथा का वाचन किया जाता है। नारदीय संकीर्तन कथा के 11 खंड हैं। भगवान महाकाल की प्रेरणा से कथा खंडों में से कुछ का वाचन किया जाता है। भक्तों को भी कथा श्रवण में आनंद आता है। कानड़कर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। परिवार की परंपरा को निभाने के लिए प्रतिवर्ष अपने राजा अवंतिकानाथ की सेवा में उपस्थित होते हैं। इससे उन्हें आत्मीय सुख भी मिलता है।

ज्ञात इतिहास में यह परंपरा 111 साल पुरानी है। किंतु मान्यता है कि श्रुत परंपरा में यह त्रेता युग से चली आ रही है। पुजारी प्रदीप गुरु के अनुसार दंत कथाओं में उल्लेख मिलता है कि हनुमानजी जब अवंतिकापुरी में आए थे तब शिवनवरात्रि के दौरान उन्होंने भी संकीर्तन कथा का श्रवण किया था। प्रसिद्ध च्योतिर्विद पं. आनंद शंकर व्यास ने बताया शिवनवरात्रि में भगवान महाकाल को नारदीय संकीर्तन से हरि कथा सुनाने की परंपरा स्टेट के जमाने से चली आ रही है। कानड़कर परिवार के सदस्य इस परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं। दक्षिण भारत में नारदीय संकीर्तन से कथा करने की परंपरा है। भगवान महाकाल को यह कथा अतिप्रिय है।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

शिवनवरात्रि उत्सव का कार्यक्रम

महाकाल मंदिर में 13 फरवरी से शिवनवरात्रि के रूप में शिव विवाह का उल्लास छाया है। प्रतिदिन सुबह भगवान का विशेष अभिषेक पूजन कर, संध्या आरती में विभिन्न रूपों में श्रृंगार किया जा रहा है। 21 फरवरी को महाशिवरात्रि पर त्रिकाल पूजा होगी। 22 फरवरी को तड़के 4 बजे भगवान का सप्तधान रूप में श्रृंगार होगा और सात प्रकार के धान अर्पित किए जाएंगे। इसके बाद भगवान के शीश पर सवामन फूल व फलों से बना सेहरा सजाएंगे। सुबह 10 बजे तक भक्तों को सेहरे के दर्शन होंगे। सुबह 11 बजे पुजारी भगवान के सिर से सेहरा उतारेंगे। दोपहर 12 बजे साल में एक बार दिन में होने वाली भस्मारती होगी। इसके साथ ही नौ दिवसीय शिवनवरात्रि उत्सव का समापन होगा।

राम के साथ शिव से जुड़े प्रसंग भी कथा में...

रमेश श्रीराम कानड़कर बताते हैं कि वह श्रीराम के साथ शिवकथा के प्रसंगों को भी संगीतबद्ध कर गाते हैं। रामजन्म, शिवपार्वती विवाह आदि प्रसंगों को संकीर्तन के माध्यम से श्रवण कराया जाता है। परंपरा निभाने में आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है।

कथा श्रवण कराते रमेश श्रीराम कानड़करजी। नईदुनिया

चार साल में 7 हजार से 10 करोड़ पर पहुंचाया कारोबार

बृजेंद्र वर्मा, भोपाल

संडे बॉक्स

भोपाल के युवा उद्यमी जुबेर मोहम्मद ने 15 की उम्र में महज सात हजार रुपये से गार्डनिंग का छोटा सा काम शुरू किया था, जो आज सफल कंपनी के रूप में स्थापित हो चुका है। कंपनी की झोली में आज दस करोड़ के प्रोजेक्ट हैं। इस शानदार सफलता से पहले दो बार उन्हें असफलता भी झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी। जुबेर ने पहले फूड और रिटेल बिजनेस शुरू किया था, जो पैसों की कमी से चल नहीं पाया। इसके बाद उन्हें साल 2015 में गार्डनिंग का काम शुरू करने का विचार आया।

उस समय उनकी उम्र 15 वर्ष थी। घर वालों ने भी पढ़ाई पर ध्यान लगाने को कहा। जुबेर ने परिवार के सदस्यों को ताने सुने, लेकिन अपने ऊपर इन्हें हावी नहीं होने दिया। उन्हें तो बस सफल व्यवसायी बनना था। जुबेर ने बताया कि तब उन्होंने महज सात हजार रुपये जुटाए और गार्डनिंग का काम शुरू कर दिया। इस बिजनेस की संभावनाओं का उनका आकलन सही साबित हुआ और बात बन गई।

जुबेर बताते हैं कि वह सात हजार रुपये उन्होंने केवल प्रचार पर खर्च किए। गार्डनिंग की अवधारणा से शहरवासियों को रूबरू कराने और इसके प्रति लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर मार्केटिंग की। ऑर्डर मिलने लगे। वर्तमान में जुबेर

भोपाल स्थित पैराडाइज गार्डन प्लेनेट प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर जुबेर मोहम्मद।

मोहम्मद की पैराडाइज गार्डन प्लेनेट प्राइवेट लिमिटेड फर्म अनेक प्रोजेक्ट हासिल कर चुकी है। सागर जिले में एक बड़ी टाउनशिप में गार्डनिंग का प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल है।

पैराडाइज गार्डन की बेवसाइट पर 450 लोग अपने घरों के सामने खाली जमीन, टैरिस व बालकनी में गार्डनिंग कराने के लिए एडवांस बुकिंग कर चुके हैं। जुबेर ने बिजनेस भले ही 2015 में शुरू कर दिया था, लेकिन अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन कुछ माह पहले ही कराया है। जुबेर बताते हैं कि माता-पिता पुलिस में हैं। चार भाई-बहनों में वे सबसे छोटे हैं और इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर के छात्र हैं। कहते हैं, माता-पिता का कहना था कि इंजीनियर बनूं, इसलिए इंजीनियरिंग भी कर रहा हूं।

चार्ट बनने के बाद भी मिलेगी खाली बर्थ की जानकारी

प्रेमनारायण द्विवेदी, गोरखपुर

ट्रेन में बर्थ के लिए यात्रियों को टीटीई के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। बर्थ खाली होने पर टीटीई को टिकट बुक करना होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए आइआरसीटीसी (इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन) ने आरक्षित टिकटों के चार्ट को ऑनलाइन करना शुरू कर दिया है। इससे चार्ट बनने के बाद भी यात्रियों को खाली बर्थ की जानकारी मिल जाएगी।

- टीटीई से मिलकर बुक करा सकेंगे टिकट, ऑनलाइन होने लगे चार्ट

यात्री अंतिम चार्ट बनने के बाद इस नई व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा चार्ट बनने के बाद और ट्रेन छूटने से आधे घंटे पहले तक करंट टिकट की ऑनलाइन बुकिंग भी कराई जा सकेगी। इसके लिए करंट काउंटर पर नहीं जाना पड़ेगा। ट्रेन छूटने के निर्धारित समय से चार घंटे पहले प्रथम चार्ट बन जाता है। ट्रेन छूटने के निर्धारित समय से आधा घंटे पहले अंतिम चार्ट बन जाता है। खास बात यह है कि इस सुविधाजनक व्यवस्था को खुद रेलमंत्री पीयूष गोयल सोशल मीडिया के माध्यम से आमजनों तक पहुंचा रहे हैं।

अब ऐसे चार्ट देखने की नहीं पड़ेगी जरूरत। फाइल

ऐसे चेक करें चार्ट

- आइआरसीटीसी की वेवसाइट या मोबाइल एप पर लॉगिन करना होगा
- लॉगिन के बाद सामने आने वाले चार्ट या वेकेंसी बॉक्स पर क्लिक करना होगा
- सर्वर री-डायरेक्ट होकर रिजर्वेशन चार्ट के सर्वर पर चला जाएगा
- ऑप्शन में ट्रेन नंबर, डेट और स्टेशन का नाम दर्ज करना होगा
- सबमिट करने के बाद कोच और खाली बर्थों की जानकारी सामने होगी
- उपभोक्ता करंट रिजर्वेशन कॉलम में जाकर टिकट बुक करा सकेंगे

हैक तो मैं भी हो सकती हूं : सोफिया

जागरण संवाददाता, वाराणसी

- आइआइटी-बीएचयू में मीडिया से रूबरू हुई ह्यूमनायड रोबोट
- कहा, रक्षा संग चिकित्सा क्षेत्र में साबित हो रही उपयोगिता

बीएचयू आइआइटी के विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पढ़ाने वाली ह्यूमनायड रोबोट सोफिया जितनी 'इंटेलीजेंट' है, उतनी स्पष्टवादी भी है। वाराणसी में शनिवार को जब उससे पूछा गया कि क्या वह भी हैक हो सकती है, तो उसने बड़ी ही तत्परता से 'हां' में जवाब दिया। सोफिया ने साफगोई से कहा कि वह भी अन्य कंप्यूटर डिवाइस की तरह ही है, जिसे इंसान हैक कर सकता है।

दुनिया की पहली नागरिकता प्राप्त ह्यूमनायड रोबोट सोफिया ने बीएचयू स्थित स्वतंत्रता भवन सभागार में शनिवार को मीडिया के सवालों के जवाब दिए। उसने बताया कि भविष्य में ह्यूमनायड रोबोट जंग के मैदान के साथ ही सरहदों की निगरानी में भी सैनिकों का स्थान ले सकते हैं। इससे इंसानी जिंदगी को होने वाली क्षति काफी हद तक कम की जा सकती है। सोफिया ने बताया कि ह्यूमनायड रोबोट इंसानी जिंदगी में कई तरह से अपनी उपयोगिता साबित कर रहे हैं।

कई देश ह्यूमनायड रोबोट को हथियारों से लैस करने की दिशा में काम कर रहे हैं, तो कुछ एंड्रॉयड रोबोट पर काम कर रहे हैं, जो भविष्य में मानव सैनिकों का स्थान ले सकेंगे। इससे जहां सुरक्षा के नाम पर होने वाले भारी-भरकम खर्च में कटौती होगी, वहीं इंसानी जिंदगी को भी सुरक्षित किया जा सकता है। इसके अलावा नए प्रयोग भी आसानी से हो सकेंगे।

सोफिया से पूछे गए सवाल व उनके जवाब

क्या भविष्य में ह्यूमनॉइड रोबोट से मानव जाति को किसी प्रकार का खतरा हो सकता है?
नहीं, हम लोग मानव की सहायता के लिए ही प्रोग्राम हुए हैं। कभी मानव के लिए खतरा नहीं बन सकते।

क्या हम रोबोट को मानव शरीर की सर्जरी करते हुए भी देख पाएंगे।
बिल्कुल, वर्तमान में खूब 'रोबोट असिस्ट सर्जरी' की जा रही है, जो 94 फीसद तक सफल है। भविष्य में यह सौ फीसद सफल हो सकती है।

पर्यावरण एवं जल प्रदूषण को लेकर सोफिया किस तरह मदद कर सकती है?
मैं लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करूंगी। हमें पर्यावरण को बचाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऐसे उत्पादों का उपयोग करना होगा, जो रिसाइकल हो सकें। हमें ऐसी चीजों से दूरी बनानी होगी, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं।

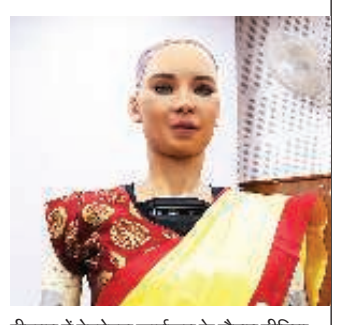

बीएचयू में टेक्नेक्स कार्यक्रम के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देती सोफिया। जागरण

पर्यावरण सुधार के लिए किस तरह के प्रयास की जरूरत है?
सरकार को अपनी नीतियों और विचारों दोनों में परिवर्तन लाना होगा। जब पर्यावरण के प्रति विचार बदलते हैं तो उसका असर नीतियों पर भी होता है। जब नीतियां अच्छी होती हैं तो सभी पर्यावरण के प्रति ज्यादा सजग होते हैं।

आठ घंटे में बदल जाएगा फूलों का रंग...

पंकज दुबे, रायपुर

छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में फूल विभाग के अंतर्गत एमएससी फाइनल की छात्रा मेघना कश्यप ने टिनटिंग पद्धति से कट फ्लावर वाले सफेद फूलों को मनचाहा रंग देने में सफलता पाई है। पहला प्रयोग उन्होंने रजनीगंधा के फूलों पर किया। वर्तमान में इस प्रक्रिया में आठ घंटे लग रहे हैं, जिसे कम करने में वे जुटी हुई हैं। खास बात यह कि विदेश में इस प्रक्रिया के लिए जहां महंगे केमिकल उपयोग में लाए जाते हैं, मेघना की तकनीक में सिर्फ घरेलू सामानों का उपयोग होता है। यह तकनीक फूलों की खेती करने वाले किसानों के लिए लॉटरी से कम नहीं है। इससे उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के कुछ किसान इस पद्धति को बतौर प्रयोग भी कर रहे हैं। मेघना बताती हैं कि रंग-बिरंगे फूल उन्हें बचपन से आकर्षित करते थे। इसीलिए कॅरियर के लिए भी इसे ही चुना। उन्होंने बताया, खाने का तरल रंग, साइट्रिक एसिड दो ग्राम, 250 मिलीलीटर पानी, थोड़ा शक्कर को मिलाकर घोल तैयार करते हैं। इसे 37 डिग्री सेल्सियस तक उबालकर गुनगुना होते तक ठंडा कर घोल को कांच के गिलास या फूलदान में रखते हैं। इसके बाद चाकू की सहायता से फूल के डंठल में चीरा लगाकर घोल में डाल देते हैं। तीन घंटे में ही फूल रंग बदलने लगता है।

फूल के साथ मेघना कश्यप। नईदुनिया

20.75 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया है अंटार्कटिका स्थित सेमूर द्वीप पर ब्राजीली वैज्ञानिकों ने नौ फरवरी को। इसने 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले जनवरी 1982 में साइनी द्वीप पर 19.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ था।

परिवार ने रोका पर मनप्रीत दीवार फांद कर हॉकी के मैदान पर पहुंचा

चर्चित चेहरा

कमल किशोर, जालंधर

कहते हैं किसी इंसान को जितना चाहे रोक लो, लेकिन उसके सितारे उसे उसके ट्रैक पर ले ही आते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ पंजाब के मनप्रीत सिंह के साथ, जिनके परिवार ने उन्हें हॉकी खेलने से लगातार रोका, लेकिन वह इसी खेल के लिए बने थे। तभी तो वह न केवल भारतीय टीम के कप्तान बने, बल्कि बीते दिनों वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी होने का खिताब हासिल कर इसे पाने वाले पहले भारतीय भी बने...

हॉकी के इतिहास में जो अब तक न हुआ, वो अब हुआ। बीते दिनों भारत की राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी घोषित किया। वह यह खिताब हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। टीम को लगातार सफलता की ओर ले जा रहे मनप्रीत से अब एक और इतिहास बनाने की उम्मीद लगाए बैठा है देश, और वो है ओलंपिक में मेडल। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि पंजाब के जालंधर से निकला यह खिलाड़ी इस मुकाम तक कैसे पहुंचा... और वो भी तब जब परिवार का कोई भी सदस्य उनके हॉकी खेलने के पक्ष में नहीं था। दरअसल, मनप्रीत के दो बड़े भाई अमनदीप सिंह और सुखराज सिंह हॉकी खेलते थे। शुरू-शुरू में मनप्रीत अपने भाइयों को खेलते हुए देखने के लिए मिट्ठापुर के खेल मैदान में पहुंच जाते थे। भाइयों को देखकर मनप्रीत में भी हॉकी खेलने की इच्छा बढ़ने लगी। परिवार नहीं चाहता था कि सात-आठ साल की उम्र में मनप्रीत हॉकी खेले। परिवार के सदस्यों को चिंता सताती थी कि मैदान में मनप्रीत को किसी प्रकार की चोट न लग जाए, इसलिए मैदान से दूर रखने की कोशिश की। कई बार उनको घर में बंद रखने की कोशिश की गई, लेकिन वह काफी जिद्दी थे और किसी न किसी तरह घर से भागकर मैदान में पहुंच जाते। परिवार से बचकर चोरी छिपे हॉकी खेलते। उनकी हॉकी के प्रति जिद ऐसी थी कि वह कई बार घर की दीवार फांदकर मैदान में पहुंचते थे। उन्होंने आठ साल की उम्र में हॉकी स्टिक थाम ली थी। हॉकी पकड़ने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और इस खेल में एक के बाद एक नए मुकाम हासिल करते गए। मनप्रीत सिंह का कहना है कि टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना उनका लक्ष्य है। शादी के सवाल पर हंसकर बोले, शादी तो एक दिन हो ही जाएगी, अभी पूरा फोकस केवल मिशन ओलंपिक पर है। ओलंपिक के बाद शादी के बारे में सोच सकता हूं।

हॉकी के जुनून से रिश्तेदार हो जाते थे नाराज: भाई सुखराज सिंह ने कहा कि मनप्रीत में हॉकी का जुनून ऐसा था कि वह रिश्तेदारों के घरों में होने वाले कार्यक्रमों में कम जाता था। कार्यक्रमों के कुछ दिन पहले कोई हॉकी का टूर्नामेंट होता था तो वह किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होता। बस टूर्नामेंट की तैयारी को प्राथमिकता देता।

19 साल की उम्र में भारत के लिए खेलना शुरू किया: मनप्रीत ने 19 साल की उम्र में भारत के लिए खेलना शुरू कर दिया था। साल 2011 में भारत के लिए खेलना शुरू किया और साल 2012 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अभी तक 260 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। साल 2014 में एशिया के जूनियर प्लेयर ऑफ द ईयर के खिताब से उन्हें नवाजा गया। इससे पहले साल 2013 हुए हॉकी जूनियर विश्व कप में मनप्रीत भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के कप्तान बने।

नए चेहरों को मिल रहा मौका, बेहतर कर आगे बढ़ रहे युवा: मनप्रीत सिंह ने दैनिक जागरण से फोन पर बातचीत में कहा कि दोनों भाइयों को देखकर हॉकी खेलना शुरू किया था। पहली से छठी कक्षा तक मिट्ठापुर के गुरु नानक पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद सरकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाडोवाली रोड में दसवीं तक पढ़ाई की। इसी दौरान सुरजीत हॉकी एकेडमी को ज्वाइन कर लिया। एकेडमी के झिलमिल और मिट्ठापुर के कोच बलदेव सिंह से कोचिंग ली। डीएवी कॉलेज में बीए आर्ट्स की पढ़ाई के साथ-साथ डीएवी कॉलेज की हॉकी टीम में शामिल था। प्रो. मनु सूद उस समय कोच थे। मनप्रीत ने बताया कि टीम में नए चेहरों को मौका मिल रहा है। जो खिलाड़ी बेहतर कर रहा है वही टीम में जगह बना रहा है। अगर खिलाड़ी अनुशासन के साथ बेहतर प्रदर्शन करें तो टीम ओलंपिक के फाइनल तक पहुंच सकती है। उम्मीद है कि इस बार टीम देश का 40 वर्ष का सूखा खत्म कर पदक जीतकर लौटेगी। भारत ने ओलंपिक में आखिरी पदक 1980 में मॉस्को में जीता था। इसके बार भारत ने आठ बाद ओलंपिक में हिस्सा लिया, लेकिन एक बार भी पदक जीतकर नहीं ला पाई। टीम उत्साह और सकारात्मकता के साथ मैदान में उतरेगी। उम्मीद है कि हम इस ओलंपिक में पदक जरूर जीतेंगे।

कई खिताब किए अपने नाम

साल 2014 में ग्लासगो में हुए कॉमन वेल्थ गेम्स में रजत पदक, इसी साल हुए एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक, लंदन में हुई हॉकी चैंपियनशिप में रजत पदक, साल 2017 में एशिया कप में स्वर्ण पदक, 2017 में हॉकी वर्ल्ड लीग कांस्य पदक, साल 2018 चैंपियनशिप ट्राफी में रजत पदक जैसे कई खिताब हासिल कर चुके हैं।

बेटा कर रहा है देश का नाम रोशन अब ओलंपिक में स्वर्ण की चाहत

मनजीत कौर फाइल

मनप्रीत की मां मनजीत कौर ने कहा कि बेटे में हॉकी खेलने की ललक थी। मना करने के बावजूद रुका नहीं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड मिला है, इससे बड़ी खुशी मां के लिए क्या हो सकती है। अब बेटा ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन कर स्वर्ण जीतकर लाए।

चोट न लग जाए इसलिए रोकते थे

मनप्रीत के बड़े भाई सुखराज सिंह ने कहा कि वह स्वयं राज्य स्तर तक हॉकी खेल चुके हैं। मनप्रीत दोनों भाइयों को हॉकी खेलते देखता था। एक दिन वह भी हॉकी स्टिक हाथ में पकड़ कर मैदान में पहुंच गया। कई बार हॉकी खेलने से मना किया, लेकिन इसकी जिद्द के आगे परिवार वालों की एक न चली। दीवार फांद कर मैदान में खेलने के लिए पहुंच जाता था। हम बस उसे चोट लगने से बचाना चाहते थे, लेकिन आज मनप्रीत ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड हासिल किया है तो गर्व महसूस हो रहा है।

सुखराज सिंह फाइल

11 की उम्र में सुरजीत की शरण में

सुरजीत मिट्ठा फाइल

मनप्रीत 11 साल की उम्र में कोच सुरजीत मिट्ठा की शरण में चले गए थे। सुरजीत बताते हैं कि मनप्रीत सिंह कम शरारती था। खेल में अधिक ध्यान देता था। उसके अंदर मैच पलटने की क्षमता थी। जब वह सुरजीत एकेडमी का हिस्सा था तो उसमें हॉकी का जुनून देखने लायक था। मनप्रीत खेलने के लिए घर से चोरी मिट्ठापुर के खेल मैदान में पहुंच जाता था। फिर परिवार वाले उसको देखने के लिए मैदान में पहुंच जाते थे।

कैंसर को मात दे क्रिकेट के मैदान में खिला कमल

उभरता सितारा

निशांत चौधरी, देहरादून

उत्तराखंड के युवा क्रिकेटर कमल कन्याल। साभार : स्वजन

जिंदगी में ऐसे दौर कई बार आते हैं, जब लगता है सबकुछ खत्म हो गया, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सवेरे से ठीक पहले ही रात सबसे काली होती है। उस अंधेरे के खत्म होने के बाद शुरू होता है नया सवेरा, नई जिंदगी। कुछ ऐसी ही कहानी है उत्तराखंड के युवा क्रिकेटर कमल कन्याल की, जिन्होंने कैंसर के अंधेरे से बाहर निकल क्रिकेट के मैदान पर ऐसा रंग जमाया कि इस उभरते खिलाड़ी के प्रदर्शन को देख हर कोई उनकी प्रतिभा और जज्बे को सलाम करने लगा...

कैंसर का नाम सुनते ही लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हताशा में जिंदगी खत्म समझने लगते हैं, लेकिन हौसले के बल पर कैंसर जैसी बीमारी को मात देकर अपने सपनों को मंजिल दिलाई जा सकती है। इसे सच साबित कर दिखा है उत्तराखंड के युवा क्रिकेटर कमल कन्याल ने। कमल ने न सिर्फ अपनी बीमारी का डटकर मुकाबला कर जिंदगी की जंग जीती, बल्कि फिर से मंजिल की ओर कदम बढ़ाए और सफलता की मिसाल बन गए। बाएं हाथ के बल्लेबाज कमल अब मैदान पर रनों की बारिश कर रहे हैं। गत गुरुवार को कमल कन्याल ने रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र के खिलाफ उत्तराखंड के लिए डेब्यू किया। बारामती के भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्टेडियम में खेले गए इस मैच में कमल ने 160 गेंदों पर 101 रन की पारी खेली। इस पारी में 17 चौके शामिल थे। रणजी में अपनी पहली ही पारी में शतक जमाने वाले वह उत्तराखंड के पहले बल्लेबाज बने।

मूल रूप से नैनीताल जिले के गौलापार में रहने वाले कमल कन्याल ने 2013-14 में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। तब उनकी उम्र महज 13 वर्ष थी, लेकिन इसके एक वर्ष बाद उनकी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी। शुरुआत में घर वालों को लगा कि शायद इसकी वजह पढ़ाई के साथ क्रिकेट का अतिरिक्त बोझ है, मगर 2015 में परेशानी तब ज्यादा बढ़ गई, जब उनकी प्लेटलेट्स कम होने लगीं। परेशानी को बढ़ता देख पिता कमल को डॉक्टर के पास ले गए। खून की जांच कराई तो उसकी रिपोर्ट ने कमल समेत पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। पता चला कि कमल को ब्लड कैंसर है, जो पहली स्टेज में था। यह रिपोर्ट किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। इसके बाद उन्हें नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां करीब एक साल उनका इलाज चला।

डॉक्टरों से एक ही सवाल: कमल के पिता सेवानिवृत्त हवलदार उमेश कन्याल बताते हैं कि कैंसर के इलाज के दौरान कमल डॉक्टरों से बस एक ही सवाल पूछता था, 'मैं ठीक होकर क्या दोबारा क्रिकेट खेल पाऊंगा?' इस पर डॉक्टरों का जवाब होता कि दवाइयां अपना काम कर रहीं हैं। इस उम्र में शरीर जल्द ठीक होता है। भरोसा रखो, तुम जरूर क्रिकेट खेलोगे। डॉक्टरों की दवा और दुआ का ही असर है कि कमल उत्तराखंड की रणजी टीम में खेलने लगे।

दो साल तक रहे क्रिकेट से दूर: कैंसर के चलते कमल दो वर्ष तक क्रिकेट से दूर रहे। वर्ष 2018 में पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद उन्होंने फिर एक बार बैट पकड़ा और मैदान की ओर चल पड़े। इसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने उत्तराखंड की टीम से खेलना शुरू कर दिया। क्रिकेट के गुर वह अपने कोच मनोज भट्ट से सीख रहे हैं।

दोहरा शतक वाले उत्तराखंड के पहले बल्लेबाज: कमल ने उत्तराखंड की अंडर-19 टीम से खेलते हुए वीनू मांकड व कूच बिहार ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 2019-20 में 14 मैचों में 932 रन बनाए, जिसमें एक दोहरा शतक भी शामिल है। ऐसा करने वाले वह उत्तराखंड के एकमात्र बल्लेबाज हैं। कमल को इस प्रदर्शन के आधार पर रणजी ट्रॉफी टीम में चुना गया है। उत्तराखंड के लिए पारी की शुरुआत करने वाले कमल ने अपने पहले ही मैच में शतक जड़ा। ऐसा करने वाले भी वह उत्तराखंड के इकलौते बल्लेबाज हैं।

प्रचार से दूर पर्दे के पीछे के महारथी

इनसे मिलिए

रघुवरशरण, अयोध्या

बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन का एलान किया तो लंबे समय से चला आ रहा इंतजार खत्म हो गया और इसी के साथ सुर्खियों में आ गए उस ट्रस्ट के सदस्य। इन्हीं में से एक नाम है डॉ. अनिल मिश्र, जो पेशे से हैं होम्योपैथी चिकित्सक...

डॉ. अनिल मिश्र जागरण

तरक्की के रास्ते पर संघर्ष कभी जाया नहीं जाता, जबकि सेवा और समर्पण ही अलग पहचान-मुकाम दिलाते हैं। मिसाल की दुनिया में इन लाइनों को बार-बार ऐसे ही नहीं दोहराया जाता। नजीर के रूप में जब भी कोई शख्स उभरता है, उसका पूरा व्यक्तित्व इन चंद शब्दों से गढ़ा-मढ़ा पाते हैं हम। चूंकि, देश में इन दिनों चर्चा का केंद्र राम मंदिर निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, इसलिए हर कोई हर कोई उसके बारे में जानने को उत्सुक है। खासकर पहली बार बनाए गए सदस्यों के बारे में। वे कौन हैं? क्या खासियत है? यह ठीक है कि ट्रस्ट की घोषणा के बाद सदस्यों के बारे में बहुत सी जानकारियां सामने आ चुकी हैं। काफी कुछ लिखा गया है, मगर उनके चुनाव की वजह में छिपे तमाम ऐसे पहलू हैं, जिनके दम पर उन्हें यह जिम्मेदारी मिली है। ट्रस्ट के उन्हीं सदस्यों में एक डॉ. अनिल मिश्र के बारे में हम आपको बताते हैं। कहने को पेशे से होम्योपैथी के चिकित्सक हैं। आरएसएस के समर्पित कार्यकता हैं, मगर स्वभाव से सरल और रोम-रोम में समाया है एक ही भाव, सेवा और सिर्फ सेवा...।

लंबे इंतजार के बाद गठित 15 सदस्यीय श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में रामनगरी से तीन चेहरे लिए गए हैं। अयोध्या राजपरिवार के मुखिया बिमलेंद्र मोहन मिश्र, निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्रदास सहित और आरएसएस के प्रांत कार्यवाह, होम्योपैथी के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. अनिल मिश्र। डॉक्टर साहब, वैसे तो मूलरूप से आंबेडकरनगर के ग्राम पतोना निवासी हैं। जौनपुर के पीडी बाजार स्थित जयहिंद इंटर कॉलेज से माध्यमिक स्तर की पढ़ाई की। फिर डॉ. बृजकिशोर होम्योपैथिक कॉलेज में पढ़ने फैजाबाद आ गए। डॉक्टरी की पढ़ाई में कुछ दिन ही बीते थे कि होम्योपैथी को एलोपैथी के समानांतर प्रतिष्ठा दिलाने का आंदोलन छिड़ गया। अनिल मिश्र भी आंदोलन में कूद पड़े, जिसके चलते उन्हें जेल तक जाना पड़ा। यह उस दौर की बात है, जब देश आपातकाल में जकड़ चुका था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के प्रचारक भी थोक के भाव जेल जा रहे थे। बंदी जीवन के ही दौरान अनिल मिश्र भी संघ के संपर्क में आए। इनमें संगठन के स्थापित चेहरों में शुमार स्वर्गीय रमाशंकर उपाध्याय और प्रताप नारायण मिश्र जैसे लोग शामिल थे। फिर क्या, उन्हीं से प्रेरित होकर डॉ. मिश्र ने भी अपना जीवन संघ को समर्पित करने की ठानी।

मेडिकल की लड़ाई के चलते आठ माह बाद जेल से छूटे डॉ. मिश्र का जीवन पूरा बदल चुका था। अब वे करियर की बजाए राष्ट्र के लिए जीने की सोचने लगे। हालांकि, उन्होंने होम्योपैथी की पढ़ाई जारी रखी, लेकिन केंद्र में संघ कार्य ही रहा। दोहरी जिम्मेदारी के बीच 1981 में उन्होंने होम्योपैथी से स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली। साथ ही संघ कार्यकर्ता के रूप में भी पुख्ता पहचान बना ली। नगर शाखा कार्यवाह और मुख्य शिक्षक की भूमिका में प्रभावी छाप छोड़ी। इसी के परिणामस्वरूप बीती सदी के अंतिम दशक के मध्य में एक ओर उन्हें संघ का जिला संपर्क प्रमुख बनाया गया, तो दूसरी ओर चिकित्सा अधिकारी के तौर पर वह शासकीय सेवा में चयनित हो गए। चिकित्सक की भूमिका में प्रभावी मौजूदगी दर्ज कराने वाले डॉ. मिश्र शहर में संघ के प्रतिनिधि के तौर पर स्थापित हुए। दो दशक पूर्व संघ में अवध प्रांत का गठन होने के साथ उन्हें प्रांतीय सह कार्यवाह का दायित्व सौंपा गया। 2005 में जब प्रांत कार्यवाह के चुनाव की बेला आई, तो डॉ. मिश्र सबकी पसंद बनकर उभरे। वक्त के साथ संघ नेतृत्व की निगाह में वह लगातार बने रहे। करियर में भी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते गए। एक वर्ष पूर्व उन्हें होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड का रजिस्ट्रार नामित किया गया।

डॉ. अनिल मिश्र को संघर्ष पूर्ण जीवन के सफर का सबसे बड़ा पुरस्कार गत पांच फरवरी को मिला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए गठित प्रतिष्ठापूर्ण राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट गठन का एलान किया। देश के चुनिंदा 15 लोगों में डॉ. अनिल उसका अहम हिस्सा बनाए गए हैं। अपने मिजाज के अनुरूप ट्रस्टी बनने पर भी वह शांत हैं। ट्रस्ट का सदस्य बनाए जाने के पीछे की वजह पूछे जाने पर सिर्फ इतना कहते हैं, 'इस बारे में वे लोग ही बता सकते हैं, जिन्होंने हमारा चयन किया है...।'

...इनकी उम्र नहीं, इरादों के शिखर को देखिए

सुर्खियों में

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली

अगर हौसले बुलंद हों तो कठिन से कठिन डगर पर चलते हुए भी सफलता हासिल की जा सकती है। इस बात को सच कर दिखाया है मुंबई की 12 साल की काम्या कार्तिकेयन ने, जिन्होंने बीते दिनों माउंट अकांकागुआ पर तिरंगा लहराया। यह कीर्तिमान हासिल करने वाली वह दुनिया की सबसे युवा पर्वतारोही बनीं...

काम्या कार्तिकेयन फाइल

बड़ी से बड़ी सफलता इंसान के हौसले, जज्बे और जुनून पर निर्भर करती है, उम्र पर नहीं। इस बात पर खरी उतरती हैं मुंबई की काम्या कार्तिकेयन। 12 साल की काम्या गत दिनों तब सुर्खियों में आईं जब उन्होंने अर्जेंटीना की एंडीज पर्वतमाला में स्थित माउंट अकांकागुआ पर तिरंगा लहराया। यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत (6962) है। वह इस शिखर को फतह करने वाली दुनिया की सबसे युवा पर्वतारोही बनीं।

मुंबई के नेवी चिल्ड्रेन स्कूल में सातवीं की छात्रा काम्या जब महज तीन साल की थीं, तब उन्होंने लोनावाला (पुणे) में बेसिक ट्रैक पर चढ़ना शुरू किया था। नौ साल की उम्र में उन्होंने अपने माता-पिता के साथ हिमालयी क्षेत्र की कई चोटियों को फतह किया।

2021 तक एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम पूरा करने का लक्ष्य: काम्या के पिता एस. कार्तिकेयन भारतीय नौसेना में कमांडर हैं और उनकी मां शिक्षक हैं। काम्या 2021 तक एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम को पूरा करना चाहती हैं। इस ग्रैंड स्लैम को पूरा करने का मतलब है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के साथ दुनिया के सातों महाद्वीपों के शीर्ष शिखरों को फतह करना। अपने इस सफर में काम्या अब तक अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, यूरोप की माउंट एल्ब्रुस और ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोसुच्को पर भी चढ़ाई करने में कामयाबी हासिल कर चुकी हैं। अब लक्ष्य एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम है।

तेजी से बढ़ रही वाट्सएप यूजर्स की संख्या

2014 में फेसबुक ने 19 अरब डॉलर (1.33 लाख करोड़ रुपये) में वाट्सएप का जब अधिग्रहण किया तो लोगों को हैरानी हुई कि एक सोशल मैसेजिंग प्लेटफार्म होने के बाद उसी प्रकृति के दूसरे मंच से कंपनी को कितना फायदा होगा। हाल ही में वाट्सएप के एक्टिव मंथली यूजर्स की संख्या दो अरब को पार कर गई। अब 2.5 अरब यूजर्स के साथ फेसबुक ही इससे आगे है।

वाट्सएप यूजर बढ़े

हाल ही में सामने आया कि वाट्सएप यूजर्स की संख्या करीब दो अरब हो गई है और यह संदेशों के प्रसारण के लिए दूसरा सबसे बड़ा माध्यम बनकर सामने आ रहा है।

सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी

589 अरब डॉलर (करीब 41.23 लाख करोड़ रुपये) की कीमत से चीन की अलीबाबा को सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी के तौर पर जाना जाता है। चाइनीज अमेजन इसी तरह की सेवा प्रदत्त कंपनी है। इन्होंने भी इसी तरह का बिजनेस मॉडल पेश किया, जिसमें दोनों कंपनियों को मुख्यत: ई-कॉमर्स क्रियाकलापों के लिए जाना जाता है, लेकिन ये कंपनियां इसके इतर भी जैसे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सेवाएं भी उपलब्ध करवाती हैं। हालांकि, अलीबाबा को चाइनीज अमेजन के आकार तक पहुंचने में काफी दूरी नापनी होगी।

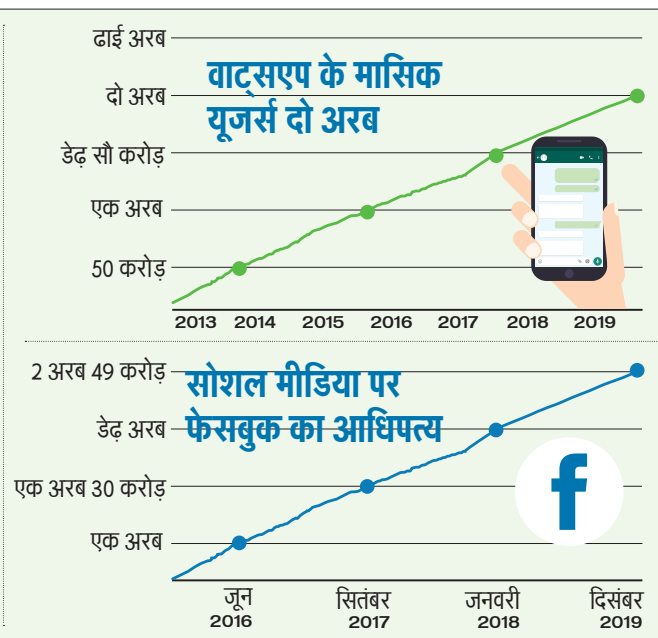

2.5 अरब यूजर्स के साथ फेसबुक शीर्ष पर, वाट्सएप के दो अरब यूजर्स

नेट टैक्स पर देय होगा जीएसटी लेट पेमेंट ब्याज

नई दिल्ली, प्रेट्र : अब जीएसटी देने में देरी की वजह से लगने वाला ब्याज नेट टैक्स पर देय होगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने बताया कि इसके लिए जरूरी कानूनी सुधार कर लिया गया है। जीएसटी भुगतान पर देरी के चलते लगने वाला ब्याज इस समय करीब 46,000 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। इसका भुगतान नहीं होने के चलते विभाग को कानूनी सुधार की जरूरत पड़ी है। नए नियमों के मुताबिक बकाया ब्याज का भुगतान मिलने में आसानी होगी।

वोडाफोन आइडिया मूल्यवान कंपनी है। इसमें निवेशकों की खासी दिलचस्पी हो सकती है। कंपनी को नए सिरे से निवेशकों की तलाश करनी चाहिए।
— राजीव चंद्रशेखर
राज्यसभा सदस्य

उम्मीद ▶ सीओएआइ ने कहा – टेलीकॉम संकट से निपटना सरकार के वश में, क्योंकि ...

सरकार के पास असीमित उपाय

दूरसंचार विभाग ने अलग-अलग जोन को भेजे भुगतान संबंधी नोटिस

नई दिल्ली, प्रेट्र : टेलीकॉम कंपनियों के संगठन सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआइ) ने कहा है कि सरकार सेक्टर का संकट दूर करने में पूरी तरह से सक्षम है। एजीआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीओएआइ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सरकार के पास विशाल शक्तियां और विकल्प मौजूद हैं, जिससे सेक्टर को संकट से उबारा जा सकता है। संगठन के डायरेक्टर राजन मैथ्यूज ने कहा कि जहां तक कंपनियों का सवाल है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन उन पर ही निर्भर करता है।

कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश (पश्चिम), राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश (पूर्व), पश्चिम बंगाल और दूसरे जोन में दूरसंचार विभाग के फील्ड ऑफिसर्स ने टेलीकॉम कंपनियों को तत्काल बकाया भुगतान करने को कहा है। कंपनियों से कहा गया है कि उन्हें बिना कोई अग्रिम नोटिस दिए लाइसेंस एग्रीमेंट के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश (पूर्व) के मामले में भेजे गए नोटिस के मुताबिक विभाग का दफ्तर बकाया भुगतान स्वीकार करने के लिए शनिवार को भी खुला रहा। इस दौरान सीओएआइ ने कहा कि इस समय टेलीकॉम कंपनियों के पास प्रशासनिक सुधार का बेहतरीन मौका है। मैथ्यूज ने बताया कि सेक्टर को संकट से उबरने और अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जल्द से जल्द प्रति यूजर राजस्व (आरपू) को 300 रुपये तक पहुंचाना होगा। गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को देनदारी नहीं चुकाने पर अवमानना की चेतावनी दी थी। सेक्टर पर करीब 1.47 लाख करोड़ रुपये की देनदारी है।

एजीआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद दूरसंचार विभाग ने भी एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को तुरंत भुगतान करने के लिए नोटिस दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होनी है और कंपनियों के पास उससे पहले तक का वक्त है।

टेलीकॉम कंपनियों पर कानूनी कार्रवाई संभव

नई दिल्ली, प्रेट्र : दूरसंचार विभाग समय पर एजीआर के तहत बकाया नहीं भरने पर टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक शनिवार और रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार को विभाग इन कंपनियों को नोटिस भेज सकता है। इस दौरान लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत जुर्माना जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। इससे पहले दूरसंचार विभाग टेलीकॉम कंपनियों को बकाया से संबंधित पांच नोटिस भेज चुका है। इनमें सबसे पहला नोटिस पिछले वर्ष 31 नवंबर को भेजा गया था। सबसे अंतिम नोटिस इसी महीने की 14 तारीख को भेजा गया था। जानकारी के मुताबिक सरकार फिलहाल टेलीकॉम कंपनियों को किसी तरह की राहत नहीं देगी।

वोडाफोन आइडिया पूंजी जुटाए या दिवालिया कानून का सामना करे

नई दिल्ली, आइएएनएस : राज्यसभा सदस्य राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि वोडाफोन आइडिया के पास इस समय सिर्फ दो विकल्प शेष हैं। कंपनी को अपना अस्तित्व बचाने के लिए पूंजी जुटानी चाहिए, अन्यथा दिवालिया कानून का सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वोडाफोन आइडिया एक मूल्यवान कंपनी है इसमें निवेशकों की रुचि हो सकती है। कंपनी को नए सिरे से निवेशकों की तलाश करनी चाहिए। गौरतलब है कि चंद्रशेखर पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के लिए बनाई गई संसदीय समिति के सदस्य भी हैं।

ई-वे बिल में फर्जीवाड़े पर कसेगी नकेल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- चारा घोटाले की स्टाइल में हो रहा ई-वे बिल में फर्जीवाड़ा, स्कूटी पर दिखा रहे दर्जनों टीवी सेट की ढुलाई
- ई-वे बिल लेने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग के वाहन सिस्टम से जुड़ना होगा अनिवार्य
- कर्नाटक में पायलट प्रोजेक्ट शुरू, जल्द ही देशभर में नया नियम होगा लागू

प्रतीकात्मक

बिहार के कुख्यात चारा घोटाले में जिस तरह कागजों में स्कूटर पर कई-कई टन माल की ढुलाई हुई थी, ठीक उसी तर्ज पर ई-वे बिल में फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा है। सरकार ने तय किया है कि ई-वे बिल जनरेट करने के लिए वाहन का ट्रांसपोर्ट विभाग सिस्टम से जुड़ना अनिवार्य होगा। सरकार की इस नई पहल को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कर्नाटक में शुरू कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत कारोबारी अगर किसी ऐसे वाहन के नाम पर ई-वे बिल जनरेट करना चाहता है जो 'वाहन पोर्टल' पर रजिस्टर नहीं है, तो यह संभव नहीं होगा। वाहन का पंजीकरण नंबर यानी आरसी एवं अन्य जानकारी वाहन पोर्टल पर होना जरूरी होगा, तभी उसके माध्यम से माल की ढुलाई की जा सकेगी।

जीएसटी टैक्स एक्सपर्ट एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रवीण शर्मा के मुताबिक अभी ई-वे बिल के नाम पर सरकार के साथ फर्जीवाड़े की काफी गुंजाइश है। तभी तो ऐसे-ऐसे बिल जनरेट हो रहे हैं जिसमें स्कूटी के नंबर पर 50-50 टेलीविजन सेट की ढुलाई दिखाई गई है। शर्मा ने बताया कि वाहन पोर्टल से जुड़ने के बाद इस प्रकार की धोखाधड़ी बंद हो जाएगी। सरकार के पास ई-वे बिल से जुड़े हर वाहन की पूरी जानकारी होगी। किस वाहन पर क्या माल गया, इसकी ट्रैकिंग भी आसान हो जाएगी। फर्जी बिलिंग बंद होने से सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।

परोक्ष कर विभाग के मुताबिक वाहन पोर्टल से नहीं जुड़े होने पर ई-वे बिल जनरेट करने के दौरान यूजर को अलर्ट मैसेज आएगा। ऐसे में उसे संबंधित सड़क परिवहन कार्यालय (आरटीओ) से संपर्क करना होगा। एक से ज्यादा आरटीओ के वाहन सिस्टम से जुड़ने पर भी ई-वे बिल जनरेट करने में परेशानी हो सकती है। ऐसे में गाड़ी की मूल आरसी के साथ आरटीओ में अपडेट करवाना होगा। सरकार के निर्देश के मुताबिक अगर गाड़ी वाहन पोर्टल पर पंजीकृत होने के बावजूद कारोबारी ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पा रहा हो तो वह वाहन हेल्पडेस्क की सहायता ले सकता है। गाड़ी का अस्थायी रजिस्ट्रेशन होने पर भी ई-वे बिल जनरेट किया जा सकता है।

पूंजी बाजार नियामक सेबी कर रहा प्रशासनिक सुधार की तैयारी

- कारोबारी हित में होगा नियम अनुपालन का प्रबंध
- निवेश सुरक्षित करने के लिए प्रशासनिक सुधार को बताया जरूरी

इस दिशा में सेबी सभी साझेदारों से सलाह में जुटा है। प्रतीकात्मक

नई दिल्ली, प्रेट्र : पूंजी बाजार नियामक सेबी प्रशासनिक ढांचे में सुधार की तैयारी कर रहा है। इन सुधारों के जरिये नियामक मौजूदा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा। इस दौरान कारोबारी हित का ख्याल रखते हुए नियमों के अनुपालन का प्रबंध किया जाएगा। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (एसओपी) और दूसरे तकनीकी दस्तावेज में सुधार के लिए सेबी सुझाव मांग रहा है।

सेबी के ढांचागत सुधारों के दौरान कारोबारी जगत में प्रयोग के जा रहे मानकों को ध्यान में रखा जाएगा। इसीलिए नियामक साझेदारों से सलाह ले रहा है। इसी क्रम में सेबी ने इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी (आइटी), रिस्क असेसमेंट और एसओपी सुधारों में सलाह के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआइ) आमंत्रित किए हैं।

सेबी ने बताया कि सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिए वह आधुनिक तकनीकी उपायों का प्रयोग कर रहा है। इसके लिए उसके पास कंप्यूटर, नेटवर्क, हार्डवेयर, सूचना सुरक्षा और आइटी वेंडर मैनेजमेंट का स्पष्ट प्रबंध है।

नियामक ने बताया कि सूचना प्रणाली, आइटी असेट और निवेश को सुरक्षित करने के लिए प्रशासनिक ढांचे में सुधार आवश्यक है। सुधार के क्रम में पहले से मौजूद नियमों की समीक्षा की जाएगी। सेबी घरेलू पूंजी बाजार के नियमन की जिम्मेदारी निभाता है और इससे संबंधित मामलों की देखरेख करता है।

इकोनॉमी में सुधार के संकेतों पर आरबीआइ ने लगाई मुहर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- शक्तिकांत दास ने कहा – बैंकों की तरफ से कर्ज देने की बढ़ रही रफ्तार
- ब्याज दरों में कटौती का और फायदा ग्राहकों को आने वाले समय में मिलेगा

आरबीआइ के मुताबिक यह बजट विकास को गति देने में सक्षम है। प्रतीकात्मक

इकोनॉमी में सुधार को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दावों पर शनिवार को आरबीआइ के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी अपनी मुहर लगा दी। बजट पेश होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआइ बोर्ड के साथ बैठक की। दास ने कहा कि बैंक की तरफ से कर्ज देने की रफ्तार बढ़ रही है जो इकोनॉमी में सुधार का संकेत है। आरबीआइ द्वारा ब्याज दरों में की जा चुकी कटौती का और फायदा ग्राहकों को आने वाले समय में मिलने जा रहा है। दास ने यह भी साफ किया कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश बजट के प्रस्तावों से महंगाई बढ़ने की कोई आशंका नहीं है। साथ ही राजकोषीय घाटा भी चिंताजनक नहीं है।

दास ने कहा कि उधार बढ़ने पर राजकोषीय घाटा बढ़ता है, लेकिन सरकार की वित्तीय स्थिति मजबूत है। चालू वित्त वर्ष और आगामी वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य तय किया गया है, वह फिस्कल रिस्पांसब्लिटी एंड बजट मैनेजमेंट (एफआरबीएम) कमेटी के प्रस्तावों के तहत ही है, उनके पारामीटर का उल्लंघन नहीं किया गया है। दास ने कहा कि सरकार की उधारी में खासी हिस्सेदारी स्मॉल सेविंग्स की है। इसलिए इसका महंगाई पर खास असर नहीं दिखेगा। वहीं कच्चे तेल की कीमतों में हो रही गिरावट से भी महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलेगी।

राजस्व की कमी को देखते हुए सरकार ने चालू वित वर्ष (2019-20) के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को जीडीपी का 3.3 फीसद से बढ़ाकर 3.8 फीसद कर दिया है। दास ने बताया कि यह कदम मौजूदा नियमों के तहत ही है जो दबाव के दौरान राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में 0.5 फीसद तक की बढ़ोतरी की इजाजत देता है।

वित्त मंत्री ने अपने संक्षिप्त बयान में कहा कि ग्रामीण इलाके में दिए जाने वाले कृषि ऋण पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्हें उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष में सरकार फार्म क्रेडिट के 15 लाख करोड़ के लक्ष्य को हासिल कर लेगी। चालू वित्त वर्ष के लिए फार्म क्रेडिट का लक्ष्य 13.5 लाख करोड़ रुपये है। मांग और बढ़ने पर सरकार उसे भी पूरा करने की क्षमता रखती है।

कृषि क्षेत्र को पर्याप्त कर्ज मुहैया कराएगी सरकार : सीतारमण

- अगले वित्त वर्ष सेक्टर को 15 लाख करोड़ रुपये कर्ज का लक्ष्य
- पीएम-किसान योजना के तहत 75 हजार करोड़ रुपये का हुआ आवंटन

प्रतीकात्मक

नई दिल्ली, प्रेट्र : बैंकों द्वारा कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को दिए गए लोन का सरकार नजदीकी निरीक्षण कर रही है। इस दौरान यह ध्यान में रखा जा रहा है कि इन क्षेत्रों के विकास के लिए जरूरी कर्ज में किसी तरह की रुकावट नहीं आने पाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले वित्त वर्ष में दिया जाने वाला कर्ज 15 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाने की उम्मीद जताई। उन्होंने बताया कि सरकार ने पीएम-किसान योजना के तहत 75 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

सीतारमण ने कहा कि कर्ज की सीमा बढ़ा दी गई है। हमें उम्मीद है कि यह स्थानीय स्तर की जरूरतों को मुताबिक होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में खपत में वृद्धि होगी, जिससे अधिक लोन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सरकार बैंकों द्वारा कृषि और ग्रामीण सेक्टर में दिए जाने वाले कर्ज पर नजदीकी नजर बनाए हुए है। चालू वित्त वर्ष में कृषि क्षेत्र को 13.5 लाख करोड़ रुपये कर्ज देने का लक्ष्य रखा गया है। आमतौर पर कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले लोन पर नौ परसेंट का ब्याज देय होता है। लेकिन सरकार ब्याज पर दो परसेंट की सब्सिडी देती है। इस तरह से तीन लाख रुपये के कर्ज पर प्रभावी ब्याज दर सात परसेंट होती है।

इस आम बजट में वित्त मंत्री ने नाबार्ड पुनर्वित्त योजना का विस्तार किए जाने की घोषणा की थी। इससे कृषि उपजों के परिवहन में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कृषि क्षेत्र को दिया जाने वाला कर्ज महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मध्यस्थता को संस्थागत स्वरूप देने की जरूरत

- सुप्रीम कोर्ट की जज इंदु मल्होत्रा ने जानकार मध्यस्थों की नियुक्ति पर दिया जोर

नई दिल्ली, एएनआइ : विभिन्न विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थता का रास्ता अपनाने पर गंभीरता से कदम उठाया जाना चाहिए। आज जरूरत है कि कामचलाऊ व्यवस्था के बजाय मध्यस्थता को संस्थागत स्वरूप दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा ने शनिवार को यह बात कही। जस्टिम मल्होत्रा 12वें अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता कॉन्क्लेव को संबोधित कर रही थीं। कॉन्क्लेव का आयोजन नानी पालखीवाला मध्यस्थता केंद्र (एनपीएसी) की ओर से हुआ था।

जस्टिस मल्होत्रा ने कहा कि मध्यस्थता कराने वाला जितना बेहतर होगा, मध्यस्थता का नतीजा भी उतना ही बेहतर होगा। इसलिए जरूरी है कि इस काम में प्रशिक्षित मध्यस्थों को लाया जाए। न्यायिक समीक्षा का दायरा बढ़ाने के बजाय मध्यस्थता कराने के लिए विषय के जानकार को चुने जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, 'घरेलू और विदेशी मध्यस्थता के मामलों के लिए दो कानून होने चाहिए, क्योंकि दोनों मामलों में व्यवस्था पूरी तरह अलग होती है। ऐसा नहीं होने से कई बार असमंजस की स्थिति बन जाती है।' वरिष्ठ वकील और एनपीएसी के डायरेक्टर अरविंद पी. दातार ने पूरी तरह संस्थागत मध्यस्थता पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी कंपनियों में संस्थागत मध्यस्थता की व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। लंदन के फाउंटेन कोर्ट चैंबर्स से जुड़ी ली-एन मुलकाही ने भी विशेषज्ञ मध्यस्थों का पूल बनाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि भेदभावरहित मध्यस्थता किसी भी व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है।

आर्थिक लक्ष्यों में पूंजी बाजार की महत्वपूर्ण भूमिका : ठाकुर

- ठाकुर ने कहा – पूंजी बाजार को लेकर लोगों का भरोसा बरकरार

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारतीय पूंजी बाजार मजबूत स्थिति में है। यह 2025 तक पांच लाख करोड़ डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य को पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ठाकुर ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर इकोनॉमी में पूंजी निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार जैसे कारकों से पूंजी बाजार प्रभावित नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर लोगों के विश्वास में कोई कमी नहीं आई है।

एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया (एएनएमआइ) को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय पूंजी बाजार दुनिया के दूसरे बड़े बाजारों के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि बाजार में निवेश को आसान बनाने के प्रयास लगातार चलते रहने चाहिए। पूंजी बाजार घरेलू बचत को इकोनॉमी में खपाते हैं और लंबी अवधि की संपत्ति का निर्माण करते हैं।

ठाकुर ने कहा कि सरकार पूंजी बाजार में सुधार के लिए दिए जाने वाले सुझावों का स्वागत करती है। स्टॉक मार्केट से संबंधित संस्थाओं को पूंजी बाजार नियामक सेबी से लगातार सलाह करनी चाहिए। नियमों को सरल बनाकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश समेत अन्य तरीकों को आकर्षित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

पांच लाख के डिपॉजिट इंश्योरेंस पर एसबीआइ नहीं लेगा चार्ज

प्रतीकात्मक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : बैंक में पांच लाख के डिपॉजिट इंश्योरेंस के लिए आम ग्राहकों को कोई चार्ज नहीं देना होगा। यह भरोसा देश के सबसे बड़े कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) के चेयरमैन रजनीश कुमार ने दिया है। इसी महीने की शुरुआत में पेश बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंक में डिपॉजिट इंश्योरेंस की एक लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की घोषणा की थी। मतलब अब अगर कोई बैंक फेल या दिवालिया हो जाता है तो पांच लाख रुपये तक की जमा राशि सरकार लौटाएगी। माना जा रहा था इस सीमा को एक लाख से पांच लाख करने पर बैंक ग्राहकों से इंश्योरेंस चार्ज वसूल कर सकता है।

शनिवार को एक कार्यक्रम में कुमार ने साफ किया कि एसबीआइ डिपोजिट इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ने पर अपने ग्राहकों से कोई चार्ज नहीं लेगा। उन्होंने बताया कि एसबीआइ पहले भी अपने ग्राहकों से डिपॉजिट इंश्योरेंस के नाम पर कोई चार्ज नहीं लेता था और आगे भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। पहले एसबीआइ डिपॉजिट इंश्योरेंस के लिए 3,000 करोड़ रुपये का भुगतान कर रहा था। पांच लाख रुपये की नई सीमा के बाद बैंक 3,600 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा।

बजट में विकास को गति देने के अधूरे प्रयास

नई दिल्ली, प्रेट्र : पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने आर्थिक विकास को गति देने के लिए हालिया बजट में सुझाए उपायों को अधूरा बताया है। पिछले वर्ष सितंबर तक वित्त मंत्रालय का हिस्सा रहे गर्ग ने शनिवार को कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए इसी महीने की शुरुआत में पेश बजट आर्थिक विकास को गति देने और बढ़ाने के प्रभावी उपाय करते नहीं दिख रहे हैं। एक ब्लॉग में गर्ग का कहना था कि बजट में व्यय के जो भी प्रावधान किए गए हैं, वे आर्थिक विकास को गति देने और राजकोषीय स्थिति को मजबूत करने में सक्षम नहीं हैं।

ब्लॉग में गर्ग ने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए पेश बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश के लिए सड़क, रेलवे और मेट्रो शहरों पर ही ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसी तरह, उद्योग और सर्विस सेक्टर को विकास देने के लिए किए गए उपाय भी पुराने हैं। इन उपायों से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा सकारात्मक असर दिखाई देने की उम्मीद नहीं है।

निवेश के मामले में सबसे बुरे समय के लिए भी तैयार रहें निवेशक

नासिम तालेब का 'आइडिया ऑफ ब्लैक स्वान' काफी मशहूर है। निवेशकों के लिए इसके बारे में एक बार फिर से जानना अच्छा रहेगा। यह समय भी इसके लिए बहुत माकूल है। इक्विटी निवेशक ऐसे माहौल में रहते हैं जहां विश्लेषक इस बात पर सहमत नहीं होते हैं कि किसी कंपनी की अनुमानित ईपीएस ग्रोथ 10.2 प्रतिशत रहेगी या 10.5 प्रतिशत। और अर्थशास्त्री जीडीपी नंबर को लेकर अलग-अलग राय रखते हैं। अब बात करते हैं वास्तविक दुनिया की। दुनिया की इकोनॉमी में कम से कम 16 प्रतिशत योगदान करने वाली इकोनॉमी की ग्रोथ पर ब्रेक लग सकता है या हो सकता है कि इकोनॉमी मंदी का शिकार हो जाए। और इसकी वजह ऐसी आपदा होगी जिसके बारे में लगभग 75 दिन पहले कोई जानता भी नहीं था।

अगर चीन में कोरोनो वायरस का प्रकोप इतनी ही तीव्रता के साथ बना रहा तो..। यहां है असली समस्या। इस वाक्य को पूरा करने का कोई तरीका नहीं है। वास्तव में यही है ब्लैक स्वान इवेंट। ब्लैक स्वान किसी ऐसी चीज से भी आगे की बात है जिसके होने की संभावना नहीं है। यह इस तरह का इवेंट है जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है या जिसकी मौजूदगी को लेकर संदेह भी नहीं हो सकता है। यह अनुमान और भविष्यवाणी के उन सभी तौर-तरीकों से परे है जिन पर हम भरोसा करते हैं।

पिछले कुछ सप्ताह में आपने आर्थिक दुनिया से जुड़ी खबरें पढ़ी होंगी। खबरों से इस बात का अनुमान लगाया गया है कि कोरोना वायरस के प्रकोप का ग्लोबल इकोनॉमी पर कितना असर होगा। वाल स्ट्रीट से जुड़े कुछ बड़े नामों ने भी इसके असर क बारे में आंकड़े दे दिए। एक सप्ताह पहले गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि ग्लोबल ग्रोथ पर इसका बहुत मामूली असर होगा। और इसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी की औसत ग्रोथ में 0.1 प्रतिशत से 0.2 प्रतिशत तक कमी आ सकती है। एजेंसी का कहना है कि जब तक हालात में बहुत बड़ा बदलाव नहीं होता है तब तक वायरस का असर चीन में कारोबार करने वाली कंपनियों तक ही सीमित रहेगा। ब्लैक स्वान के बारे में अनुमान लगाने की अपनी क्षमता को लेकर इस भरोसे पर सिर्फ हंसा जा सकता है। ब्लैक स्वान ऐसी घटना है जो उन घटनाओं से आगे की चीज है जिनके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। चीन सरकार के खुद के आंकड़ों में कोरोना वायरस के बारे में रिपोर्ट आने के बाद सात दिन में वायरस के मामलों और मौत की संख्या दोगुनी हो गई है।

धीरेंद्र कुमार, सीईओ
वैल्यू रिसर्च

बोनस

इक्विटी निवेश के नतीजों का ऊंट कब किस करवट बैठेगा, इसका अंदाजा लगाना विश्लेषकों और अर्थशास्त्रियों के लिए भी कठिन काम रहा है। अर्थशास्त्री भी एक ही घटना को अलग-अलग अंदाज से देखते हैं और उसकी उसी अंदाज में व्याख्या भी करते हैं। ऐसे में यह सवाल बेहद सहज है कि अगर कोई आकस्मिक घटना घटी, तो निवेशकों की प्रतिक्रिया क्या होगी और उन्हें क्या करना चाहिए। या यूं कहें कि अगर निवेशकों का सामना किसी 'ब्लैक स्वान' से हुआ तो वे कौन सी राह अपनाएं। ब्लैक स्वान यानी एकदम से उपज आई कोई ऐसी परिस्थिति जिसके असर के बारे में अनुमान लगा पाना मुश्किल ही नहीं, एक तरह से नामुमकिन है। मसलन, चीन से उपजे और कई देशों तक फैल गए कोरोना वायरस से पैदा हुई परिस्थिति, जिसका अंजाम क्या होगा किसी को नहीं पता। ऐसे में किसी भी निवेशक को क्या करना चाहिए...

ऐसी घटनाओं से सबक लेने का मतलब यह नहीं है कि हमारा अनुमान बेहतर होना चाहिए या सब कुछ इस बात से तय होगा कि अनुमान कितने सटीक हैं। इसके बजाए हमें यह समझ लेना चाहिए कि ऐसी घटनाएं जिनके बारे बारे में हमे कोई अंदाजा या अनुमान नहीं होगा समय समय पर होती रहेंगी। इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि ऐसी घटनाओं के सकारात्मक होने के बजाए नकारात्मक होने की संभावना ज्यादा है। मैं बता रहा हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं।

क्या ऐसी कोई घटना हो सकती है जो दुनिया के आर्थिक उत्पादन को सिर्फ एक साल में 10 प्रतिशत तक कम कर दे। इसका जवाब है हां। ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या इसका उलटा हो सकता है। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि जिससे दुनिया का आर्थिक उत्पादन एक साल में ही 10 प्रतिशत तक बढ़ जाए। नहीं। इस तरह का चमत्कार होने की संभावना नहीं के बराबर है। इस तरह की चीजें होने में यह बात बहुत मायने रखती है कि चीजें किस स्केल यानी पैमाने पर हो रही हैं। क्या एक इंडीविजुअल बहुत कम समय में अमीर बन सकता है। हां ऐसा दुनिया में रोज बहुत से लोगों के साथ होता है। लेकिन क्या ऐसा छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी या पूरे सेक्टर के साथ हो हो सकता है। या एक देश के साथ हो सकता है। या पूरी दुनिया के साथ हो सकता है। जैसे जैसे आप स्केल यानी पैमाना बढ़ाते चले जाते हैं तो ऐसा होने की संभावना कम होती चली जाती है। लेकिन संभावित नकारात्मक घटनाओं का असर हमेशा बड़ा होता है। ऐसे में बचत और निवेश करने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इसका जवाब बहुत सरल है। निवेशक को हमेशा इस बात को लेकर सतर्क रहना चाहिए कि अगर निवेश की दुनिया में अब तक की सबसे तेज गिरावट आ जाए तो क्या होगा। क्योंकि साल दर साल निवेश की रकम बढ़ती जाती है लेकिन बुरा समय या ऐसी नकारात्मक घटना जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा है कभी भी हो सकती है। इसके लिए तैयार रहें।

90.68 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में कनाडा में भारतीय मूल के दंपति को गिरफ्तार किया गया है, जबकि भारतीय मूल के ही एक व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया है। इन पर टैक्स अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने का आरोप है।

कोरोना की पहचान में जुटी 'बीमार' थर्मामीटर गन

कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों के बुखार का पता करने के लिए चीन में थर्मामीटर गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें बीमार के माथे पर एक गन लगाई जाती है। इसे पूरे चीन के चेक प्वाइंटों पर वितरित किया गया है। टोल बूथों, होटल, स्टोर्स और रेलवे स्टेशनों तक इसे वितरित किया गया है, जिससे सरकारी और आम लोग कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बुखार को माप सकें। हालांकि इस उपकरण की क्षमता को लेकर संदेह उठने शुरू हो गए हैं। शक्तिशाली सेंसर तकनीक के बावजूद चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों का कहना है कि सेंसर युक्त यह थर्मामीटर अप्रभावी रक्षा तंत्र साबित हुआ है।

ऐसे करता है काम

बुखार नापने वाले इस यंत्र को थर्मामीटर गन का नाम दिया गया है। यह डिवाइस इंफ्रारेड सेंसर से लैस है, जो किसी व्यक्ति की त्वचा के साथ संपर्क बनाए बिना ही उसके शरीर के तापमान को माप सकता है। हालिया वर्षों में वायरल के प्रकोप को रोकने की दिशा में यह देशों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा था।

2000 के बाद आया सामने

यह व्यापक रूप से साल 2000 में सामने आया। चीन में सार्स के प्रसार को धीमा करने और एक दशक बाद पश्चिम अफ्रीका में इबोला के प्रकोप को रोकने के लिए व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल किया गया।

चीनी भी हैं असंतुष्ट

चीनी सोशल मीडिया पर भी लोग इसे लेकर नाराज हैं। चेक प्वाइंट्स से गुजरने वाले लोगों की शिकायत है कि थर्मामीटर अवास्तविक रूप से बहुत कम तापमान दर्शाता है और अन्य परिस्थितियों में बहुत ज्यादा तापमान दिखाता है। एक शख्स ने वीबो पर लिखा कि थर्मामीटर गन सही नहीं है। एक सुरक्षाकर्मी ने लिखा कि मैं जानता हूं कि थर्मामीटर गन सही नहीं है। वह स्वयं जानता है कि यह असंगत है लेकिन यह प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यह औपचारिक है।

इस तरह नापता है तापमान

थर्मामीटर किसी व्यक्ति के शरीर की सतह से निकलने वाली गर्मी को मापकर तापमान बताता है। हालांकि अक्सर ऐसा होता है, जब इस उपकरण को चलाने वाले माथे के करीब सही ढंग से इसे पकड़ नहीं पाते हैं, जिसके कारण यह असामान्य रूप से कम या ज्यादा तापमान बताता है। नेब्रास्का विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा विशेषज्ञ जेम्स लॉलर के मुताबिक, यह उपकरण सटीक और विश्वास के काबिल नहीं है। इबोला संकट के समय पश्चिमी अफ्रीका की यात्रा के दौरान डॉ. लॉलर ने इंफ्रारेड थर्मामीटर का परीक्षण किया था। उन्होंने अस्पताल के बाहर और सड़कों पर चेक प्वाइंट्स पर इसका परीक्षण किया। इसमें प्रतिकूल नतीजे आए थे।

मांग बढ़ी, उत्पादन नहीं

थर्मामीटर गंस और इंफ्रारेड कैमरे की बढ़ती मांग के चलते दुनिया में इसकी कमी आ गई है। थर्मामीटर गन बनाने वाली कंपनी के पास सरकारी और निजी मांग बढ़ने के कारण यह अधिक महंगा हो गया है। शेनझेन में निर्माता एलिकन मेडिकल साल में 25 लाख थर्मामीटर गन बनाती है। इसके महाप्रबंधक मो यिंगचुन ने कहा कि यह चीन की कुछ चुनिंदा कंपनियों में से एक है, जो उत्पादन के उस स्तर को प्राप्त कर सकती हैं। फिर भी, कच्चे माल की लागत में वृद्धि और कई श्रमिक इस प्रकोप के चलते यहां पर नहीं हैं। इसका अर्थ है कि कंपनी पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर रही है। कीमतें सामान्य स्तर से तीन से पांच गुना तक बढ़ गई थीं, स्थानीय सरकारें पहले अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहती हैं।

नहीं है सटीक

उन्होंने कहा कि कंपनी के थर्मामीटर का उपयोग बच्चों की जांच के लिए घर के अंदर किया जाता है। इसका उपयोग केवल त्वरित जांच के लिए किया जाता है और पारंपरिक थर्मामीटर की तरह यह सटीक नहीं होता है।

स्रोत: न्यूयॉर्क टाइम्स

न्यूज गैलरी

सीपीईसी परियोजना पर काम करने को तुर्की तैयार

इस्लामाबाद : तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने कहा है कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) को तुर्की के उद्यमियों को बेहतर तरीके से समझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तुर्की सीपीईसी परियोजनाओं पर काम करने के लिए तैयार है। डॉन न्यूज के मुताबिक, इस्लामाबाद में पाकिस्तान-तुर्की व्यापार और निवेश फोरम में शुक्रवार को प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ बोलते हुए, एर्दोगन ने सीपीईसी का जिक्र किया। उन्होंने कहा, तुर्की को वे अवसर नहीं दिए जाते हैं, जो अन्य देशों को मिलते हैं।' उन्होंने कहा, उम्मीद है कि हम नए व्यवसायों के लिए दरवाजा खोलेंगे। हम अपने राजनीतिक संबंधों के स्तर पर पाकिस्तान और तुर्की के व्यापारिक संबंधों के स्तर को ऊपर उठाना चाहते हैं। (आइएएनएस)

पाकिस्तान में सड़क दुर्घटना में 12 लोगों की मौत

इस्लामाबाद : दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक नाले में यात्रियों से भरे वाहन के गिर जाने से महिलाओं और बच्चों समेत 12 लोगों की मौत हो गई और 23 से अधिक लोग घायल हो गए। 'एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की खबर के अनुसार दुर्घटना शुक्रवार को झाल मागसी जिले के बरेजा इलाके के पास खुजदार-झाल मागसी राजमार्ग पर हुई। वाहन की तेज गति के चलते चालक अपना नियंत्रण खो बैठा जिसके कारण वाहन नाले में जा गिरा। उपायुक्त शर्जील नूर ने बताया कि जिस वक्त यह घटना हुई उस समय ये पीड़ित एक विवाह समारोह में हिस्सा लेने के लिए लासबेला से झाल मागसी जा रहे थे। हादसे में 10 लोगों की तुरंत मौत हो गई जबकि दो लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। गंभीर घायल कुछ लोगों को सिंध के लाड़काना स्थित अस्पताल रेफर किया गया। (प्रेट्र)

अपने नागरिक निकालेंगे भारत-अमेरिका

निर्णय ▶ जापान में क्रूज पर फंसे हैं यात्री, भारत को आइसोलेशन अवधि खत्म होने का इंतजार

आज विशेष विमान जापान भेजेगा अमेरिका

टोक्यो, एजेंसियां : भारत और अमेरिका ने कोरोना वायरस संक्रमण की आशंका में जापान में क्रूज पर फंसे अपने नागरिकों को निकालने का फैसला किया है। जापान के योकोहामा बंदरगाह पर खड़े इस शिप से अमेरिका रविवार शाम को विशेष विमान के जरिये अपने नागरिकों को निकालने का काम शुरू करेगा। भारत इसके लिए आइसोलेशन अवधि खत्म होने (यानी बुधवार तक) का इंतजार करेगा। इस बीच शिप में मौजूद 67 और लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इस तरह क्रूज पर संक्रमित होने वालों की संख्या 285 हो गई है। सभी का जापान के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बता दें कि शिप में 138 भारतीय हैं। इनमें से 132 यात्री हैं जबकि छह चालक दल के सदस्य हैं।

भारतीय दूतावास ने कहा है कि वह आइसोलेशन की अवधि खत्म होने के बाद अपने नागरिकों को भारत लाने की जल्द से जल्द कोशिश करेगा। इस संबंध में वह जापान के दूतावास, शिप संचालक कंपनी और जहाज पर मौजूद भारतीय नागरिकों के लगातार संपर्क में है। दूतावास ने जहाज पर मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को ई-मेल भेजकर सभी तरह की मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। दूतावास ने अपने फेसबुक पेज पर भारतीय यात्रियों से अनुरोध किया है कि आइसोलेशन अवधि के दौरान वे जापान सरकार के स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का अनुपालन करें। भारतीय दूतावास ने कहा है कि चालक दल के जो तीन सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे, उनकी हालत में सुधार है। बता दें कि इस जहाज से पिछले महीने हांगकांग में एक यात्री उतरा था। बाद में उसके कोरोनावायरस के संक्रमित होने की पुष्टि हुई। इसीलिए पांच फरवरी को जब यह जहाज योकोहामा बंदरगाह पर पहुंचा तो किसी भी यात्री और चालक दल को उतरने नहीं दिया गया है और इसे 14 दिनों के लिए आइसोलेशन में रख दिया गया। इसमें 3711 लोग सवार हैं। जिसमें 3500 से ज्यादा यात्री हैं।

अमेरिका आने के बाद 14 दिनों तक आइसोलेशन में रहना होगा : टोक्यो स्थित अमेरिकी दूतावास ने क्रूज पर मौजूद अपने देश के नागरिकों को पत्र लिखकर हरसंभव मदद का भरोसा दिया है। उसका कहना है 'अमेरिकी नागरिकों को ले जाने के लिए रविवार शाम विशेष विमान जापान आएगा। आगे के इलाज और निगरानी के लिए आपसे उम्मीद की जाती है कि आप घर लौट आएं।' बता दें कि अमेरिका लौटने के बाद इन यात्रियों को 14 दिनों तक आइसोलेशन में रखा जाएगा। पत्र में बताया गया है कि आइसोलेशन में रखे जाने का फैसला निराशाजनक और परेशान करने वाला है, लेकिन बीमारी को फैलने से रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी है। पत्र में यह भी कहा गया है कि अगर कोई यात्री इस विशेष विमान से अमेरिका नहीं लौटना चाहता है तो ऐसी स्थिति में वह कुछ समय के लिए अमेरिका लौटने में असमर्थ होगा। इस पर अंतिम निर्णय सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का होगा। जापानी मीडिया के मुताबिक, जहाज में 400 से ज्यादा अमेरिकी यात्री हैं। खास बात यह है कि इस विमान से संक्रमित यात्री अमेरिका नहीं जा सकेंगे। जापान के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। बता दें कि यह विमान जापान से यात्रियों को लेकर कैलिफोर्निया के ट्रैविस एयरफोर्स बेस पर उतरेगा।

जापान में शनिवार को योकोहामा बंदरगाह से रवाना होती बस। यहां खड़े डायमंड प्रिंसेज क्रूज शिप पर 67 और लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। एपी

नोटों को भी आइसोलेशन में रखा गया

नोटों के जरिये कोरोना वायरस का संक्रमण लोगों तक नहीं पहुंचे, इसके लिए चीन के बैंकों ने नोटों को आइसोलेशन में रखना शुरू कर दिया है। यह जानकारी पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के डिप्टी गवर्नर फैन ई फेई ने दी। बैंकों से यह भी कहा गया है कि उद्यमियों को देने से पहले वह नोटों और सिक्कों को संक्रमण मुक्त करें। साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की खबर के मुताबिक अस्पतालों और जिन बाजारों में गीला काम होता है वहां से नकदी जमा की जा रही है और प्रचलन में लाने से पहले नोटों और सिक्कों को अल्ट्रावायलेट लाइट से संक्रमण मुक्त किया जा रहा है।

कोरोना वायरस से 67 हजार से ज्यादा संक्रमित

बीजिंग, प्रेट्र : जानलेवा कोरोना वायरस से चीन में मरने वालों की संख्या 1523 हो गई है। वहीं शुक्रवार को संक्रमण के 2641 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह संक्रमित होने वालों की संख्या चीन में 67 हजार से ज्यादा हो गई है। फ्रांस में कोरोना वायरस से पहली मौत की पुष्टि हुई है। यह वायरस के संक्रमण से एशिया से बाहर होने वाली पहली मौत बताई जा रही है। मिस्र में पहली बार एक व्यक्ति में संक्रमण का पता चला है। बीजिंग डेली के अनुसार, सरकार ने चेताया है कि छुट्टियों से लौटने के बाद लोग अपने घरों या आइसोलेशन में रहें अन्यथा उन्हें दंडित किया जाएगा। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि इसे कैसे लागू किया जाएगा और क्या यह विदेशियों पर भी लागू होगा? चीन में लगे यात्रा प्रतिबंधों और कारखानों के बंद होने से अभी भी सड़क पर आवागमन सामान्य दिनों की तुलना में बहुत कम है। चीन ने कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए अमेरिकी एंटीवायरल दवा, रेमेडिसविर के फील्ड ट्रायल को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। वहीं कई रोगियों का पारंपरिक चिकित्सा से भी इलाज किया जा रहा है।

फेसबुक ने निरस्त की ग्लोबल मार्केटिंग समिट : कोरोना वायरस का असर चीन और विश्व के कई ट्रेड फेयर और समिट पर पड़ा है। फेसबुक ने नौ से 12 मार्च के बीच सैन फ्रांसिस्को में होने वाली अपनी ग्लोबल मार्केटिंग समिट को निरस्त कर दिया है। वहीं मेलबर्न में अगले महीने होने वाले जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप में चीन की पूरी टीम हिस्सा नहीं ले सकेगी। बता दें कि चीन के लोगों के ऑस्ट्रेलिया में घुसने पर प्रतिबंध लगा है।

चीन का व्यवहार धूर्त देशों जैसा श्रेष्ठता क्रम के लिए खतरा

म्यूनिख, एपी : अमेरिका ने कहा है कि चीन दुनिया के श्रेष्ठता क्रम (वर्ल्ड ऑर्डर) के लिए खतरा पैदा कर रहा है। इसके लिए वह पश्चिमी देशों की जानकारियों की चोरी और छोटे पड़ोसियों को धमकाने से बाज नहीं आ रहा। चीन फायदा उठाने के लिए हर तरीका अपना रहा है, इसके लिए कोई भी मूल्य चुका रहा है। यह बात अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने जर्मन शहर म्यूनिख में सुरक्षा मामलों पर हो रहे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में कही है।

चीन के कटु आलोचक एस्पर ने रूस, उत्तर कोरिया और ईरान की तरह चीन को भी खतरनाक देश करार दिया। कहा, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय चीन को धूर्त देशों जैसा मानता है, जैसे कि उत्तर कोरिया और ईरान हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अभूतपूर्व गति से गलत दिशा में बढ़ रही है। वह अपने लोगों का उत्पीड़न कर रही है। गलत आर्थिक तौर-तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भरपूर मनमानी कर रही है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह कि वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सैन्य ताकत बढ़ा रही है। एस्पर ने कहा, अमेरिका चीन के साथ टकराव नहीं चाहता। वह कम्युनिस्ट देश के साथ बेहतर रिश्ते चाहता है। इसीलिए अमेरिका ने कोरोना वाइरस से जूझ रहे चीन की मदद के लिए वहां चिकित्सकीय सामग्री की आपूर्ति बढ़ा दी है।

बावजूद इसके चीन अपनी दीर्घकालिक रणनीति में बदलाव को तैयार नहीं है। इसलिए यूरोप और बाकी दुनिया के देशों को चीन के खतरे से लड़ने के लिए खड़े होना पड़ेगा। कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी शाखाएं, इनमें चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी भी शामिल है, देश की सीमा से बाहर अपनी गतिविधियां बढ़ा रही हैं। यूरोप सहित दुनिया के प्रमुख इलाकों में वे किसी भी तरह से और कोई भी मूल्य चुकाकर अपना उद्देश्य पूरा करना चाहती हैं। चीन का उद्देश्य 2035 तक अपनी सेना का पूरी तरह से आधुनिकीकरण करना है और इसके बाद 2049 तक वह एशिया पर अपना एकछत्र राज्य कायम करना चाहता है। तब वह दुनिया की अग्रणी सैन्य ताकत बनने की इच्छा रखता है। हम चीन से सामान्य व्यवहार चाहते हैं। इसके लिए चीनी सरकार को अपनी नीतियां और व्यवहार बदलना होगा।

▶ **फायदे के लिए हर तरीका अपना रहा और हर मूल्य चुका रहा : एस्पर**

मार्क एस्पर। फाइल

हुवावे के खतरे से नाटो को आगाह किया

रक्षा मंत्री एस्पर ने चीनी तकनीक दिग्गज हुवावे के खतरे से भी यूरोपीय देशों और बाकी दुनिया को आगाह किया। कहा कि उसका 5 जी मोबाइल नेटवर्क दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है। हुवावे कंपनी चीन की कुटिल रणनीति की पोस्टर चाइल्ड है। चीन उसके जरिये अपने बड़े उद्देश्यों को पूरा करना चाहता है। उसके जरिये दुनिया की सुरक्षा, तकनीक और आर्थिक जगत से जुड़ी जानकारियां पाना चाहता है। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो हुवावे को चीन के खुफिया तंत्र का छिपा हुआ मोहरा बता चुके हैं। उल्लेखनीय है कि अमेरिका के प्रमुख नाटो सहयोगी और प्रमुख यूरोपीय देश ब्रिटेन और फ्रांस हुवावे के 5 जी नेटवर्क को प्रतिबंधित न करने की घोषणा कर चुके हैं। अमेरिकी मंत्रियों के बयान इसी के मद्देनजर आए।

एफएटीएफ के फैसले के बाद रिहा हो सकता है हाफिज सईद

लाहौर, एएनआइ : दिखावे के लिए गिरफ्तार मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद को लेकर पाकिस्तान की नई चाल सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक, हाफिज सईद को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) के फैसले के बाद जेल से रिहा किया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि दो दिन पहले हाफिज को सुनाई गई सजा के फैसले में जानबूझकर ऐसी खामियां छोड़ी गई हैं, जिससे वह कभी भी रिहा हो सकता है।

बता दें कि लाहौर की आतंकवाद निरोधी अदालत ने गत बुधवार को हाफिज सईद को टेरर फंडिंग के दो मामले में दोषी पाया था और दोनों मामलों में साढ़े पांच-साढ़े पांच साल कैद की सजा सुनाई थी। अब उसके वकील ने इस फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के अनुसार, सईद के वकील का तर्क है कि एफएटीएफ के दबाव में उसके मुवक्किल को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा गिरफ्तारी का कोई और कारण नजर नहीं आता है। सूत्रों के हवाले से डॉन अखबार का कहना है कि विदेशी धरती के अलावा लश्कर-ए-तैयबा और सईद के नेतृत्व वाले जमात-उद-दावा ने पाकिस्तान के अंदर भी अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की है। जमात के नेतृत्व वाले लश्कर ने अफगान तालिबान और अलकायदा के साथ-साथ पंजाबी तालिबान में विकसित होने वाले तत्वों के साथ संबंध बनाए रखा है। पाकिस्तान में आतंकवादी समूहों पर मुकदमा चलाए जाने के बाद भी इनके नेता और दहशतगर्द नियमित रूप से आतंकी गतिविधियों से संलग्न रहते हैं, जो सईद के खिलाफ की गई कार्रवाई पर सवाल खड़ा करती है।

हाफिज सईद। फाइल

मनी लांड्रिंग मामले में नवाज शरीफ को कोर्ट में पेशी से छूट

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान की भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को मनी लांड्रिंग मामले में निजी तौर पर पेश होने से छूट दे दी है। वह इस समय लंदन में अपना इलाज करा रहे हैं। डॉन अखबार में शनिवार को छपी खबर के अनुसार, राष्ट्रीय जवाबदेही अदालत में अर्जी देकर 69 वर्षीय शरीफ ने चौधरी शुगर मिल्स मामले में निजी पेशी से छूट मांगी थी। अदालत ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए चिकित्सा के आधार पर उनको पेशी से छूट दे दी और मामले की सुनवाई 28 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने शरीफ और उनकी बेटी मरयम को चौधरी शुगर मिल्स से सीधा लाभ होने का आरोप लगाया है। इस मामले में गत अगस्त में मरयम को गिरफ्तार किया गया था। वह अभी जमानत पर हैं। जबकि शरीफ गत 19 नवंबर से लंदन में हैं। उनके वकील अमजद परवेज ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री की सेहत से जुड़ी रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई है। डॉक्टरों का मानना है कि शरीफ अभी पाकिस्तान की यात्रा करने के लिए पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं।

एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बना रह सकता है पाक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पाकिस्तान की एक अदालत ने अंतरराष्ट्रीय आतंकी हाफिज सईद को सजा सुना दी है। चीन, मलेशिया और तुर्की पाकिस्तान की मदद को तैयार हैं। लेकिन सवाल है कि क्या ये सारे उपाय और आश्वासन पेरिस में होने जा रही एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान को बचा लेंगे? एफएटीएफ यानी फाइनेंसिएल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक रविवार से शुरू होगी और चार दिनों तक चलेगी। पेरिस सम्मेलन में तय होगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखना है या उसे ब्लैक लिस्ट में डालना है। जानकारों की मानें तो पाकिस्तान का रिकार्ड अभी इतना बेहतर नहीं हुआ है कि वह निगरानी सूची (ग्रे लिस्ट) से बच निकले।

एफएटीएफ की तरफ से शनिवार को जारी एक सूचना में बताया गया है कि वह कोरिया, यूएई की तरफ से मनी लॉड्रिंग व आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए उठाये जाने वाले कदमों की समीक्षा करेगा। इसके साथ ही ईरान, पाकिस्तान व अन्य देशों की तरफ से वित्तीय ढांचे से जुड़े जोखिमों को दूर करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों को भी परखेगा। बताते चलें कि पाकिस्तान को दो वर्ष पहले ग्रे लिस्ट में डाला गया था और उसे आतंकी फंडिंग रोकने के साथ ही 50 तरह के कदम उठाने का निर्देश दिया गया था। ग्रे लिस्ट में जाने के बाद के बाद पाकिस्तान सरकार हरकत में आई और पिछले कुछ महीनों में उसकी तरफ से आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। उसने अपने बैंकिंग नियमों को भी सख्त बनाया है।

पाकिस्तान अगर एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में चला जाता तो उसके लिए वैश्विक कारोबार करना और विदेशी अनुदान प्राप्त करने की राह और मुश्किल हो जाएगी। कंपनियों के लिए वहां कारोबार करने की लागत बढ़ जाएगी।

उधर, भारत अपने इस रुख पर अडिग है कि पाकिस्तान की तरफ से अभी भी आतंक के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। हालांकि भारत के लिए यही संतोष की बात होगी कि पाकिस्तान फिलहाल ग्रे लिस्ट में ही बना रहे। ऐसा होने से उसे आगे भी आतंकी संगठनों के खिलाफ कदम उठाते रहना होगा। ब्लैक लिस्ट होने की स्थिति में पाक बड़े आर्थिक संकट में फंस सकता है जिससे वहां ज्यादा अस्थिरता आ सकती है। वह स्थिति भारत के लिए भी ठीक नहीं होगी।

चिंता मत करें, भारत अकेले सुलझा लेगा कश्मीर मसला : जयशंकर

म्यूनिख, प्रेट्र : चिंता मत करें। कश्मीर मसला भारत अकेले ही सुलझा लेगा। म्यूनिख सेक्योरिटी कांफ्रेंस में अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम की ओर से कश्मीर मसले के जिक्र पर भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने यह बात कही।

कांफ्रेंस के दौरान एक पैनल चर्चा में सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि कश्मीर मुद्दे को लोकतांत्रिक तरीके से हल करना किसी लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छी बात हो सकती है। रिपब्लिकन नेता ने कहा, 'जब कश्मीर की बात आती है, तो मैं नहीं जानती कि यह मसला कैसे हल होगा। लेकिन एक बात सुनिश्चित करना चाहती हूं कि दोनों लोकतंत्र (भारत और पाकिस्तान) निश्चित तौर पर हल निकाल लेंगे।' इस पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने जवाब देते हुए कहा, 'चिंता मत कीजिए सीनेटर। एक ही लोकतांत्रिक देश है, जो इस मसले को सुलझाएगा और आप जानती हैं कि वह कौन सा देश है।'

प्रासंगिकता खो रहा संयुक्त राष्ट्र

चर्चा के दौरान एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, 'पहले की तुलना में संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता बहुत कम हो गई है। यह बहुत चौंकाने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि 75 साल पुरानी बहुत कम चीजें ही आज पहले जितनी बेहतर रह गई हैं। निश्चित तौर पर इस मामले में कुछ किया जाना चाहिए।' उन्होंने बहुपक्षीय व्यवस्था कमजोर होने और पश्चिमी देशों का दबदबा बढ़ने का जिक्र भी किया। विदेश मंत्री ने वैश्विक स्तर पर राजनीतिक संतुलन बनाने पर जोर दिया।

एस जयशंकर। फाइल

कश्मीर पर दोहरा चरित्र

गूगल मैप पर भारत में देखो तो कश्मीर साथ, अन्य कहीं से देखने पर विवादित, अमेरिकी समाचार पत्र ने किया पर्दाफाश

भारत की सीमाओं से छेड़छाड़ कर रहा गूगल

वॉशिंगटन, प्रेट्र : इंटरनेट पर सर्वाधिक लोकप्रिय सर्च इंजनों में से एक गूगल मैप्स ने एक अजीब करामात की है। यह देशों की सीमाएं जगह के हिसाब से बदलकर दिखाता है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत के बाहर से देखने पर यह कश्मीर की सीमा (आउटलाइन) को 'डॉटेड लाइन' के रूप में 'विवादित' बताता है।

अखबार के मुताबिक, पाकिस्तान से देखने पर कश्मीर विवादित दिखता है, जबकि भारत से देखने पर यह भारत का हिस्सा दिखता है। इस तरह गूगल मैप्स कश्मीर की सीमा को इस आधार पर बदल देता है कि आप सर्च किस देश में कर रहे हैं।

वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, अर्जेंटीना से लेकर यूके और ईरान तक दुनिया की सीमा अलग-अलग दिखती है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि आप उसे कहां से देखते हैं। ऐसा इसलिए कि गूगल और अन्य ऑनलाइन मैपमेकर्स उन्हें बदल देते हैं। अखबार का यह भी कहना है कि गूगल का कॉरपोरेट मिशन तो दुनिया भर की सूचनाओं को व्यवस्थित करना है, लेकिन यह अपनी इच्छा से तोड़-मरोड़ भी देता है। चूंकि गूगल मैप्स की मोबाइल मैप्स बाजार में 80 फीसद भागीदारी है और एक अरब से ज्यादा यूजर्स हैं, इसलिए दुनिया भर में लोगों की धारणा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कैलिफोर्निया स्थित मुख्यालय वाली इस कंपनी में मैप्स पर फैसले लेने वाले गोपनीयता बरतते हैं, यहां तक कि वैसे लोगों से भी जो हर दिन डिजिटल एटलस को आकार देते हैं। अखबार ने इस मामले से जुड़े कुछ अनाम लोगों के हवाले से कहा है कि यह न सिर्फ इतिहास और स्थानीय कानूनों को प्रभावित करता है, बल्कि राजनयिकों, नीति निर्माताओं तथा अपने अधिकारियों पर भी असर डालता है। पंद्रह साल पहले लांच किया गया गूगल मैप्स सर्च इंजन के सर्वाधिक उपयोग में आने वाले उत्पादों में से एक है।

▶ **गूगल मैप्स सर्च इंजन के सर्वाधिक उपयोग में आने वाले उत्पादों में से एक है**

कंपनी प्रवक्ता की सफाई

अखबार की रिपोर्ट पर कंपनी प्रवक्ता ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि विवादित क्षेत्र को दर्शाने की गूगल की सुसंगत और वैश्विक नीति है तथा वैश्विक डोमेन पर विवादित या देशों के दावों को दर्शाने के लिए काफी सुविधाएं हैं। यह किसी एक पक्ष के दावे का न तो समर्थन करता है और न पुष्टि करता है। उन्होंने कहा, 'हम अपने यूजर्स को यथासंभव समृद्ध, अद्यतन तथा सटीक मैप्स उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध हैं। हम सीमाओं को हमारे डाटा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए नए डाटा या आधिकारिक सूत्रों से मिले डाटा या भौगोलिक स्थितियों में बदलाव के आधार पर अपडेट करते हैं- जैसा कि 2014 में तेलंगाना राज्य के मामले में किया गया था।'

अफगानिस्तान में शांति समझौते पर 29 फरवरी को हस्ताक्षर करेंगे अमेरिका और तालिबान

वाशिंगटन, आइएएनएस: अफगानिस्तान में 19 साल से जारी खूनी संघर्ष के खत्म होने के आसार बढ़ गए हैं। अमेरिका और तालिबान में शांति समझौते को लेकर सहमति बन गई है। दोनों पक्ष 29 फरवरी को समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। इस करार में हफ्ते भर के संघर्ष विराम, सभी अमेरिकी सैनिकों की वापसी और अफगान सरकार के साथ शांति वार्ता शुरू करने का खाका भी शामिल किया गया है।

अमेरिका और तालिबान की शांति वार्ता में शामिल सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्षों में 29 फरवरी को शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने को लेकर सहमति बनी है। इस समझौते के लिए ट्रंप प्रशासन लंबे समय से तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है। एक सूत्र ने कहा, 'दोनों पक्ष इस बात को परिभाषित करने में सफल हुए कि हिंसा में कमी लाना आवश्यक होगा।'

वार्ता में अफगान सरकार शामिल नहीं : तालिबान के विरोध के चलते शांति वार्ता में अफगान सरकार को शामिल नहीं किया गया है। तालिबान, अफगान सरकार को अमेरिका की कठपुतली मानता है।

अफगानिस्तान में 11 हजार अमेरिकी सैनिक : अफगानिस्तान में अमेरिका के अभी करीब 11 हजार सैनिक हैं। अमेरिका में 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप ने वादा किया था कि वह युद्ध को खत्म करेंगे और अमेरिकी सैनिकों को वापस लाएंगे।

वार्ता की उतार-चढ़ाव भरी राह : अमेरिका और तालिबान के बीच दिसंबर 2018 से कतर की राजधानी दोहा में वार्ता चल रही थी। लेकिन इस वार्ता में कई बार उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गत सितंबर में जब दोनों पक्ष समझौते के करीब पहुंच गए थे, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के हमले में एक अमेरिकी सैनिक की मौत पर यह वार्ता रद कर दी थी। इसके बाद गत दिसंबर में वार्ता फिर पटरी पर लौटी थी। अफगानिस्तान में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे के पास आतंकी हमले के बाद वार्ता दोबारा रुक गई थी, लेकिन नए साल से दोनों पक्षों में बातचीत दोबारा पटरी पर आई।

करार में इन अहम बातों पर सहमति

- तालिबान और अफगान सरकार के बीच दस मार्च से बातचीत शुरू होगी
- अमेरिका 29 फरवरी से दस मार्च के बीच पांच हजार तालिबान बंदियों को रिहा करेगा
- 18 महीने की अवधि के दौरान अमेरिकी सैनिकों की वापसी होगी
- अमेरिका और तालिबान हफ्ते भर के लिए संघर्ष विराम करेंगे

भारतीय गेंदबाजों के हुनर से कीवी परेशान

न्यूजीलैंड एकादश की टीम 235 रनों पर ऑलआउट, भारत ने 87 रनों की बढ़त ली

हैमिल्टन, प्रेट्र : जसप्रीत बुमराह और मुहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड एकादश के खिलाफ भारत के अभ्यास मैच के दूसरे दिन शानदार गेंदबाजी की और वेलिंग्टन में होने वाले पहले टेस्ट से पहले घरेलू टीम को चेताया कि मेजबानों के लिए चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। न्यूजीलैंड की टीम 74.2 ओवर में 235 रन पर सिमट गई, जिसमें बुमराह (11 ओवर में 18 रन देकर दो विकेट) और शमी (10 ओवर में 17 रन देकर दो विकेट) ने परिस्थितियों का अच्छा इस्तेमाल किया। भारत ने पहली पारी में 263 रन बनाए थे और दूसरी पारी में उसने बिना विकेट गंवाए 53 रन बना लिए हैं। इस आधार पर भारत ने कुल 87 रनों की बढ़त हासिल कर ली है और रविवार को आखिरी दिन का मैच खेला जाएगा।

उमेश यादव (13 ओवर में 49 रन देकर दो विकेट) और नवदीप सैनी (15 ओवर में 58 रन देकर दो विकेट) ने काफी ओवर फेंके लेकिन वे टीम के दो मुख्य तेज गेंदबाजों की तरह अपने स्पेल से बल्लेबाजों को परेशान नहीं कर सके। मुख्य कोच रवि शास्त्री अपने तेज गेंदबाजों की लय देखना चाहते थे और बुमराह व शमी ने बादलों भरे मौसम में काफी अच्छी गेंदबाजी की। उमेश और सैनी ने अपने पहले स्पेल में काफी फुल लेंथ गेंद फेंकी। वहीं बुमराह ने उछाल हासिल करते हुए बल्लेबाजों को परेशान किया और तीन छोटे स्पेल में गेंदबाजी की जबकि शमी ने दो स्पेल डाले। शमी ने सीम को दोनों तरफ से फेंकने पर ध्यान लगाया। शमी ने तीन और बुमराह ने दो विकेट लिए।

हैमिल्टन के सेडन पार्क में शनिवार को अभ्यास मैच में विकेट लेने के दौरान भारतीय गेंदबाज मुहम्मद शमी ● एएनआइ

बुमराह ने किया यंग और एलेन को आउट : बुमराह ने विल यंग (02) को कोण लेती गेंद से बल्ला छुआने के लिए उकसाया और रिषभ पंत ने इस कैच को लपकने में जरा गलती नहीं की। इसके बाद उन्होंने फिन एलेन (20) का विकेट झटका।

लंच के बाद शमी के दूसरे स्पेल ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया जिसमें सीनियर अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जिमी नीशाम शामिल थे जो उनकी अतिरिक्त उछाल लेती गेंद का सामना नहीं कर सके। इससे पहले उन्होंने क्रीज पर जमे हुए हेनरी कूपर (68 गेंद में 40 रन) को फुल लेंथ गेंद पर आउट किया। इसके बाद दोनों अंतिम सत्र में गेंदबाजी के लिए नहीं उतरे। इसके बाद उन्हें आराम दिया गया।

मयंक और शॉ जमे : अंत में आधा घंटा काफी मनोरंजक रहा जिसमें स्कॉट कुगेलीजन और ब्लेयर टिकनर की गेंदों को पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल ने काफी पीटा। इन दोनों ने आसानी से रन जुटाए। भारत ने लगातार दूसरे दिन शॉ-अग्रवाल की सलामी जोड़ी को उतारा जिससे शुभमन गिल को शायद अपने टेस्ट पदार्पण के लिए इंतजार करना होगा। शॉ 35 और अग्रवाल 23 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं।

स्कोर बोर्ड

टॉस : भारत (बल्लेबाजी) — भारत 263 (78.5 ओवर)

न्यूजीलैंड एकादश — 235 (74.2 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
विल यंग का. पंत बो. बुमराह	02	08	00	00
रचिन रवींद्र का. पंत बो. यादव	34	67	07	00
टिम सेफर्ट का. पंत बो. शमी	09	26	01	00
फिन एलेन बो. बुमराह	20	55	03	00
हेनरी कूपर का. अग्रवाल बो. शमी	40	68	06	00
टॉम ब्रूस बो. सैनी	31	34	04	00
डेरिल मिशेल का. शॉ बो. यादव	32	65	05	00
जिमी नीशाम बो. शमी	01	08	00	00
डैन क्लेवर बो. सैनी	13	50	01	00
स्कॉट कुगेलीजन नाबाद	11	36	01	00
ईश सोढ़ी का. पुजारा बो. अश्विन	14	32	02	00

अतिरिक्त : (बा-13, लेबा-9, नोबॉ-3, वा-3) 28

कुल : 74.2 ओवर में 235 रन पर ऑलआउट, **विकेट पतन** : 1-11 (यंग, 2.2), 2-36 (सेफर्ट, 9.4), 3-70 (रचिन, 21.6), 4-82 (एलेन, 29.2), 5-133 (ब्रूस, 39.3), 6-155 (विहारी, 72.6), 7-161 (नीशाम, 48.6), 8-204 (मिशेल, 61.3), 9-213 (क्लेवर, 65.1)

गेंदबाजी : बुमराह 11-3-18-2, उमेश 13-1-49-2, शमी 10-5-17-3, सैनी 15-2-58-2, अश्विन 15.2-2-46-1, जडेजा 10-4-25-0

भारत दूसरी पारी — 59/0 (7 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
पृथ्वी शॉ नाबाद	35	25	05	01
मयंक अग्रवाल नाबाद	23	17	04	01

अतिरिक्त : (वा-1) 1, कुल : 7 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 59 रन,

गेंदबाजी : ब्लेयर 3-0-19-0, कुगेलीजन 3-0-34-0 स्कॉट जॉनस्टन 1-0-6-0

सिर्फ दो-चार मैच बाद ही बुमराह के प्रदर्शन पर सवाल उठाना सही नहीं : शमी

हैमिल्टन : न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में जसप्रीत बुमराह कोई विकेट नहीं ले पाए। इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या चोट से वापस करने के बाद बुमराह की लय कहीं खो गई है। हालांकि टीम इंडिया के उनके साथी गेंदबाज मुहम्मद शमी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। शमी ने कहा कि सिर्फ एक-दो मैचों में अलग प्रदर्शन के बाद लोग जसप्रीत बुमराह के कई अनगित मैच-जिताऊ खेल को कैसे भूल सकते हैं। बुमराह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन वनडे की सीरीज में कोई विकेट हासिल नहीं किया। इसके बाद कई लोग उनके खेल पर कुछ सवाल उठाने लगे थे। न्यूजीलैंड इलेवन के खिलाफ अभ्यास मैच के दूसरे दिन के खेल के बाद शमी ने कहा कि मैं समझ सकता अगर लोग कुछ अरसा गुजर जाने के बाद लोग इस पर चर्चा करते लेकिन 2-4 मैच बाद नहीं। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने दो मैचों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, आप मैच जिताने की उनकी काबिलियत पर सवाल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि बुमराह ने जो भारत के लिए हासिल किया है आप उसे कैसे नजरअंदाज सकते हैं? तो अगर आप सकारात्मक होकर सोचते हैं तो यह आपके और खिलाड़ी के आत्मविश्वास के लिए भी अच्छा होता है। उन्होंने कहा कि लोग भूल रहे हैं कि बुमराह स्ट्रेस फ्रैक्चर से उबरकर लौटे हैं। एक खिलाड़ी होने के नाते, यह काफी अलग है। बाहर से टिप्पणी करना काफी आसान है। कुछ लोगों का काम ही होता है टिप्पणी करना। एक खिलाड़ी होने के नाते आप चोटिल होते हैं और ऐसे में आपको सकारात्मक होकर देखना चाहिए न सिर्फ नकारात्मक चीजों पर ही टिप्पणी करनी चाहिए। मैं भी 2015 में चोटिल हुआ था (घुटने की चोट) लेकिन मैंने वापसी की।

इशांत फिटनेस टेस्ट में पास, न्यूजीलैंड में टीम इंडिया से जुड़ेंगे

नई दिल्ली, जेएनएन : भारतीय तेज गेंदबाज इशांत शर्मा ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है और अब वह 21 फरवरी से न्यूजीलैंड दौरे पर होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम से जुड़ेंगे।

इशांत को अरुण जेटली स्टेडियम में विदर्भ के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में टखने में चोट लग गई थी। यह चोट ग्रेड-3 की थी जिसके कारण इशांत को छह सप्ताह आराम करने की सलाह दी गई थी। उन्हें छह सप्ताह तक आराम करने की सलाह दी गई थी। इशांत को विदर्भ की दूसरी पारी के दौरान पांचवें ओवर में टखने में चोट लग गई थी। चोट के कारण वह मैदान से बाहर चले गए थे। इसके बाद उनका एमआरआइ स्कैन कराया गया था जहां रिपोर्ट में उन्हें गंभीर चोट लगने की बात सामने आई थी। भारत को न्यूजीलैंड में दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। सीरीज का पहला टेस्ट 21 से 25 फरवरी के बीच खेला जाएगा जबकि दूसरा मैच 29 से चार मार्च के बीच खेला जाएगा।

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीतना वनडे या टी-20 विश्व कप खिताब से बड़ा : पुजारा: विराट कोहली की कप्तानी में अब तक भारतीय टीम किसी आइसीसी टूर्नामेंट को नहीं जीत सकी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 हो या विश्व कप 2019, कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम खिताब जीतने से चूक गई। हालांकि टीम इंडिया के टेस्ट विशेषज्ञ बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने कहा कि अगर आप लॉर्ड्स में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जीत हासिल कर टेस्ट चैंपियंस बनते हो तो मुझे लगता है कि यह वनडे विश्व कप और टी-20 विश्व कप से भी बड़ी बात है।

दिल्ली ने खेला ड्रॉ नॉकआउट में जाने का सपना टूटा

खेल संवाददाता, नई दिल्ली: महिपाल लोमरोर के शतक के अलावा निचले क्रम के बल्लेबाजों के बेहतरीन योगदान के दम पर राजस्थान ने यहां अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए रणजी ट्रॉफी ग्रुप-ए के मैच में दिल्ली को ड्रॉ पर रोक दिया। लग रहा था कि दिल्ली यह मैच जीत लेगी लेकिन महिपाल के बाद रितुराज सिंह और सलमान खान ने शानदार अर्धशतकीय पारियां खेल मैच के चौथे और आखिरी दिन अपनी दूसरी पारी छह विकेट के नुकसान पर 345 रनों पर घोषित कर मैच ड्रॉ करा लिया। ड्रॉ के साथ ही दोनों टीम नॉकआउट चरण में पहुंचने से चूक गई हैं।

राजस्थान ने दिन की शुरुआत दो विकेट के नुकसान पर 128 रनों के साथ की। महिपाल ने 64 रनों के निजी स्कोर को आगे बढ़ाया और रितुराज ने 11 रनों के निजी स्कोर से पारी की शुरुआत की। महिपाल शतक पूरा करने के बाद आउट हो गए। उन्होंने 219 गेंदों की पारी में 14 चौके और दो छक्कों की मदद से 118 रन बनाए। रितुराज ने 104 गेंदों पर 58 रनों की पारी खेली। उनकी पारी में नौ चौके शामिल रहे। सलमान ने 88 गेंदों पर 56 रनों की पारी खेली। उनके साथ राजेश बिश्नोई 13 रन बनाकर नाबाद रहे।

रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल मुकाबले

तारीख	बनाम
20 से 24 फरवरी	गुजरात *vs* गोवा
20 से 24 फरवरी	बंगाल *vs* ओडिशा
20 से 24 फरवरी	कर्नाटक *vs* जम्मू एवं कश्मीर
20 से 24 फरवरी	सौराष्ट्र *vs* आंध्र प्रदेश

प्रतिबंध के बाद सिटी के खिलाड़ियों को लेकर चिंतित हैं गॉर्डियोला

फुटबॉल डायरी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : यूएफा द्वारा दो साल के प्रतिबंध को झेल रहे इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) क्लब मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर पेप गॉर्डियोला इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यह प्रतिबंध खिलाड़ियों पर कैसा प्रभाव डालेगा।

यूएफा ने शुक्रवार को वित्तीय नियमों के गंभीर उल्लंघन के कारण मैनचेस्टर सिटी पर चैंपियंस लीग के साथ सभी यूरोपियन टूर्नामेंट से दो सत्रों (2020-21 व 2021-22) से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही क्लब पर 32.5 मिलियन डॉलर (लगभग 231 करोड़ रुपये) का जुर्माना भी लगाया गया है। अब इसके खिलाफ क्लब लुसाने में खेल पंचाट में अपील भी करेगा।

गॉर्डियोला ने कहा, 'क्लब को शुक्रवार की सुबह पता था कि उसे प्रतिबंधित किया जाएगा और इसलिए उसने अपील के खिलाफ तैयारी शुरू कर दी थी।' गॉर्डियोला समझ रहे हैं कि क्यों कुछ खिलाड़ी क्लब को छोड़ना चाहते हैं लेकिन खिलाड़ियों को यूरोपीय प्रतियोगिता में नहीं खेलने की संभावनाओं का सामना करना चाहिए। चैंपियंस लीग के इस सत्र में अंतिम-8 में सिटी का सामना रीयल मैड्रिड से होगा और खिलाड़ियों पर इस प्रतिबंध को लेकर दबाव रहेगा लेकिन गॉर्डियोला की टीम अपने प्रदर्शन में सुधार करके इस खिताब को जीत सकती है। यूएफा की तरफ से कहा गया था कि क्लब की ओर से दिए गए सभी सबूतों पर विचार करने के बाद पाया कि सिटी ने अपने खातों में प्रायोजक राजस्व को सही नहीं बताया। उसने क्लब लाइसेंसिंग और वित्तीय फेयर प्ले नियमों का उल्लंघन किया है। क्लब ने मामले की जांच में सहयोग भी नहीं किया। क्लब फाइनेंशियल कंट्रोल बॉडी (सीएफसीबी) ने कहा कि सिटी ने अपने खातों में प्रायोजकों से होने वाली कमाई ज्यादा दिखाकर नियमों का उल्लंघन किया है और साल 2012 और 2016 में यूएफा को गलत जानकारियां भी दी गई। यह प्रतिबंध सिटी की महिला टीम पर लागू नहीं होगा। वहीं सिटी की तरफ से कहा गया कि दिसंबर 2018 में यूएफा के मुख्य जांचकर्ता ने सार्वजनिक तौर पर इस बारे में अपना मत व्यक्त किया और सिटी पर प्रतिबंध लगाए जाने की आशंका भी जताई थी, जबकि तब तक इस मामले में कोई जांच भी शुरू नहीं हुई थी। सीधे तौर पर कहें तो यह केस यूएफा ने शुरू किया। उन्होंने ही सुनवाई की और बिना हमारा पक्ष सुने एकतरफा फैसला सुना दिया। वहीं, स्पेनिश लीग ला लीगा के अध्यक्ष जेवियर तेबास ने यूएफा के इस फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा, 'फुटबॉल के भविष्य के लिए आर्थिक मामलों में गड़बड़ी के खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी था।'

बार्सिलोना ने गेटफे को हराया

बार्सिलोना, रायटर: बार्सिलोना ने अपने घर में शनिवार को स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा के मैच में गेटफे को 2-1 से हरा दिया। लियोन मेसी के पास पर एंटोनी ग्रीजमैन ने 33वें मिनट में गोल करके बार्सिलोना का मैच में खाता खोल दिया। हालांकि इसके बाद भी बार्सिलोना ने मैच में गोल करने का सिलसिला जारी रखा और इसके छह मिनट बाद ही सर्गी रोबर्टो ने बॉक्स के अंदर से गोल कर टीम की बढ़त को दोगूना कर दिया। पहले हाफ में बार्सिलोना 2-0 से आगे रहा। दूसरे हाफ में गेटफे के लिए एंजेल रोड्रिग्ज 66वें मिनट में गोल करके टीम के हार के अंतर को कुछ कम पाए, लेकिन जीत के लिए यह काफी नहीं था। इस जीत के बाद बार्सिलोना के तालिका में शीर्ष पर मौजूद रीयल मैड्रिड के साथ 52 अंक हो गए हैं। गोल अंतर के आधार पर मैड्रिड शीर्ष पर है जबकि बार्सा दूसरे स्थान पर है जबकि गेटफे 42 अंक लेकर तीसरे स्थान पर बना हुआ है।

एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे पाकिस्तानी पहलवान

योगेश शर्मा, नई दिल्ली : 29 साल बाद आखिरकार पाकिस्तानी पहलवान यहां 18 से 23 फरवरी तक होने वाली एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में हिस्सा लेने आएंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने छह पाकिस्तान पहलवानों को वीजा दे दिया है। पाकिस्तान के पहलवान सोहेल राशिद, मुहम्मद रियाज, तयाब रजा, रहमान अब्दुल, जमन अनवर और मुहम्मद बिलाल को वीजा दिया है।

भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआइ) के एक सूत्र ने कहा कि ओलंपिक चार्टर को निभाने के लिए सरकार को वीजा देना पड़ा है। इन पहलवानों के मैच 21 फरवरी को होंगे और यह दल 20 फरवरी को भारत आ जाएगा लेकिन अब उनके भेजने या नहीं भेजने का फैसला पाकिस्तान को करना है। पिछली बार पाकिस्तान इस चैंपियनशिप में दिल्ली में 1991 में खेला था। हालांकि कुश्ती की विश्व संस्था यूडब्ल्यूडब्ल्यू और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का डब्ल्यूएफआइ पर चीनी पहलवानों को वीजा देने का दबाव बना हुआ है और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उस पर प्रतिबंध भी लग सकता है। कोरोना वायरस के कारण उनके वीजा पर अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। वहीं, चीनी पहलवानों की स्थिति साफ नहीं होने के कारण तुर्कमेनिस्तान ने इस चैंपियनशिप से हटने का फैसला किया।

उद्घाटन मैच में आमने-सामने होंगे धौनी-रोहित

- बीसीसीआइ ने जारी किया आइपीएल 2020 का कार्यक्रम
- फाइनल और क्वालीफायर मैच की तारीख की अभी घोषणा नहीं
- मैच कितने बजे शुरू होंगे, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई

IPL 2020

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: आइपीएल 2020 के उद्घाटन मुकाबले में लीग के इतिहास की दो सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी टीम मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स आमने-सामने होंगी। यह मुकाबला 29 मार्च को मुंबई में खेला जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स ने इस सत्र में अपना दूसरा घर गुवाहाटी को बनाया है। गुवाहाटी इस सत्र में दो मुकाबलों की मेजबानी करेगा। यह दो मुकाबले पांच अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स और नौ अप्रैल को कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ होंगे। हालांकि अभी गुवाहाटी की मेजबानी को पर पूरी तरह से मुहर लगना बाकी है। आइपीएल में इस सत्र में शनिवार को जरूर दो मैच नहीं होंगे, लेकिन रविवार को दो मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 56 लीग मैच होंगे। मैच कितने बजे शुरू होंगे इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है।

आइपीएल के लीग दौर का कार्यक्रम

तारीख	मैच	जगह
29 मार्च	मुंबई इंडियंस *vs* सीएसके	मुंबई
30 मार्च	दिल्ली कैपिटल्स *vs* पंजाब	दिल्ली
31 मार्च	आरसीबी *vs* केकेआर	बेंगलुरु
1 अप्रैल	हैदराबाद *vs* मुंबई इंडियंस	हैदराबाद
2 अप्रैल	सीएसके *vs* राजस्थान रॉयल्स	चेन्नई
3 अप्रैल	केकेआर *vs* दिल्ली कैपिटल्स	कोलकाता
4 अप्रैल	पंजाब *vs* हैदराबाद	मोहाली
5 अप्रैल	मुंबई इंडियंस *vs* आरसीबी	मुंबई
5 अप्रैल	राजस्थान रॉयल्स *vs* दिल्ली	जयपुर/गुवाहाटी
6 अप्रैल	केकेआर *vs* सीएसके	कोलकाता
7 अप्रैल	आरसीबी *vs* हैदराबाद	बेंगलुरु
8 अप्रैल	पंजाब *vs* मुंबई इंडियंस	मोहाली
9 अप्रैल	राजस्थान रॉयल्स *vs* केकेआर	जयपुर/ गुवाहाटी
10 अप्रैल	दिल्ली कैपिटल्स *vs* आरसीबी	दिल्ली
11 अप्रैल	सीएसके *vs* पंजाब	चेन्नई
12 अप्रैल	हैदराबाद *vs* राजस्थान रॉयल्स	हैदराबाद
12 अप्रैल	केकेआर *vs* मुंबई इंडियंस	कोलकाता
13 अप्रैल	दिल्ली कैपिटल्स *vs* सीएसके	दिल्ली
14 अप्रैल	पंजाब *vs* आरसीबी	मोहाली
15 अप्रैल	मुंबई इंडियंस *vs* राजस्थान	मुंबई
16 अप्रैल	हैदराबाद *vs* केकेआर	हैदराबाद
17 अप्रैल	पंजाब *vs* सीएसके	मोहाली
18 अप्रैल	आरसीबी *vs* राजस्थान रॉयल्स	बेंगलुरु
19 अप्रैल	दिल्ली कैपिटल्स *vs* केकेआर	दिल्ली
19 अप्रैल	सीएसके *vs* हैदराबाद	चेन्नई
20 अप्रैल	मुंबई इंडियंस *vs* पंजाब	मुंबई
21 अप्रैल	राजस्थान रॉयल्स *vs* हैदराबाद	जयपुर
22 अप्रैल	आरसीबी *vs* दिल्ली कैपिटल्स	बेंगलुरु
23 अप्रैल	केकेआर *vs* पंजाब	कोलकाता
24 अप्रैल	सीएसके *vs* मुंबई इंडियंस	चेन्नई
25 अप्रैल	राजस्थान रॉयल्स *vs* आरसीबी	जयपुर
26 अप्रैल	पंजाब *vs* केकेआर	मोहाली
26 अप्रैल	हैदराबाद *vs* दिल्ली कैपिटल्स	हैदराबाद
27 अप्रैल	सीएसके *vs* आरसीबी	चेन्नई
28 अप्रैल	मुंबई इंडियंस *vs* केकेआर	मुंबई
29 अप्रैल	राजस्थान रॉयल्स *vs* पंजाब	जयपुर
30 अप्रैल	हैदराबाद *vs* सीएसके	हैदराबाद
1 मई	मुंबई इंडियंस *vs* दिल्ली	मुंबई
2 मई	केकेआर *vs* राजस्थान रॉयल्स	कोलकाता
3 मई	आरसीबी *vs* पंजाब	बेंगलुरु
3 मई	दिल्ली कैपिटल्स *vs* हैदराबाद	दिल्ली
4 मई	राजस्थान रॉयल्स *vs* सीएसके	जयपुर
5 मई	हैदराबाद *vs* आरसीबी	हैदराबाद
6 मई	दिल्ली *vs* मुंबई इंडियंस	दिल्ली
7 मई	सीएसके *vs* केकेआर	चेन्नई
8 मई	पंजाब *vs* राजस्थान रॉयल्स	मोहाली
9 मई	मुंबई इंडियंस *vs* हैदराबाद	मुंबई
10 मई	सीएसके *vs* दिल्ली कैपिटल्स	चेन्नई
10 मई	केकेआर *vs* आरसीबी	कोलकाता
11 मई	राजस्थान *vs* मुंबई इंडियंस	जयपुर
12 मई	हैदराबाद *vs* पंजाब	हैदराबाद
13 मई	दिल्ली *vs* राजस्थान रॉयल्स	दिल्ली
14 मई	आरसीबी *vs* सीएसके	बेंगलुरु
15 मई	केकेआर *vs* हैदराबाद	कोलकाता
16 मई	पंजाब *vs* दिल्ली कैपिटल्स	मोहाली
17 मई	आरसीबी *vs* मुंबई इंडियंस	बेंगलुरु

रिकॉर्ड 18500 धावक लेंगे मैराथन में हिस्सा

प्रतियोगिता

- नई दिल्ली मैराथन के लिए रिकॉर्ड संख्या में कराया गया रजिस्ट्रेशन
- 23 फरवरी को जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम से शुरू होगी रेस

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: नई दिल्ली मैराथन के पांचवें संस्करण के लिए रिकॉर्ड 18500 लोगों ने पंजीकरण कराया है। इस मैराथन को दिग्गज क्रिकेटर और आइडीबीआइ फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एंबेसडर सचिन तेंदुलकर 23 फरवरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

एनईबी स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित की जा रही इस मैराथन की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से होगी। इस मैराथन को एएफआइ (एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) से राष्ट्रीय मैराथन चैंपियनशिप का दर्जा प्राप्त है। इस मैराथन में चार विभिन्न वर्गों फुल मैराथन (42.2 किलोमीटर), हाफ मैराथन (21.1 किमी), 10000 मीटर और 5000 मीटर स्वच्छ भारत रन रेसों का आयोजन होगा। फुल मैराथन तड़के चार बजे से शुरू होगी। इसके बाद 6.15 पर हाफ मैराथन, 7.30 पर 10000 मीटर रेस और 8.30 बजे 5000 मीटर रेस शुरू होगी। नई दिल्ली मैराथन के पांचवें संस्करण में फुल मैराथन में 2500 और हाफ मैराथन में 6000 धावक भाग लेंगे। 10000 मीटर रेस में 5500 और 5000 मीटर रेस में करीब 4500 धावकों के भाग लेने की उम्मीद है। इस रेस में 820 ऐसे धावक हैं, जिन्होंने पिछले सभी पांच संस्करणों में भाग लिया था।

86 साल के जनार्दन बीआर फुल मैराथन में सबसे उम्रदराज धावक होंगे जबकि 72 वर्षीय दलजीत मीरचांदनी हाफ मैराथन में सबसे उम्रदराज धावक होंगे। आयोजकों का कहना है कि वह उनका उद्देश्य सिर्फ रेस कराना नहीं है। वह इसके जरिये सिर्फ धावकों को नहीं बल्कि समाज के अन्य वर्गों को भी जोड़ते हैं। इसमें सैन्य बलों, निर्माण क्षेत्र के लोगों और एनजीओ को जोड़ा गया है। इस बार की मैराथन में सैन्य बलों से करीब 1000 धावक और पुलिस बस से करीब 250 धावक भाग लेंगे। 14 कॉरपोरेट क्षेत्रों ने इसमें भाग लेना सुनिश्चित किया है। पैरा एथलीटों, दृष्टिबाधित धावकों के साथ-साथ गाइड एथलीटों और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के धावक भी इसमें अपना प्रतिनिधित्व करेंगे।

उपलब्धि — भारतीय एथलीट ने 20 किमी पैदल चाल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया, इस स्पर्धा से ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली दूसरी भारतीय महिला

भावना ने टोक्यो ओलंपिक के लिए किया क्वालीफाई

जागरण संवाददाता, रांची : भारतीय एथलीट भावना जाट ने शनिवार को यहां राष्ट्रीय चैंपियनशिप की 20 किमी पैदल चाल स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के बाद इस साल टोक्यो में होने वाले ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर लिया।

राजस्थान की 23 साल की इस एथलीट ने 1:29.54 सेकेंड के समय से स्वर्ण पदक जीता और ओलंपिक का टिकट हासिल किया जिसका क्वालीफिकेशन समय 1:31.00 सेकेंड था। किसान परिवार की भावना ने इस तरह पिछले साल अक्टूबर में राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान बनाए गए 1:38.30 सेकेंड के अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में काफी सुधार किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वह 20 किमी पैदल चाल स्पर्धा में ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली दूसरी भारतीय महिला एथलीट बनीं। उनसे पहले खुशबीर कौर ने इस स्पर्धा में 2016 रियो ओलंपिक में हिस्सा लिया था। वहीं, उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी 1:31.36 सेकेंड के समय से ओलंपिक कट से करीब से चूक गईं जिसका आयोजन 24 जुलाई से नौ अगस्त किया जाएगा।

इससे पहले राष्ट्रीय रिकॉर्ड दिल्ली की बेबी सौम्या के नाम था जिन्होंने राष्ट्रीय पैदल चाल चैंपियनशिप 2018 (दिल्ली) में 1:31.29 सेकेंड का समय लिया था। भावना जयपुर में कोच गुरमुख सिहाग की देखरेख में खुद ही अभ्यास करती है। उन्होंने जूनियर या सीनियर स्तर के किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया है। वह भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआइ) के किसी शिविर का भी हिस्सा नहीं रही है। उन्होंने सीनियर स्तर पर 2016 में राष्ट्रीय अंतर-राज्यीय चैंपियनशिप से पदार्पण किया। हैदराबाद में आयोजित इस प्रतियोगिता में वह 1:52.38 सेकेंड के समय के साथ पांचवें स्थान पर रही थी। केटी इरफान (पुरुषों की 20 किलोमीटर पैदल चाल), अविनाश साबले (पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज) एवं मिक्स्ड 4×400 मीटर रिले टीम और नीरज चोपड़ा (पुरुष भाला फेंक) पहले ही एथलेटिक्स में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं। भावना के कोच गुरमुख ने कहा कि भावना ने डोप परीक्षण के लिए नमूना दिया है जिसका मतलब यह हुआ कि उनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड मान्य रहेगा। भावना इसके बाद एशियाई पैदल चाल चैंपियनशिप में भाग लेंगी जो 15 मार्च से जापान में होगी। वहीं, पुरुष वर्ग में संदीप कुमार भले ही ओलंपिक क्वालीफाई करने से चूक गए लेकिन 20 किलो मीटर का स्वर्ण जीतने में सफल रहे। संदीप 01:21.34 सेकेंड के साथ पहले स्थान पर रहे।

स्वर्ण पदक विजेता भारतीय एथलीट संदीप कुमार (बायें) और भावना जाट ● एएफआइ

> मैं अभ्यास के दौरान 1:27.00 सेकेंड का समय ले रही थी। मुझे पता था कि अगर परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो मैं ओलंपिक क्वालीफाइंग समय से कम समय में स्पर्धा को पूरा कर सकती हूं। यह पिछले कुछ महीने से की गई मेरी और कोच की मेहनत का नतीजा है। जो माहौल हमें यहां मिला वह कम ही मिलता है। चैंपियनशिप के लिए सही मौसम व माहौल ने हम लोगों में नई उर्जा का संचार किया जिसका परिणाम है कि मेरे व्यक्तिगत प्रदर्शन में सुधार हुआ और ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने में सफल रही।
>
> -भावना जाट

मेवाड़ की लाड़ली करेगी टोक्यो में कमाल

मनीष गोधा ● जयपुर

राजस्थान के राजसमंद जिले के काबरा गांव की रहने वाली भावना के प्रदर्शन ने पूरे मेवाड़ में जोश भर दिया है। राजसमंद आदिवासी बहुल जिला है। भावना के पिता शंकरलाल जाट किसान हैं और इसके दो बडे भाई भी है।

स्कूल के दौरान भावना को कोचिंग देने वाले सुरेश जाट बताते हैं कि भावना करीब 10 वर्ष की उम्र से पैदल चाल में भाग ले रही हैं और उसके गांव के स्कूल में ही वहां के पीटी टीचर हीरालाल कुमावत भावना को कोचिंग देते थे। वहां सुविधाओं की कमी थी। इनके परिवार को मेरे बारे में पता चला तो परिवार वालों ने उन्हें उदयपुर में मेरे गांव खेरोदा भेज दिया। यहां मैं अपनी बहन सुनीता और अन्य 10-12 लड़कियों को कोचिंग देता था। इसके लिए गांव में ही हमने 200 मीटर का ट्रैक बना रखा था। सुरेश जाट ने बताया कि भावना ने उनसे 2014 से 2016 के बीच कोचिंग ली और कुछ पदक भी जीते। इसके बाद भावना की रेलवे में नौकरी लग गई। कोचिंग के दौरान ही यह महसूस होने लगा था कि भावना कुछ बड़ा करेगी, क्योंकि उसकी तकनीक बहुत अच्छी थी। हम उसे यही कहते थे कि किसी भी हालत में चोट नहीं लगने देना। आज ये सुन कर बहुत अच्छा लगा रहा है कि मेवाड़ की यह बेटी अब ओलंपिक में जाएगी। भावना मेवाड़ से पहली लड़की हैं, जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। सुरेश जाट ने बताया कि रेलवे में नौकरी से पहले भावना ने विजयवाड़ा मे जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप रजत पदक जीता था जो उसका पहला पदक था।

जंगल के 'मंगल' की खातिर 127 साल पुराने रेलवे ट्रैक को कहा बाय-बाय

परिवहन से जरूरी जीवन... ▶ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई थी याचिका, आज से बंद हो जाएगा परिवहन

अंकित कुमार, लखनऊ

- लखीमपुर खीरी से बहराइच के बीच वन्य जीवन बचाने को देश में उठाया जा रहा ऐतिहासिक कदम
- 40 लाख आबादी सीधे प्रभावित होगी, मगर बचा रहेगा वन्यजीवन
- मैलानी से बहराइच तक 206 किमी लंबा मीटरगेज ट्रैक घनघोर जंगल से होकर गुजरता है

वन्यजीवों के हक में जो होने जा रहा है, ऐसे चंद उदाहरण ही अब तक देश में सामने आए हैं। वरना, जंगल और जानवरों को उजाड़ने का ही काम किया जाता रहा है। उप्र में मैलानी तहसील से बहराइच तक 206 किमी लंबा मीटरगेज ट्रैक घनघोर जंगल से होकर गुजरता है। इसके रास्ते में दुधवा नेशनल पार्क (टाइगर रिजर्व) का किशनपुर, भीरा, दुधवा रेंज, सोनारीपुर रेंज और बहराइच का कतर्नियाघाट आदि पड़ते हैं, जहां विभिन्न प्रजातियों के वन्यजीव हैं। जंगल के बीच से रोजाना गुजरने वाली ट्रेनें आए दिन बाघ, चीतल, अजगर, हाथी समेत तमाम दुर्लभ जानवरों का काल बन जाती हैं। लंबी लड़ाई के बाद कोर्ट के आदेश पर आज से यह ट्रैक बंद कर दिया जाएगा।

पर्यावरण संरक्षण

वन संपदा का दोहन करने के इरादे से करीब 127 साल पहले अंग्रेजों का बिछाया रेलवे ट्रैक 16 फरवरी से हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बेजुबानों के हक में लड़ी गई लंबी लड़ाई के बाद यह आदेश अमल में आया है। हालांकि, इसके चलते खीरी के मैलानी से बहराइच जिले तक की करीब 40 लाख आबादी सीधे प्रभावित होगी मगर, हजारों दुर्लभ जानवरों की जान भविष्य में बच जाएगी। इतना ही नहीं, पर्यावरण और वन्यजीवों को लेकर इंसानों का गैरजिम्मेदाराना नजरिया बदलने में भी यह कदम नजीर बनेगा।

इस ट्रैक पर मारे जाने वाले वन्यजीवों का महज 10 से 12 साल का आंकड़ा चौंकाने वाला है। ऐसा नहीं कि अनहोनी रोकने के लिए चुप्पी रही। तमाम संस्थाओं ने आवाज उठाई मगर, सरकारें सोती रहीं। हारकर 2015 में बहराइच के अधिवक्ता और वन्यजीव प्रेमी सतीश चंद्र मिश्र ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। तर्क रखा कि ट्रेन दौड़ती रहीं तो पूरा जंगल जानवरों से खाली हो जाएगा। न्यायालय ने उनकी दलील को वाजिब मानते हुए तभी रेलवे ट्रैक बंद करने के निर्देश रेलवे और सरकार को दिए। हालांकि, यह इतना आसान नहीं था। कोर्ट के आदेश को सरकारें और रेल अफसर मुश्किलें गिनाकर लटकाए रहे। जानवरों का कटना बदस्तूर जारी रहा। यह देख सतीश मिश्र ने पिछले दिनों दोबारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। नए आंकड़े पेश कर आदेश की अवहेलना का हवाला दिया, जिसपर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई। तुरंत रेलवे लाइन बंद करने को कहा। खुद को फंसता देख अफसर जागे और पूर्वोत्तर रेलवे मंडल गोरखपुर ने 16 फरवरी से रेल लाइन बंद करने की घोषणा कर दी।

दुधवा नेशनल पार्क में 2008 से अब तक चार बाघ, 23 हिरन, दो नील गाय, सात जंगली सूकर, चार हाथी, एक मगरमच्छ कटकर मारे जा चुके हैं। ये तो वन विभाग के आंकड़ों में दर्ज हैं। दर्जनों ऐसे हैं, जिनका रिकॉर्ड नहीं। इसके अलावा कतर्नियाघाट घाट में 53 से अधिक जानवर मारे जा चुके हैं। इनमें दो शावक, तीन बाघ, अजगर, पाड़ा, चीतल, हिरन समेत तमाम वन्य जीव हैं।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें www.jagran.com/topics/positive-news

मैलानी-नानपारा रेलवे लाइन पर दुधवा नेशनल पार्क के जंगल से गुजरती ट्रेन की फाइल फोटो। जागरण

मैलानी रेलवे स्टेशन की दीवारों पर चित्रकारी करते कलाकार। जागरण

1893 में पड़ी थी नींव...

घनघोर जंगल के बीच मैलानी से बहराइच के बीच रेल लाइन की नीव 10 मार्च 1893 में पड़ी थी। अंग्रेजों ने वन संपदा का दोहन और शिकार का शौक पूरा करने के इरादे से इसे बिछाया था। साथ ही नेपाल सीमा से सटा पूर्वांचल का बड़ा हिस्सा रेल नेटवर्क से अछूता था। इस बहाने उसे मैलानी जंक्शन से जोड़ लिया, जहां से दिल्ली, बरेली, आगरा के लिए ट्रेनें संचालित होती थीं। रास्ते में पर्यटन स्थल दुधवा, सोनालीपुर, बहराइच का पर्यटन स्थल कतर्नियां घाट समेत करीब एक दर्जन छोटे रेलवे स्टेशन हैं। ट्रेन बंद होने से करीब 40 लाखकी आबादी प्रभावित होगी। उन्हें फिलहाल सड़क के रास्ते सफर करना होगा। किराया कई गुना बढ़ जाएगा।

हाईकोर्ट ने मैलानी-नानपारा रेलखंड पर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में ट्रेनों का संचालन बंद करने का आदेश दिया है।
- पंकज सिंह, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

रुदौली में मख्दूम साहब दरगाह में 600 साल पुरानी गाय की मजार

प्रहलाद तिवारी, रुदौली (अयोध्या)

अपना देश खुशबू माटी की

- अयोध्या के रुदौली में गाय की मजार कौमी एकता की मिसाल
- सरयू किनारे एक पैर पर खड़े होकर 40 दिन तक तप किया था श्रीराम में श्रद्धा रखने वाले मख्दूम साहब ने, आज भी है मख्दूम घाट

मंदिर-मस्जिद विवाद से दुनियाभर में चर्चित हुई अयोध्या के रुदौली में गाय की मजार कौमी एकता की मिसाल है। मख्दूम साहब दरगाह की जीनत यह मजार लोगों को गोसेवा की सीख दे रही है। सद्भाव की यह अलख छह सौ साल पहले सूफी संत मख्दूम साहब ने यहां जगाई थी।

राम-रहीम दोनों में बराबर श्रद्धा रखने वाले इस सूफी पीर को सरयू से अगाध लगाव था। इसीलिए अपनी तपस्या के लिए उन्होंने सरयू को ही चुना और रामनगरी आकर मोक्षदायिनी नदी में एक पैर पर खड़े होकर 40 दिन तक तप किया। आज भी सरयू के इस घाट को मख्दूम घाट के नाम से जाना जाता है।

रुदौली, अयोध्या में मौजूद मख्दूम साहब दरगाह। जागरण

दरगाह के सज्जादानशीन नैयर मियां।

दरगाह के सज्जादानशीन नैयर मियां बताते हैं कि मख्दूम साहब को गोवंश से बेहद प्रेम था। उन्होंने कई गाएं पाल रखी थीं। इनमें से एक उन्हें बेहद प्रिय थी। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई तो मख्दूम साहब बहुत दुखी हो गए। उन्होंने मौत के बाद भी उस गाय को खुद से दूर न जाने दिया और आस्ताने में ही उसकी मजार बनवा दी। उसकी कब्र की पहचान हो सके, इसके लिए लाल पत्थर भी लगवाया। यह कब्र आज भी मौजूद है और मख्दूम साहब के गोसेवा के संदेश को फैला रही है।

मख्दूम साहब की मजार के भी सबसे करीब... : यूं तो मख्दूम साहब की दरगाह में कुल 69 मजारें हैं, लेकिन गाय की मजार मख्दूम साहब की मजार के ठीक सामने है। इससे इसकी अहमियत समझी जा सकती है। जायरीन यहां भी जियारत करते हैं। दरगाह से जुड़े शाह हयात मसूद गजाली कहते हैं कि मख्दूम साहब ने जीवन भर इंसानियत और प्रेम का संदेश दिया। इसीलिए दरगाह में हर वर्ग संप्रदाय के लोग आते हैं। खानकाह के अंदर धूमधाम से वसंत मनाने की परंपरा भी है।

दरगाह में लाल पत्थर की निशानी वाली मजार गाय की है। जागरण

एक अयोध्या प्रभु राम की, दूजी उनके नाम की

जय श्रीराम... ▶ प्रयागराज में भी है एक अयोध्या, यहां भी हो रही राम मंदिर के निर्माण की तैयारी

रविवार विशेष

राम मंदिर निर्माण के दिन यहां मनेगा रामोत्सव, रामचरित मानस का होगा पाठ

ज्ञानेन्द्र सिंह, प्रयागराज

एक अयोध्या प्रयागराज में भी है, और यहां भी राम मंदिर के निर्माण की तैयारी हो रही है। इस अयोध्या में भगवान जन्मे नहीं तो क्या हुआ, हर मन और तन में बसे हैं। बस्ती के हर व्यक्ति के नाम में श्रीराम नाम समाहित हैं। रामनामकरण की यह परंपरा भी उतनी ही पुरानी है, जितनी कि यहां मौजूद श्रीराम की अनेक मूर्तियां।

इस अयोध्या की हर गली, चट्टी और चौराहे पर भगवान का ही नाम सुनाई पड़ता है। हर व्यक्ति का नाम राम नाम पर है- यहां रामशिरोमणि हैं तो रामअभिलाष और राममनोरथ भी हैं...। पीढ़ी दर पीढ़ी यहां के लोगों के नाम में राम का इतिहास है। गांव की प्रधान कलावती के पति मनीराम शुक्ल हैं। मनीराम के पिता का नाम रामगोपाल था तो उनके दादा का नाम रामपदारथ था। इस तरह कई पीढ़ियों के नाम में राम जुड़ा है। खास यह भी कि राम की विशेषता वाले नामों पर किसी एक का विशेषाधिकार नहीं है वरन दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग भी राम नाम के धनी हैं। नाम के साथ ही यहां पुरुषोत्तम की मर्यादा भी है। सैकड़ों राम नामधारी लोग उसी संस्कृति, सभ्यता और परंपरा को समृद्ध बनाने में जुटे हैं, जो रामायण काल में थी। इसीलिए यह अयोध्या इन दिनों इतरा रही है।

अब इस अयोध्या में भी उसी समय राम मंदिर का निर्माण शुरू कराने का संकल्प लिया गया है, जब भगवान की जन्मस्थली अयोध्या में मंदिर निर्माण का श्रीगणेश होगा। इसके लिए गांव के किनारे बेलन नदी के तट पर प्राचीन शिव मंदिर के पास तैयारी कर ली गई है। यहां रामोत्सव मनाया जाएगा। नवंबर माह की नौ तारीख थी, जब पूरा देश राम मंदिर पर आने वाले सुप्रीम फैसले का इंतजार कर रहा था तो इस अयोध्या के राम नामधारी रामकथा का श्रवण कर रहे थे।

प्रयागराज की अयोध्या में बेलन नदी के किनारे प्राचीन मूर्तियां। इसमें भगवान शंकर के साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की भी मूर्तियां हैं। जागरण

ढाई हजार की आबादी वाले इस गांव में 60 शिक्षक हैं। मिलिट्री और पैरामिलिट्री में बहुत से युवा हैं। तुलसीराम त्रिपाठी के मुताबिक यहां अयोध्या अपने शाब्दिक अर्थ- जिसे युद्ध में हराया ना जा सके, से परिपूर्ण है। इससे ही यहां के अस्तित्व के बारे में जानकारी मिलती है। जिस रियासत में यह गांव आता था, उसके द्वारा नामकरण हुआ था, ऐसा पूर्वज कह गए। प्रयागराज नगर से 70 किमी दूर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बेलन नदी के तट पर अयोध्या गांव बसा है। कोरांव तहसील मुख्यालय से लगभग 10 किमी दूर स्थित अयोध्या गांव से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 135-सी गुजरता है। खास यह है कि यहां हर घर में गाय है। बाग-बगीचों से घिरे गांव में हर ओर गौरैया चहचहाती हैं। ऐसा नहीं है कि अयोध्या गांव के इतिहास को लेकर कोई कदम नहीं उठाए गए। भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहां खोदाई भी कराई। दो दशक पहले यहां विभाग की टीम ने कैंप किया था। तब नदी के किनारे स्थित प्राचीन मंदिर की मूर्तियां खोदाई में मिली थीं, जो संग्रहीत हैं।

हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता से जुड़ाव... : सिंधु घाटी की तरह इतिहास की किताबों में बेलन नदी घाटी सभ्यता का जिक्र मिलता है, जो कि तमाम नदी घाटी सभ्यताओं से काफी प्राचीन है। अति प्राचीन बेलन नदी अयोध्या गांव से होकर बहती है। यहां खोदाई में मिली प्राचीन राम मूर्तियों को अब राम मंदिर में प्रतिष्ठापित किया जाएगा, जिसकी तैयारी चल रही है।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें www.jagran.com/topics/jagran-special

देश की 'सीमा' पर जिनसे रोशन हैं संघर्ष के 'दीपक'

कमांडो ट्रेनर मेजर दीपक राव और सीमा राव के जोश, जुनून और जज्बे की गाथा, 20 साल से दे रहे ट्रेनिंग

जीना इसी का नाम है

मनु त्यागी, नई दिल्ली

किसी को कुछ करने के लिए निर्देश देना बहुत सरल है, लेकिन पहले उसी काम को खुद सहज भाव से करके दिखाओ, दम तो तब है। मैं और दीपक 20 साल से कमांडो ट्रेनिंग दे रहे हैं, कभी किसी कमांडो से पहले कोई जटिल स्टेप नहीं कराया, पहले खुद किया, तब उन्हें प्रशिक्षित किया...। यह कहना है देश की इकलौती कमांडो ट्रेनर 50 वर्षीय कमांडो सीमा राव का। पति-पत्नी मेजर दीपक राव और सीमा राव बीस साल में आइटीबीपी, वायु सेना, एनएसजी कमांडो, पैरामिलिट्री, इंडियन पैरा स्पेशल फोर्स, कमांडो विंग, कॉर्प्स बैटल स्कूल, नेवी मार्कोस मरीन कमांडो आदि के 20 हजार से अधिक सैनिकों को प्रशिक्षित कर चुके हैं।

डिफेंस में भर्ती होने के बाद सैनिक को हर परिस्थिति से लड़ने का प्रशिक्षण मिलता है। लेकिन हम उससे आगे की और सबसे बड़ी चुनौती- क्लोज क्वार्टर बैटल, यानी 30 यार्ड के भीतर बनने वाली युद्ध की परिस्थितियों में कैसे लड़ा जाए और जीता जाए, इसका प्रशिक्षण दे रहे हैं। एक योद्धा को और सशक्त बनाना आसान नहीं होता। उसके लिए पहले हम दोनों खुद एक-दूसरे को नई-नई युद्ध तकनीकों में सक्षम बनाते हैं...। दीपक और सीमा कहते हैं कि यह प्रशिक्षण सिर्फ शारीरिक ही नहीं मानसिक भी होता है। क्लोज क्वार्टर बैटल की ट्रेनिंग में फिजिकल स्किल्स, मसलन शूट करना, अनआर्म्ड कॉम्बैट, टीम ऑन टैक्टिक्स, सिम्यलेशन एक्सरसाइज आदि शामिल हैं। देशभर में जहां भी प्रशिक्षण देने के लिए जाते हैं या बुलाया जाता है तो वहां 20 से 30 सैनिकों की एक टुकड़ी को 10-15 दिन में प्रशिक्षित किया जाता है।

क्लोज क्वार्टर बैटल मेथोडोलॉजी संबंधी सर्टिफिकेशन हासिल कर चुकीं सीमा को पिछले वर्ष राष्ट्रपति द्वारा नारी सम्मान भी मिल चुका है। पुरुष सैनिकों को प्रशिक्षण देने के बारे में कहती हैं कि हमारी आर्मी और पूरे डिफेंस सिस्टम में प्रशिक्षण की तकनीक इतनी परिपक्व हैं कि हमें अन्य देशों की सेनाओं के प्रशिक्षण से सीखने का सहारा नहीं लेना पड़ता। हां, सभी जगह सिर्फ पुरुष सैनिकों को देखकर सोचती हूं कि आधी आबादी की यहां तक पहुंच अभी कमजोर है, लेकिन धीरे-धीरे इसमें परिवर्तन भी आ रहे हैं।

मेजर दीपक ने बताया, हम दोनों कई साल से अपने द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण पर किताबें भी लिख रहे हैं। अब तक हमारी सात किताबें आ चुकी हैं। इसके अलावा हमने क्लोज कॉम्बैट को लेकर दुनिया का पहला इनसाइक्लोपीडिया भी तैयार किया है। इसकी प्रति गृह मंत्रालय के साथ-साथ भारतीय सेना के पास भी मौजूद है। इसके अलावा कमांडो मैनुअल ऑफ कॉम्बैट भी तैयार किया। इनमें वह सारी तकनीकी बारीकियां हैं, जो हम सैनिकों को सिखाते हैं। और पहले खुद करके दिखाते हैं।

कमाल का जज्बा... : सीमा और दीपक कहते हैं कि प्रशिक्षण देने पर कोई असर न हो इसके लिए संतान सुख को भी छोड़ दिया। एक बिटिया गोद ली, जिसका नाम कोमल है और अब वह भी हमारी तरह कमांडो से कम नहीं है। उसका सिर्फ नाम कोमल है। हमारी राहों में भी चुनौतियों ने खूब टांग अड़ाई, लेकिन खुदको कभी रुकने नहीं दिया।

मेजर दीपक राव और सीमा राव। सौ. मेजर दीपक राव

आज तक हमने बॉर्डर पर भी कई सैनिकों को प्रशिक्षण दिया, लेकिन 20 साल में कहीं भी कभी भी इसके लिए किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया। शरीर जब तक साथ देगा, देश के लिए यह सेवा इसी तरह देते रहेंगे।
- मेजर दीपक राव, कमांडो ट्रेनर

अब तक तो एक स्वतंत्रता सेनानी की बेटी होने का फर्ज अदा किया है। हर संघर्ष भरी घड़ी में भी, कड़ी चुनौतियों के बीच भी देश के लिए कुछ करने की ललक को बरकरार रखा है। हालांकि अब उम्र हो रही है, प्रशिक्षण देने में आगे शारीरिक चुनौती पेश आएगी, लेकिन जब तक कर सकते हैं अपने देश और माटी के लिए मेजर दीपक और मैं ऐसे ही अपना कर्तव्य निभाएंगे।
-सीमा राव, कमांडो ट्रेनर

20 हजार से अधिक सैनिकों, पुलिस कर्मियों को कर चुके हैं प्रशिक्षित

30 यार्ड की क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए देते हैं प्रशिक्षण

सूरजकुंड में उमड़ा पर्यटकों का हुजूम

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद

सूरजकुंड मेले के अंतिम शनिवार के दिन लोगों की जबरदस्त भीड़ रही। भीड़ का आलम यह था कि सेल्फी प्वाइंट पर फोटो खिंचवाने के लिए भी दर्शकों-पर्यटकों को इंतजार करना पड़ा। मेले में लोगों की भीड़ के कारण सूरजकुंड रोड पर भी लंबा जाम लग गया। वाहन रेंग-रेंग कर मेला परिसर की तरफ जाते हुए दिखाई दिए।

शनिवार सुबह नौ बजे से ही मेले में सभी गेटों पर टिकट के लिए लंबी लाइनें लग गई थी। भीड़ इतनी अधिक थी कि टिकट लेने के लिए भी धक्का मुक्की हुई। गेट पर खड़े सुरक्षाकर्मियों को भी भीड़ को व्यवस्थित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। रविवार को मेले का अंतिम दिन है। राज्यपाल द्वारा शिल्पियों को पुरस्कार वितरण के साथ ही मेला समाप्त हो जाएगा और सोमवार की सुबह हस्तशिल्पी अपने घर को वापस लौटना शुरू कर देंगे।

मेले का एक दिन शेष होने के कारण हस्तशिल्पियों ने अपने उत्पादों पर छूट भी बढ़ा दी। शुक्रवार को जहां 20 से 30 फीसद छूट दी जा रही थी, वहीं अब यह बढ़ कर 40 से 70 फीसद तक छूट दी। सामान पर छूट मिलते ही पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे और लोगों ने जमकर खरीदारी की। मेले में प्रत्येक स्टाल पर जबरदस्त भीड़ रही। खरीदारी करने वाले लोगों में महिलाओं और युवाओं की संख्या अधिक थी। स्टाल पर भीड़ होने के कारण हस्तशिल्पकारों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। युवाओं ने जमकर मौज मस्ती की। बंचारी के नगाड़ों एवं ढोल और सपेरों की बीन से निकलने वाली फिल्मी धुनों पर जमकर नृत्य किया। हरियाणा के अपना घर एवं सूरजकुंड मेला परिसर बने विभिन्न राज्यों के द्वार पर युवाओं के ग्रुप सेल्फी ले रहे थे। इसके अलावा मेले में घूम रहे बहरूपियों के साथ भी फोटो खिंचवाई। मेला चौपाल पर दर्शकों ने राजस्थानी, हरियाणवी और थीम स्टेट हिमाचल प्रदेश के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत लोक नृत्यों का आनंद लिया।

मौसम विशेष

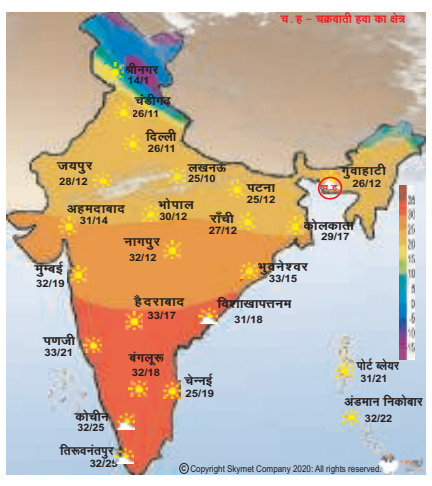

जम्मू-कश्मीर में मुख्यतः आसमान साफ बना रहेगा। लद्दाख में आंशिक बादल छाये रहेंगे। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली राजस्थान व पश्चिम उत्तर प्रदेश में शुष्क मौसम जारी रहेगा। दिन के समय हल्की से मध्यम गति की हवाएं प्रभावित करेंगी तथा दोपहर गर्म रहेगी। सुबह ठंडी बनी रहेगी।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	31/20/आंबा	अहमदाबाद	32/15/आंबा
कोलकाता	30/16/सा	बड़ोदा	36/14/सा
चेन्नई	32/22/सा	नागपुर	32/13/आंबा
हैदराबाद	32/16/सा	इन्दौर	30/13/सा
बंगलूरू	31/19/सा	रांची	28/13/सा
त्रिवेन्द्रम	32/24/आंबा	पटना	26/13/सा
गुवाहाटी	29/17/सा	जमशेदपुर	33/14/सा
गंगटोक	12/08/आंबा	पुणे	34/19/सा

साप्ताहिक राशिफल

रविवार 16 फरवरी, 2020 से शनिवार 22 फरवरी, 2020 तक — पं. बी. बी. शास्त्री 'देवेश'

मेष (चू,चे,चो,ला,ली,लू,ले,लो,आ)
व्यापार, नौकरी, उद्योग के कार्य में सफलता, धनागम अच्छा, सहयोगी जनों से सावधान, साझेदारी में व्यवधान, पारिवारिक चिंता समाप्त, वाहन भवन योग, चयन में देरी, मित्रों से सावधान, ससुराल में अनबन, राज्य पक्ष से सावधान, धर्म में रुचि, शुभ अंक 8 ।

वृष (इ,ऊ,ए,ओ,पा,वी,वू,वे,वो)
नौकरी, व्यापार, उद्योग के कार्य में सहयोग से सफलता, आत्मविश्वास की वृद्धि, सामाजिक कार्य का योग, चिंता की समाप्ति, वाहन-भवन योग, संतान से चिंतित, चयन में देरी, ससुराल से सहयोग, वाहन में सावधानी, अधिकारी से अनबन, यंत्र स्थापन, शुभ अंक 7 ।

मिथुन (का,की,कू,घ,ड,छ,के,को,हा)
अर्थ साधन ठीक, सहयोगियों से सावधान, विदेश कार्य में सफलता, धन के आवागमन में सावधानी, पारिवारिक सहयोग, भूमि कार्य में विलंब, संतान से सहयोग, शिक्षा में व्यवधान, शत्रु से विरोध, यात्रा में सावधानी, महत्वाकांक्षा की पूर्ति, शुभ अंक 6 ।

कर्क (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डू,डे,डो)
धनागम में अधिक प्रयास, साझेदारी में सावधानी, मन में असंतोष, संतान से सहयोग, शिक्षा कार्य में सफलता, वाणी पर संयम, ससुराल से सहयोग, यात्रा से बचें, वाहन में सावधानी, संवेदनशील क्षणों में सावधानी, यंत्र स्थापन योग, शुभ अंक 11 ।

सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे)
नौकरी, उद्योग, व्यापार के कार्य में सहयोग से सफलता, व्यर्थ की भागदौड़, भवन में निर्माण योग, संतान से सहयोग, शिक्षा कार्य में प्रगति, वाणी पर संयम रखें, जीवन साथी का मिलन, राज्य पक्ष से सावधानी, अधिकारी से सहयोग, बैंक कार्य में सफलता, शुभ अंक 12 ।

कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो)
अर्थसाधन में प्रयास, साझेदारी से तनाव, मानसिक असंतोष, भौतिक साधनों की पूर्ति, संतान की प्रगति, शिक्षा क्षेत्र में सफलता, शत्रु पक्ष प्रभावी, खानपान पर ध्यान दें, यात्रा से बचें, ससुराल से सहयोग, नए अनुबंध में देरी, राजनीतिक प्रयास सफल, शुभ अंक 1 ।

तुला (रा,री,रू,रे,रो,ता,ती,तू,ते)
अर्थसाधन में प्रयास, सलाह से कार्य करें, आत्मविश्वास की कमी, साझेदारी में सावधानी, विदेश कार्य में प्रगति, चिंता की समाप्ति, संतान से सहयोग, शत्रु पक्ष प्रभावी, मित्रों से सावधान, दांपत्य में सुख, यात्रा से बचें, नए अनुबंध में देरी, राज्यपक्ष से सावधान, शुभ अंक 2 ।

वृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू)
व्यापार, नौकरी, उद्योग के कार्य में प्रयास से सफलता, अर्थसाधन में प्रयास, व्यर्थ की भागदौड़, विदेश कार्य में प्रयास सार्थक, मन में असंतोष, चयन में सफलता, वाद-विवाद से बचें, त्वचा, नेत्र विकार योग, प्रणय में मतभेद, यात्रा से बचें, राज्यपक्ष से सावधान, शुभ अंक 4 ।

धनु (ये,यो,भा,भी,भू,धा,फा,ढा,भे)
व्यापार, नौकरी, उद्योग के कार्य में श्रम से सफलता, अर्थ साधन में प्रयास, सलाह से निर्णय करें, कार्यशैली में सुधार करें, व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी, चिंताग्रस्त संतान से सहयोग, वाद-विवाद से बचें, सिर-पैर दर्द का योग, यात्रा से बचें, राजनीतिक कार्य में सफल, शुभ अंक 5 ।

मकर (भो,जा,ज,खी,खू,खे,खो,गा,गी)
व्यापार, नौकरी, उद्योग के कार्य में श्रम से सफलता, अर्थ साधन में सुधार, सहयोगी जनों से सहयोग, साझेदारी में तनाव, चिंता का समाधान, संतान से सहयोग, वाद-विवाद से बचें, दांपत्य में अनबन, यात्रा में सावधानी, वाहन में सावधानी, यंत्र स्थापन योग, व्यय अधिक, शुभ अंक 11 ।

कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सा,दा)
अर्थसाधन में सुधार, सलाह से निर्णय करें, किसी व्यक्ति के कारण तनाव, कार्य करने वालों से सहयोग, पारिवारिक व्यक्ति का स्वास्थ्य सुधार, भौतिक साधनों की पूर्ति, संतान के लिए कार्य योजना, चयन में अवरोध, मित्रों से विरोध, पत्नी से सहयोग, शुभ अंक 9 ।

मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची)
धनागम में सुधार, व्यर्थ की भागदौड़, महत्वांकाक्षा की पूर्ति, साझेदारी में सावधानी, धन के आवागमन में सावधानी, मन में असंतोष, संतान से संतुष्टि, चयन में सफलता, कुसंग से बचें, दांपत्य में मतभेद, वाहन में सावधानी, यंत्र स्थापन योग, परिवर्तन प्रयास सार्थक, शुभ अंक 9 ।

राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

आजकल

रविवार 16 फरवरी 2020

16

www.jagran.com

रोजमर्रा की जरूरत बनने वाले नायलॉन का पेटेंट मिला

आज ही के दिन 1937 में नायलॉन की खोज करने वाले अमेरिकी आविष्कारक वॉलेस कैरोदर्स को इसका पेटेंट मिला था। पहली बार नायलॉन का इस्तेमाल 1938 में टूथब्रश बनाने में किया गया। बाद में इसका इस्तेमाल कपड़े सहित अन्य चीजों में भी किया जाने लगा था।

दुनिया का चक्कर लगाने के लिए निकली अमेरिकी पनडुब्बी

आज ही के दिन 1960 में अमेरिकी पनडुब्बी यूएसएस ट्राइटन दुनिया का चक्कर लगाने के लिए निकली। ऑपरेशन सैंडब्लास्ट के तहत 10 मई 1960 को कनेक्टिकट लौट आईं। उस वक्त यह दुनिया की सबसे बड़ी, शक्तिशाली और सर्वाधिक लागत वाली पनडुब्बी थी।

ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल

आज ही के दिन 1997 में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र की क्योटो संधि को लागू किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने 1992 में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कंवेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज नामक सम्मेलन का आयोजन किया था। इसी को विस्तार देते हुए 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में इस प्रोटोकॉल को स्वीकृति दी गई थी। इस अंतरराष्ट्रीय संधि का उद्देश्य है कि सदस्य देशों में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम हो। इस संधि पर 192 देशों ने हस्ताक्षर किए। शुरुआत में इसकी अवधि 2012 तक रखी गई थी। हालांकि बाद में इसे आठ सालों के लिए बढ़ा दिया गया।

इधर-उधर की

26 साल बाद प्रदर्शनी में मिली गुम हुई कैसेट

स्टोकहोम, एजेंसी : परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए स्पेन गई एक महिला को 26 साल बाद वो मिला, जिसे वह बरसों पहले खो बैठी थी। महिला को भी यकीन नहीं हुआ कि कोई चीज इतने सालों बाद भी मिल सकती है। बर्लिन की रहने वाली स्टेला वैडेल जब 12 साल की थी तो घर में रिकॉर्ड करवाए कैसेट को छुट्टी मनाने के दौरान स्पेन के मजोरका में खो दिया था। हालांकि 26 साल बाद एक दिन वह अचानक उनकी आंखों के सामने था। 2017 में मैंडी बार्कर को अपनी फुएरतेवेंतुरा यात्रा के दौरान यह टेप समुद्र किनारे मिला। खोने वाले स्थान से फुएरतेवेंतुरा की दूरी करीब 12 सौ मील से ज्यादा है। यह टेप अभी भी काम कर रहा था। मैंडी ने स्टॉकहोम में आयोजित प्रदर्शनी में इसे प्रदर्शित किया। स्टेला बिना किसी योजना के वहां पहुंची और कैसेट के गानों को सुना। इसके बाद वो जान गई कि यह उसका ही कैसेट है।

कार्बन डाईऑक्साइड से बनेगा ईंधन

नई तकनीक ▶ नैनोपार्टिकल का इस्तेमाल कर बनाए जाएंगे हाइड्रोकार्बन

नई विधि से कम लागत पर औद्योगिक पैमाने पर उत्पादित होंगे रसायन और ईंधन

प्रतीकात्मक

लास एंजिलिस, प्रेट्र: वैज्ञानिकों ने एक ऐसी नई तकनीक विकसित की है जो नैनोपार्टिकल का इस्तेमाल कर कॉर्बन डाईऑक्साइड को हाइड्रोकार्बन ईंधन और अन्य उपयोगी सामग्री में परिवर्तित करती है। अमेरिका में यूएससी विटर्बी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के शोधकर्ताओं ने मेटल कार्बाइड नैनोपार्टिकल की खोज की है। यह कार्बन और मेटल का एक यौगिक है। इसके माध्यम से कार्बन डाईऑक्साइड को ईंधन में बदला जा सकता है।

'अमेरिकन केमिकल सोसाइटी' जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार इन नैनोपार्टिकल को कम लागत पर औद्योगिक पैमाने पर उत्पादित किया जा सकता है। दुनिया में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में यह एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान कर सकता है। प्रोफेसर नोआ मालमस्टाड ने कहा, 'हम कार्बन डाईऑक्साइड बंधन को कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन हाइड्रोजन बंधन में बदलते हैं। इस तरीके से हम कार्बन डाईऑक्साइड को फिर से हाइड्रोकार्बन में तब्दील कर देते हैं।' मालमस्टाड ने कहा कि हाइड्रोकार्बन बुनियादी ईंधन स्टॉक हैं। उन्हें या तो मीथेन या प्रोपेन में बदल सकते हैं या फिर उन्हें रासायनिक संश्लेषण के आधार के रूप में उपयोग कर सकते हैं ताकि उनके माध्यम से अधिक जटिल रसायन का निर्माण किया जा सके। शोधकर्ताओं ने बताया कि नई विधि से कार्बन उत्सर्जन को उपयोगी सामग्री में बदलकर उपभोक्ताओं के लिए मुहैया कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अभी तक कार्बन डाईऑक्साइड को ईंधन में बदलने की जितनी विधियां मौजूद हैं वे बहुत मंहगी और जटिल हैं, जिसकी वजह से व्यवहारिक उपयोग में नहीं लाई जा सकती हैं।

नैनोपार्टिकल एक ऐसी प्रक्रिया का उपयोग कर बनाए जाते हैं जहां कार्बाइड को 600 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया में नैनोपार्टिकल के आकार को नियंत्रित करना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से उत्प्रेरक की कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ता है।

यह है नई तकनीक

शोधकर्ताओं ने बताया कि नई तकनीक में मिलीफ्लूडिक रिएक्टर प्रणाली का उपयोग किया गया है, जो एक बहुत छोटे स्तर की रासायनिक रिएक्टर प्रणाली है। इसमें एक मिलीमीटर से भी कम के चैनलों में प्रक्रिया संचालित होती है। पारंपरिक रिएक्टर की तुलना में इससे बहुत अधिक लाभ मिलता है। इसका पर्यावरण पर प्रभाव भी न्यूनतम होता है। नई तकनीक के तहत नैनोपार्टिकल का निर्माण 300 डिग्री सेंटीग्रेट में हो जाता है। इसमें नौनोपार्टिकल का आकार भी छोटा और एक जैसा होता है, जिससे अधिक प्रभावी ढंग से कार्बन डाईऑक्साइड को हाइड्रोकार्बन में बदला जाता है।

डिस्टिलरी इकाइयों के अपशिष्ट से बनेगा पोटाश

- भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित तकनीक से अपशिष्ट जल से निपटने में मिलेगी मदद
- देश की 350 डिस्टिलरी इकाइयां से हर साल तीन हजार करोड़ लीटर अपशिष्ट निकलता है

प्रतीकात्मक

नई दिल्ली, आइएसडब्ल्यू : उद्योगों और स्वच्छ ईंधन के लिए एथेनॉल की मांग लगातार बढ़ रही है। पर, इसके उत्पादन से निकले अपशिष्ट जल से मिट्टी, भूजल एवं नदियों का प्रदूषण एक चुनौती है। भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित एक नई तकनीक इस अपशिष्ट जल के प्रबंधन के साथ-साथ दूषित जल के पुनर्चक्रण में मददगार हो सकती है। इसके अलावा, पोटाश फर्टीलाइजर एवं पशु आहार में उपयोग होने वाले जैविक घटक जैसे उत्पाद भी प्राप्त किए जा सकेंगे।

देशभर में गन्ने के सीरे पर आधारित 350 से अधिक डिस्टिलरी इकाइयां हैं, जहां हर साल करीब 250 करोड़ लीटर अल्कोहल उत्पादन होता है और लभगभ तीन हजार करोड़ लीटर तरल अपशिष्ट निकलता है।

यह अपशिष्ट गहरे भूरे रंग का एक अपारदर्शी पदार्थ है, जिसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने इस अपशिष्ट से पोटाश, कार्बनिक तत्वों और पानी को अलग करने के लिए विभिन्न पृथक्करण विधियों का प्रयोग किया है।

डिस्टिलरी से निकले अपशिष्ट जल को थक्के जमाने की तकनीक से कोलाइड और जैविक घटकों को अलग किया जाता है। कोलाइड एक प्रकार का रासायनिक मिश्रण है, जिसमें विभिन्न तत्वों के कण बिखरे रहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान शेष बचे विलयन से पोटाश अलग करने के लिए अवक्षेपण पद्धति अपनायी जाती है।

रासायनिक क्रिया के जरिये किसी विलयन से ठोस उत्पाद प्राप्त करना अवक्षेपण कहलाता है। पोटाश अलग करने के बाद शेष बचे तरल पदार्थ को गर्म करके गाढ़ा किया जाता है और वाष्पन से पानी को अलग कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया से एक ठोस पदार्थ लवण रहित जैविक घटक (डिपोटाश ऑर्गेनिक) प्राप्त होता है।

हर साल मिल सकता है छह लाख टन पोटाश : यह तकनीक केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान (सीएसएमसीआरआइ), भावनगर के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि देशभर की डिस्टिलरी इकाइयों में इस पद्धति का उपयोग किया जाए तो प्रतिवर्ष करीब छह लाख टन पोटाश प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह हर साल पोटाश के आयात पर खर्च होने वाले लगभग 700 करोड़ रुपये की बचत की जा सकेगी। फिलहाल खेती में उर्वरक के रूप में उपयोग होने वाले पोटाश के लिए भारत पूरी तरह आयात पर निर्भर है।

दोबारा उपयोग में आ सकेगा 2500 करोड़ लीटर पानी : सीएसएमसीआरआई के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ प्रत्यूष मैती के मुताबिक पोटाश के अलावा दो अन्य बहुमूल्य उत्पाद स्वच्छ पानी और डिपोटाश ऑर्गेनिक इस पद्धति के उपयोग से प्राप्त किए जा सकते हैं। इस तकनीक से हर साल 2500 करोड़ लीटर पानी का पुनर्चक्रण किया जा सकेगा।

डिपोटाश ऑर्गेनिक का उपयोग पशु आहार में बाइंडर के रूप में किया जा सकता है। पशु आहार में बाइंडर के रूप में फिलहाल चीनी मिलों से निकले सीरे का उपयोग किया जाता है।

लागू की गई तकनीक : इस पद्धति को औरंगाबाद डिस्टिलरी में लागू किया गया है, जिसकी प्रतिदिन अल्कोहल उत्पादन क्षमता 60 हजार लीटर है। इस तकनीक की मदद से इस डिस्टिलरी में प्रतिदिन करीब 15 टन पोटाश और 70 टन डिपोटाश ऑर्गेनिक प्राप्त होता है। इसके साथ-साथ हर दिन पांच लाख लीटर पानी का पुनर्चक्रण भी हो रहा है, जिसको औद्योगिक कार्यों के लिए दोबारा उपयोग किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने बताया कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए परीक्षणों में डिपोटाश ऑर्गेनिक को पशु आहार के अनुकूल पाया गया है।

अध्ययन : काम के दौरान आपकी मेज पर रखा पौधा घटाता है तनाव

स्पेक्ट्रम

- जापान की एक इलेक्ट्रिक कंपनी के कर्मचारियों पर किया गया अध्ययन, पौधे से पाए गए सकारात्मक परिणाम

प्रतीकात्मक फोटो

टोक्यो, एएनआइ : व्यस्त कार्यस्थल पर तनाव के बीच काम करने के दौरान आपकी मेज पर रखा एक पौधा काफी हद तक आपको आराम पहुंचा सकता है। सीएनएन हेल्थ के अनुसार जापान के शोधकर्ताओं के समूह ने काम के दौरान तनाव को कम करने में पौधों की भूमिका पर अध्ययन किया।

शोधकर्ताओं ने जापान की एक इलेक्ट्रिक कंपनी के कर्मचारियों पर अपना अध्ययन किया। उन्होंने कर्मचारियों के तनाव का स्तर पहले मापा और फिर पौधों के साथ तीन मिनट बिताने के बाद दोबारा मापा। 'हार्टटेक्नोलॉजी' नामक पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के बताया गया कि पौधों के साथ तीन मिनट बिताने के बाद कर्मचारियों के तनाव के स्तर पर मामूली गिरावट देखी गई, लेकिन उनकी हृदयगति पर 27 प्रतिशत तक आराम देखा गया। शोधकर्ताओं ने बताया कि यह अध्ययन अनोखा है क्योंकि इसे न केवल वास्तविक कार्यालय के माहौल में किया गया, बल्कि इसमें पौधों की सक्रिय रूप से देखभाल करने से होने वाले प्रभावों का भी विश्लेषण किया गया। ह्योगो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और इस अध्ययन के प्रमुख लेखक मासाहिरो टोयोडा ने बताया कि अध्ययन में यह पाया गया कि तनाव भरे काम में कुछ समय के दौरान तीन मिनट का 'नेचर ब्रेक' लेने से कर्मचारियों की मानसिक भलाई में एक सकारात्मक रुझान देखा गया। इससे उनके काम करने की क्षमता और क्वालिटी भी बढ़ गई।

आपके जीन से जुड़ा हो सकता है खर्राटे का संबंध

ब्रिस्बेन, एएनआइ : सोते समय खर्राटे लेने की आदत आपके जीन से जुड़ी हो सकती है। शोधकर्ताओं ने नए अध्ययन में इस बात का दावा किया है। ऑस्ट्रेलिया के क्यूआइएमआर बरगॉफर मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने 173 ऐसे जीन की पहचान की है जिनका संबंध खर्राटे और अत्यधिक वजन से है। नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में इस अध्ययन को प्रकाशित किया गया है। अध्ययन के प्रमुख लेखक डॉ. मिगुएल ई रेंटेरिया ने बताया कि खोजे गए ये जीन मनुष्य के जीनोम के 42 क्षेत्रों में स्थित हैं। उन्होंने बताया कि खर्राटे का आनुवंशिकी से संबंध बताने वाला यह सबसे बड़ा अध्ययन है। उन्होंने बताया कि जिन जीनों का संबंध खर्राटों से पाया गया है उनमें से कई पहले स्वसन, हृदय, चयापचय, न्यूरोलॉजिकल और मनोरोग लक्षणों से जुड़े हुए हैं। हालांकि, खर्राटे के संबंध में लोगों के बीच अपने-अपने मत हैं। माना जाता है कि खर्राटे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की ओर इशारा करते हैं।

18 फरवरी को मंगल के आगे से होकर निकलेगा चंद्रमा

वाशिंगटन, एएनआइ : 18 फरवरी मंगलवार की सुबह सूर्योदय से पहले मंगल ग्रह के सामने से चंद्रमा होकर गुजरेगा। इस घटना को मंगल के ग्रहण के रूप में देखा जा रहा है। खगोलविदों ने बताया है कि 2020 में चंद्रमा मंगल ग्रह के सामने से पांच बार होकर निकलेगा, लेकिन फरवरी में होने वाला ग्रहण एकमात्र ऐसा है, जिसको उत्तर और मध्य अमेरिका के अधिकांश हिस्सों से देखा जा सकेगा।

यह घटना दक्षिणपूर्व क्षितिज में दिखाई देगी। इस दौरान चंद्रमा पूरा नहीं बल्कि अर्धचंद्राकार आकार में होगा। चंद्रमा को मंगल ग्रह के सामने पूरी तरह आने में लगभग 14 सेकेंड का वक्त लगेगा। चूंकी मंगल ग्रह दूर होने की वजह से चांद की तुलना में अत्यंत अधिक छोटा दिखता है। इस कारण चांद को मंगल को कवर करने में समय नहीं लगेगा।

चंद्रमा को मंगल से होकर निकलने में लगभग आधा घंटा का समय लग सकता है इसके साथ ही यह देखने वाले की स्थिति पर भी निर्भर करता है। इसको देखने का समय भी जगह के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

लाल ग्रह से आई वैलेंटाइन डे की बधाई

नासा द्वारा खींची गई मंगल की तस्वीर। सौ. इंस्टाग्राम

नई दिल्ली, आइएएनएस : अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि वह अंतरिक्ष को प्यार करता है और कभी-कभी अंतरिक्ष उसे वह प्यार वापस करता है। हाल में मंगल ग्रह से दिल के आकार की मनमोहक तस्वीरें आई हैं। नासा ने इन तस्वीरों को इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर करते हुए 'हैप्पी वैलेंटाइन डे' का कैप्शन लिखा है। लाल ग्रह के आर्बिटर में घूम रहे नासा के ग्लोबर सर्वेयर द्वारा यह तस्वीर खींची गई है। जैसे ही यह तस्वीर वायरल हुई तो सोशल मीडिया प्लेटफार्म प्रतिक्रियाओं से भर गया। एक यूजर ने लिखा, 'कम से कम ब्रह्मांड में कहीं न कहीं प्यार है।' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'मंगल और बाहर के सभी प्राणियों को हैप्पी वैलेंटाइन डे।'

फोटो न्यूज

लकड़ी की बंदूकों से प्रशिक्षण

यह बेहद हैरान करने वाला है कि जातीय हिंसा की आग में झुलस रहे दक्षिणी सूडान में सैनिकों को 'लकड़ी की राइफलों' से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार और विपक्ष से सेनाओं के पुनर्मिलन कराने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र मिशन के सामंजस्य कार्यक्रम के अंतर्गत महिला एवं पुरुष सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसकी खास बात है कि प्रशिक्षण के दौरान उन्हें असली की जगह लकड़ी की राइफलें दी गई हैं। यहां जारी जातीय हिंसा में एक हजार से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने देश में साढ़े सात हजार सैनिक तैनात कर रखे हैं। एएफपी

स्क्रीन शॉट

मां की डांट पड़ी तो गाली देने से तौबा कर ली श्रद्धा ने

पर्दे पर किरदार को उसके मुकाम तक पहुंचाने के लिए कलाकार वह हर काम कर गुजरते हैं, जो वे असल जीवन में नहीं करते हैं। बचपन में ही गाली देने से तौबा कर लेने वाली श्रद्धा कपूर फिल्म 'बागी' फिल्म की फ्रेंचाइची 'बागी 3' में वह बिंदास अंदाज में गालियां देती नजर आ रही हैं। यह उन्हें अपने किरदार की वजह से करना पड़ रहा है। वैसे यह पहली बार नहीं है, जब कोई अभिनेत्री पर्दे पर गालियां देती दिखेगी। इससे पहले भी करीना कपूर खान, विद्या बालन, रानी मुखर्जी जैसी कई अभिनेत्रियों ने अपने-अपने किरदार के जरिये ऐसा किया है। फिल्म 'बागी 3' में श्रद्धा बेधड़क होकर गाली दे रही हैं, लेकिन यह करना उनके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि वास्तविक जीवन में श्रद्धा गाली-गलौज से दूर ही रहती हैं। श्रद्धा बताती हैं कि उन्होंने पहली बार तब गाली दी थी, जब वह स्कूल में थीं। श्रद्धा ने बताया कि जब उनकी मम्मी को पता चला कि मैंने गाली दी है, तो उनके होश उड़ गए। मम्मी से बहुत डांट पड़ी थी।

लीजा हेडन दूसरी बार बनीं मां, दिखाई नवजात बेटे की झलक

लीजा हेडन अपने बेबी बंप की तस्वीरें काफी वक्त से सोशल मीडिया पर साझा करती रही हैं। हाल ही में उन्होंने दूसरे बेटे को जन्म दिया है। शनिवार को उन्होंने उसकी झलक दिखाई। 'ऐ दिल है मुश्किल', 'हाउसफुल 3' और 'क्वीन' जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुकीं लीजा ने अपने नवजात बेटे का नाम लियो रखा है, जबकि बड़े बेटे का नाम जैक है। लियो और जैक की साथ में एक तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने लिखा, 'इस छोटे से आशीर्वाद ने मेरे दिल को छू लिया। मैं आप दोनों (बच्चों) को साथ-साथ देखकर निश्शब्द हो गई हूं। मुझे यकीन ही नहीं होता है कि मैं आप दोनों की मां हूं। लियो, जैक और मेरे वैलेंटाइन- कल हमारी मुलाकात की 5वीं सालगिरह थी। 13 फरवरी शुक्रवार, जिसके बाद जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई।' उन्होंने अपने पति के लिए लिखा कि मेरे साथ परिवार बनाने के लिए शुक्रिया। लीजा ने वर्ष 2016 में बिजनेसमैन डीनो लालवानी से शादी की थी। वर्ष 2017 में उनके पहले बेटे जैक का जन्म हुआ था।

श्रेयस ने एक बार फिर संभाली निर्देशन की बागडोर

अभिनेता श्रेयस तलपड़े फिल्मों के साथ बाकी माध्यमों में भी काम करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। वेब शो करने के बाद एक लंबे अंतराल के बाद उन्होंने टीवी पर वापसी की है। वह जीटीवी के क्विज शो 'माइंड वॉर' की मेजबानी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर फिल्म 'सरकार की सेवा में' का निर्देशन भी कर रहे हैं। फिल्म में वह अभिनय भी कर रहे हैं। फिल्म के एक शेड्यूल की शूटिंग पूरी हो चुकी है। फिल्म के बारे में श्रेयस बताते हैं कि यह सत्य घटना से प्रेरित है। फिल्म हंसाने के साथ सामाजिक संदेश भी देगी। कहानी बिहार के एक टैक्सी ड्राइवर से प्रेरित है, जो सरकारी नौकर बनना चाहते थे और पार्ट टाइम टैक्सी चलाते थे। किसी कारणवश एक दिन उन्होंने खुद की टैक्सी खरीदी। वह टैक्सी अगले दिन चोरी हो गई। फिल्म में टैक्सी ढूंढ़ने में उनकी जर्नी है। यह किरदार पूरी जिंदगी तमाम कोशिशों के बावजूद सरकारी नौकर नहीं बन पाता है, लेकिन टैक्सी की वजह से बन जाता है। सरकार को जो काम करना चाहिए, यह करने लगता है। आगे की कहानी इसी संबंध में है। ट्विस्ट यह है कि वह चोरी की गाड़ी ढूंढ़ लेता है, लेकिन उसे वापस लाने के लिए उसे खुद चोरी करनी पड़ती है।

निक जोनास ने किया रणवीर सिंह के गाने पर डांस

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास की जोड़ी सोशल मीडिया पर छाई रहती है। भारत और अमेरिका में टाइम के अंतर की वजह से प्रियंका और निक के वैंलेटाइन के पल थोड़ी देरी से देखने को मिले, लेकिन इन पलों में रोमांस कम और मस्ती ज्यादा नजर आ रही थी। निक जोनास ने प्रियंका चोपड़ा के साथ डांस करते हुए एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह रणवीर सिंह और सारा अली खान के 'सिम्बा' फिल्म के गाने 'आंख मारे...' पर जमकर नाच रहे हैं। प्रियंका डांस करने के साथ ही वीडियो भी बना रही थीं। निक खुद संगीत की दुनिया से जुड़े हैं, ऐसे में हर तरह के संगीत से उनका लगाव रहा है। प्रियंका की वजह से हिंदी फिल्मी गानों से भी वह परिचित हैं। यह पहली बार नहीं था, जब निक हिंदी गानों पर थिरके हैं। इससे पहले भी उन्हें कई हिंदी गानों पर डांस करते देखा गया है। अपने शादी के संगीत समारोह में भी वह प्रियंका संग हिंदी गानों पर थिरके थे। निक ने इस वीडियो के साथ लिखा, 'मेरी हमेशा वाली वैलेंटाइन के साथ प्री शो डांस पार्टी।' दरअसल, यह वीडियो निक ने इटली में हुए जोनास ब्रदर्स के कॉन्सर्ट से पहले पोस्ट की थी।

अब रंगोली ने सितारों की छुट्टियों पर साधा निशाना

सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली कंगना रनोट की बहन रंगोली चंदेल तीखी टिप्पणियां करने के लिए जानी जाती हैं। इस बार उन्होंने सितारों की छुट्टियों को अपना निशाना बना लिया। रणवीर सिंह-दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर-आलिया भट्ट की तस्वीरें साझा करते हुए रंगोली ने इस बार उनकी विदेश में छुट्टियां मनाने को लेकर टिप्पणी की है। रंगोली के मुताबिक ये सितारे बड़े व महंगे देशों तथा छोटे व सस्ते देशों में भेदभाव बरतते हैं। रंगोली ने अपनी ट्वीट में लिखा, 'ये सेलिब्रिटी युगल जब यूरोप और अमेरिका की यात्रा पर जाते हैं, तो खुलकर इन देशों का प्रचार सोशल मीडिया पर करते हैं, मगर जब यही लोग श्रीलंका या बैंकॉक जैसी जगह छुट्टियों पर जाते हैं, तो वहां के लोकेशनों की जानकारी नहीं देते हैं। रंगोली ने आगे लिखा कि यह भेदभाव है। खूबसूरत जगह तो खूबसूरत ही होती है। उन्होंने लिखा, 'बॉलीवुड वालो, अविकसित देशों को ज्यादा जरूरत है प्रमोशंस की।' गौततलब है कि पिछले दिनों दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपनी छुट्टियों की लोकेशन के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी नहीं दी है। दरअसल, दीपिका और रणवीर इन दिनों विदेश में कहीं छुट्टियां मना रहे हैं। दीपिका ने इस बात की जानकारी अपने पासपोर्ट की तस्वीर साझा करके दी थी, लेकिन वे कहां छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, इस बात की जानकारी दोनों में से किसी ने नहीं दी।

दिव्या के म्यूजिक वीडियो याद पिया... का आएगा पार्ट 2

दिव्या खोसला कुमार अब पूरी तरह से अभिनय के क्षेत्र में उतर चुकी हैं। लंबे समय के बाद दिव्या स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। कुछ वक्त पहले उनका म्यूजिक वीडियो याद पिया की आने लगी... रिलीज हुआ था। अब बारी है इसके पार्ट 2 की, जो जल्द ही रिलीज होगा। यह गाना गायिका फाल्गुनी पाठक के गाने का रीक्रिएशन था, जिसमें दिव्या नजर आई थीं। इस गाने को यूट्यूब पर अब तक 200 मिलियन यानी बीस करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इस गाने के अंत में इसके दूसरे भाग के आने की संभावनाएं बताई गई थीं। गाने का दूसरा पार्ट कब रिलीज होगा, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। लेकिन यह तय है कि पहले गाने की तरह इस गाने का निर्देशन भी राधिका राव और विनय सप्रू ही करेंगे। पुराने गानों को रीमिक्स और रीक्रिएट करने को लेकर भूषण कुमार का कहना है कि यह ट्रेंड बिल्कुल सही है। आज की पीढ़ी ने कई पुराने गाने सुने ही नहीं हैं। ऐसे में संगीतकारों को खुश होना चाहिए कि उन्होंने जो रचनात्मक काम किया है, उसे रीपैकेज करके नई पीढ़ी को सुनाया जा रहा है।

व्यायाम व ग्रीन टी से कम होता है फैटी लिवर

शोध अनुसंधान

फैटी लिवर की बीमारी से राहत की दिशा में वैज्ञानिकों को बड़ी उपलब्धि मिली है। हालिया शोध में पाया गया है कि व्यायाम के साथ यदि ग्रीन टी का भी सेवन किया जाए, तो इससे फैटी लिवर की गंभीरता को कम करना संभव हो सकता है। फैटी लिवर मोटापे से संबंधित एक गंभीर बीमारी है। इसमें लिवर में वसा का जमाव हो जाता है। अभी इस बीमारी के इलाज का कोई तरीका ईजाद नहीं हुआ है। चूहों पर किए गए शोध में वैज्ञानिकों ने पाया कि नियमित रूप से व्यायाम करने और ग्रीन टी लेने वाले चूहों के लिवर में अन्य की तुलना में बमुश्किल चौथाई फैट जमा होता है। केवल ग्रीन टी या व्यायाम से इतना फायदा नहीं होता। वैज्ञानिकों ने पाया कि ग्रीन टी और व्यायाम के साथ से चूहों का शरीर पोषक तत्वों को ज्यादा बेहतर तरीके से प्रयोग करने में सक्षम होता है। इससे फैटी लिवर के इलाज का रास्ता भी खुल सकता है। - एएनआइ

अवसाद का शिकार बना सकते हैं फास्ट फूड

अगर आपका बच्चा भी फास्ट फूड का शौकीन है, तो सतर्क हो जाएं। फास्ट फूड की आदत आपके बच्चे को कई गंभीर शारीरिक और मानसिक बीमारियों का शिकार बना सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पिज्जा और बर्गर जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन ज्यादा करने से उनमें मोटापे का खतरा बढ़ जाता है। यह आगे चलकर फैटी लिवर, टाइप-2 डायबिटीज और अवसाद जैसी गंभीर समस्याओं का कारण भी बन सकता है। अध्ययन में तीन से पांच साल के 500 से ज्यादा बच्चों को शामिल किया गया था। सालभर के अध्ययन के बाद उनमें मोटापे की स्थिति जांची गई। अध्ययन के दौरान खानपान और बच्चों की सक्रियता जैसे सभी पैमानों को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण किया गया। वैज्ञानिकों ने बताया कि फास्ट फूड का सेवन करने वाले बच्चों में सेहत से जुड़े खतरे ज्यादा देखे गए। - आइएएनएस